# राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड

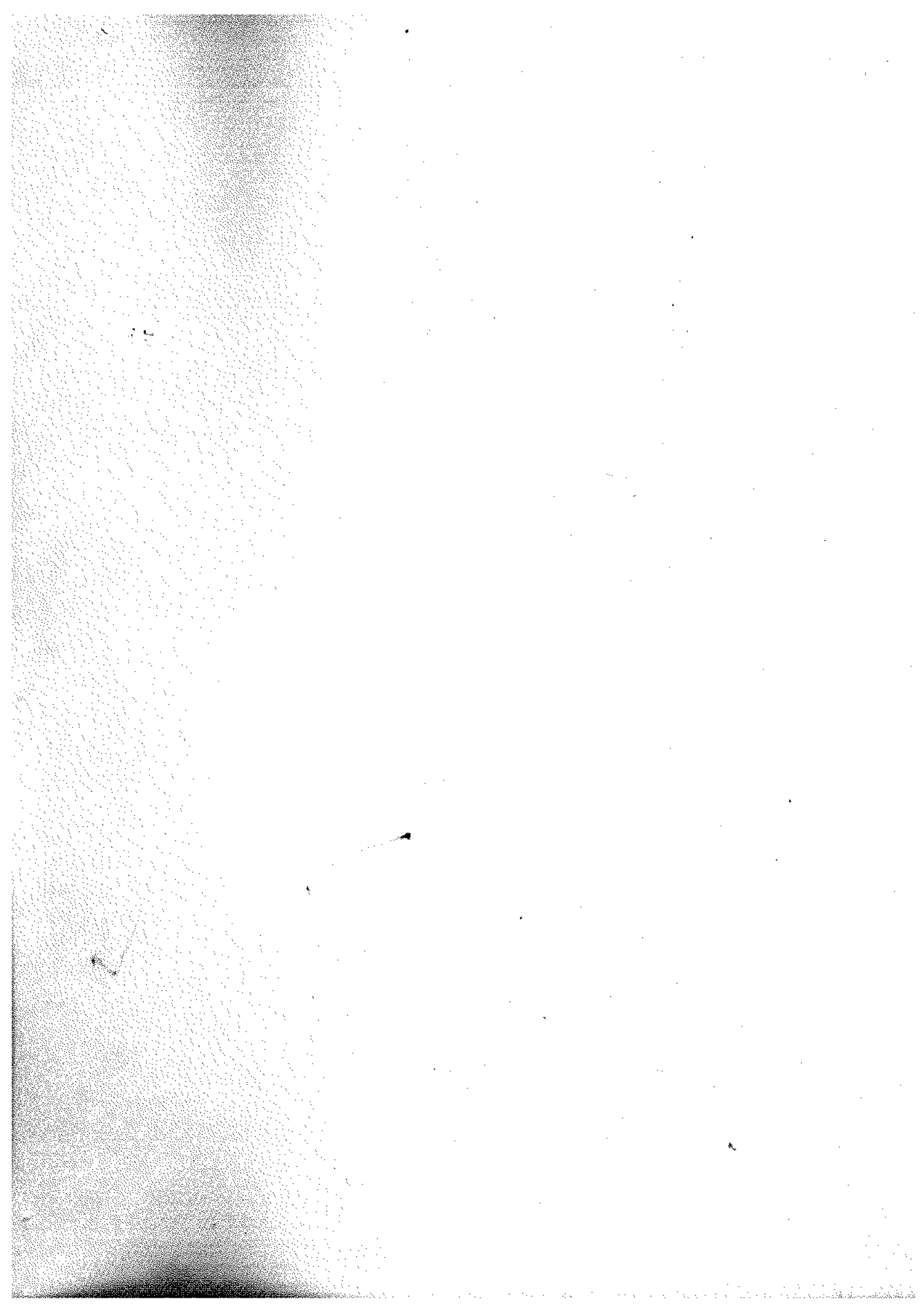
(एनआईसीडीसी लि.)

**(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)**

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

NICDC
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
*India Reimagined*

## वित्तीय वर्ष 2020-21



**संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया एल.ए.एफ.इ.ए. एस -सी.बी.II067/18/2019-सी.बी.-II दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय**

**मंत्रालय का नाम**: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

**विभाग का नाम**: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

**संगठन का नाम**: राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)

| क्रम संख्या | विवरण | टिप्पणी | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत्त / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है | निगम | | |
| 2 | संगठन की स्थापना का वर्ष | 2008 | | |
| 3 | क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी) | | |
| 4 | संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम | कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 | | |
| 5 | क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करे) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें) | हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न हैं) | | |
| 6 | यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हां में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें। | 31 दिसंबर | | |
| 7 | क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है। | वार्षिक | | |
| 8 | क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं; (हाँ या नहीं में इंगित करे) | हाँ | | |
| 9 | यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हां है, तो पिछले तीन वर्षों यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें। | वित्तीय वर्ष | लोकसभा | राज्यसभा |
| | | 2017-18 | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| | | 2018-19 | 04.12.2019 | 06.12.2019 |
| | | 2019-20 | 15.12.2021 | 12.02.2021 |
| 10 | यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है; तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है। | लागू नहीं | | |

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

**Rule 236** **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

**Rule 236** **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

**Rule 237** **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

**Rule 238 (1) Utilization Certificates.** In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

**Rule 238** **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

**Rule 238** **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in -aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

**Rule 238** **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

# 13वीं वार्षिक रिपोर्ट

# तथा

# लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

# (वित्तीय वर्ष 2020-21)

NICDC
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
*India Reimagined*

# राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड

(एनआईसीडीसी लि.)

**(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)**

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

# विषय सूची


| क्र.सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | कंपनी का परिचय | 1 - 3 |
| 2. | अध्यक्ष का संदेश | 4 - 5 |
| 3. | कॉरपोरेट सूचना | 6 |
| 4. | वार्षिक आम बैठक की सूचना | 7 - 19 |
| 5. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट | 20 - 59 |
| 6. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट | 60 - 62 |
| 7. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | 63 - 75 |
| 8. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण | 76 - 101 |
| 9. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट | 102 - 109 |
| 10. | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण | 110 - 141 |

## कंपनी का परिचय

प्रमुख आर्थिक संचालक के रूप में विर्निमाण के साथ योजनाबद्ध शहरीकरण की प्रकिया शुरु करने और देश के औद्योगिक /विनिर्माण विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने के संबंध में भारत सरकार ने 2007 में प्रथम औद्योगिक गलियारा परियोजना के रूप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना अवधारणा की घोषणा की। परियोजना का उद्देश्य एक सक्षम नीतिगत ढांचे में लॉजिस्टिक लागतों को कम करने के लिए पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारे द्वारा उपलब्ध कराई गई उच्च गति, उच्च सम्पर्क क्षमता का दोहन कर स्मार्ट, स्थायी औद्योगिक शहरों का निर्माण करना है। तदनुसार, डीएमआईसी परियोजना को विकसित और क्रियान्वित करने के लिए जनवरी 2008 में एक विशेष प्रयोजन योजना अर्थात् दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) निगमित की गई।

वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में डीएमआईसी के लिए औद्योगिक्र शहरों में विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने हेतु वित्तपोषण सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने सितंबर, 2011 में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के रूप में समर्पित निधि के सृजन का अनुमोदन किया। तत्पश्चात भारत सरकार ने डीएमआईसी सहित सभी औद्योगिक गलियारों के समन्वित और समेकित विकास के लिए मौजूदा डीएमआईसी-पीआईटीएफ के कार्यक्षेत्र के विस्तार को अनुमोदित दिया और इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः नामित किया। नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

परियोजना के अंतर्गत, भारत सरकार की निधियों का उपयोग करके और प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड से एनआईसीडीआईटी द्वारा इक्विटी अथवा ऋण के रूप में परियोजना एसपीवी में निवेश और संबंधित राज्य सरकार से इक्विटी के रूप में आने वाली भूमि द्वारा ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों को विकसित किया जा रहा है। डीएमआईसीडीसी परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य कर रही है जो नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए विभिन्न पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरिंग का अध्ययन करती है। यह विभिन्न विशेष परियोजनाओं के परियोजना विकास संबंधी कार्य भी करती है। इन परियोजना संबंधी विकास गतिविधियों को करने के संबंध में परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) से डीएमआईसीडीसी को निधियां अनुदान के रूप में जारी की जा रही है।

डीएमआईसीडीसी, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट, डाऊनस्ट्रीम सिटी लेवल एसपीवी और प्रोजेक्ट लेवल एसपीवी के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करती है। नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट के कार्यक्षेत्र और अधिकारों में विस्तार के कारण डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है और भारत

सरकार द्वारा डीएमआईसीडीसी की घोषणा की गई अथवा भविष्य में घोषित की जाने वाली सभी इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्टों की परियोजना विकास सम्बन्धी गतिविधियों को करने का दायित्व सौंपा गया है। इसलिए 17 फरवरी, 2020 से कंपनी का नाम डीएमआईसीडीसी से बदल कर एनआईसीडीसी (नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) कर दिया गया।

एनआईसीडीसी के मौजूदा इक्विटी शेयरहोल्डरों में भारत सरकार (49 प्रतिशत), जिसका प्रतिनिधित्व उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जाता है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) (26 प्रतिशत) और हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोरपोरेशन (हुडको) (19.9 प्रतिशत), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) (4.1 प्रतिशत) एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (1.0 प्रतिशत) जैसे वित्तीय संस्थान शामिल है।

**<u>कंपनी की संस्थानिक और वित्तीय संरचना: -</u>**

भारत सरकार ने 2011 में डीएमआईसी प्रोजेक्ट के चरण-I में औद्योगिक शहरों का विकास करने के लिए पांच वर्षों की अवधि में डीएमआईसी प्रोजेक्ट की वित्तीय और संस्थानिक संरचना के लिए 17500 करोड़ रुपए (अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए के अध्यधीन 7 नोड में प्रत्येक के लिए औसतन 2,500 करोड़ रूपए) का बजटीय समर्थन अनुमोदित किया है। डीएमआईसी के अंतर्गत, परियोजना विकास संबंधी गतिविधियों को करने के लिए बजटीय समर्थन के रूप में 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई है।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट सहित विभिन्न अन्य औद्योगिक गलियारों के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए, भारत सरकार ने मौजूदा डीएमआईसी पीआईटीएफ के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित किया और इसे दिसंबर, 2016 में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन:निर्मित किया।

18,500 करोड़ रुपए के कोष के अलावा, अन्य सभी परियोजनाओं हेतु विभिन्न परियोजना विकास और कार्यान्वयन संबंधित कार्यों को शुरू करने के लिए 1,584 करोड़ रुपए (एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए 84 करोड़ रुपये सहित) के अतिरिक्त कोष सहित कुल 20,084 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता एनआईसीडीआईटी को दी जाती है और एनआईसीडीआईटी औद्योगिक शहरों/नोड्स/परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल विशेष प्रयोजन योजनाओं (एसपीवी) को इक्विटी और/या ऋण प्रदान करती है। परियोजना एसपीवी में निवेश इक्विटी या ऋण के रूप में सीधे एनआईसीडीआईटी द्वारा किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार इक्विटी के रूप में भूमि का हस्तांतरण करती है।

भारत सरकार विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है और एनआईसीडीसी को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर नेशनल मास्टर प्लान के भाग के रूप में 2024-25 तक 04 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 32 नोडों/प्रोजेक्टों वाले ग्यारह (11) औद्योगिक गलियारों के संबंध में परियोजना विकासात्मक संबंधी गतिविधियां करने का दायित्व सौंपा गया है।

औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम का उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमताओं का दोहन करने के प्रयासों को पूरक करना तथा जीडीपी में अपना योगदान बढ़ाना है। सुगम पहुंच के साथ सक्षमता, औद्योगिक गलियारों को वैश्विक विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और निवेश गंतव्य हब और सर्वोत्तम इन-हाऊस अवसंरचना के साथ स्मार्ट शहरों के लिए परिकल्पित किया गया है। इसका उद्देश्य मांग से पूर्व गुणवत्ता वाली अवसंरचना का सृजन करना और विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए तत्काल आवंटन हेतु विकसित भूखंडों को तैयार रखना और भारत को वैश्विक वैल्यू चैन में एक सशक्त खिलाड़ी बनाना है। औद्योगिक गलियारा नोडों को स्थायी, स्मार्ट और लोचदार विनिर्माण हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों/नोडों को स्थायी अवसंरचना एवं भूखंड लेवल पर प्लग एंड प्ले अवसंरचना के साथ उपलबध कराने हेतु विकसित किया जाता है। राज्य सरकार(रों) द्वारा जल/बिजली की निश्चित उपलब्धता के साथ संस्पर्शी भूखंड और औद्योगिक नोडों को विकसित करने के लिए साइट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप (747 एकड़) (आईआईटीजीएन), मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप (1100 एकड़) (आईआईटीवीयूएल) में प्रमुख आवश्यक अवसंरचना गतिविधियां संबंधी कार्य पूरा हो गया है। जबकि, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर) (22.5 वर्ग किलोमीटर), गुजरात और शेंद्रा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (ऑरिक) (18.55 वर्ग किलोमीटर), औरंगाबाद, महाराष्ट्र में प्रमुख आवश्यक अवसंरचना गतिविधियां पूरी होने के समीप हैं।

अभी तक ह्यूओसुंग (दक्षिण कोरिया), एनएलएमके (रूस), हैयर (चीन), टाटा केमिकल्स और अमूल जैसे निवेशकों सहित करीब 16,750 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 742.75 एकड़ जमीन के कुल 126 भूखंडों को आवंटित किया गया है।

उपरोक्त प्लॉटों के अतिरिक्त, औद्योगिक एवं अन्य उपयोगों (अर्थात् वाणिज्यिक एवं आवासीय) हेतु तत्काल आवंटन के लिए 6,882 एकड़ विकसित भूखंड [शेंद्रा 1,233 एकड़; बिडकिन 1,746 एकड़; धोलेरा 2,619 एकड़, विक्रम उद्योगपुरी 841 एकड़; ग्रेटर नोएडा 443 एकड़] उपलब्ध हैं।

# अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मैं कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैठक में सभी सम्मानित शेयरधारकों का स्वागत करता हूं। वित वर्ष 2020-21 के लिए अपनी कंपनी के परिचालनिक प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। गत वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा । श्रमिकों के पलायन, उनको पुनः एकत्रित करने में कठिनाइयां, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण अवसंरचना क्षेत्र भी गंभीर रूप से प्रभावित रहा जिससे परियोजनाओं की योजनाएं तैयार करने और उनके निष्पादन में देरी हुई। इन कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी अपने लक्ष्यों को पूरा करने और प्राप्त करने में सक्षम रही।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप (आईआईटीजीएन) (747 एकड़) और मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप (आईआईटीवीयूल) (1,100 एकड़) में प्रमुख अवसंरचना संबंधी गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) (22.5 वर्ग किलोमीटर) और औरंगाबाद के शेंद्रा बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (ऑरिक) (18.55 वर्ग किमी) में पूरी होने वाली हैं। इस प्रकार, अब तक, कुल 11,002.64 एकड़ भूमि विकसित की गई है और आवंटन के लिए उपलब्ध है जिसमें से 6,365.31 एकड़ औद्योगिक उपयोग के लिए है और 4637.33 एकड़ वाणिज्यिक, आवासीय और संस्थागत उपयोग के लिए है।

इसके अलावा, ह्योसुंग (दक्षिण कोरिया), एनएलएमके (रूस), हैयर (चीन), टाटा केमिकल्स और अमूल जैसे एंकर निवेशकों सहित लगभग 758 एकड़ के 138 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिससे 16,750 करोड़ रु. का संयुक्त निवेश आकर्षित हुआ है। वर्ष के दौरान परियोजना विकास और कार्यान्वयन के लिए एनआईसीडीआईटी को 2600 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत और जारी की गई, जो अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटन और उपयोग है। ये राशि एसपीवी को जारी कर दी गई है।

30 दिसंबर 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 2024-25 तक 04 चरणों में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित 32 नोड्स/परियोजनाओं सहित 11 (ग्यारह) औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति दी। इसके अलावा, कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र (आंध्र प्रदेश), तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र (कर्नाटक) और ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) के लिए विभिन्न प्रमुख अवसंरचना के निर्माण हेतु प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई जिनकी संयुक्त अनुमानित लागत 7,725.05 करोड़ रुपये है।

इन औद्योगिक गलियारों को विकसित करने के लिए एनआईसीडीसी को अधिदेश प्राप्त है। सरकार ने इन आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमोडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री गतिशक्ति समग्र रूप से एक अवसंरचना विकास कार्यक्रम है जो सभी संबंधित मंत्रालयों की विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के एकीकरण को सुगम बनाएगा और व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कमियों को दूर करेगा। इसका उद्देश्य सुगम जीवन,

व्यापार करने में आसानी, व्यवधानों को कम करना और लागत दक्षता के साथ कार्यों को तेजी से पूरा करना है। आपकी कंपनी इस नेशनल मास्टर प्लान को तैयार करने में शामिल थी।

इस समय एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) प्रोजेक्ट भारत में 17 बंदरगाहों पर संचालित है जिसमें लगभग 170 कंटेनर फ्रेट स्टेशन/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, लगभग 60 टोल प्लाजा, 4 एकीकृत चेक पोस्ट और 9 विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं जो एक्जिम कंटेनर मूवमेंट को पूर्ण उन्नत दृश्यता प्रदान करता है । एलडीबी के जरिए अब तक 42 मिलियन कंटेनरों को सफलतापूर्वक ट्रैक किया जा चुका है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी एशिया के एक सबसे बड़े कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर प्रोजेक्ट अर्थात् इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) द्वारका, नई दिल्ली के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में भी काम करती है, जहां निर्माण गतिविधियां तेजी से चल रही हैं और इस परियोजना के अगले साल पूरा होने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी ने औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए नीति आधारित ऋण (पीबीएल) के रूप में एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से 500 मिलियन यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता की मांग की है जिसे दो किस्तों में जारी किया जाएगा। हाल ही में, एडीबी के बोर्ड ने 250 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण की पहली किश्त को मंजूरी दे दी है।

हमने परियोजना के पूरा होने के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, फिर भी ऐसी चुनौतियां मौजूद हैं जिसका सामना कोई भी उभरती अर्थव्यवस्था करती हैं। इनमें प्राथमिक है शहरीकरण की त्वरित दर, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग और ठोस आर्थिक परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकास पहलों के बीच एकीकरण को बनाए रखना । ये सभी कारक हमारी ओर से अधिक से अधिक भागीदारी और समर्पण की मांग करते हैं। औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत परिकल्पित परियोजनाएं ऐसी अवसंरचनाओं का निर्माण कर चुनौतियों को पूरा करती है जो विश्व स्तरीय मानदंडों को पूरा करते हुए चिरस्थायी, विश्वसनीय और प्रत्यास्थी हो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम परिणाम देने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे।

भविष्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है जो समावेशी विकास के साथ सतत और एकीकृत विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति को प्रेरित करने के हमारे संकल्प में दृढ़ता से परिलक्षित होता है। स्मार्ट बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में अपनी विशेषज्ञता के कारण हम स्वयं को भारत को एक विकसित विश्व अर्थव्यवस्था में बदलने के राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति अधिक जवाबदेह मानते हैं। मैं निदेशक मंडल के अपने सदस्यों को उनके अटूट समर्थन, अनुकरणीय दूरदर्शिता और बहुमूल्य परामर्श के संदर्भ में उदार योगदान के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ । अंत में, हमारी कुशल श्रमशक्ति अपने उत्कृष्ठ कार्य और एक बहु-कार्यात्मक संगठन के रूप में हमारे लचीलेपन के लिए प्रशंसा और श्रेय के पात्र है।

हस्ता.

(अनुराग जैन)
अध्यक्ष

## कॉरपोरेट सूचना

### निदेशक मंडल

श्री अनुराग जैन, आईएएस
अध्यक्ष

श्री शैलेन्द्र सिंह, आईएएस
निदेशक

श्री अमृत लाल मीणा, आईएएस
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
प्रबंध निदेशक

श्री राजेन्द्र रत्नू, आईएएस
निदेशक

श्री काज़ुशिगे गोबे
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

श्री एम. नागराज
निदेशक

डॉ. सुब्रह्मण्यम दूरवसूला
निदेशक

### लेखा परीक्षा समिति

श्री राजेन्द्र रत्नू, आईएएस
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

डॉ. सुब्रह्मण्यम दूरवसूला
निदेशक

### नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री राजेन्द्र रत्नू
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

डॉ. सुब्रह्मण्यम दूरवसूला
निदेशक

### कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

श्री राजेन्द्र रत्नू
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

डॉ. सुब्रह्मण्यम दूरवसूला
निदेशक

### मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल

### उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

श्री अभिषेक चौधरी

### संवैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एस.पी. चोपड़ा एंड
एसोसिएट्स,
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

### आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स वीएसपीवी एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

### सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स विकास गेरा एवं
एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

### बैंकर

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
होटल अशोक,
चाणक्य पुरी, नई दिल्ली

### पंजीकृत कार्यालय

08वां तल, टॉवर-1,
जीवन भारती भवन,
124 कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110001

# वार्षिक आम बैठक

# सूचना

# सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) के सदस्यों की 13वीं (तेरहवी) वार्षिक आम सभा बैठक सोमवार, 13 दिसंबर, 2021 को दोपहर 04:30 बजे 8वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 पर निम्न कारोबार संव्यवहार करने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगीः-

**साधारण कारोबार:** -

1. 31 मार्च, 2021 को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित), उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।

2. **श्री राजेन्द्र रत्नू, कंपनी के निदेशक, जो क्रमानुसार रिटायर हो रहे है, उनके स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है** और इस संबंध में विचार करने, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्न संकल्प को आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन के साथ एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

   **"संकल्प किया जाता है कि** श्री राजेन्द्र रत्नू, कंपनी के निदेशक, जो क्रम आने पर रिटायर हो रहे है और जिन्होंने पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के 152 के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो बारी आने पर रिटायर होने के पात्र है।"

3. **श्री तोशिहिको कुरिहारा, कंपनी के निदेशक, जो क्रमानुसार रिटायर हो रहे है, उनके स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है** और इस संबंध में विचार करने, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्न संकल्प को आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन के साथ एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

   **"संकल्प किया जाता है कि** श्री तोशिहिको कुरिहारा, कंपनी के निदेशक, जो क्रम आने पर

रिटायर हो रहे है और जिन्होंने पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के 152 के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो बारी आने पर रिटायर होने के पात्र है।"

4. **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा नामित किए गए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक को नियुक्त करना और पारिश्रमिक निश्चित करना** और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो निम्न संकल्प को आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन के साथ एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:-

**"संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है तो, उनके अनुपालन में मैसर्स एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स, नई दिल्ली (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 000346एन) जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2021 के पत्र सं. सीए. वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी (0)/216 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नामित किया गया है, उनकी सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए सहमति प्रदान की जाती है।"

**"यह भी संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक को सीएंडएजी कार्यालय द्वारा अनुशंसा के अनुसार संविधिक लेखा परीक्षक को देय लेखा परीक्षा फीस निर्धारित करने सहित निबंधन एवं शर्तों को निश्चित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

**<u>विशेष कारोबार:</u> -**

5. **कंपनी के निदेशक के रूप में श्री अनुराग जैन (डीआईएनः 01779759) की नियुक्ति को नियमित करना** और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना: -

**"संकल्प किया जाता है कि** श्री अनुराग जैन (डीआईएनः 01779759) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 27 सितंबर, 2021 को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन होने की तिथि तक पद पर है तथा उनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाते है और वह बारी आने पर रिटायर होने के पात्र होंगे"।

6. **कंपनी के निदेशक के रूप में श्री कजुशिगे गोबे (डीआईएनः 09276761) की नियुक्ति को नियमित करना** और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना: -

**"संकल्प किया जाता है कि** श्री कजुशिगे गोबे (डीआईएनः 09276761) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 10 अगस्त, 2021 को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन होने की तिथि तक पद पर है तथा उनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाते है और वह बारी आने पर रिटायर होने के पात्र होंगे"।

7. **कंपनी के निदेशक के रूप में श्री अमृत लाल मीणा (डीआईएनः 06626193) की नियुक्ति को नियमित करना** और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना: -

**"संकल्प किया जाता है कि** श्री अमृत लाल मीणा (डीआईएनः 06626193) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 5 नवंबर, 2021 को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन होने की तिथि तक पद पर है तथा उनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाते है और वह बारी आने पर रिटायर होने के पात्र होंगे"।

8. **कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री अमृत लाल मीणा (डीआईएनः 06626193) को नियुक्त करना** और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक **साधारण संकल्प** के रूप में आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना: -

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमों की अनुसूची V और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठनीय धारा 196, 197 के प्रावधानों के अनुसार, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन या फिर से लागू होने के साथ), सदस्यों की सहमति श्री अमृत लाल मीणा (डीआईएन: 06626193) को सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए एतद्वारा दी जाती है ।

कंपनी के निदेशक 05 नवंबर, 2021 से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, और वह बारी आने पर रिटायर होने के पात्र होंगे।

"**यह भी संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो तो, उसके अनुसार, श्री अमृत लाल मीणा, कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक को 05 नवंबर, 2021 से एतद्वारा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया जाता हैं।

"**यह भी संकल्प लिया जाता है कि** श्री अमृत लाल मीणा कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसी भी परिश्रामिक अथवा अनुलाभ के पात्र नहीं होंगे"

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा**
**कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**

**हस्ता.**

**(अभिषेक चौधरी)**
**उपाध्यक्ष- कॉरपोरेट मामलें, मानव संसाधन**
**एवं कंपनी सचिव**
**सदस्यता सं. - एफ6701**

दिनांकः 16 नवंबर, 2021
स्थानः नई दिल्ली

## सूचना:

1. वैश्विक महामारी कोविड-19 के भारी प्रकोप को देखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र जिसे दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाए, द्वारा सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा वार्षिक आम सभा आयोजित करने की अनुमति दी है।

2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसार, सदस्यों को प्रॉक्सी नियुक्त करने और वोट डालने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, वीसी/ओएवीएम द्वारा बैठक में शामिल होने और उसमें भाग लेने तथा ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने के लिए निगमित निकाय अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के पात्र है।

3. सदस्य बैठक की शुरुआत के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम सभा में शामिल हो सकते है।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, आम सभा में शामिल सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के उद्देश्य से की जाएगी।

5. कॉरपोरेट सदस्यों से वार्षिक आम सभा बैठक में उनकी ओर से शामिल होने तथा वोट देने के लिए उनके प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के लिए बोर्ड संकल्प/पॉवर ऑफ एटार्नी की यथोचित प्रमाणित प्रतिलिपि भेजने का अनुरोध किया जाता है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के प्रावधानों के अनुरूप, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से संबंधित संव्यवहार करने के लिए मद नंबर 5 से 8 पर निर्धारित व्याख्यात्मक विवरण को यहां संलग्न किया गया है।

7. आगामी बैठक में नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का विवरण नोटिस के "अनुलग्नक" में दिया गया है।

8. 13वीं वार्षिक आम सभा बुलाने की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कंपनी की वेबसाइट www.nicdc.in पर अपलोड कर दी गई है।

9. आम सभा के दौरान सांविधिक रजिस्टरों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य abhishekchaudhary@nicdc.in. पर कंपनी को लिखित में अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

10. सदस्य अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे गए आमंत्रण लिंक द्वारा वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते हैं। सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण:-

### मद संख्या 2

श्री राजेन्द्र रत्नू, क्रम आने पर पद छोड़ने के लिए देय कंपनी के निदेशक, इस वार्षिक आम सभा में क्रम आने पर पदभार छोड़ते है। पात्र होने के कारण श्री राजेन्द्र रत्नू अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं और बारी आने पर रिटायर होने के लिए देय के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया गया है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री राजेन्द्र रत्नू को छोड़कर, कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 2 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

### मद संख्या 3

श्री तोशिहिको कुरिहारा क्रम आने पर पद छोड़ने के लिए देय कंपनी के निदेशक, इस वार्षिक आम सभा में क्रम आने पर पदभार छोड़ते है। पात्र होने के कारण श्री तोशिहिको कुरिहारा अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं और बारी आने पर रिटायर होने के लिए देय के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया गया है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री तोशिहिको कुरिहारा को छोड़कर, कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 2 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

### मद संख्या 4

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने दिनांक 18 अगस्त, 2021 के अपने पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी (0)/216 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स को नामित किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) एवं (7) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की पूरक लेखा परीक्षा के लिए प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-I को सौंपा गया है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया जाता है।

कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

**मद संख्या 5 :**

श्री अनुराग जैन (डीआईएनः 01779759) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 27 सितंबर, 2021 को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त अतिरिक्त निदेशक वार्षिक आम सभा तक पद धारण करते है। उनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है और कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री अनुराग जैन को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद सं. 5 में निर्धारित संकल्प की अनुशंसा करता है।

**मद सं. 6:**

श्री काज़ुशिगे गोबे (डीआईएनः 09276761) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के प्रावधानों के अनुसार 10 अगस्त, 2021 को निदेशक मंडल द्वारा एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार वार्षिक आम सभा तक अतिरिक्त निदेशक का पद धारण करते है। उनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है और कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री काज़ुशिगे गोबे को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए मद सं. 6 में निर्धारित संकल्प की अनुशंसा करता है।

**मद सं. 7 एवं 8:**

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 5 नवंबर, 2021 द्वारा प्रेषित किया है कि श्री के संजय मूर्ति, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी लिमिटेड) के सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय में नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप श्री अमृत लाल मीणा, अपर सचिव, (लॉजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग 5 नवंबर, 2021 से 3 वर्ष की अवधि या नई नियुक्ति होने तक अथवा अन्य आदेशों तक, जो भी पहले हो, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड पद पर नई नियुक्ति की जाती है।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने 08 नवंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में श्री अमृत लाल मीणा को कंपनी के बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों को निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की भी सिफारिश की गई है। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन, श्री अमृत लाल मीणा को कंपनी के बोर्ड में सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है।

श्री अमृत लाल मीणा के नियुक्त होने के अतिरिक्त, कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों का इस नोटिस के आइटम नंबर 7 और 8 में निर्धारित संकल्प से कोई संबंध या रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु मद संख्या 7 और 8 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

**निदेशक मंडल के आदेश द्वारा**
**कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**

**हस्ता.**

**(अभिषेक चौधरी)**
**उपाध्यक्ष- कॉरपोरेट मामलें, मानव संसाधन**
**एवं कंपनी सचिव**
**सदस्यता सं. - एफ6701**

दिनांकः 16 नवंबर, 2021
स्थानः नई दिल्ली

## 13वीं वार्षिक आम सभा
## के अंतर्गत नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त ब्यौरा

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवालय मानक के 1.2.5 के अनुसार

| नाम | श्री अनुराग जैन<br>(डीआईएन: 01779759) | श्री काजुशिगे गोबे<br>(डीआईएन:09276761) |
|---|---|---|
| आयु | 56 वर्ष | 49 वर्ष |
| शैक्षणिक योग्यता | आईआईटी, खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक | टोक्यो विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक डिग्री |
| अनुभव | श्री अनुराग जैन मध्य प्रदेश कैडर में 1989 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। उन्होंने 27 सितंबर, 2021 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव का पदभार ग्रहण किया।<br><br>उन्हें वित्त क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास का व्यापक अनुभव है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश (5.5 वर्ष) और प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव (3.5 वर्ष) के रूप में कार्य किया है। वह अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), मध्य प्रदेश सरकार में थे और 2 साल के लिए वित्त विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। वर्तमान कार्यभार संभालने से पहले, वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे।<br><br>वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम 'प्रधान | श्री काजुशिगे गोबे वर्तमान में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) में महानिदेशक, सामाजिक अवसंरचना वित्त विभाग, अवसंरचना और पर्यावरण वित्त समूह के पद पर हैं। अपने वर्तमान पद पर वह सड़क, रेलवे, ओएफएन, दूरसंचार, आईसीटी आदि सहित सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने में जेबीआईसी के वैश्विक पदचिह्न का नेतृत्व करते हैं। वह भारत में जेबीआईसी के संचालन का पर्यवेक्षण भी करते हैं।<br><br>मार्च 1994 में टोक्यो विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री पूरी करने के तुरंत बाद, वह जापान के तत्कालीन निर्यात आयात बैंक (अब जेबीआईसी) में शामिल हो गए।.<br><br>26 से अधिक वर्षों में उन्होंने ट्रेजरी संचालन सहित व्यावसायिक क्षेत्रों और संगठनात्मक कार्यों में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में |

| | | |
|---|---|---|
| | मंत्री जन धन योजना की सबसे सफल पहलों में से एक की अवधारणा और कार्यान्वयन का श्रेय दिया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में, वे लोक सेवा वितरण प्रबंधन अधिनियम, देश में एक दर्जन से अधिक राज्यों द्वारा अपनाई गई एक नवीन अवधारणा के अधिनियमन के प्रमुख प्रस्तावक थे। सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश सरकार के रूप में उन्होंने राज्यों और संघ की रिपोर्ट के ई-तैयारी मूल्यांकन में राज्य को शीर्ष पायदान पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। | अपने व्यापार और निवेश का विस्तार करने में जापानी निर्माण कंपनियों को सक्षम बनाने में अत्यधिक योगदान दिया है। विनिर्माण क्षेत्र के अलावा, उन्होंने 2011 से 2013 तक विदेशी परिवहन क्षेत्र की परियोजनाओं का भी सपोर्ट किया।<br><br>1998 से 2000 तक, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में जापान के कार्यकारी निदेशक कार्यालय में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2017 से 2020 तक पेरिस में जेबीआईसी प्रतिनिधि कार्यालय के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों (यूके और आयरलैंड को छोड़कर) और अन्य यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में जेबीआईसी पहलों का नेतृत्व भी किया।<br><br>वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी पिछली भूमिका में, उन्होंने ब्लू डॉट नेटवर्क की संचालन समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यूएसडीएफसी और डीएफएटी के साथ त्रिपक्षीय अवसंरचना साझेदारी की पहल को बढ़ाया और जापानी व्यवसायों की वैश्विक चुनौतियों को सक्षम बनाने हेतु नीति तैयार की। |
| **नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें** | कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्ति। | कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्ति। |
| **प्राप्त किया गया पारिश्रमिक (सिटिंग फीस सहित, यदि कोई हो तो)** | - | - |
| **भुगतान किया जाने** | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक | | |
| निदेशक मंडल में प्रथम नियुक्ति की तिथि | 27 सितंबर, 2021 | 10 अगस्त, 2021 |
| एनआइसीडीसी में शेयर की हिस्सेदारी | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ संबंध | कंपनी के किसी भी निदेशक से कोई परस्पर संबंध नहीं है | कंपनी के किसी भी निदेशक से कोई परस्पर संबंध नहीं है |
| वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अन्य निदेशक मंडल में निदेशक | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| किसी और कंपनी में निदेशक मंडलों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

## 13वीं वार्षिक आम सभा
## के अंतर्गत नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का ब्यौरा

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवालय मानक के के अनुसार 1.2.5

| | |
|---|---|
| **नाम** | **श्री अमृत लाल मीणा**<br>(डीआईएन:06626193) |
| **आयु** | 56 वर्ष |
| **शैक्षणिक योग्यता** | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी टेक और आईआईएम, बैंगलोर से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट-ग्रेजुएशन डिप्लोमा। |
| **अनुभव** | श्री अमृत लाल मीणा, आईएएस वर्तमान में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (लॉजिस्टिक्स) हैं। इससे पूर्व वह बिहार सरकार में सचिव थे और ग्रामीण विकास, शहरी विकास, भवन निगम सहित विभिन्न विभागों को देखते थे। उन्होंने बिहार में सड़कों के बेहतर और टिकाऊ नेटवर्क के निर्माण के लिए बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग में प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया। उनके कार्यकाल में सड़कों और पुलों के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को भारी गति मिली है। प्रमुख नदियों पर नए पुलों का निर्माण और राजमार्गों को चार लेन का बनाने का कार्य सराहनीय है।<br>श्री मीणा ने इससे पहले भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। उन्होंने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए भी काम किया था। उन्होंने नौ वर्षों से अधिक समय तक बिहार राज्य के पांच जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया था। |
| **नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें** | कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्ति। |
| **प्राप्त किया गया पारिश्रमिक (सिटिंग फीस सहित, यदि कोई हो तो)** | - |
| **भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक** | - |
| **निदेशक मंडल में प्रथम नियुक्ति की तिथि** | 05 नवंबर, 2021 |
| **एनआइसीडीसी में शेयर की हिस्सेदारी** | कुछ नहीं |
| **अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के** | कंपनी के किसी भी निदेशक से कोई परस्पर संबंध नहीं है |

| | |
|---|---|
| साथ संबंध | |
| वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे | लागू नहीं |
| अन्य निदेशक मंडल में निदेशक | कुछ नहीं |
| आज की तिथि में अन्य निदेशक मंडलों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता | कुछ नहीं |

# निदेशक मंडल

# की रिपोर्ट

# ***निदेशक मंडल की रिपोर्ट***

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मामलों पर 13$^{वीं}$ **(तेरहवीं)** निदेशक मंडल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

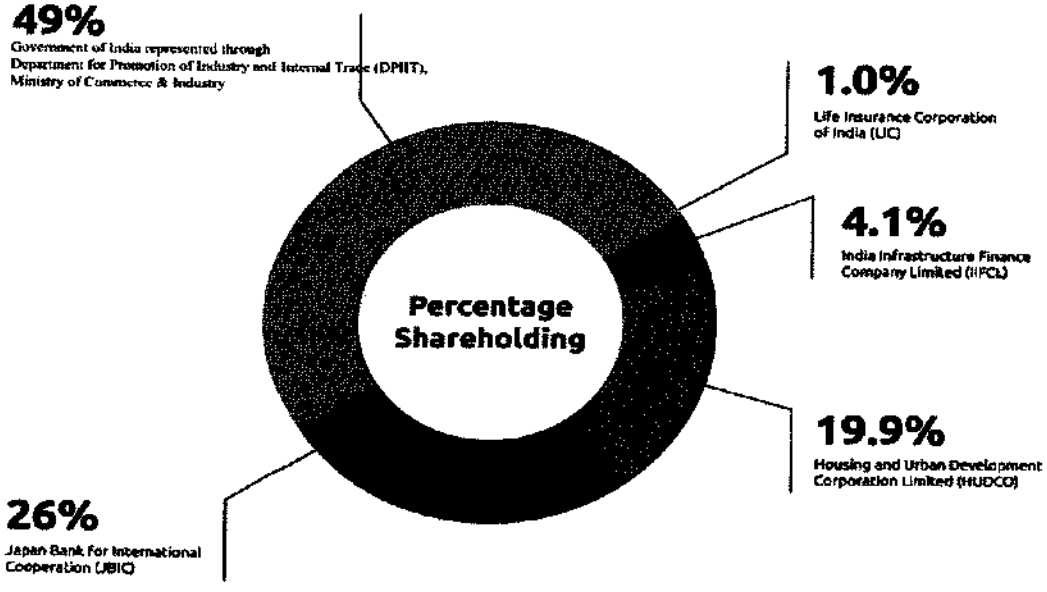
नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन (एनआईसीडीसी) लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के रूप में पहचाने जाने वाली), भारत सरकार, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन (जेबीआईसी), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और लाइफ इंश्योरेंस कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एलआईसी) के बीच निगमित एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है।

कंपनी को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित अथवा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के संबंध में परियोजना विकासात्मक गतिविधियां करना सौंपा गया है। कंपनी, विभिन्न औद्योगिक टाऊनशिप, इंडस्ट्रियल नोड/क्लस्टर तथा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए परियोजना विकास भागीदार और नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य कर रही है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

औद्योगिक गलियारा परियोजना, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डीएफसी) द्वारा उपलब्ध "उच्च गति - उच्च क्षमता" संपर्कता का दोहन कर भावी औद्योगिक शहरों का निर्माण है।

**कंपनी का शेयरधारिता स्वरुप निम्नानुसार है:**



## 1. वित्तीय विवरण सारः

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का सार निम्नानुसार हैः

*(राशि रूपए में)*

| विवरण | 2020-21 | 2019-20 |
|---|---|---|
| कुल आय | 32,14,27,948 | 22,52,42,116 |
| कुल व्यय | 14,28,31,850 | 18,46,11,883 |
| कर व्यय | 5,21,51,825 | 1,15,83,966 |
| **कर पश्चात् वर्ष के लिए लाभ/(हानि)** | **12,64,44,273** | **2,90,46,267** |

## 2. कंपनी के कार्यों की स्थितिः

औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम का उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमता का दोहन करने और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके योगदान को बढ़ाने के प्रयासों को पूरा करना है। आसान पहुंच वाले औद्योगिक गलियारों की कल्पना वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य केंद्रों और सर्वश्रेष्ठ इन-क्लास बुनियादी ढांचे के साथ स्मार्ट शहरों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य मांग से पहले गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार करना और विकसित भूखंडों को तत्काल आवंटन के लिए तैयार रखना है ताकि विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जा सके और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया जाए। औद्योगिक कॉरिडोर नोड्स संधारणीय, स्मार्ट और प्रत्यास्थी विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों/नोड्स को संधारणीय बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाता है और प्लॉट स्तर पर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार(रों) को इन औद्योगिक नोडों के विकास के लिए जल/विद्युत और साइट कनेक्टिविटी के निश्चित आवंटन के साथ निकटवर्ती भूखंड उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के भाग के रूप में 04 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों को अनुमोदित किया है।

### क. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रथम घोषित इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट था और 2014-15 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया था जिसमें पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

#### 1. धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर), गुजरातः

- डीएसआईआर को लगभग 920 वर्ग किमी क्षेत्र में विकसित किए जाने की योजना तैयार की गई है और चरण-1 के 22.5 वर्ग किमी संक्रियण क्षेत्र को उकेरा गया है जिसमें ट्रंक अवसंरचना कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं;
- भारत सरकार ने संक्रियण क्षेत्र के लिए पांच पैकेजों में विभाजित 2784.82 करोड़ रुपये के विभिन्न अवसंरचना घटकों के निविदा पैकेजों को मंजूरी दे दी है;

- राज्य सरकार ने 44.26 वर्ग किलोमीटर भूमि डीआईसीडीएल (एसपीवी) को अंतरित कर दी है और समतुल्य 2551.94 करोड़ रुपये की इक्विटी जारी कर दी गई है;
- एंकर निवेशक के रूप में टाटा केमिकल्स के साथ 245 एकड़ के 04 प्लॉट आवंटित किए गए है,
- आबंटन के लिए 1,290 एकड़ औद्योगिक भूमि तुरंत उपलब्ध है;
- सोलर पार्क के 1000 मैगा वाट में से 300 मैगा वाट टाटा सोलर पॉवर लिमिटेड को दे दिया गया है;
- इसके अतिरिक्त, डीएसआईआर के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के भाग के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अहमदाबाद से धोलेरा तक 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बाहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए निर्माण पैकेज दे दिए गए हैं, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भीमनाथ धोलेरा रेल लिंक तैयार किया जा रहा है;
- एनआईसीडीआईटी ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात राज्य में डीएमआईसी के दूसरे नोड के रूप में 102 वर्ग किमी क्षेत्र वाले मंडल-बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एमबीएसआईआर) को शामिल करने पर सहमति दे दी है।

2. <u>शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए), महाराष्ट्र</u>

- एसबीआईए के भाग-1 के रूप में 40.2 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है;
- राज्य सरकार ने शेंद्रा इंडस्ट्रियल के लिए समग्र 8.39 वर्ग किमी और बिडकिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए 28.8 वर्ग किमी भूमि एसपीवी को अंतरित कर दी है। क्रमशः 602.80 करोड़ रूपए और 2397.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी राशि जारी कर दी गई है;
- शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, भारत सरकार ने 1533 करोड़ रु. के विभिन्न अवसंरचना घटकों के निविदा पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। प्रमुख ट्रंक अवसंरचना पैकेजों का कार्य पूरा हो गया हैं;
- माननीय प्रधान मंत्री जी ने 7 दिसंबर, 2019 को परियोजना राष्ट्र को समर्पित की;
- शेंद्रा के लिए भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में ह्योसंग (100 एकड़) को एक प्लॉट सहित 310 एकड़ में 93 प्लॉट आबंटित किए गए हैं। 09 कंपनियों ने अपना व्यवसायिक परिचालन भी शुरू कर दिया है;
- बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, भारत सरकार ने 3 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 6414.21 करोड़ रुपए के अवसंरचा पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। सेक्टर-ए (10.32 वर्ग किमी.) के लिए ट्रंक अवसंरचना कार्य पूरे होने वाले है;
- एसबीआईए में आबंटन के लिए 1,350 एकड़ औद्योगिक भूमि तुरंत उपलब्ध है।

3. <u>इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश</u>

- परियोजना के लिए एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित कर दी गई है और 617.20 करोड़ रूपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है;
- भारत सरकार ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 1,097.5 करोड़ रूपए की राशि के निविदा पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। प्रमुख अवसरंचना पैकेजों का कार्य पूरा हो चुका हैं;

- भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में हैयर (123.7 एकड़) सहित 05 प्लॉट जिनका माप 153.89 एकड़ है, आबंटित कर दिए गए हैं;
- आबंटन के लिए 170 एकड़ औद्योगिक भूमि तुरंत उपलब्ध है।

4. **<u>इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट, उज्जैन, मध्य प्रदेश</u>**

- राज्य सरकार ने 1,026 एकड़ भूमि एसपीवी को अंतरित कर दी है और 55.93 करोड़ रूपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है;
- भारत सरकार ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 749.1 करोड़ रूपए के निविदा पैकेजों को स्वीकृति दे दी है;
- भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में अमूल सहित 31 एकड़ के माप वाले 04 प्लॉट;
- आवंटन के लिए 450 एकड़ औद्योगिक भूमि तुरंत उपलब्ध है।

5. **<u>खुशखेड़ा भिवानी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन (केबीएनआईआर), राजस्थान</u>**

- राज्य सरकार ने 12 अक्टूबर, 2020 को सूचित किया कि केबीएनआईआर की विकास योजना को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है;
- रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कोरपोरेशन) को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है;
- 558 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्यों के लिए अप्रैल, 2021 में परामर्शदाता को नियुक्त किया गया हैं।

6. **<u>जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए), राजस्थान</u>**

- राज्य सरकार ने 12 अक्टूबर, 2020 को सूचित किया है कि जेपीएमआईए विकास योजना को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) के रूप में अधिसूचित किया गया है;
- 2,659 हैक्टेयर क्षेत्र को दो भागों में विकसित करने के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्यों के लिए मार्च, 2021 में परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;
- 1,459 हेक्टेयर (चरण I) में से 700 हेक्टेयर क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में है।

7. **<u>दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (डीपीआईए), महाराष्ट्र</u>**

- जनवरी, 2021 में राज्य सरकार ने 2,402 हेक्टेयर (5,935 एकड़) भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है जिसमें से 1,466 हेक्टेयर (3,622 एकड़) भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में है।
- भूखंडों के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य जारी है।

ख. <u>चेन्नई बेंगलूरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) और कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार</u>

1. <u>आंध्र प्रदेश में कृष्णपटनम नोड</u>

- 12,798 एकड़ में से, सक्रियण क्षेत्र के रूप में 2,500 एकड़ क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां पूरी हो गई है;
- 30 दिसंबर, 2020 को भारत सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति दी गई;
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1814.51 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और 453.22 करोड़ रूपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना तैयार करने के लिए ईपीसी निविदा कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

2. <u>कर्नाटक में तुमकुरु नोड</u>

- 8,483 एकड़ में से सक्रियण क्षेत्र के रूप में 1,736 एकड़ क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां पूरी हो गई है;
- 30 दिसंबर, 2020 को भारत सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृति दी गई;
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1668.30 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और 586.74 करोड़ रूपए की मैचिंग इक्विटी जारी कर दी गई है;
- प्रमुख अवसंरचना निर्माण करने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति हेतु ईपीसी निविदा के लिए प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

3. <u>तमिलनाडु में पोन्नेरी नोड</u>

- 4,000 क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य करने के लिए अक्टूबर, 2020 में परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;
- मई 2021 में, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लगभग 3,375 एकड़ भूमि उपलब्ध है और भूमि को पोन्नेरी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अधिसूचित किया गया है।

ग. <u>कोयम्बतूर के रास्ते कोच्ची का सीबीआईसी में विस्तार:</u>

1. <u>केरल में पलक्कड़ नोड</u>

- 1,878 एकड़ भूमि क्षेत्र को चिह्नित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भी किया गया है तथा अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है;
- विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य करने के लिए सितंबर, 2020 में परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।

2. **तमिलनाडु में धर्मपुरी नोड**

- राज्य सरकार द्वारा 1,773 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है;
- विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य करने के लिए सितंबर, 2020 में परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।

घ. **अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी)**

1. **पश्चिम बंगाल में रघुनाथपुर, 2,483 एकड़**

- विस्तृत मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और परियोजना के लिए पर्यावरण मंज़ूरी संबंधित गतिविधियां जारी है;
- दिनांक 22 जून, 2021 को डब्ल्यूबीआईडीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सोननगर से डानकुनी तक ईडीएफसी की वित्तपोषण योजना के बारे में स्पष्टता न होने के कारण प्रोजेक्ट लंबित है।

2. **उत्तराखंड में खुरपिया फार्म्स, 1002 एकड़**

- राज्य सरकार ने अगस्त, 2020 में परियोजना के लिए 1002 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है;
- जनवरी, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है और कार्य प्रकियाधीन है।

3. **हरियाणा में हिसार, 1605 एकड़**

- राज्य सरकार ने दिसंबर, 2020 में परियोजना के लिए 1605 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है;
- फरवरी, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है और कार्य प्रकियाधीन है।

4. **पंजाब में राजपुरा-पटियाला, 1,100 एकड़**

- राज्य सरकार ने फरवरी, 2021 में परियोजना के लिए 1100 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है;
- फरवरी, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है और कार्य प्रकियाधीन है।

5. **उत्तर प्रदेश में आगरा, 1,059 एकड़**

- राज्य सरकार ने जनवरी, 2021 में परियोजना के लिए 1059 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है;
- जुलाई, 2021 के अंत तक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों

के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया जाना है;

- एनआईसीडीआईटी ने एकेआईसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दूसरे नोड के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रयागराज (1,141 एकड़) पर ब्राऊनफील्ड साइट को शामिल करने की स्वीकृति दे दी है।

6. <u>बिहार में गया, 1,670 एकड़</u>

- राज्य सरकार ने मार्च, 2021 में परियोजना के लिए 1670 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की है;
- विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियों के लिए शीघ्र ही परामर्शदाता को नियुक्त किया जाएगा।

7. <u>झारखंड</u>

- जनवरी, 2021 में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि न्यू बहरी की पूर्ववर्ती साइट उपलब्ध नहीं है इसलिए वैकल्पिक स्थान को ढूंढा जा रहा है। वैकल्पिक साइट के भूमि ब्यौरों पर पुष्टि अभी भी प्रतीक्षित है।

- एनआईसीडीआईटी ने एकेआईसी के अंतर्गत एक औद्योगिक नोड के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र (2000 एकड़) को शामिल करने पर स्वीकृति दे दी है एवं आईएमसी की स्थापना के लिए परियोजना विकास गतिविधियां शुरु कर दी है।

**ङ. <u>विजाग - चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर:</u>**

- एनआईसीडीआईटी ने वीसीआईसी के चरण-1 में प्राथमिकता वाले नोड के रूप में विशाखापट्नम और चित्तूर को विकसित किए जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में एक अतिरिक्त नोड के रूप में कडप्पा को भी शामिल किए जाने का अनुरोध किया है।
  1. **चित्तूर नोडः** 8,967 एकड़ भूमि के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने एवं प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है और कार्य प्रक्रियाधीन है;
  2. **कडप्पा नोडः** 5,076 एकड़ भूमि के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने एवं प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है और कार्य प्रक्रियाधीन पर है;
  3. **विशाखापट्नम (नाकापल्ली क्लस्टर, 1,100 एकड़)** - राज्य सरकार ने नोड के लिए स्वयं परियोजना का विकास करने का विचार किया है।

**च. <u>बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी)</u>**

1. जनवरी, 2021 में कर्नाटक सरकार ने पुष्टि की है कि **धारवाड़** में औद्योगिक नोड विकसित करने के लिए 6400 एकड़ भूमि उपलब्ध है। उल्लिखित नोड के लिए परियोजना विकास गतिविधियां शुरु हो गई हैं। जुलाई, 2021 में विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है;
2. मार्च, 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने सतारा में इंडस्ट्रियल नोड विकसित करने के लिए 5,000 एकड़

भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है। मई, 2021 में विस्तृत मास्टर योजना तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य के लिए परामर्शदाता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज जारी कर दिए गए थे। अगस्त, 2021 तक परामर्शदाता की नियुक्ति होने की संभावना है।

**छ. <u>हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी):</u>**

- एनआईसीडीआईटी ने अगस्त, 2020 में तेलंगाना राज्य में हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;
- राज्य सरकार ने तेलंगाना राज्य में हैदराबाद-वारंगल इंडस्टियल कोरिडोर के अंतर्गत **हैदराबाद फार्मा सिटी** के लिए मास्टर प्लान और लागत अनुमान तैयार कर लिए हैं;
- फार्मा सिटी प्रोजेक्ट के लिए, राज्य सरकार ने परियोजना विकसित किए जाने के लिए भारत सरकार के साथ अपनी भागीदारी के संबंध में पुष्टि की है।

**ज. <u>हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचएनआईसी):</u>**

- एनआईसीडीआईटी ने अगस्त, 2020 में तेलंगाना राज्य में हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;
- राज्य सरकार ने तेलंगाना में हैदराबाद-नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के अंतर्गत **ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया** के लिए मास्टर प्लान और लागत अनुमान तैयार कर लिए हैं;
- ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, राज्य सरकार ने प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट (पीडीआर) कम बिजनस प्लान रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे एनआईसीडीआईटी के विचारार्थ हेतू प्रस्तुत किया जाएगा।

**झ. <u>हैदराबाद बेंगलूरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी):</u>**

- एनआईसीडीआईटी ने अगस्त, 2020 में एचबीआईसी को शामिल करने तथा आंध्र प्रदेश राज्य के **ओरवकल** में प्राथमिकता नोड की मंजूरी दे दी है;
- जनवरी, 2021 में ओरवकल नोड, 9800 एकड़ (आंध्र प्रदेश) के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्य के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।

**ञ. <u>ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी) प्रोजेक्ट:</u>**

- एनआईसीडीआईटी ने अगस्त, 2020 में ओईसी को शामिल करने और साथ ही दो प्राथमिकता नोडों के परियोजना विकास गतिविधियां को शुरु करने की सहमति दे दी है, यथा,
  - गोपालपुर - भुवनेश्वर - कलिंगनगर (**जीबीके नोड**); और
  - पारादीप - केंद्रापाड़ा - धमरा - सुबरनरेखा (**पीकेडीएस नोड**)

- जीबीके और पीकेडीएस नोड में 11,366 एकड़ भूमि के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरी कार्यों के लिए परामर्शदाता को नियुक्त कर लिया गया है।

ट. <u>दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी)</u>

- दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारे को डीएफसी के उत्तर-दक्षिण गलियारे के साथ सोचा गया है। प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा मौजूदा एनएच नेटवर्क और भविष्य में उत्तर-दक्षिण डीएफसी का लाभ उठाएगा;
- समग्र डीएनआईसी क्षेत्र के लिए जुलाई, 2021 में परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता चयन हेतु निविदा जारी की गई है।

<u>अन्य परियोजनाएं</u>

1. <u>मॉडल सोलर प्रोजेक्ट, नीमराणा, राजस्थानः</u>

- 24 जुलाई, 2015 से, 5 मेगावाट की परियोजना को चालू और ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है;
- 1 जून, 2021 को 1 मेगावाट माइक्रो ग्रिड चालू किया गया और पीपीए निष्पादन के बाद बिजली की आपूर्ति शुरू हुई।

2. <u>लॉजिस्टिक डेटा सर्विस प्रोजेक्टः</u>

- लॉजिस्टिक डाटा बैंक (एलडीबी) की परियोजना को एक ही स्थान पर वास्तविक समय पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए कंटेनर कार्गो मूवमेंट पर नज़र रखने हेतु सेवा, आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों (बंदरगाहों, सीमा शुल्क, ट्रेनों, आईसीडी आदि) की मौजूदा आईटी प्रणालियों को एकीकृत करने हेतु परिकल्पित किया गया था;
- जेएनपीटी में परिचालन 1 जुलाई, 2016 को शुरू हुआ;
- सभी प्रमुख और कुछ छोटे बंदरगाहों पर अखिल भारतीय स्तर पर सेवा चालू है और 30 जून, 2021 तक 38 मिलियन से अधिक कंटेनरों को टैग/डी-टैग किया गया है।

<u>लॉजिस्टिक्स परियोजनाएं</u>

1. <u>नांगल चौधरी, हरियाणा में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच)</u>

- भारत सरकार द्वारा मई, 2018 में प्रोजेक्ट अनुमोदित किया गया;
- प्रोजेक्ट के लिए महेन्द्रगढ़ ज़िले में लगभग 886 एकड़ भूमि की पहचान की गई है और प्रोजेक्ट एसपीवी को 686 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 208.05 करोड़ रूपए

की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है;

- लगभाग 158 एकड़ भूमि पर मुकदमा चल रहा है और मामला माननीय पंजाव और हरियाणा उच्च न्यायालय के पास लंबित है। राज्य सरकार को इसे शीघ्र हल करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई की अगली तिथि 13 अक्टूबर, 2021 है;
- जल, बिजली एवं सड़क संबंधित बाहरी कनेक्टिविटी कार्यों के लिए, राज्य सरकार ने निक्षेप आधार पर कार्य शुरु कर दिए हैं;
- कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए रेल अधिनियम के अंतर्गत डीएफसीसीआईएल द्वारा 25 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जानी है और इसके अतिरिक्त, डीएफसीसीआईएल परियोजना स्थल तक बाहरी रेल कनेक्टिविटी के लिए कार्यों को निष्पादित करेगी। आंतरिक रेल साइडिंग के लिए निविदा तैयार करने का कार्य जारी है।

2. <u>उत्तर प्रदेश के दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और बोराकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)</u>

- परियोजना को भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2020 में अनुमोदित किया गया;
- एमएमएलएच और एमएमटीएच के लिए अपेक्षित 479 हेक्टेयर भूमि में से 369 हेक्टेयर भूमि पहले से ही जीएनआईडीए के स्वामित्व में है और शेष 84 हैक्टेयर भूमि को एलएआरआर अधिनियम के तहत अधिगृहीत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, डीएफसीसीआईएल/एनसीआर द्वारा 23 हेक्टेयर भूमि को रेल अधिनियम में अधिकृहीत की जानी है;
- 227.48 हैक्टेयर भूमि प्रोजेक्ट एसपीवी को अंतरित की गई और एनआईसीडीआईटी द्वारा 853.05 करोड़ रूपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है;
- एमएमएलएच के लिए - बाहरी रेल साइडिंग कनेक्टिविटी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है;
- एमएमटीएच के लिए - अद्यतन ईएसपी के साथ अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) और अन्य हितधारकों को प्रस्तुत कर दी गई है। प्रोजेक्ट के लिए जनरल कन्सलटेंट नियुक्त किया जा रहा है।

3. <u>सानंद, गुजरात में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी)</u>

- राज्य सरकार ने नवंबर, 2020 में 199 हैक्टेयर भूमि उपलब्धता की पुष्टि की और फरवरी, 2021 में भूमि अनंतिम मूल्यांकन के बारे में सूचना दी जिसके आधार पर परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया गया;
- राज्य सरकार को जून, 2021 में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट शेयर की;
- परियोजना में आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

**आईआईसीसी प्रोजेक्ट, द्वारका, नई दिल्ली**

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 10 नवंबर, 2017 की अपनी बैठक में 25703 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर पीपीपी और गैर-पीपीपी मोड में एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर और उससे सम्बंधित संरचनाएं विकसित करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) विकसित करने की स्वीकृति दी। परियोजना को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक विशेष प्रयोजन कंपनी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी लिमिटेड) द्वारा विकसित किया जाएगा।
- परियोजना को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर, दो प्रदर्शनी हॉलों और संबंधित आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं वाले चरण-I की अनुमानित लागत 5,178 करोड़ रूपए (197 करोड़ रूपए की वित्तीय लागत सहित) लगाया गया है और विकसित किया जा रहा है। एलएंडटी को प्रमुख अवसंरचना सहित चरण-I घटक विकसित करने हेतु संपूर्ण परियोजना के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। मूलतः परियोजना को अक्टूबर, 2019 तक पूरा करने की योजना तैयार की गई थी जिसे संशोधित कर अगस्त, 2020 कर दिया गया है। 16 जुलाई, 2021 तक कार्य की प्रगति 69.21 प्रतिशत है। चरण-II में तीन और प्रदर्शनी हॉलों, रंगभूमि (एरेना) और होटल, छोटे व्यवसायिक स्थान तथा कार्यालय स्थान जैसी पूरक अवसंरचनाओं का वाणिज्यिक विकास का निर्माण शामिल होगा। भारत सरकार चरण-I को विकसित करने के लिए इक्विटी के रूप में 2,442.39 करोड़ रूपए की अतिरिक्त बजटीय सहायता उपलब्ध कराएगी। चरण-I और चरण-II के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता को आईआईसीसी लिमिटेट द्वारा आंतरिक प्रोद्भव और बैंकों से ऋणों द्वारा पूरी की जा रही है।
- एनजीटी प्रतिबंध और 2020 और 2021 में कोविड-19 के कारण कार्य रूकने के मामले हुए। प्रारंभ में ठेकेदारों को भूमि सौंपने में देरी के साथ-साथ ठेकेदारों द्वारा प्रोजेक्ट स्थल कई मोर्चों पर देरी हुई थी।
- मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर की गई परियोजना समीक्षा के अनुसार, ईपीसी ठेकेदार ने अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती और सामग्री संसाधनों द्वारा कार्य को सभी पहलूओं से मई, 2022 तक पूरा करने की वचनबद्धता दी है।
- होटल और कार्यालय हेतु भूखंडों का मौद्रिकीकरण करने के प्रयास किए गए थे, बहरहाल, बाजार से प्राप्त प्रतिक्रियाएं संतोषजनक नहीं थी और उम्मीद से कम थी। कोविड परिदृश्य के उपरांत बाजार आकलन के पश्चात् फिर प्रयास किए जाएंगे।

3. **सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां:**

31 मार्च, 2021 को कंपनी के पास एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड (जिसे पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) नामक एक ही सहायक कंपनी है।

समीक्षा अवधि के दौरान, निदेशक मंडल ने सहायक कंपनी के मामलों की समीक्षा की है।

इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनी के कार्य निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं, वितीय विवरणों के साथ निर्धारित फार्म एओसी-1 में संलग्न है।

4. <u>लाभांश</u>:

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है।

एनआईसीडीसी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की पूंजी पुन:संरचना पर डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27.05.2016 के का.ज्ञा. न० 5/2/2016 के तहत जारी दिशा-निर्देशों पर वितीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए लाभांश के भुगतान से संबंधित प्रावधानों को लागू करने से छूट प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव डीपीआईआईटी के माध्यम से डीआईपीएएम को भेजा गया था। 12 मार्च, 2021 को सचिव, डीआईपीएएम की अध्यक्षता में आयोजित सीपीएसई (सीएमसीडीसी) में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी समिति की बैठक में एनआईसीडीसी लिमिटेड को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए न्यूनतम लाभांश की घोषणा से संबंधित पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट देने पर विचार किया गया था।

यद्यपि, वित्त वर्ष 2019-20 के प्रस्ताव को डीआईपीएएम द्वारा भूलवश छोड़ दिया गया था और उपरोक्त बैठक के लिए एक एजेंडा आइटम के रूप में नहीं किया जा सका। बैठक के दौरान एनआईसीडीसी ने डीआईपीएएम से 2018-19 के प्रस्ताव के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2019-20 के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। डीआईपीएएम के सचिव ने उल्लेख किया कि वित्त वर्ष 2019-20 के प्रस्ताव को डीआईपीएम की आगामी बैठक में लिया जाएगा और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए छूट की अनुमति दे दी गयी।

इसी तरह, कंपनी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम लाभांश के भुगतान के लिए छूट चाहेगी, तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5. <u>आरक्षित कोष</u>:

समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा 12,64,44,273/- रुपए कंपनी के आरक्षित कोष में अंतरित किए गए है।

6. <u>व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो तो</u>:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

7. <u>वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में ब्यौरा</u>:

29 जुलाई, 2020 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स वीएसपीवी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल समझते है की कंपनी के आकार के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दायरा पर्याप्त है।

8. <u>भविष्य में कंपनी की स्थिति और परिचालन पर प्रभाव डालने वाले नियामक अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेशों का ब्यौरा</u>:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियामक अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी की स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालन पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

9. **31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हो:**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

10. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व:**

समीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-"क"** में संलग्न है।

11. **निक्षेप:**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो कोई निक्षेप स्वीकार किया है और न ही कंपनी के पास कोई अदत्त अथवा अ-दावी निक्षेप है।

12. **सांविधिक लेखा परीक्षक:**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (जिसे अन्य लागू प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने अपने दिनांक 18 अगस्त, 2020 के पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी(0)/423 द्वारा मेसर्स एसपी चोपड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 000346एन) को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की पूरक लेखा परीक्षा, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-I को सौंपा है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) सांविधिक लेखा परीक्षक को नामित करेंगे। इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूरक लेखा परीक्षा, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-I को सौंपी जाएगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी की 14वीं वार्षिक आम सभा तक कार्यालय में रहेंगे।

13. **लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:**

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है। लेखा परीक्षक रिपोर्ट में संदर्भित लेखों पर नोट स्वत: स्पष्ट में आने वाले है और इसलिए निदेशकों की कोई टिप्पणी नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी की समीक्षा और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।

**14. <u>सचिवीय लेखा परीक्षक</u>:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु 29 जुलाई, 2020 को आयोजित कंपनी की बैठक में मैसर्स विकास गेरा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक-"ख"** पर संलग्न है।

**15. <u>सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट</u>:**

**सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निम्न प्रेक्षण किए हैं: -**

| सचिवीय लेखा परीक्षक टिप्पणी | प्रबंधन टिप्पणियां |
|---|---|
| कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के प्रावधानों के अनुसार महिला निदेशक को नियुक्ति करने की आवश्यकता थी जिसे कंपनी द्वारा नहीं किया गया। | एनआईसीडीसी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है, जिसके पास कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 49 प्रतिशत है। इसलिए, परंपरा के रूप में, डीपीआईआईटी कंपनी के निदेशक मंडल के महिला निदेशक का नाम सुझाएगी।<br>तदनुसार, एनआईसीडीसी द्वारा पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2020, 12 मई 2020, 11 जून 2020, 13 जुलाई 2020, 21 अगस्त 2020, 05 अक्टूबर 2020, 07 दिसंबर 2020, 09 फरवरी 2021, 27 अप्रैल, 2021 और 27 मई 2021 के पत्रों द्वारा अति शीघ्र कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक का नाम सुझाने के लिए कहा गया है।<br>कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक का पद भरने के लिए 10 जून, 2021 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की 59वीं बैठक में भी उल्लिखित मामले पर यथोचित चर्चा/विचार-विमर्श किया गया और एनआईसीडीसी ने दिनांक 30 जून, 2021 के अपने पत्र द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए महिला निदेशक के रूप में डीपीआईआईटी द्वारा किसी अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया है। |

**16. <u>पूंजी संरचना</u>:**

कंपनी की प्राधिकृत, जारी और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक की कीमत 10/- (दस) रुपए वाले 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयरों में बंटी है जो 100,00,00,000 रुपए (केवल एक सौ करोड़ रुपए) है।

**17. <u>धारा 92(3) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न का सार</u>:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) में

जैसा प्रावधान किया गया है, वार्षिक रिटर्न का सार <u>अनुलग्नक- "ग"</u> में फार्म संख्या **एमजीटी - 9** में संलग्न है।

18. <u>उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा अर्जन और बर्हिप्रवाह:</u>

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

**क) उर्जा संरक्षण*:**

i. उर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम अथवा उर्जा संरक्षण पर प्रभाव : **लागू नहीं**

ii. उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम : **लागू नहीं**

iii. उर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश : **लागू नहीं**

**ख) प्रौद्योगिकी समाहनः**

i. प्रौद्योगिकी समाहन के लिए किए गए प्रयास : **लागू नहीं**

ii. उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे उत्पन्न लाभ : **लागू नहीं**

iii. आयतित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरू से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात) : **लागू नहीं**
(क) आयात की गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा;
(ख) आयात का वर्ष;
(ग) क्या प्रौद्योगिकी समाहन पूरी तरह किया गया;
(घ) यदि पूरी तरह समाहन नहीं किया गया तो क्षेत्र जहां समाहन नहीं किया गया; और तत्संबंधी कारण; और

iv. अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय : **लागू नहीं**

**ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और बर्हिप्रवाह:**

i. वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के अनुसार अर्जित विदेशी मुद्रा : **कुछ नहीं**

ii. वर्ष के दौरान वास्तविक बहिर्प्रवाह के अनुसार विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह : **कुछ नहीं**

*[*नोट: कंपनी की मुख्य गतिविधि औद्योगिक गलियारें/निवेश क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/ औद्योगिक नोड/विशेष आर्थिक क्षेत्र/ टाउनशिप में, आधुनिक औद्योगिक, भौतिक/सामाजिक अवसंरचना को उपलब्ध कराना, प्रोत्साहित करना और स्थापित करना है। उर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समाहन करना लागू नहीं है। बहरहाल, कपंनी विभिन्न परियोजना विकासात्मक गतिविधियों द्वारा उर्जा संरक्षण के अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रही है।]*

19. **निदेशक मंडल:**

(क) **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन:**

| क्र.सं. | निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम | नियुक्ति की तिथि | अवधि की समाप्ति |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री मुनिअप्पा नागराज | 17 जुलाई, 2020 | - |

श्री गिरिधर अरमाने, भा.प्रा.से., सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), (अतिरिक्त प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को 10 जून, 2021 से एनआईसीडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

***क्रम आने पर रिटायरमेंट:-***

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी के आर्टिकलस ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू और श्री तोशिहिको कुरिहरा, आगामी आम सभा में क्रम आने पर रिटायर होंगे और पात्र होने के कारण उन्हें पुनर्नियुक्ति की पेशकश की जाती है।

(ख) **निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी के निदेशक मंडल की चार (04) बैठक आयोजित की गई। निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | विवरण | निदेशक मंडल की बैठक की तिथि |
|---|---|---|
| 1. | 55वीं निदेशक मंडल बैठक | 27 मई, 2020 |
| 2. | 56वीं निदेशक मंडल बैठक | 29 जुलाई, 2020 |
| 3. | 57वीं निदेशक मंडल बैठक | 06 नवंबर, 2020 |
| 4. | 58वीं निदेशक मंडल बैठक | 28 दिसंबर, 2020 |

20. **निदेशक मंडल की समितियां:**

निदेशक मंडल की निम्न तीन समितियां है:-

**लेखा परीक्षा समिति:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति' को निम्नानुसार गठित किया है:-

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | गैर-कार्यकारी निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी | गैर-कार्यकारी निदेशक | सदस्य |
| 3. | डॉ. डी. सुब्रह्मण्यम, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (परिचालन), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड (हुडको) | गैर-कार्यकारी निदेशक | सदस्य |

*30 मार्च, 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री जय प्रकाश बत्रा की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप निदेशक मंडल ने 27 मई, 2020 की अपनी 55वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति जिसमें सभी गैर-कार्यकारी निदेशक सदस्य थे, का पुनर्गठन किया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति ने 29 जुलाई, 2020 और 06 नवंबर, 2020 को दो बैठको का आयोजन किया।

**<u>नामांकन और पारिश्रमिक समिति</u>**:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति निम्नानुसार पुनर्गठित की है:-

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | गैर-कार्यकारी निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी | गैर-कार्यकारी निदेशक | सदस्य |
| 3. | डॉ. डी. सुब्रह्मण्यम, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (परिचालन), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड (हुडको) | गैर-कार्यकारी निदेशक | सदस्य |

*30 मार्च, 2020 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री जय प्रकाश बत्रा की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप निदेशक मंडल ने 27 मई, 2020 की अपनी 55वीं बैठक में नामांकन और परिश्रामिक समिति जिसमें सभी गैर-कार्यकारी निदेशक सदस्य थे, का पुनर्गठन किया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, नामांकन और परिश्रामिक समिति ने 06 नवंबर, 2020 और 28 दिसंबर, 2020 को दो बैठको का आयोजन किया गया।

**कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति:**

कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने 27 मई, 2020 की अपनी 55वीं बैठक में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया है:-

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | श्रेणी | पदनाम |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | गैर-कार्यकारी निदेशक | अध्यक्ष |
| 2. | श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी | गैर-कार्यकारी निदेशक | सदस्य |
| 3. | डॉ. डी. सुब्रह्मण्यम, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (परिचालन), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड (हुडको) | गैर-कार्यकारी निदेशक | सदस्य |

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की एक बैठक 28 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी।

**21. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक:**

वित्तीय वर्ष 2020-21 को दौरान कंपनी ने श्री के संजय मूर्ति, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री अभिषेक चौधरी, उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट कार्य, मानव संसाधन और कंपनी सचिव को परिश्रामिक का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा फार्म संख्या एमजीटी - 9 के उप खंड VI(क) और VI(ख) में उल्लिखित है।

**22. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण:**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई ऋण अथवा गारंटी नहीं दी गई अथवा न ही कहीं निवेश किया गया।

**23. धारा 188(1) के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था का विवरण:**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा कोई अनुबंध अथवा समझौता नहीं किया गया।

**24. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक पर्याप्तता:**

कंपनी के पास जोखिम अथवा अवसर जो कंपनी के परिचालन पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं अथवा जिनके लाभ के लिए अधिकतम दोहन किया जा सकता है, उन अवसरों की पहचान करने और अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन है। जोखिम अथवा अवसरों को संभालने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु प्रक्रियां और पद्धतियां मौजूद है।

कंपनी का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसके व्यापार की प्रकृति और आकार एवं परिचालन की जटिलता के अनुरूप है। इन्हें सांविधिक के साथ-साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से जांचा और प्रमाणित किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षणों और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाइयों को लेखा परीक्षा समिति में रिपोर्ट किया जाता है।

**25. <u>निदेशक के दायित्व विवरण:</u>**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के उप खंड (ग) के अनुसार यह बताया गया है कि:

**(क)** वार्षिक लेखों को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया;

**(ख)** निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और निरंतर उपयोग किया एवं निर्णय लिए तथा अनुमान लगाए जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण है;

**(ग)** निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने तथा उन्हें ढूंढने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

**(घ)** निदेशकों ने वार्षिक लेखों को सतत् आधार पर तैयार किया; और

**(ङ)** निदेशकों ने सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां तैयार की थी और ये प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

**26. <u>सूचना का अधिकार:</u>**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपीलों की स्थिति निम्नानुसार है:

| प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपील | आरटीआई आवेदन | | | | 31.03.2021 को लंबित आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|
| | खारिज | सूचना उपलब्ध कराई गई | अन्य जन प्राधिकरणों को अंतरित | आवेदक को वापिस | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आवेदन | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| अपील | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**27. <u>निदेशक मंडल का निष्पादन मूल्यांकन:</u>**

कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार स्थान पर है, जो प्रभाविता को सुनिश्चित करने और स्टेकहोल्डरों के महत्व को बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रबंधन कार्यों को निरीक्षण करने के सशक्त है।

**28. <u>लागत लेखा परीक्षक:</u>**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

**29. <u>कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निबटान) अधिनियम 2013 के अनुपालन में नीति:</u>**

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निबटान) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति को यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निबटान के लिए गठित किया गया है। समिति कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए 'शून्य असिहष्णुता' के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक करती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

**30. <u>सतर्कता:</u>**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई सतर्कता संबंधी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया और कंपनी में कोई पुराना मामला लंबित नहीं है।

**31. <u>सचिवीय मानक:</u>**

कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी उपयुक्त सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

**32. <u>प्रत्येक अर्हता, आरक्षण एवं प्रतिकूल टिप्पणियों अथवा प्रकटनों पर निदेशक मंडल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अथवा टिप्पिणयां:</u>**

सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट किसी अर्हता, आपत्ति अथवा टिप्पणी से मुक्त है और सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अर्हता पर स्पष्टीकरण को इस रिपोर्ट के पाइंट सं. 15 पर प्रस्तुत किया गया है।

33. <u>अभिस्वीकृति:</u>

कंपनी का निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों, स्टाफ के सदस्यों और प्रबंधकर्ताओ को कंपनी के परिचालन में उनके योगदान के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। निदेशक भारत सरकार, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलमेंट कोरपोरेशन (हुडको), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और भारतीय जीवन बीमा निगम और अपने बैंकरों को धन्यवाद देते हैं। निदेशक कंपनी के प्रबंधन के प्रति अपने निरंतर समर्थन, सहयोग और विश्वास के लिए शेयरधारकों को भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी और से**

हस्ता.

**(गिरिधर अरमाने)**
**अध्यक्ष**
**पता: बी9, टॉवर 7, साऊथ मोती बाग,**
**दक्षिण पश्चिम दिल्ली - 110021**

**दिनांक: 10.08.2021**
**स्थान: नई दिल्ली**

# सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक विवरण

(01 अप्रैल, 2020 से शुरु होने वाले वित्तीय वर्ष से 31 मार्च, 2021 तक)

**1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप-रेखा**

एनआईसीडीसी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने और मजबूत, विकसित टिकाऊ समुदायों के निर्माण और देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करने की कल्पना करता है।

**2. सीएसआर समिति की संरचना:**

कंपनी के निदेशक मंडल की सीएसआर समिति की संरचना और दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को आयोजित 04वी बैठक में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार थी:-

| क्र.सं. | निदेशक का नाम | पदनाम/निदेशक का स्वरुप | वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | गैर-कार्यकारी निदेशक | 1 | 1 |
| 2. | डॉ. डी. सुब्रह्मण्यम, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (परिचालन), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड (हुडको) | गैर-कार्यकारी निदेशक | 1 | 1 |
| 3. | श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी | गैर-कार्यकारी निदेशक | 1 | 1 |

**3. वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर प्रोजेक्ट प्रदर्शित हो।**

कंपनी की सीएसआर समिति की संरचना और कंपनी की सीएसआर नीति का वेब लिंक नीचे दिया गया है:-

**https://www.nicdc.in/download.aspx?mpgid=34&pgidtrail=34&utid=11**

4. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, तो नियम 8 के उप-पैरा (3) के अनुसार की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन का ब्यौरा उपलब्ध कराएं (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समंजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: -

| क्र.स. | वित्तीय वर्ष | पिछले वित्त वर्ष के लिए समंजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपए में) | वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो तो (रुपए में) |
|---|---|---|---|
| कुछ नहीं | | | |

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः- 5,98,28,334/- रुपए

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का शुद्ध औसत लाभ का दो प्रतिशतः 11,96,567/- रूपए
(ख) पिछले वित्तीय वर्षों के सीएसआर प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों के कारण उत्पन्न अधिशेषः कुछ नहीं
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समंजन खाते के लिए अपेक्षित राशिः कुछ नहीं
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व (7क+7ख-7ग): 11,96,567/- रुपए

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय अथवा वहन नहीं की गई राशिः

| वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई राशि (रुपए में) | व्यय नहीं की गई राशि (रुपए में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 135(6) के अनुसार व्यय नहीं किए गए सीएसआर खाते में कुल अंतरित राशि | | 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत उल्लिखित किसी फंड में अंतरित राशि | | |
| | धनराशि | अंतरण की तिथि | फंड का नाम | धनराशि | अंतरण की तिथि |
| 11,96,567 * | लागू नहीं | | लागू नहीं | | |

** 11,96,567/- रूपए की सीएसआर निधि 31 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत अनुसूचित) में दी गई थी।*

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं की तुलना में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | परियोजना का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं) | परियोजना का स्थान | | परियोजना अवधि | परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपए में) | चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपए में) | धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए व्यय नहीं किए गए सीएसआर खाते में अंतरित की राशि (रूपए में) | कार्यान्वयन का माध्यम - प्रत्यक्ष (हां/नहीं) | क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन का माध्यम | |
| | | | | राज्य | जिला | | | | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| लागू नहीं | | | | | | | | | | | | |

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के आलावा अन्य व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | प्रोजेक्ट का नाम | अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद | स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं) | प्रोजेक्ट का स्थान | | प्रोजेक्ट के लिए व्यय की गई राशि (रूपए में) | कार्यान्वयन का माध्यम - प्रत्यक्ष (हां/नहीं) | क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन का माध्यम | |
| | | | | राज्य | जिला | | | नाम | सीएसआर पंजीकरण संख्या |
| लागू नहीं | | | | | | | | | |

(घ) उपरि प्रशासनिक खर्चों में व्यय की गई राशिः कुछ नहीं

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो तोः लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) - कुछ नहीं

(छ) समंजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो तोः कुछ नहीं

| क्र.सं. | विवरण | राशि (रूपए में) |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत | 11,96,567 |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि | 11,96,567 |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि [(ii)-(i)] | कुछ नहीं |
| (iv) | पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों के कारण उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो तो | कुछ नहीं |
| (v) | पिछले तीन वर्षों में समंजन खाते के लिए उपलब्ध धनराशि [(iii)-(iv)] | कुछ नहीं |

9. (क) पूर्ववर्ती तीन पिछले वर्षों के लिए व्यय नहीं की गई सीएसआर धनराशि का ब्यौरा:

| क्र.सं. | पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष | धारा 135(6) के अंतर्गत व्यय नहीं किए गए सीएसआर खाते में अंतरित धनराशि (रुपए में) | रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपए में) | धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी फंड में अंतरित राशि, यदि कोई हो तो | | | बाद के वर्षों में व्यय के लिए शेष राशि (रुपए में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | फंड का नाम | राशि (रूपए में) | अंतरण की तिथि | |
| लागू नहीं। | | | | | | | |

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों से जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की सीएसआर राशि का ब्यौरा:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.स. | प्रोजेक्ट आईडी | प्रोजेक्ट का नाम | वित्तीय वर्ष जिसमें प्रोजेक्ट शुरु हुआ था | प्रोजेक्ट अवधि | प्रोजेक्ट के लिए कुल आवंटित राशि (रूपए में) | रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में प्रोजेक्ट पर व्यय की गई राशि (रुपए में) | रिपोर्ट किए वित्तीय वर्ष के अंत में संचयी राशि (रूपए में) | प्रोजेक्ट की स्थिति - पूर्ण/जारी |
| लागू नहीं। | | | | | | | | |

**10. पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन अथवा अधिगृहण के मामले में, कृपया परिसंपत्तियों का विवरण (परिसंपत्ति-वार ब्यौरा) उपलब्ध कराएं जिन्हें वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि के द्वारा सृजित अथवा अधिगृहीत किया गया था?**

(क) पूंजीगत परिसंपत्तियो के सृजन अथवा अधिगृहण की तिथि - कुछ नहीं

(ख) पूंजीगत परिसंपत्तियो के सृजन अथवा अधिगृहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि - कुछ नहीं

(ग) कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभधारकों के ब्यौरे जिनके नाम ऐसी पूंजीगत परिसंपत्तियां पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं

(घ) सृजित या अधिगृहीत (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारणों को स्पष्ट करें।

लागू नहीं

| | |
|---|---|
| हस्ता. | हस्ता. |
| (मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक) | (अध्यक्ष, सीएसआर समिति) |

**अनुलग्नक-"ख"**

**फार्म सं.-एमआर-3**

**सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिको की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)]

सेवा में,

सदस्य,
**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट**
**कोरपोरेशन लिमिटेड**
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर
डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)
08वां तल, टॉवर-1, जीवन भारती बिल्डिंग,
124 कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

मैने "**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)** (जिसे बाद में कंपनी कहा जाएगा)" द्वारा लागू किए गए सांविधिक प्रावधानों और उपयुक्त कॉरपोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस विधि से की गई थी कि जो हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उसके आधार पर हमारा अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराते है।

कंपनी की पुस्तकें, कार्यवृत पुस्तकें, फार्म और जमा की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा प्रस्तुत अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा किए जाने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंट और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, एतद्वारा मैं रिपोर्ट करता हूं कि मेरे अभिमत में, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र मौजूद है, जो इस विधि और बाद में रिपोर्ट किए जाने के अध्यधीन है:

मैने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा

रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और जमा की गई रिटर्नों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है:

1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
2) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीमा के नियम;
3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियम तथा उप-नियम;
4) प्रबंधन अभ्यावदेन के अनुसार कंपनी पर लागू अन्य निम्नलिखित कानून, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;
(ii) उपदान संदाय अधिनियम, 1972;
(iii) दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954;
(iv) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1999

मैंने निम्नलिखित उप खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(क). सामान्य और बोर्ड बैठक के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ख). गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध होने के संबंध में समझौता नहीं किया है।

समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निदेशों, मानकों के उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों का अच्छी तरह से अनुपालन किया है और उपरोक्त परिच्छेदो के संबंध में कोई गैर-अनुपालन/प्रेक्षण/लेखा परीक्षा अर्हता, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

**मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि**

कंपनी का निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशक, गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ यथोचित रूप से गठित है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन हुए हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के प्रावधानों के अनुसार महिला निदेशक की नियुक्ति करनी थी जिसे कंपनी द्वारा नहीं किया गया है।

बोर्ड मीटिंग आयोजित किए जाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अन्य जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।

बहुमत से निर्णय लिया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के दृष्टिकोण प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

**मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि**

लागू, उपयुक्त लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं परिचालन के अनुरूप कंपनी में यथोचित प्रणाली और प्रक्रिया मौजूद है।

**मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि**

बोर्ड संरचना/प्रणाली और लेखा परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में कोई भी गैर-अनुपालन/प्रेक्षण/लेखापरीक्षा अर्हता, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 10 अगस्त, 2021**

**कृते विकास गेरा**
**एंड एसोसिएट्स**

हस्ता.
**विकास गेरा**
**प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव**
**एफसीएस सं. 5248**
**सीपी सं.: 4500**

**यूडीआईएनःएफ005248सी**000754150

**नोटः** इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का आंतरिक भाग है।

*'अनुलग्नक क'*

सेवा में,

सदस्य,
**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट**
**कोरपोरेशन लिमिटेड**
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर
डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)
08वां तल, टॉवर-1, जीवन भारती बिल्डिंग,
124 कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001.

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकार्ड के रख-रखाव का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय दस्तावेजों की सामग्रियों की परिशुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। जांच के आधार पर परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों से सही तथ्य प्रदर्शित हो। हमें विश्वास हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां, हमारे अभिमत के लिए उचित आधार उपलब्ध कराती है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों और खातों की परिशुद्धता एवं सत्यता का कोई सत्यापन नहीं किया है क्योंकि ये सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नामित विशेषज्ञों की समीक्षा के विषय है।

4. हमने कंपनी पर लागू वित्तीय क़ानून जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर नियमों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की है क्योंकि ये सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नामित विशेषज्ञों की समीक्षा के विषय है।

5. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के क्रम आदि के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

6. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानक के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का

दायित्व है। हमारी परीक्षण जांच आधार पर पद्धतियों के सत्यापन तक सीमित है।

7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासतन है और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन की कुशलता और प्रभाविता का सूचक है।

8. कोविड-19 के कारण हमने सचिवीय लेखापरीक्षा जो हमें उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सूचना के आधार पर की है और हम विश्वास करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई गई सूचना कंपनी के मूल दस्तावेजों से उपलब्ध कराई गई है।

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 10 अगस्त, 2021**

**कृते विकास गेरा**
**एंड एसोसिएट्स**

हस्ता.
**विकास गेरा**
**प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव**
**एफसीएस सं. 5248**
**सीपी सं.: 4500**

अनुलग्नक- "ग"

**फार्म सं. एमजीटी-9**

**वार्षिक रिटर्न का सार**

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के रूप में**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

| I | **पंजीकरण एवं अन्य विवरण** | |
|---|---|---|
| i) | सीआईएन | यू45400डीएल2008पीएलसी172316 |
| ii) | पंजीकरण तिथि | 7 जनवरी, 2008 |
| iii) | कंपनी का नाम | **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) |
| iv) | कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी | शेयर द्वारा सीमित कंपनी/गैर-सरकारी भारतीय कंपनी |
| v) | पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण | 08वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 |
| vi) | क्या सूचीबद्ध कंपनी है (जी हां/जी नहीं) | नहीं |
| vii) | रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो तो | एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड<br>चौथा तल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाऊंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 |

| II | **कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां** | | |
|---|---|---|---|
| **कंपनी के कुल टर्नओवर में 10% अथवा उससे अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा** | | | |
| **क्र.सं.** | **मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण** | **उत्पाद/सेवा का कोड (एनआईसी)** | **कंपनी के कुल टर्नओवर का %** |
| 1. | कंपनी की मुख्य गतिविधि आधुनिक, भौतिक और सामाजिक औद्योगिक अवसंरचना सहित औद्योगिक गलियारों/निवेश क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्रों/आर्थिक क्षेत्र/इंडस्ट्रियल नोड/विशेष आर्थिक क्षेत्र/टाऊनशिप को सुगम, प्रोत्साहित और स्थापित करना है। | 42909 (अन्य सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एन.ई.सी.) | 100% |

| III | **नियंत्रक, सहयोगी एवं संबंद्ध कंपनियों का ब्यौरा** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **कंपनी का नाम एवं पता** | **सीआईएन/ जीएलएन** | **नियंत्रक/ सहयोगी/संबंद्ध** | **धारित शेयरों का %** | **लागू धारा** |
| 1. | एनआईसीडीसी नीमराणा सौलर पॉवर लिमिटेड, 08वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 | यू40300डीएल2014पीएलसी266439 | सहयोगी कंपनी | 100% | 2(87)(ii) |

**IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेक-अप)**

**i. कोटिवार शेयर धारिता**

| शेयरधारकों की कोटि | वर्ष की शुरूआत में शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमैट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | डीमैट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | |
| **क. प्रवर्तक** | | | | | | | | | |
| **(1) भारतीय** | | | | | | | | | |
| क) व्यैक्तिक/ एचयूएफ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ख) केन्द्रीय सरकार | 4,90,00,000 | 0 | 4,90,00,000 | 49.00 | 4,90,00,000 | 0 | 4,90,00,000 | 49.00 | 0.00 |
| ग) राज्य सरकार(रें) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| घ) निकाय निगम | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| च) अन्य (ट्रस्ट) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| **उप-जोड़ (क)(1)** | 4,90,00,000 | 0 | 4,90,00,000 | 49.00 | 4,90,00,000 | 0 | 4,90,00,000 | 49.00 | 0.00 |
| **(2) विदेशी** | | | | | | | | | |
| क) एनआरआई-व्यैक्तिक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ख) अन्य - व्यैक्तिक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ग) निकाय निगम | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| घ) बैंक/वित्तीय संस्थान | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ङ) अन्य | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **उप जोड़ (क)(2)** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** |
| **प्रवर्तकों की शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)** | **4,90,00,000** | **0** | **4,90,00,000** | **49.00** | **4,90,00,000** | **0** | **4,90,00,000** | **49.00** | **0.00** |
| **ख. सार्वजनिक शेयरधारिता** | | | | | | | | | |
| **1. संस्थान** | | | | | | | | | |
| क) म्युचल फंड | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ख) बैंक/वित्तीय संस्थान | 2,39,99,998 | 2 | 2,40,00,000 | 24.00 | 2,39,99,998 | 2 | 2,40,00,000 | 24.00 | 0.00 |
| ग) केन्द्रीय सरकार | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| घ) राज्य सरकार(रें) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ङ) वैंचर कैपिटल फंड | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| च) बीमा कंपनियां | 10,00,000 | 0 | 10,00,000 | 1.00 | 10,00,000 | 0 | 10,00,000 | 1.00 | 0.00 |
| छ)एफआईआई | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ज) विदेशी वैंचर कैपिटल फंड | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| झ) अन्य विदेशी शेयरधारिता (एफआईआई/एफसी/एफएफआई/एनआरआई/ओसीबी) | 2,60,00,000 | 0 | 2,60,00,000 | 26.00 | 2,60,00,000 | 0 | 2,60,00,000 | 26.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **उप जोड़ (ख)(1)** | 5,09,99,998 | 2 | 5,10,00,000 | 51.00 | 5,09,99,998 | 2 | 5,10,00,000 | 51.00 | 0.00 |
| **2. गैर संस्थानिक** | | | | | | | | | |
| क) निकाय निगम | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ख) व्यैक्तिक | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| i. 1 लाख रुपए तक की नाममात्र की शेयरपूंजी रखने वाले व्यैक्तिक शेयरधारकों की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ii. 1 लाख रुपए से अधिक की नाममात्र की शेयरपूंजी रखने वाले व्यैक्तिक शेयरधारकों की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ग) अन्य: i. क्लीयरिंग सदस्य | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ii. गैर-निवासी | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| iii. विदेशी कंपनी | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| iv. ट्रस्ट | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **उप जोड़ (ख)(2)** | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)** | 5,09,99,998 | 2 | 5,10,00,000 | 51.00 | 5,09,99,998 | 2 | 5,10,00,000 | 51.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| सकल जोड़ (क+ख+ग) | 9,99,99,998 | 2 | 10,00,00,000 | 100.00 | 9,99,99,998 | 2 | 10,00,00,000 | 100.00 | 0.00 |

| (II) | प्रवर्तकों की शेयरधारिता | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता | | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | | | वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन % |
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के शेयरों का कुल % शेयर | कुल शेयरों का गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के शेयरों का कुल % शेयर | कुल शेयरों का गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का % | |
| 1. | सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति | 4,89,99,998 | 49% | - | 4,89,99,998 | 49% | - | कुछ नहीं |
| | श्री शैलेन्द्र सिंह, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | 01 | | - | 01 | | - | कुछ नहीं |
| | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), | 01 | | | 01 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व | | - | | - | कुछ नहीं | |

| (iii) | प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करे, यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है) कोई परिवर्तन नहीं | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता | |
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| कुछ नहीं | | | | | |

| (iv) | शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशक, प्रवर्तक एवं जीडीआर एवं एडीआरधारकों को छोड़कर) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | |
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1. | जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) | 2,60,00,000 | 26% | 2,60,00,000 | 26.00% |
| 2. | हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) | 1,99,00,000 | 19.90% | 1,99,00,000 | 19.90% |
| 3. | इंडिया इंफ्रास्टक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) | 40,99,998 | 4.10% | 40,99,998 | 4.10% |
| | श्री पीआर जयशंकर के साथ संयुक्त रूप से आईआईएफसीएल | 01 | | 01 | |
| | श्री राजीव मखीजा के साथ संयुक्त रूप से आईआईएफसीएल | 01 | | 01 | |
| 4. | भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) | 10,00,000 | 1.00% | 10,00,000 | 1.00% |

| (v) | निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए | वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता | |
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| | कुछ नहीं | | | | |

| V | ऋणग्रस्तता | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | बकाया ब्याज/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी ऋणग्रस्तता | | | | |
| | | निक्षेपों के अतिरिक्त सुरक्षित ऋण | असुरक्षित ऋण | निक्षेप | कुल ऋणग्रस्तता |
| 1 | वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | i) मूल धनराशि | - | - | - | - |
| | ii) बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया | - | - | - | - |
| | iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं | - | - | - | - |
| | **जोड़ (i+ii+iii)** | - | - | - | - |
| 2 | **वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन** | - | - | - | - |
| | वृद्धि | - | - | - | - |
| | कटौती | - | - | - | - |
| 3 | **शुद्ध परिवर्तन** | - | - | - | - |
| 4 | **वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता** | - | - | - | - |
| | i) मूल धनराशि | - | - | - | - |
| | ii) बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया | - | - | - | - |
| | iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं | - | - | - | - |
| **जोड़ (i+ii+iii)** | | - | - | - | - |

| **VI** | **निदेशकों और प्रमुख कार्मिकों को पारिश्रमिक** | | |
|---|---|---|---|
| **क.** | **प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक** | | |
| **क.सं.** | **पारिश्रमिक का विवरण** | **प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (श्री के संजय मूर्ति - सीईओ एवं प्रबंध निदेशक)** | **कुल धनराशि (रुपए में)** |
| | **सकल वेतन** | | |
| 1 | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | 48,82,542 | 48,82,542 |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मान | 8,10,201 | 8,10,201 |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ | - | - |
| 2 | स्टॉक ऑप्शन | - | - |
| 3 | स्वेट इक्विटी | - | - |
| 4 | कमीशन | - | - |
| | लाभ के % रूप में | - | - |
| | अन्य (स्पष्ट करें) | - | - |
| 5 | अन्य, कृपया स्पष्ट करें | - | - |
| | **जोड़ (क)** | 56,92,743 | 56,92,743 |
| | **अधिनियम के अनुसार सीलिंग** | - | - |

| ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक | | | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | निदेशक का नाम | जोड़ |
| 1. | • स्वतंत्र निदेशकों के लिए बोर्ड/समिति बैठकों में शामिल होने के लिए फीस | कुछ नहीं | |
| | • कमीशन | | |
| | • अन्य, कृपया स्पष्ट करे | | |
| जोड़ (1) | | | |
| 2 | • अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक | कुछ नही | |
| | • बोर्ड/समिति बैठकों में शामिल होने के लिए फीस | | |
| | • कमीशन | | |
| | • अन्य, कृपया स्पष्ट करे | | |
| जोड़ (2) | | कुछ नहीं | |
| जोड़ (ख)= (1)+(2) | | | |
| जोड़ (क+ख) | | | |

| ग. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | | |
| | सकल वेतन | श्री अभिषेक चौधरी (कंपनी सचिव) | श्री पी के अग्रवाल (सीएफओ) | कुल धनराशि |
| 1 | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | 46,01,820 | 47,79,204 | 93,81,024 |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मान | 6,86,700 | 6,03,375 | 12,90,075 |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ | - | - | - |
| 2 | स्टॉक ऑप्शन | - | - | - |
| 3 | स्वेट इक्विटी | - | - | - |
| 4 | कमीशन | - | - | - |
| | लाभ के % रूप में | - | - | - |
| | अन्य (स्पष्ट करे) | - | - | - |
| 5 | अन्य कृपया स्पष्ट करे | - | - | - |
| जोड़ | | 52,88,520 | 53,82,579 | 1,06,71,099 |

| VII | जुर्माना/सजा/अपराध का समझौता | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | जुर्माना/सजा/अपराध के निपटान में लगी राशि का ब्यौरा | प्राधिकारण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय) | अपील, यदि की गई हो (ब्यौरा दें) |
| क. | कंपनी | | | | | |
| | जुर्माना | कोई नहीं | | | | |
| | सजा | | | | | |
| | समझौता | | | | | |
| ख. | निदेशक | कोई नहीं | | | | |
| | जुर्माना | | | | | |
| | सजा | | | | | |
| | समझौता | | | | | |
| ग. | चूक में शामिल अन्य अधिकारी | कोई नहीं | | | | |
| | जुर्माना | | | | | |
| | सजा | | | | | |
| | समझौता | | | | | |

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता.

**(गिरिधर अरमाने)**
**अध्यक्ष**
**पताः बी9, टॉवर 7, साऊथ मोती बाग,**
**दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली-110021**

**दिनांकः 10.08.2021**
**स्थानः नई दिल्ली**

# वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Trust in Public Interest

गोपनीय

संख्या/No. PDA/Infra/NIC/DMICDC/21-53/2020-21/160

**भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,**
**कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली**
**INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,**
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 6/10/21

सेवा मे,

सी.ई.ओ.एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
8 वां फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिग, 124 कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

**विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।**

महोदय,

मै इस पत्र के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) एवं 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करती हूँ। इन **शून्य** टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षको की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

संलग्न: शून्य टिप्पणियाँ

(रिना अकोइजम)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** के एकल वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसे उनके द्वारा **10 अगस्त, 2021** की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुंच किए बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा दस्तावेजों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत लेखा परीक्षक रिपोर्ट में जोड़ा जाए।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के**
**लिए और उनकी ओर से**

**हस्ता.**

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 06 अक्टूबर, 2021**

**(रिना अकोइजम)**
**लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर)**
**नई दिल्ली**

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 जिसे अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसे उनके द्वारा **10 अगस्त, 2021** की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है लेकिन इसकी सहायक कंपनियों यथा एनआईसीडीसी नीमराणा सौलर पॉवर कंपनी लिमिटेड की पूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुंच किए बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा दस्तावेजों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत लेखा परीक्षक रिपोर्ट में जोड़ा जाए।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के**
**लिए और उनकी ओर से**

**हस्ता.**

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 06 अक्टूबर, 2021**

**(रिना अकोइजम)**
**लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर)**

**नई दिल्ली**

# एकल वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

**एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

## अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड के खातों की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों, उप-निर्देशों को पूरा कर लिया है।

**कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण संख्या 000346N**

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 10 अगस्त, 2021**

हस्ता.

**अंकुर गोयल**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. 099143**

**एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

## स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट

## नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों हेतु
## (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)

### स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

### अभिमत

हमने **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की तिथि का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स शामिल है।

हमारे अभिमत में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और उस पर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडएलोन विवरण अपेक्षित सूचना देते हैं जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षा की गई है और 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और उनके नकदी प्रवाह पर अधिनियम की धारा 133 जिसे समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा परीक्षा मानक) नियम, 2006 के साथ पढ़ा जाए और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य और सही दृष्टिकोण देते हैं।

### अभिमत का आधार

हमने अधिनियम (लेखा परीक्षा मानक) की धारा 143(10) के अंतर्गत विर्दिनिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के खंड 'स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व' में आगे बताया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित है, सहित इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु उचित है।

### स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, यदि कोई हो तो, शामिल है (लेकिन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

पृष्ठ 2 पर जारी

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम तत्संबंधी निकाले गए निष्कर्षों पर कोई आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व उपलब्ध होने पर उपरोक्त पहचानी गई अन्य सूचना को पढ़े और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा प्राप्त की गई जानकारी भौतिक रूप से गलत है।

जब हम निदेशक रिपोर्ट को अनुलग्नकों सहित, यदि कोई हो तो पढ़ते है, उसके के आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस बोर्ड रिपोर्ट में कोई गलतबयानी है, तो हमें उस तथ्य को प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

**स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व**

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का एक सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं।
उत्तरदायित्व में परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन दस्तावेजों की पर्याप्त रूप से देखरेख, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करना; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को डिज़ाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन में थे, जो स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं और किसी भी गलत कथन, जो चाहे धोखाधड़ी से हो अथवा चूक से हो, उससे मुक्त रखते हो, भी शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन सतत् आधार पर जारी रहने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जहां लागू हो, सतत् आधार से संबंधित मुद्दों और लेखांकन के आधार पर सतत् आधार उपयोग करना बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी परिशोधित करने अथवा परिचालन बंद करने का इच्छुक है अथवा ऐसा करने के लिए वास्तविक विकल्प नहीं है, के संबंध में उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

**स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से किसी गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा चूक से, मुक्त है और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित रूप से आश्वासन, उच्च श्रेणी का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी भी मौजूद गलत कथन को सदैव ही ढूंढ लेगी। गलत कथन धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हो सकते हैं और अगर इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय चाहे वह निजी रूप से हो अथवा समग्र रूप में, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो, तो यह महत्वपूर्ण माने जाते है।

पृष्ठ 3 पर जारी

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है और लेखापरीक्षा में पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

- स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रणाली डिजाइन व निष्पादित करना, तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप पता न लग पाने के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से न हो।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा प्रबंधन वर्ग द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के सतत् आधार और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो एक सतत् आधार में जारी रहने के लिए कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी को सतत् आधार पर जारी रहने से रोक सकती हैं।

- प्रकटनों सहित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु तथा यह मूल्यांकन करना कि क्या स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाया गया हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते है।

हम, अन्य मामलों मे, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण मे पाई गई महत्वपूर्ण कमियां जिन्हे हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचाना, अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति, को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते है तथा जहां आवश्यक हो वहां उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।.

**अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") में अपेक्षा के अनुसार, हम **अनुलग्नक-'क'**, आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते है।

पृष्ठ 4 पर जारी

2. हम कंपनी की पुस्तकों और रिकार्डों की इस प्रकार की जांच जैसा उचित समझा गया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्देशों और उप-निर्देशों पर अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार **अनुलग्नक-'ख'** में अपनी रिपोर्ट संलग्नित कर रहे है,

3. जैसा कि अधिनियम की धारा **143(3)** द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारे अभिमत में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

ग) इस रिपोर्ट के अनुसार जांचे गए स्टैंडएलोन तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का स्टैंडएलोन विवरण और स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण लेखों की संबंधित पुस्तकों के अनुसार है;

घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016, अधिसूचित किए जाने तक, सहित पढ़ा जाए, के अंतर्गत लेखांकन मानकों के अनुपालन में है;

ड) 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी के निदेशक मंडल और सहायक कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को अधिनियम की धारा 164 के उप खंड (2) के अनुसार कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं है;

च) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के अनुसार नियंत्रक कंपनी के इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभाविता के संबंध में संदर्भ के लिए **अनुलग्नक - 'ग'** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;

छ) धारा 197 के प्रावधानों जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाए, कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सार्वजनिक कंपनी नहीं है जैसा अधिनियम की धारा 2(71) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, इसलिए यह धारा लागू नहीं होती है; और

ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन किया हैं - संदर्भ स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का नोट 25 देखें;

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभासी हानि नहीं थी; और

पृष्ठ 5 पर जारी

iii) कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित किया जाना था।

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 अगस्त, 2021

हस्ता.

अंकुर गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 099143
यूडीआईएनः 21099143एएएसीवाई6093

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'क'

***(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ (1) के संदर्भ में)***

कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर सत्य और सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा के आधार और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा लेखापरीक्षा की सामान्य अवधि में हमारे द्वारा लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों की जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में;

क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के परिमाणात्मक विवरण और स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरों को दर्शाने वाले यथोचित दस्तावेज रखे हैं।

ख) जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सत्यापित किए जाते हैं, जो हमारे अभिमत में व्यापार के आकार एवं इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रकृति पर विचार करते हुए उपयुक्त है। इस प्रकार के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई खामी नहीं पाई गई है।

ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। इसलिए यह खंड लागू नहीं होता हैं।

(ii) कंपनी के पास कोई स्टॉक नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता हैं।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व वाली पार्टनरशिप अथवा अन्य पार्टियों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित, कोई भी ऋण नहीं दिया है।

(iv) हमारे अभिमत और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत शामिल ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं किया हैं।

(v) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के सूचना के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा अन्य संबंधित प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी निक्षेप को स्वीकार नहीं किया है।

(vi) भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 148 की उप धारा (1) में उल्लेख किए गए अनुसार लागत रिकार्डों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।

पृष्ठ 2 पर जारी

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'ख'

*(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ (2) के संदर्भ में)*

वर्ष 2020-21 के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश और उप-निर्देश

| क्र.सं. | निर्देश/उप-निर्देश | लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया | उन पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई | स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| क | **निर्देश** | | | |
| 1 | क्या कंपनी में आईटी प्रणाली द्वारा लेखांकन लेन-देनों को प्रोसेस करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों को प्रोसेस करने से वित्तीय जटिलताओं के साथ लेखों की सत्यनिष्ठता पर प्रभाव, यदि कोई हो तो, बताएं। | हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के लेखा लेन-देनों को 'टेली ईआरपी9' सॉफ्टवेयर में लेखाबद्ध किया जाता है और आईटी प्रणाली के बाहर प्रोसेस नहीं किया जाता है। | किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। | कोई प्रभाव नहीं। |
| 2 | क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की अक्षमता के कारण मौजूदा ऋण को पुनर्संरचनाबद्ध करने अथवा कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो, वित्तीय प्रभावों को बताएं। क्या ऐसे मामलों को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया था? | हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की अक्षमता के कारण मौजूदा ऋण को पुनर्संरचनाबद्ध करने अथवा कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है | किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। | कोई प्रभाव नहीं। |

पृष्ठ 2 पर जारी

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | क्या केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से किन्हीं विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाले धन/अनुदान/अनुवृत्ति राशि को उचित रूप से लेखाबद्ध/निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | भारत सरकार ने विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए विभिन्न परियोजना विकास/प्रारंभिक गतिविधियां शुरू करने के लिए परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) की स्थापना को मंजूरी दी, जिसके लिए कंपनी नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है जिसे 'आरक्षित और अधिशेष' के तहत पूंजी आरक्षित निधि के रूप में प्रकटन किया गया है।<br><br>हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान को इसकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है और इसे स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट 14 में प्रकट किया गया है। | किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। | कोई प्रभाव नहीं। |
| B | उप -निर्देश | | | |
| | कुछ नहीं | | | |

**कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन**

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 10 अगस्त, 2021**

हस्ता.

**अंकुर गोयल**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. 099143**
**यूडीआईएनः 21099143एएएसीवाई6093**

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'ग'

***(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 3(घ) के संदर्भ में)***

**कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार, हमने उक्त तिथि को **कंपनी** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग अर्हता पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और चूक को रोकना एवं पहचान करना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं परिपूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित इसके व्यापार को उचित एवं प्रभावी रूप से करने को सुनिश्चित करना शामिल है।

**लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी की हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने "आईसीएआई" द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट" ("गाइडेंस नोट") और लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किए गए हैं, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और बनाया रखा गया था और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी भौतिक पहलूओं पर प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और निर्धारितकिए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की गलतबयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

पृष्ठ 2 पर जारी

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित रूप से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करे कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से दर्ज़ किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति के अनुसार ही किया जा रहा हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान के बारे में समय पर पता लगाना एवं रोकना जिसका स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं**

मिलीभगत की संभावना अथवा गतिविधियों पर अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, चूक अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जो स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों के अनुपालन में कमी अथवा पद्धतियों के क्षरण के कारण जोखिम के अध्यधीन है, अपर्याप्त हो सकता है।

**अभिमत**

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्राप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जिन्हें 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया' द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखा परीक्षा' पर गाइडेंस नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किये गए थे।

**कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन**

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 10 अगस्त, 2021**

हस्ता.

**अंकुर गोयल**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. 099143**
**यूडीआईएन: 21099143एएएसीवाई6093**

# एकल वित्तीय विवरण

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)**

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को स्टैंडएलोन तुलन पत्र**

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **इक्विटी एवं दायित्वाएं** | | | | | |
| **शेयरधारकों की निधियां** | | | | | |
| (क) शेयर पूंजी | 3 | 1,00,00,00,000 | | 1,00,00,00,000 | |
| (ख) आरक्षित एवं अधिशेष | 4 | 7,20,42,39,917 | 8,20,42,39,917 | 6,64,44,64,486 | 7,64,44,64,486 |
| **गैर-चालू दायित्वाएं** | | | | | |
| (क) अन्य दीर्घकालिक दायित्वाएं | 5 | - | | 10,00,000 | |
| (ख) दीर्घकालिक प्रावधान | 6 | 50,82,006 | 50,82,006 | 40,34,648 | 50,34,648 |
| **चालू दायित्वाएं** | | | | | |
| (क) व्यापार देय | 7 | | | | |
| (i) सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के कुल देय बकाया | | 1,22,67,665 | | - | |
| (ii) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर देनदारों के कुल देय बकाया | | 19,45,73,463 | | 34,67,21,642 | |
| (ख) अन्य चालू दायित्वाएं | 8 | 3,92,32,340 | | 3,89,29,711 | |
| (ग) लघुकालिक प्रावधान | 9 | 13,98,476 | 24,74,69,944 | 6,34,204 | 38,62,85,557 |
| **जोड़** | | | **8,45,67,91,867** | | **8,03,57,84,691** |
| **परिसंपत्तियां** | | | | | |
| **गैर चालू परिसंपत्तियां** | | | | | |
| (क) संपत्तियां, संयंत्र और उपकरण | 10 | 2,05,90,852 | | 2,29,08,194 | |
| (ख) अमूर्त परिसंपत्तियां | 10 | 19,12,114 | | 28,72,205 | |
| (ग) अचल निवेश | 11 | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 | |
| (घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 12 | 35,06,596 | | 23,56,521 | |
| (ङ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम | 13 | 5,54,010 | | 5,52,000 | |
| (च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां | 14 | 6,74,17,95,338 | 6,89,83,58,710 | 8,14,08,56,958 | 6,29,95,45,878 |
| **चालू परिसंपत्तियां** | | | | | |
| (क) व्यापार प्राप्य | 15 | 1,38,12,500 | | 1,32,50,000 | |
| (ख) रोकड़ और बैंक शेष | 16 | 1,48,03,59,067 | | 1,61,56,66,589 | |
| (ग) लघुकालिक ऋण और अग्रिम | 17 | 66,37,827 | | 28,07,052 | |
| (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 18 | 5,76,23,763 | 1,55,84,33,157 | 10,45,15,172 | 1,73,62,38,813 |
| **जोड़** | | | **8,45,67,91,867** | | **8,03,57,84,691** |
| **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां** | 2 | | | | |
| लेखों पर संलग्न लेखे स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग हैं। | 3-37 | | | | |

समसंख्यक तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
**कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण सं. 000346एन**

हस्ता.

**सीए अंकुर गोयल**
**(साझेदार)**
**(सदस्यता सं. 099143 )**

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता.

**(के संजय मूर्ति)**
**सीईओ एवं प्रबंध निदेशक**
**(डीआईएन : 03532374)**

हस्ता.

**(पी. के. अग्रवाल)**
**मुख्य वित्तीय अधिकारी**

हस्ता.

**(राजेंद्र रत्नू)**
**निदेशक**
**(डीआईएन : 02855304)**

हस्ता.

**(अभिषेक चौधरी)**
**उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त, 2021

यूडीआइएन: 21099143एएएएसी6093

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)**

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडएलोन विवरण**

| विवरण | नोट | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|---|
| परिचालन से आमदनी | 19 | 25,00,00,000 | 13,28,00,400 |
| अन्य आय | 20 | 7,14,27,948 | 9,24,41,716 |
| कुल आमदनी | | 32,14,27,948 | 22,52,42,116 |
| व्यय | | | |
| - कर्मचारी हितलाभ व्यय | 21 | 5,29,64,572 | 4,81,17,518 |
| - मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 22 | 85,40,502 | 68,23,649 |
| - अन्य व्यय | 23 | 8,12,26,776 | 12,96,70,716 |
| कुल व्यय | | 14,28,31,850 | 18,46,11,883 |
| कर पूर्व लाभ | | 17,85,96,098 | 4,06,30,233 |
| कर व्यय | | | |
| - चालू कर | | 5,32,43,105 | 1,22,16,066 |
| - पिछले वर्ष | | 58,795 | 7,732 |
| - आस्थगित कर | | (11,50,075) | (6,39,832) |
| वर्ष के लिए लाभ | | 12,64,44,273 | 2,90,46,267 |
| आमदनी प्रति इक्विटी शेयर (समतुल्य 10/- रुपए प्रति शेयर) | 24 | | |
| - प्रति शेयर मूल आमदनी | | 1.26 | 0.29 |
| - प्रति शेयर तनुकृत आमदनी | | 1.26 | 0.29 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | | |
| लेखों पर संलग्न लेखे स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग हैं। | 3-37 | | |

समसंख्यक तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
**कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
**फर्म पंजीकरण सं. 000346एन**

हस्ता.

**सीए अंकुर गोयल**
**(साझेदार)**
**(सदस्यता सं. 099143)**

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता.

**(के संजय मूर्ति)**
**सीईओ एवं प्रबंध निदेशक**
**(डीआईएन : 03532374)**

हस्ता.

**(राजेंद्र रत्नू)**
**निदेशक**
**(डीआईएन : 02855304)**

हस्ता.

**(पी. के. अग्रवाल)**
**मुख्य वित्तीय अधिकारी**

हस्ता.

**(अभिषेक चौधरी)**
**उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त, 2021

यूडीआइएन: 21099143एएएएसी6093

## नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
## (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

### 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|---|
| **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | | |
| कर पूर्व शुद्ध लाभ | | 17,85,96,096 | 4,66,30,233 |
| **समायोजन के लिए:** | | | |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | | 86,40,502 | 68,23,649 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि | | 595 | 2,11,346 |
| ब्याज आय | | (6,03,39,463) | (8,31,80,413) |
| कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ | | 12,68,97,732 | (3,55,15,185) |
| **समायोजन के लिए:** | | | |
| व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी | | (5,62,500) | 2,39,72,026 |
| अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी | | 1,93,09,667 | 85,85,342 |
| व्यापार देयों में वृद्धि/(कमी) | | (13,98,80,514) | 5,62,64,682 |
| अन्य देयों में वृद्धि/(कमी) | | 2,63,643 | (39,69,601) |
| **परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी/(प्रयुक्त)** | | 80,28,028 | 4,93,37,264 |
| भुगतान किए कर (रिफंड का शुद्ध) | | (3,09,56,320) | (2,20,21,272) |
| **परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)** | | (2,49,28,292) | 2,73,15,992 |
| **पूंजी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | | |
| परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियां | | 45,00,00,000 | 52,70,00,000 |
| परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों से अर्जित ब्याज | | 92,26,079 | 2,07,33,908 |
| परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता | | (82,45,81,611) | (74,52,54,031) |
| स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियां | | 10,00,000 | - |
| स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज | | 203 | - |
| स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता | | (10,00,000) | - |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की (खरीद) | | (53,63,964) | (2,37,17,201) |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री | | 500 | 50,593 |
| बैंकों के साथ निक्षेपों (वृद्धि)/कमी | | (9,94,81,710) | 97,36,618 |
| ब्याज आय | | 6,03,39,463 | 8,31,80,413 |
| **निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)** | | (20,98,60,940) | (12,82,69,700) |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | - | - |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)** | | - | - |
| **रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)** | | (23,47,89,232) | (10,09,53,708) |
| वर्ष की शुरूआत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य | | 1,61,56,66,589 | 1,71,66,20,297 |
| **वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य** | | 1,38,08,77,357 | 1,61,56,66,589 |
| **रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक :** | | | |
| रोकड़ शेष | | 2,153 | 8,373 |
| चालू खातों में बैंक के पास शेष | | 12,18,38,907 | 4,27,319 |
| अवधि जमाओं में बैंक के पास शेष | | 1,25,90,36,297 | 1,61,52,30,897 |
| | | 1,38,08,77,357 | 1,61,56,66,589 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | | |
| लेखों पर संलग्न लेखे स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग हैं। | 3-37 | | |

समसंख्यक तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 00334Cएन

हस्ता.

सीए अंकुर गोयल
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 099143)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(के संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03532374)

हस्ता.

(पी. के. अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता.

(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन : 02855304)

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त, 2021
यूडीआइएन: 21099143एएएसीआई6093

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**

**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)**

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट**

**नोट 1- कंपनी की सूचना**

भारत सरकार ने प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में विनिर्माण के साथ नियोजित शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और देश के औद्योगिक/विनिर्माण विकास को मजबूत गति देने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 2007 में पहले औद्योगिक गलियारे के रूप में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) परियोजना की अवधारणा की घोषणा की।

तदनुसार, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) को डीएमआईसी परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के रूप में 7 जनवरी 2008 को निगमित किया गया था।

सितंबर, 2011 में, भारत सरकार ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट में औद्योगिक शहरों के विकास हेतु डीएमआईसी प्रोजेक्ट की वित्तीय और संस्थानिक संरचना को अनुमोदन दिया और डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के रूप में एक परिक्राम्य कार्पस के साथ समर्पित निधि सृजन को भी अनुमोदन दिया।

डीएमआईसीडीसी नए greenfield इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए विभिन्न पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरिंग अध्ययन करने के लिए एक परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य करती है। डीएमआईसीडीसी को डीएमआईसी-पीआईटीएफ के लिए और डीएमआईसी क्रियान्वित करने के लिए सभी एसपीवी और राज्य सरकार एजेंसियों के लिए भी परियोजना विकास पार्टनर/नॉलेज पार्टनर का अधिदेश है।

दिसंबर 2016 में भारत सरकार ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के अधिदेश का विस्तार किया और देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः नामित किया।

डीएमआईसीडीसी को अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए नॉलेज पार्टनर नियुक्त होने तक डीएमआईसी कार्य के अलावा सभी औद्योगिक गलियारों के संबंध में एनआईसीडीआईटी के लिए एक नालेज पार्टनर के रूप में कार्य करने का अधिदेश दिया गया था।

विस्तारित अधिदेश को देखते हुए 17 फरवरी 2020 से कंपनी का नाम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) से बदलकर नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) कर दिया गया।

इसके बाद, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के समग्र ढांचे के भीतर औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 4 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 32 परियोजनाओं सहित 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं (पहले अनुमोदित 5 औद्योगिक गलियारों सहित) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।

**नोट 2 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

**2.1 स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार**

कंपनी के संलग्न स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), अधिसूचित एवं लागू किए जाने की सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों जो कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ के पठनीय है, जिस तरह से आवश्यक है, प्रोद्भवन आधार पर परंपरागत ऐतिहासिक लागत पर तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के संदर्भ में सामान्य अनुदेशों में परिभाषित लघु और मध्यम आकार की कंपनी (एसएमसी) के तहत कंपनी एक स्तर - III श्रेणी का उद्यम है। तदनुसार, कंपनी ने लघु और मध्यम आकार कंपनियों पर लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है।

कंपनी ने सामान्य परिचालन चक्र के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और दायित्वाओं को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया है। सेवाओं की प्रकृति और सेवाओं को प्रदान करने और नकद और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्ति और दायित्वाओं के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

**2.2 अनुमानों का उपयोग**

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ('जीएएपी') के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आवश्यकतानुसार आकलन और अनुमान लगाने की ज़रूरत होती है, जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। यद्यपि इस तरह के अनुमान और मान्यताएं सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित एवं विवेकपूर्ण आधार पर तैयार किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिणाम ज्ञात/साकार होते हैं।

**2.3 संपत्ति संयंत्र और उपकरण**

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचयी मूल्यह्रास और अपसामान्य हानियों, यदि कोई हो तो, ऐतिहासिक लागत के बाद घटाते हुए दिखाया जाता है।

ii) अधिग्रहण/निर्माण की लागत में भाड़ा, निर्माण और कमीशन प्रभार, शुल्क और कर, निर्माण अवधि के दौरान अधिग्रहण/स्थापना की तारीख तक व्यय और निर्माण/स्थापना चरण के दौरान किए गए अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं।

iii) जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक हिस्से के अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु से संबंधित बाद के खर्च को उसके बुक वैल्यू में तभी जोड़ा जाता है जब वे मौजूदा परिसंपत्ति से प्रदर्शन के पिछले आकलन से भविष्य के लाभों को आगे बढ़ाते हैं। मरम्मत और रखरखाव की लागत को जब भी खर्च किया जाता है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

v) सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली हानि, अथवा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से उत्पन्न होने वाली लाभ/हानि, जिसे लागत पर किया जाता है, सेवानिवृत्ति/निपटान के वर्ष में लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में प्रदर्शित किया जाता है।

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास, लागत के 5 प्रतिशत को अवशिष्ट मूल्य रखते हुए उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित विधि से लगाया जाता है। हालांकि, यदि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए प्रबंधन का अनुमान पूर्वोक्त अनुसूची में परिकल्पित से कम है, तो प्रबंधन के उपयोगी/शेष जीवन के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास उच्च दर पर लगाया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार और प्रबंधन द्वारा अनुमान के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

| परिसंपत्ति | उपयोगी जीवन (वर्षों में) |
|---|---|
| फर्नीचर और फिक्सचर | 10 |
| कार्यालय उपकरण | 5 |
| विद्युत संस्थापना और उपकरण | 10 |
| कम्प्यूटर - डेस्कटॉप, लैपटॉप, आदि जैसे अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण | 3 |
| कम्प्यूटर - सर्वर और नेटवर्क | 6 |

vii) 5,000 रुपये तक की लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से अवमूल्यन किया जाता है।

viii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अतिरिक्त मूल्यह्रास पर संपत्ति के अनुमानित शेष उपयोगी जीवन पर संपत्ति के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख से आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है। परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/नष्ट/ध्वस्त करने पर मूल्यह्रास परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान की तिथि तक, जैसा भी मामला हो, प्रभारित किया जाता है।

ix) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित समय-समय पर मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है

x) यदि कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त या निपटान के लिए रखे गए हैं, उन्हें लागत (शुद्ध संचित मूल्यह्रास) या अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर बताया जाता है।

xi) लीजहोल्ड सुधार की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

xii) निर्माणाधीन संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और परिसंपत्ति की लागत जो वर्ष के अंत से पहले उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में दिखाया गया है।

xiii) प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

## 2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त संपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जहां यह संभावना है कि संपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ व्यवसाय को प्राप्त होंगे और संपत्ति की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता और व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में परिलक्षित होता है जिसमें व्यय किया गया है।

अमूर्त संपत्ति में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं और इसे संचित परिशोधन की लागत को घटाते हुए अधिग्रहण/कार्यान्वयन की लागत पर बताया जाता है। इसे 5 साल की अवधि अथवा स्ट्रेट लाइन के आधार पर लाइसेंस अवधि, जो भी पहले हो, में परिशोधित किया जाता है।

## 2.5 परिसंपत्तियों का परिशोधन

एक परिसंपत्ति को तभी परिशोधित माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में परिसंपत्तियों की अग्रणी राशि की समीक्षा की जाती है और यदि आंतरिक/बाहरी कारणों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो हानि को मान्यता दी जाती है। कोई हानि उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में तब प्रभारित की जाती है जिस अवधि में किसी परिसंपत्ति को परिशोधित के रूप में पहचाना जाता है। जहां वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है वहां पूर्व लेखा अवधि में पहचानी गई परिशोधित हानि को बढ़ाया/घटाया जाता है। वसूली योग्य मूल्य परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य एवं उपयोग में मूल्य, जो भी अधिक हो, होती है।

## 2.6 सहायता अनुदान

### 2.6.1 परियोजना विकास निधि (पीडीएफ)

भारत सरकार ने विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए विभिन्न परियोजना विकास/प्रारंभिक गतिविधियां करने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड की स्थापना को स्वीकृति दी है जिसके लिए कंपनी को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से विदित, के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है जिसे आरक्षित कोष एवं अधिशेष के अंतर्गत पूंजीगत कोष में प्रदर्शित किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईसीडीआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त, फंड में से परियोजना विकास/प्रारंभिक गतिविधियों पर वहन किए गए व्ययों को निम्नानुसार प्रबंधित किया जाता है:

क) कंपनी की सहायक कंपनियों और उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जिनके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच अलग-अलग विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) बनाई गयी है, जहां भी शेयरधारकों के समझौते की शर्तों के अनुसार वसूली योग्य हो, संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी से वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाता है और 'अन्य गैर-चालू संपत्ति' के तहत प्रकटन किया जाता है;

ख) जिन परियोजनाओं के लिए खर्च नहीं किया जाना है या आगे कोई गतिविधियां नहीं की जानी हैं या एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार (सरकारों)/नोडल एजेंसी के बीच शेयरधारकों के समझौते में वसूली का प्रावधान नहीं है, उन्हें 'पूंजी आरक्षित कोष' के तहत परियोजना विकास निधि के शेष से कम किया जाता है; और

ग) उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जो प्रगति पर हैं और जहां शेयरधारकों के समझौते का निष्पादन न होने के कारण एसपीवी को अभी तक निगमित नहीं किया गया है अथवा जहां एनआईसीडीआईटी/ सीसीईए द्वारा निवेश के लिए परियोजनाओं को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है या उपरोक्त पैरा (क) और (ख) के तहत शामिल नहीं किए गए किसी भी अन्य व्यय को "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" के शीर्ष के तहत परियोजना विकास व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

2.6.2 **परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ)**

भारत सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए सरकार से धारक कंपनी द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त होता है। भारत का नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट और इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के माध्यम से और 'आरक्षित और अधिशेष' के तहत पूंजी भंडार के रूप में प्रकटन किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईसीडीआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है और गैर-वसूलनीय व्ययों को निधि शेष से पूरा किया जाता है।

2.6.3 **स्वच्छता कार्य योजना निधि (एसएपी)**

भारत सरकार ने स्वच्छता कार्य योजना के प्रति व्ययों की पूर्ति के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) की स्थापना को स्वीकृति दी है जिसके लिए कंपनी को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से विदित, के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है जिसे आरक्षित कोष एवं अधिशेष के अंतर्गत पूंजीगत कोष में प्रदर्शित किया गया है। फंड से भारत सरकार/एनआईसीडीआईटी को किसी राशि के वापसी योग्य होने पर उक्त राशि को उस वर्ष में रिफंड के शेष से घटाया जाता है।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है और गैर-वसूलनीय व्ययों को निधि शेष से पूरा किया जाता है।

## 2.7 निवेश

सहायक कंपनियों में निवेश मुख्य रूप से लंबी अवधि के लिए होता है और इसका मूल्यांकन संचित हानियों को घटाते हुए, यदि कोई हो, उस पर किया जाता है। लागत में अधिग्रहण लागत और इसके अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य आकस्मिक लागत शामिल हैं। ऐसे निवेशों के वहन मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट होने की स्थिति में प्रावधान किया जाता है। एक निवेश के मूल्य के संकेतक उसके बाजार मूल्य, निवेशिती की संपत्ति और परिणामों और निवेश से अपेक्षित नकदी प्रवाह के संदर्भ में प्राप्त किए जाते हैं।

चालू निवेशों को निम्नतर लागत अथवा उद्धृत मूल्य पर किया जाता है।

निवेशों के निपटान पर, शुद्ध निपटान आय और अग्रणीत राशियों के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

## 2.8 राजस्व मान्यता

क) कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त आमदनी को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और जब व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें लागू करने योग्य हैं, सेवाएं वितरित की गई हैं, संग्रहणीयता यथोचित रूप से सुनिश्चित है और राजस्व को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तदनुसार, सेवाओं से प्राप्त आमदनी को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

(i) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किए गए निधियों की 1% की दर से सेवा शुल्क जिसे एनआईसीडीआईटी ने 26 जुलाई 2016 को हुई बैठक में अनुमोदित किए अनुसार एक वर्ष में ₹ 20,00,00,000 की अधिकतम सीमा तक मान्यता दी गई है।

(ii) नॉलेज पार्टनर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वार्षिक आंतरिक प्रोद्भवन के 1% की दर से सेवा शुल्क आईआईसीसी के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन में निर्धारित अनुसार 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर न्यूनतम ₹ 5,00,00,000 और अधिकतम ₹ 10,00,00,000 प्रति वर्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ख) ब्याज आय को बकाया राशि और ब्याज की लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय आनुपातिक आधार पर स्वीकारा जाता है।

ग) लाभांश का लेखांकन तब किया जाता है, जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

**2.9 लीज**

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान मूल रूप से स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से रखता है। परिचालन लीज के अंतर्गत लीज भुगतानों को प्रोद्भवन आधार पर लाभ एवं हानि खाते के स्टैंडएलोन विवरण में दिखाया जाता है।

**2.10 विदेशी मुद्रा में लेन-देन**

विदेशी मुद्रा लेनदेन उक्त तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद विदेशी मुद्रा में मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों को उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। भारत के बाहर किसी देश से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशि और देनदारियों के मामले में विनिमय दरों के अंतर को इसकी लागत में समायोजित किया जाता है। अन्य सभी विनिमय अंतर लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में पहचाने जाते हैं। वायदा विनिमय अनुबंध पर प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि के दौरान व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। इस तरह के अनुबंध पर विनिमय अंतर को रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन होता है। वायदा अनुबंध के रद्दीकरण अथवा नवीनीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान आय और व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

**2.11 कर्मचारी हितलाभ**

**क) अल्पकालिक अवधि हितलाभ:**

इन्हें उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन लाभों में सरकारी कर्मचारियों को कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान शामिल है, जिसका हिसाब केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार है, संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जो वर्ष के अंत से 12 महीनों के भीतर प्राप्त या भुनाए जाने की उम्मीद है।

**ख) परिभाषित अंशदान योजना:**

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार वैधानिक भविष्य निधि, पेंशन योजना में वर्ष के दौरान भुगतान या देय कंपनी के योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी सेवाएं प्रदान करता है।

**ग) परिभाषित हितलाभ योजना:**

ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का दायित्व वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक द्वारा निर्धारित बीमांकिक लाभ या हानि को उस वर्ष के दौरान लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में पहचाना जाता है जिसका बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

**2.12 खंडवार रिपोर्टिंग**

परिचालन खंड की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और निर्णय लेने के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। लेखांकन मानक 17 के अनुसार निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता" या "सीओडीएम" है। कंपनी के पास विभिन्न औद्योगिक गलियारों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में सेवाएं प्रदान करने का केवल एक रिपोर्टिंग खंड है, जो कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

**2.13 आय पर कर**

क) कर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर दोनों शामिल है।

ख) वर्तमान आयकर, परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए कर निर्धारण अधिनियम,1961 में कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा सम्मिलित कर व्यवस्था और भारत में अधिनियमित आयकर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके कर प्राधिकरणों से भुगतान की जाने वाली या वसूली योग्य राशि पर मापा जाता है।

ग) आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के परिणामस्वरूप आस्थगित कर दायित्व जो उत्तरवर्ती लेखा अवधि में बदलने में सक्षम है, उसे रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित अथवा वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों में लेखाबद्ध किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है। उनकी वसूली के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

घ) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) उस वर्ष के दौरान वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण पर लगाया जाता है जिसमें इसका भुगतान किया जाता है। कंपनी एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को केवल उस हद तक मान्यता देती है कि इस बात के उपयुक्त साक्ष्य हैं कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यानी वह अवधि जिसके लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है। कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन पर गाइडेंस नोट के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देती है, उक्त परिसंपत्ति को स्टैंडएलोन लाभ और हानि स्टेटमेंट में क्रेडिट के माध्यम से बनाया जाता है और "न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता" के रूप में दिखाया गया है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर "न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता" संपत्ति की समीक्षा करती है और परिसंपत्ति को उस हद तक लेखाबद्ध करती है, जिस हद तक कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि वह निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य कर का भुगतान करेगी।

**2.14 आमदनी प्रति शेयर**

कंपनी "प्रति शेयर कमाई" पर लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और तनूकृत आय (ईपीएस) को रिपोर्ट करती है।

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिसे सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां सभी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर के परिणाम एंटी-डिल्यूटिव हैं।

**2.15 प्रावधान, आकस्मिक दायिताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

लेखों में किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना(ओं) के परिणामस्वरूप मौजूदा दायित्व हो और यह संभावना हो कि संसाधनों के बहिर्वाह के संबंध में दायिता का निपटान करने की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रावधानों को उनकी मौजूदा कीमत पर बट्टागत नहीं किया जाता और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट्स में तब किया जाता है जब पिछली घटना(ओं) से उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्व होते है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने/ना-होने से की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटना (ओं) से उत्पन्न होता है, जहां यह या तो संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा या एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

**2.16 रोकड़ और समतुल्य रोकड़**

नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकद, चेक, हाथ में ड्राफ्ट/ट्रांजिट में प्रेषण, बैंक शेष और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि शामिल है और जो नकद और नकद समकक्ष की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जिनकी कीमतों में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

**2.17 रोकड़ प्रवाह विवरण**

रोकड़ प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष विधि" द्वारा तैयार किया जाता है जैसा कि "रोकड़ प्रवाह विवरण" पर लेखांकन मानक 3 में निर्धारित किया गया है और कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत करता है।

स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रस्तुत किए गए रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में हाथ में नकद, चेक, हाथ में ड्राफ्ट/ट्रांजिट में प्रेषण, बैंक बैलेंस और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले डिपॉजिट शामिल हैं और जो रोकड़ और रोकड़ समतुल्य की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं।

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)**
सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट**

| विवरण | 31, मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 3 शेयर पूंजी** | | |
| **प्राधिकृत** | | |
| 10/- रुपए कीमत वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष: 10,00,00,000) | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| **निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी** | | |
| 10/- रुपए कीमत वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष: 10,00,00,000) | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| जोड़ | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |

**3.1 वर्ष की शुरुआत और वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य:**

| | 31, मार्च, 2021 को | | 31 मार्च, 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | (₹) | शेयरों की सं. | (₹) |
| वर्ष की शुरुआत में शेष | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में शेष | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |

**3.2 इक्विटी शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार**

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका सममूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित और वितरित नहीं किया गया था (लाभांश के बारे में अधिक जानकारी के लिए नोट 34 भी देखें)। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी वरीयता प्राप्त राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

**3.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा**

| | 31, मार्च, 2021 को | | 31 मार्च, 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की सं. | धारिता % | शेयरों की सं. | धारिता % |
| भारत के राष्ट्रपति | 4,90,00,000 | 49.00 | 4,90,00,000 | 49.00 |
| (सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं उनके नामिती द्वारा) | | | | |
| जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) | 2,60,00,000 | 26.00 | 2,60,00,000 | 26.00 |
| हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड | 1,99,00,000 | 19.90 | 1,99,00,000 | 19.90 |

**3.4** कंपनी ने बोनस शेयरों को जारी नहीं किया है और न ही नकदी प्राप्त किए बिना ही शेयरों को जारी किया है और तुलन पत्र की तिथि से पिछले पांच वर्षों के दौरान किन्हीं भी शेयरों को वापिस नहीं खरीदा गया है।

| विवरण | | 31, मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 को (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **नोट 4 : आरक्षित और अधिशेष** | | | | | |
| **(क.) पूंजी आरक्षित निधि - के लिए प्राप्त सहाता अनुदानः** | | | | | |
| (संदर्भ नोट 2.6) | | | | | |
| **(i) परियोजना विकास निधि** | | | | | |
| अंतिम तुलन पत्र के अनुसार | | 6,35,20,27,000 | | 5,82,50,27,000 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान | | 45,00,00,000 | 6,80,20,27,000 | 52,70,00,000 | 6,35,20,27,000 |
| **जोड़ें: परियोजना विकास निधि पर अर्जित ब्याज** | | | | | |
| अंतिम तुलन पत्र के अनुसार | | 31,33,51,562 | | 29,26,17,655 | |
| वर्ष के दौरान सावधि जमा और कर रिफंड पर ब्याज | | 92,26,079 | 32,25,77,641 | 2,07,33,907 | 31,33,51,562 |
| (घटाएं): वसूले न जा सकने वाले परियोजना विकास व्यय | | | | | |
| अंतिम तुलन पत्र के अनुसार | | (37,96,70,926) | | (33,40,67,373) | |
| वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय | | (2,36,43,131) | (40,35,14,057) | (4,56,03,553) | (37,96,70,926) |
| (घटाएं): परियोजना विकास निधि पर अर्जित ब्याज पर कर कर प्रभाव | | | (22,51,993) | | - |
| | (i) | | 6,71,88,38,591 | | 6,28,55,07,636 |
| **(ii) परियोजना कार्यान्वयन निधि** | | | | | |
| अंतिम तुलन पत्र के अनुसार (संदर्भ नोट 11.1) | | | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 |
| | (ii) | | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 |
| **(iii) स्वच्छता कार्य योजना** | | | | | |
| वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान | | | 10,00,000 | | - |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान सावधि जमाओं पर ब्याज | | | 203 | | - |
| (घटाएं): वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय | | | (10,00,000) | | - |
| | (iii) | | 203 | | - |
| **उप-जोड़** | | | **6,84,88,38,794** | | **6,41,55,07,636** |
| **(ख.) अधिशेष** | | | | | |
| अंतिम तुलन पत्र के अनुसार | | 22,89,56,850 | | 19,99,10,583 | |
| जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ | | 12,64,44,273 | 35,54,01,123 | 2,90,46,267 | 22,89,56,850 |
| **जोड़** | | | **7,20,42,39,917** | | **6,64,44,64,486** |

| विवरण | 31, मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्वाएं** | | |
| निष्पादन प्रतिभूति | - | 10,00,000 |
| जोड़ | - | 10,00,000 |

| विवरण | 31, मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 6 : दीर्घकालिक प्रावधान** | | |
| **कर्मचारी हितलाभ प्रावधान** | | |
| - ग्रेच्यूएटी) (संदर्भ नोट सं. 26) | 50,82,006 | 40,34,648 |
| जोड़ | 50,82,006 | 40,34,648 |

| विवरण | 31, मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 7 : व्यापार देय** | | |
| सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को कुल देय बकाया (संदर्भ नोट सं. 7.1) | 1,22,67,665 | - |
| सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं का कुल देय बकाया | 19,45,73,463 | 34,67,21,642 |
| जोड़ | 20,68,41,128 | 34,67,21,642 |

7.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार सूचना नीचे दी गई है। यह सूचना कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है।

| विवरण | 31, मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| i) वर्ष के अंत में एमएसएमईडी अधिनियम के तहत शामिल किए गए किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन और उस पर देय ब्याज | | |
| -मूलधन | 1,22,67,665 | - |
| - ब्याज | - | - |
| ii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि | - | - |
| iii) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना | - | - |
| iv) वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि; तथा | - | - |
| v) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से, बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की गई हो | - | - |

## 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

| विवरण | 31, मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 8 - अन्य चालू दायित्वाएं** | | |
| सांविधिक दायित्वाएं | 2,39,19,125 | 2,00,42,380 |
| अर्जित व्यय | 16,31,541 | 16,25,259 |
| व्ययों के लिए ऋणदाता | 82,06,535 | 1,69,76,866 |
| कर्मचारी संबंधित देय | 4,75,139 | 2,85,207 |
| बोली प्रतिभूति | 50,00,000 | - |
| जोड़ | 3,92,32,340 | 3,89,29,711 |

| विवरण | 31, मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 को (₹) | |
|---|---|---|---|---|
| **नोट 9 : अल्पकालिक प्रावधान** | | | | |
| **कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान** | | | | |
| - ग्रेच्यूएटी (संदर्भ नोट 26) | 3,78,464 | | 4,73,546 | |
| - अवकाश नकदीकरण | 1,69,397 | 5,47,861 | 1,60,658 | 6,34,204 |
| **अन्य प्रावधान** | | | | |
| - कर के लिए प्रावधान [ ₹ 5,46,46,484/- का शुद्ध अग्रिम कर प्रावधान (पिछले वर्ष: ₹ 2,43,65,442/-)] | | 8,48,615 | | - |
| जोड़ | | 13,96,476 | | 6,34,204 |

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)**
सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट**

**नोट 10 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां**

(₹)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास/परिशोधन | | | | शुद्ध ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल, 2020 को | वर्ष के दौरान संवर्धन | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समायोजन | 31 मार्च, 2021 को | 1 अप्रैल, 2020 को | वर्ष के लिए (संदर्भ नोट 10.2) | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समायोजन | 31 मार्च, 2021 को | 31 मार्च, 2021 को | 31 मार्च, 2020 को |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर | 52,42,629 | - | - | 52,42,629 | 12,14,426 | 10,44,258 | - | 22,58,684 | 29,83,945 | 40,28,203 |
| कार्यालय उपकरण | 1,29,45,071 | 14,64,009 | (21,900) | 1,43,87,180 | 58,43,723 | 35,62,682 | (20,805) | 93,85,600 | 50,01,580 | 71,01,348 |
| विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण | 13,80,839 | - | - | 13,80,839 | 2,20,892 | 3,01,247 | - | 5,22,139 | 8,58,700 | 11,59,947 |
| कम्प्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट | 45,46,554 | 20,99,998 | 12,881 | 66,59,433 | 32,28,557 | 14,02,216 | 5,152 | 46,35,925 | 20,23,508 | 13,17,997 |
| पट्टाधृत सुधार (कार्यालय नवीकरण) | 1,41,51,474 | 14,21,007 | - | 1,55,72,481 | 48,50,775 | 9,98,787 | - | 58,49,562 | 97,22,919 | 93,00,699 |
| चालू वर्ष का जोड़ | 3,82,66,567 | 49,85,014 | (9,019) | 4,32,42,562 | 1,53,58,373 | 73,09,190 | (15,653) | 2,26,51,910 | 2,05,90,652 | 2,29,08,194 |
| पिछले वर्ष का जोड़ | 1,37,84,852 | 2,71,85,261 | 27,03,546 | 3,82,66,567 | 1,25,44,243 | 52,55,738 | (24,41,608) | 1,53,58,373 | 2,29,08,194 | |
| अमूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 81,62,543 | 3,78,950 | (12,881) | 85,28,612 | 52,90,338 | 13,31,312 | (5,152) | 66,16,498 | 19,12,114 | 28,72,205 |
| चालू वर्ष का जोड़ | 81,62,543 | 3,78,950 | (12,881) | 85,28,612 | 52,90,338 | 13,31,312 | (5,152) | 66,16,498 | 19,12,114 | 28,72,205 |
| पिछले वर्ष का जोड़ | 81,21,018 | 41,525 | - | 81,62,543 | 37,22,427 | 15,67,911 | - | 52,90,338 | 28,72,205 | |

10.1) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में परिशोधन का निर्धारण करने के लिए कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी "एएस28- संपत्ति का परिशोधन" के अनुसार, कंपनी ने निष्कर्ष निकाला है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि इसकी परिशोधन राशि से कम नहीं है, इसलिए, कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

**10.2) वर्ष के दौरान प्रभृत किए गए मूल्यह्रास समायोजन**

| | संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | | अमूर्त परिसंपत्तियां |
|---|---|---|---|
| | कम्प्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट | पट्टाधृत सुधार (कार्यालय नवीकरण) | कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर |
| उपरोक्त नोट 10 के अनुसार मूल्यह्रास | 14,02,216 | 9,98,787 | 13,31,312 |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन | 1,53,626 | (4,490) | 2,48,489 |
| **वर्ष के लिए मूल्यह्रास** | **15,55,842** | **9,94,297** | **15,79,801** |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 11:अचल निवेश** | | |
| (अन-उद्धृत, लागत पर) | | |
| एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित), परियोजना कार्यान्वयन निधि से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के ₹ 10/- के पूर्ण प्रदत्त 1,30,00,000 इक्विटी शेयरों में (पिछले वर्ष: 1,30,00,000) गैर-व्यापारिक निवेश। (संदर्भ नोट सं. 11.1) | 13,00,00,000 | 13,00,00,000 |
| (घटाएं) : निवेश के मूल्य में कमी | - | - |
| **जोड़** | **13,00,00,000** | **13,00,00,000** |

11.1 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, 6.00 मेगा वाट मॉडल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश के लिए एसपीवी यथा एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड, पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य निधि/पूंजी निधि में से नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (जिसे पूर्व में डीएमआईसीडीसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फंड के रूप में जाना जाता था) द्वारा एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपए) की राशि अंतरित की गई थी। इस प्रकार के निवेश की राशि एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आएगी। ट्रस्ट से प्राप्त धनराशि को नोट 4 में पूंजी आरक्षित निधि के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) के रूप में दिखाया गया है।

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 12 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां:** | | |
| - लेखा और कर के अनुसार मूल्यह्रास/परिशोधन के बीच अंतर | 19,28,317 | 10,58,091 |
| - भुगतान आधार पर अनुमेय व्ययों के कारण समय अंतर | 15,78,279 | 12,98,430 |
| **जोड़** | **35,06,596** | **23,56,521** |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 13 : दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम** | | |
| (असुरक्षित, लेकिन अच्छा माना जाता है) | | |
| प्रतिभूति निक्षेप | 5,52,000 | 5,52,000 |
| पूर्वदत्त व्यय | 2,010 | - |
| **जोड़** | **5,54,010** | **5,52,000** |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 14 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां** | | |
| (असुरक्षित, लेकिन अच्छा माना जाता है) | | |
| **परियोजना विकास निधि में से परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट 2.6.1)** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार | 1,03,76,58,606 | 98,54,71,322 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय [₹ 91,50,000/- की शुद्ध बिड प्रोसेसिंग फीस (पिछले वर्ष: कुछ नहीं)] | 62,45,81,511 | 74,64,16,179 |
| | 1,66,22,40,117 | 1,73,18,87,501 |
| घटाएं: सहयोगी कंपनियों/एसपीवी को अंतरित राशि | (54,71,07,299) | (64,84,25,342) |
| (घटाएं): परियोजना विकास निधि को अंतरण | (2,36,43,131) | (4,58,03,553) |
| उप-जोड़ | **1,09,14,89,687** | **1,03,76,58,606** |
| **एसपीवी से वसूली योग्य परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट 2.6.1, 14.1 और 14.2)** | | |
| - औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड | 2,02,62,02,357 | 1,76,93,26,213 |
| - धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 3,17,83,68,542 | 2,91,46,67,473 |
| - धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड | - | 6,59,998 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड | 8,89,66,428 | 8,48,84,336 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड | 5,48,59,660 | 4,84,10,060 |
| - डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड | 6,87,98,081 | 6,87,12,587 |
| - डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 5,07,54,677 | 5,07,54,677 |
| - इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड | 8,80,82,730 | 7,45,06,230 |
| - एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 9,42,73,176 | 9,19,36,776 |
| | **5,65,03,05,651** | **5,10,38,58,350** |
| (घटाएं) - धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड अन्य चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित (संदर्भ नोट 18) | - | (6,59,998) |
| उप-जोड़ | **5,65,03,05,651** | **5,10,31,98,352** |
| जोड़ | **6,74,17,95,338** | **6,14,08,56,958** |

14.1 नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) ने 6 मार्च, 2018 को हुई अपनी तीसरी बैठक में कंपनी को निर्देश दिया है कि वह संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी को अनुदान-सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली परियोजना विकास निधियों में से सहायक कंपनियों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा वहन किए गए परियोजना विकास व्यय को स्थानांतरित करे और इसकी वसूली को तब तक स्थगित करे जब तक कि एसपीवी पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करने में सक्षम न हो। संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी पर्याप्त अधिशेष निधियां उत्पन्न नहीं कर पाई हैं इसलिए उनसे वसूली की जा सकने वाली राशि 31 मार्च, 2021 तक वसूली के कारण कम नहीं हुई है।

14.2 **एसपीवी से वसूली योग्य परियोजना विकास व्यय का संचलन**

**31 मार्च, 2021 को**

| विशेष प्रयोजन योजना | 31 मार्च, 2020 को शेष | वर्ष के दौरान वहन किया गया व्यय | वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि | 31 मार्च, 2021 को शेष |
|---|---|---|---|---|
| | (₹) | (₹) | (₹) | (₹) |
| - औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड | 1,76,93,26,213 | 25,68,76,144 | - | 2,02,62,02,357 |
| - धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 2,91,46,67,473 | 26,37,01,069 | - | 3,17,83,68,542 |
| - धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड | 6,59,998 | - | (6,59,998) | - |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड | 8,48,84,336 | 40,82,092 | - | 8,89,66,428 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड | 4,84,10,060 | 64,49,600 | - | 5,48,59,660 |
| - डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड | 6,87,12,587 | 85,494 | - | 6,87,98,081 |
| - डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 5,07,54,677 | - | - | 5,07,54,677 |
| - इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड | 7,45,06,230 | 1,35,76,500 | - | 8,80,82,730 |
| - एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 9,19,36,776 | 23,36,400 | - | 9,42,73,176 |
| | 5,10,38,58,350 | 54,71,07,299 | (6,59,998) | 5,65,03,05,651 |

31 मार्च, 2020 को

| विशेष प्रयोजन योजना | 31 मार्च, 2019 को शेष | वर्ष के दौरान वहन किया गया व्यय* | वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि | 31 मार्च, 2020 को शेष |
|---|---|---|---|---|
| | (₹) | (₹) | (₹) | (₹) |
| - औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड | 1,46,97,03,646 | 29,96,22,565 | - | 1,76,93,26,213 |
| - धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 2,59,89,60,739 | 31,47,06,734 | - | 2,91,46,67,473 |
| - धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड | 50,91,152 | 11,62,148 | (55,93,302) | 6,59,998 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड | 8,08,02,244 | 40,82,092 | - | 8,48,84,336 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड | 3,88,65,417 | 95,44,643 | - | 4,84,10,060 |
| - डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड | 6,87,12,587 | - | - | 6,87,12,587 |
| - डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 5,07,54,677 | | - | 5,07,54,677 |
| - इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड | 7,45,06,230 | - | - | 7,45,06,230 |
| - एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 7,26,29,616 | 1,93,07,160 | - | 9,19,36,776 |
| | 4,46,10,26,310 | 64,84,25,342 | (55,93,302) | 5,10,38,58,350 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 15: व्यापार प्राप्य** | | |
| (असुरक्षित, लेकिन अच्छे समझे जाते हैं) | | |
| अन्य प्राप्य * (संदर्भ नोट 15.1) | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| जोड़ | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| 15.1 निम्न से बकाया राशि शामिल है: | | |
| इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबीशन सेंटर लिमिटेड - उद्यम जिन पर प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का महत्वपूर्ण प्रभाव है | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| जोड़ | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |

* वसूले जाने की तिथि से

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **नोट 16: रोकड़ और बैंक शेष** | | | | |
| **रोकड़ और नकद समतुल्य** | | | | |
| रोकड़ हस्ते | | 2,153 | | 8,373 |
| चालू खातों में बैंक के पास शेष | | | | |
| - परियोजना विकास निधि | 2,22,851 | | 2,02,324 | |
| - स्वच्छता कार्य योजना | 286 | | - | |
| - कंपनी निधि | 12,16,15,970 | 12,18,38,907 | 2,24,996 | 4,27,319 |
| सावधि जमाओं में बैंकों के पास शेष | | | | |
| - परियोजना विकास निधि | 7,89,25,000 | | 48,05,55,897 | |
| - कंपनी निधि | 1,18,01,11,297 | 1,25,90,36,297 | 1,13,46,75,000 | 1,61,52,30,897 |
| **अन्य बैंक शेष** | | | | |
| सावधि जमाओं में बैंकों के पास शेष | | | | |
| - परियोजना विकास निधि | | 9,94,61,710 | | - |
| **जोड़** | | **1,46,03,59,067** | | **1,61,56,66,589** |

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **नोट 17 : लघुकालिक ऋण और अग्रिम** | | | | |
| (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है) | | | | |
| विक्रेताओं को अग्रिम | | 2,49,163 | | 64,494 |
| कार्मिक अग्रिम | | 50,996 | | 3,70,055 |
| पूर्वदत्त व्यय | | 20,80,144 | | 9,28,044 |
| राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष | | 9,85,559 | | - |
| निम्न से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य: | | | | |
| (i) एनआईएसीडीसी नोमराणा सौलर पॉवर लिमिटेड | 26,08,965 | | 8,08,459 | |
| (ii) इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | 6,63,000 | 32,71,965 | 6,36,000 | 14,44,459 |
| **जोड़** | | **66,37,827** | | **28,07,052** |

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **नोट 18 : अन्य चालू परिसंपत्तियां** | | | | |
| सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज [ पीडीएफ खाते के ₹ 7,24,085/- शामिल (पिछले वर्ष -₹ 41,75,663/-)] | | 4,91,37,995 | | 7,17,10,610 |
| आयकर से रिफंड योग्य [संदर्भ नोट 25(iii)] | | 83,95,605 | | 1,99,95,188 |
| अन्य वसूली योग्य | | 90,163 | | - |
| एसपीवी से वसूली योग्य | | - | | 6,59,998 |
| अग्रिम कर (पिछले वर्ष के लिए कर हेतु शुद्ध प्रावधान ₹ 1,22,16,066/-) | | - | | 1,21,49,376 |
| **जोड़** | | **5,76,23,763** | | **10,45,15,172** |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 19: परिचालन से आमदनी** | | |
| **निम्न के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में सेवा फीस** (संदर्भ नोट 2.8) | | |
| नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) | 20,00,00,000 | 8,28,00,400 |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबीशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |
| **जोड़** | **25,00,00,000** | **13,28,00,400** |

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **नोट 20 : अन्य आय** | | | | |
| कंपनी निधियों की सावधि जमाओं पर ब्याज | | 6,03,39,463 | | 8,31,80,413 |
| आयकर रिफंड पर ब्याज | | 15,56,597 | | - |
| निम्न के ऊपरी व्ययों के संविभाजन (संदर्भ नोट 20.1) | | | | |
| (i) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबीशन सेंटर लिमिटेड | 72,00,000 | | 66,44,305 | |
| (ii) एनआईसीडीसी नीमराणा सौलर पॉवर लिमिटेड | 23,00,866 | 95,00,866 | 25,16,178 | 92,60,483 |
| विविध आय | | 31,022 | | 820 |
| **जोड़** | | **7,14,27,948** | | **9,24,41,716** |

**20.1** पिछली परंपरा के अनुसार कंपनी द्वारा कार्यालय परिसर और प्रशासनिक समर्थन हेतु ऊपरी व्ययों को संबंधित कंपनी से आनुपातिक आधार पर वसूला जाता है।

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 21: कर्मचारी हितलाभ व्यय** | | |
| वेतन, मजदूरी, ग्रेच्यूएटी, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, भत्ते आदि | 4,70,34,980 | 4,21,14,060 |
| भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान | 37,23,093 | 32,63,075 |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 22,06,499 | 27,40,383 |
| **जोड़** | **5,29,64,572** | **4,81,17,518** |

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)**
सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट**

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 22: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय** | | |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास | 73,09,190 | 52,55,738 |
| अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन | 13,31,312 | 15,67,911 |
| **जोड़** | **86,40,502** | **68,23,649** |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 23: अन्य व्यय** | | |
| किराया ( संदर्भ नोट 23.1 और 29) | 4,86,03,024 | 5,66,79,394 |
| **लेखापरीक्षकों को भुगतान (संदर्भ नोट 23.2)** | | |
| लेखापरीक्षा फीस | 3,30,000 | 3,30,000 |
| प्रमाणन फीस | 5,500 | 1,05,100 |
| विज्ञापन और व्यापार संवर्धन | 81,06,776 | 4,41,90,512 |
| कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (संदर्भ नोट 31) | 11,96,567 | 21,20,824 |
| बिजली | 10,01,062 | 8,39,673 |
| हाउसकीपिंग | 17,42,671 | 15,54,785 |
| सुरक्षाकर्मी | 8,55,544 | 6,79,488 |
| पेशेवर और परामर्श प्रभार | 38,56,542 | 26,45,172 |
| बैठक और जलपान | 2,01,549 | 3,88,728 |
| मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय | 38,57,398 | 37,77,248 |
| मरम्मत और अनुरक्षण - कम्प्यूटर | 26,86,034 | 29,21,718 |
| प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | 19,19,731 | 19,33,021 |
| सूचना एवं डाक प्रभार व्यय | 15,65,391 | 14,63,594 |
| यात्रा एवं परिवहन व्यय | 26,52,634 | 57,99,852 |
| बीमा व्यय | 25,355 | 25,119 |
| निदेशकों के बैठक में उपस्थित होने हेतु फीस | - | 2,40,000 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि | 595 | 2,11,346 |
| पूर्व अवधि व्यय (संदर्भ नोट 23.3) | 2,52,806 | 33,315 |
| छात्रवृत्ति | 3,00,548 | 2,79,145 |
| विविध व्यय | 20,67,049 | 34,52,682 |
| **जोड़** | **8,12,26,776** | **12,96,70,716** |

23.1 किराए में ₹ 1,03,07,412/- (पिछले वर्ष ₹ 1,03,07,412/-) के नगरपालिका कर शामिल हैं, जिसे पट्टेदार को पट्टा समझौते के अनुसार भुगतान किया गया है।

23.2 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक पिछले लेखापरीक्षकों को किए गए भुगतान से संबंधित है।

23.3 पूर्व अवधि के खर्चों का विवरण इस प्रकार है:

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| विज्ञापन और व्यापार संवर्धन | 2,25,277 | - |
| सूचना एवं डाक प्रभार व्यय | 11,021 | - |
| यात्रा एवं परिवहन व्यय | 16,108 | - |
| पेशेवर और परामर्श प्रभार | 400 | 25,000 |
| प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | - | 8,315 |
| | **2,52,806** | **33,315** |

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)**
सीआईएन: यू45400डीएल2006पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट**

24 **प्रति शेयर आमदनी**
मूल आमदनी प्रति इक्विटी शेयर की गणना, कर पश्चात लाभ को वर्ष के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग करके की जाती है।

| | विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|---|
| क | इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात् लाभ | 12,64,44,273 | 2,90,45,267 |
| ख | ईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या) | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| ग | मूल/तनुकृत आमदनी प्रति शेयर (क/ख) | 1.26 | 0.29 |
| घ | प्रति इक्विटी शेयर का सम मूल्य | 10.00 | 10.00 |

25 **आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता (उपलब्ध न कराए जाने की सीमा तक के लिए):**

(i) **आकस्मिक देयताएं**
- कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। - -
- कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी गारंटियां - -

(ii) **प्रतिबद्धताएं**
परियोजना विकास गतिविधियों के लिए परामर्श अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है 1,61,58,92,643 1,06,92,27,426

(iii) **कराधान मामले**

अपील/संशोधन के अंतर्गत आयकर मामले

| आकलन वर्ष | दावा किया गया रिफंड (₹) | आदेश के अनुसार प्राप्त रिफंड (₹) | रुका हुआ शोध रिफंड (₹) | रोकने का कारण | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 52,64,553 | 46,85,504 | 5,79,049 | एओ ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 25.12.2019 के आदेश द्वारा 17,12,903 रुपए के व्यय की अनुमति नहीं दी। | 06.01.2020 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की प्रतीक्षा है। |
| 2018-19 | 49,71,760 | 32,24,650 | 17,47,110 | एओ ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26.04.2021 के आदेश द्वारा 4,34,057/- रुपए के व्यय की अनुमति नहीं दी और 58,89,181/- रुपए की आय को दोबारा जोड़ दिया गया। | 13.05.2021 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की प्रतीक्षा है। |
| 2019-20 | 97,58,870 | 69,14,080 | 28,44,790 | धारा 143(1) के अंतर्गत दिनांक 23.10.2020 की सूचना में 28,44,790/-रुपए के टीडीएस क्रेडिट का मिलान नहीं हुआ | 19.06.2021 को पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई है. निपटान की प्रतीक्षा है। |
| **जोड़** | | | 51,70,949 | | |

कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और कंपनी के सलाहकारों सहित प्रबंधन का मानना है कि ये मांगें अपीलीय स्तर पर टिकने लायक नहीं हैं। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी इन आकस्मिक देनदारियों के संबंध में किसी भी क्षतिपूर्ति की उम्मीद नहीं करती है, और अपीलकर्ता कार्यवाही के लंबित समाधान के लिए इन मामलों के संबंध में नकद बहिर्वाह के समय, यदि कोई हो, का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(iv) 31 मार्च, 2021 को कंपनी पर दर्ज मामलें जिनका कंपनी के ऊपर कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है: निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | याचिका सं. एवं तिथि | याचिकाकर्ता | प्रतिवादी | विचाराधीन विषय | संक्षिप्त ब्यौरा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9282/2015 | सुभ राम एवं अन्य | एनआईएसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य | राजस्थान राज्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित | काउंटर एफिडेविट में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि पार्टियों की सूची से एनआईएसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का नाम हटाया जाए और याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत की गई है।<br><br>याचिकाकर्ता ने मामले में दर्ज याचिका को संशोधित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।<br><br>संशोधित शपथिका के संबंध में एनआईएसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) द्वारा भी प्रत्युत्तर में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।<br><br>कंपनी का नाम डीएमआईसीडीसी से बदल कर एनआईसीडीसी करने का अनुरोध 8 सितंबर, 2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।<br><br>सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है। |
| 2 | 6648/2016 | इशरत मोहम्मद खान एवं अन्य | एनआईएसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य | औरंगाबाद में जयकवाडी डैम से शेंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क तक पानी की पाइपलाइन से संबंधित | 18.01.2019 को एनआईएसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का प्रतिवादी के रूप में नाम हटाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत नियम 10 के आदेश 1 के अंतर्गत आवेदन मुंबई, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद को इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि याचिका के लिए आवेदक न तो उचित पार्टी है और न ही आवश्यक पार्टी।<br><br>सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है। |

26 **कर्मचारी हितलाभों पर लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रकटन:**

क) विभिन्न परिभाषित कर्मचारी योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

**i) सुपरिभाषित अंशदान योजना**

भविष्य निधि (पीएफ) – भविष्य निधि के प्रति अंशदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। भुगतान की गई राशि को लाभ एवं हानि के स्टैंडएलोन विवरण में प्रभृत किया जाता है।

ii) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

क. ग्रेच्यूएटी (अनिधिक) – कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित हितलाभ योजना है। ग्रेच्यूएटी योजना के अंतर्गत, प्रत्येक कर्मचारी जिसने कम से कम पांच वर्ष की सेवाएं प्रदान की हो, उसके जाने पर निर्धारित 20,00,000/- रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के 15 दिनों की ग्रेच्यूएटी के पात्र है। ग्रेच्यूएटी के प्रति दायित्वा अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा से बर्खास्तगी, विकलांगता अथवा मृत्यु के कारण होती है। ग्रेच्यूएटी के संबंध में कंपनी की दायित्वा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत जाता है।

ख. अवकाश नकदीकरण (अनिधिक): नीति के अनुसार, कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 30 छुट्टियों के हकदार हैं, जिनमें से वर्ष के दौरान ही अधिकतम 10 छुट्टियों को भुनाया जा सकता है और शेष छुट्टियों को अधिकतम 90 दिनों के अध्यधीन आगे बढ़ाया जा सकता है। सेवित अवकाश जो अधिवर्षिता, त्यागपत्र, समाप्ति, निःशक्तता या मृत्यु के समय भुनाया नहीं जा सकता है। तदनुसार, छुट्टी नकदीकरण के प्रति कंपनी की दायित्व की गणना मूल वेतन की राशि के आधार पर शेष अवधि के लिए आनुपातिक अवकाश पर की जाती है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में कर्मचारी हितलाभों पर एएस-15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत अपेक्षा अनुसार अन्य प्रकटन निम्नानुसार है:

i) परिभाषित अंशदान योजना

वर्ष के लिए व्यय के रूप में स्वीकारा गया परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान, निम्नानुसार है:

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान | 31,04,083 | 27,47,849 |

ii) परिभाषित हितलाभ योजना

ग्रेच्यूएटी (अनिधिक)

निम्नलिखित तालिकाएं लाभ एवं हानि के स्टैंडएलोन विवरण में पहचाने गए शुद्ध लाभ व्यय के घटकों, वित्तपोषित/अनिधिक स्थिति और परिभाषित लाभ योजना के लिए स्टैंडएलोन तुलन पत्र में पहचानी गई राशियों को सारांशित करती हैं।

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ** | | |
| मौजूदा सेवा लागत | 9,81,478 | 8,49,601 |
| पिछली सेवा लागत | - | - |
| लाभ दायित्व पर ब्याज लागत | 3,04,303 | 2,31,586 |
| वर्ष में स्वीकारी गई शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि | 3,75,085 | 2,27,359 |
| स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ | 16,60,864 | 13,08,546 |
| **स्टैंडएलोन तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि** | | |
| परिभाषित हितलाभ दायित्वा का वर्तमान मान | 54,60,470 | 45,08,194 |
| नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मान | - | - |
| स्टैंडएलोन तुलन पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियां/(दायित्वा) | (54,60,470) | (45,08,194) |
| **परिभाषित हितलाभ दायित्वा के मौजूदा मान में परिवर्तन** | | |
| वर्ष की शुरुआत में परिभाषित हितलाभ दायित्वा | 45,08,194 | 34,30,902 |
| मौजूदा सेवा लागत | 9,81,478 | 8,49,601 |
| पिछली सेवा लागत | - | - |
| ब्याज लागत | 3,04,303 | 2,31,586 |
| भुगतान किया गया हितलाभ | (7,11,588) | (2,31,254) |
| दायित्वा पर बीमांकिक (लाभ)/हानियां | 3,75,085 | 2,27,359 |
| वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व | 54,60,470 | 45,08,194 |
| **परिभाषित हितलाभ दायित्वा का संचलन** | | |
| अचल | 50,82,006 | 40,34,648 |
| चल | 3,78,464 | 4,73,546 |
| | 54,60,470 | 45,08,194 |

**दायित्वा निश्चित करने में प्रयुक्त मुख्य सिद्धांत:**

| प्रयुक्त विधि | अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि | अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि |
|---|---|---|
| मृत्यु सारणी | आईएलएम 2012-14 | आईएलएम 2012-14 |
| 30/ 44 वर्ष/ 44 वर्ष से अधिक तक आहरण दर (%) | 8.00% प्रतिवर्ष | 8.00% प्रतिवर्ष |
| कटौती दर (%) | 6.75% प्रतिवर्ष | 6.75% प्रतिवर्ष |
| भविष्य वेतन वृद्धि (%) | 6.50% प्रतिवर्ष | 6.00% प्रतिवर्ष |
| रिटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या) | 60 साल | 60 साल |

27 **जॉइंटवार रिपोर्टिंग**

भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार कंपनी का मुख्य व्यवसाय विभिन्न औद्योगिक सलिमार्गों और अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वयन और विकसित किए जाने के लिए नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभाना है और एएस-17 – 'खंडवार रिपोर्टिंग' के अनुसार कोई ऑपरेटिंग खंड नहीं है।

28 संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखांकन मानक-18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" की आवश्यकताओं के अनुसार, संबंधित पार्टी के नाम जिनके पास महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने के लिए नियंत्रण/क्षमता मौजूद है, साथ ही लेनदेन की कुल मात्रा और उनके साथ वर्ष के अंत में शेष, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना और प्रमाणित किया गया है, नीचे बताया गया है:

I संबंधित पार्टियों की सूची और संबंध की प्रकृति जहां नियंत्रण मौजूद है

क कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले उपक्रम
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी)

ख सहायक कंपनी
एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड
(पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित)

ग संयुक्तउद्यमसहयोगी
हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

घ प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

| | |
|---|---|
| श्री के संजय मूर्ति (18 नवंबर, 2019 से) | सीईओ और प्रबंध निदेशक |
| श्री अल्केश कुमार शर्मा (15 सितंबर, 2019 तक) | सीईओ और प्रबंध निदेशक |
| श्री प्रशांत कुमार मल्लावर (17 जून 2019 से 5 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए) | सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार |
| श्री गजेंद्र रत्नू (19 सितंबर 2019, से 17 नवंबर, 2019 तक की अवधि के लिए) | सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार |
| श्री पी. के. अग्रवाल | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| श्री अभिषेक चौधरी | उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन और कंपनी सचिव |

ङ उपक्रम जिनके ऊपर प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का महत्वपूर्ण प्रभाव है
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (17 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक, 28 नवंबर, 2020 से 13 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए और 30 जून 2021 से )

II व्यापार की सामान्य अवधि में संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| वेतन/पारिश्रमिक | | |
| श्री के संजय मूर्ति | 56,92,743 | 19,00,183 |
| श्री अल्केश कुमार शर्मा | - | 32,30,880 |
| श्री पी. के. अग्रवाल | 53,82,579 | 51,83,446 |
| श्री अभिषेक चौधरी | 52,88,520 | 50,81,023 |
| प्रतिपूर्ति | | |
| एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित) | 8,07,396 | 6,48,445 |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | - | 4,232 |
| उधारी स्थायी का संविभाजन | | |
| एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित) | 23,00,866 | 26,16,178 |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | 6,00,000 | 6,44,305 |
| सेवा फीस | | |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | - | 1,25,00,000 |

III वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के साथ बकाया शेष

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| अल्प अवधि ऋण और अग्रिम | | |
| एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित) | 26,08,965 | 8,08,459 |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | 6,83,000 | 6,36,000 |
| व्यापार प्राप्य | | |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| वेतन/पारिश्रमिक देय | | |
| श्री के संजय मूर्ति | 4,30,066 | 2,03,420 |
| श्री पी. के. अग्रवाल | 1,03,551 | 1,02,581 |
| श्री अभिषेक चौधरी | 61,754 | 1,20,456 |

29 **परिचालन लीज**

कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था 6ठी मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में अपने लीज कार्यालय परिसर से संबंधित परिचालन पट्टे के संबंध में है, जिसे 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए लीज पर लिया गया है। कुल पट्टा किरायां ₹ 4,86,03,024/- (पिछले वर्ष: ₹ 5,68,79,394/- जिसमें अगोंकष होटल में कार्यालय स्थान के लिए ₹ 80,76,370/- का पट्टा किराया शामिल है जिसे 31.05.2020 को खाली कर दिया गया था) के भुगतान को लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में मान्यता दी गई है और नोट 23 में इसका प्रकटन किया गया है।

| | विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|---|
| 30 | **विदेशी मुद्रा में व्यय** | | |
| | - यात्रा | - | 3,18,704 |
| | | - | 3,18,704 |

31 **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) के आधार पर सीएसआर व्यय के लिए ₹ 11,96,567/- (पिछले वर्ष: ₹ 11,76,901/-) की राशि देय है। वर्ष के दौरान खर्च की गई /खर्च किए जाने के लिए लंबित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

| | विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|---|
| I | **कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि** | | |
| | वार्षिक सीएसआर आवंटन | 11,96,567 | 11,76,901 |
| | पिछले वर्ष से अग्रेषित | - | 9,43,923 |
| | **व्यय की जाने वाली आवश्यक सकल राशि** | 11,96,567 | 21,20,824 |
| II | **वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि** | | |
| | नकद में | 11,96,567 | 21,20,824 |
| | **जोड़** | 11,96,567 | 21,20,824 |
| III | **अहेतुक जिन पर सीएसआर व्यय किया गया** | | |
| | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में योगदान | 11,96,567 | 11,76,901 |
| | कौशल और तकनीकी सक्षमता प्रशिक्षण आयोजित करने में योगदान | - | 9,43,923 |
| | | 11,96,567 | 21,20,824 |

32 प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अलावा अन्य संपत्ति के मूल्य में और व्यापार की सामान्य अवधि में वसूली पर अमूर्त संपत्ति का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिसमें ये स्टैंडअलोन तुलन पत्र में बताए गए हैं। इसके अलावा, सभी ज्ञात देनदारियों के लिए बही खातों में पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है।

33 व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, व्यापार देय और अन्य पार्टियों आदि के अंतर्गत दिखाई देने वाले शेष सामंजस्य/पुष्टि किए जाने के अध्यधीन हैं। पुष्टिकरण/सामंजस्य के होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो तो, उन्हें पुष्टिकरण/सामंजस्य के वर्ष में लिया जाएगा, जो प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होंगे।

34 निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016-नीति द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को मौजूदा वसूली प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अध्यधीन, कर पश्चात लाभ के 30% या निवल संपत्ति के 5% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

डीआईपीएएम ने दिनांक 17 दिसंबर, 2018 के का.ज्ञा.सं. 5/3/2018-नीति (खंड II) और दिनांक 18 मार्च 2021 के का.ज्ञा. सं. 4(30) (1)/2018-ईआईपीएएम-I(पीटी) के द्वारा कंपनी को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों से छूट प्रदान की है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम लाभांश के भुगतान से छूट की मंजूरी प्राप्त करने हेतु 25 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से डीआईपीएएम को आवेदन किया है, जिसका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और स्वीकरण के बाद, इसी तरह, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम लाभांश के भुगतान से छूट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है, इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में लाभांश के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

35 कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां जैसे कि डीएमआईसीडीसी गूना पावर कंपनी लिमिटेड, डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लिमिटेड और डीएमआईसीडीसी विले भवाड़ पावर कंपनी लिमिटेड को बंद कर दिया गया है और दिनांक 09.08.2018 के नोटिस संख्या आरओसी/डीई:जेओ/248(5)/ एसटीके/74893 द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2018 से उनके नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिए गए हैं।

उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर इन सहायक कंपनियों में रखे गए शेयरों को संबंधित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अनुसार उनकी परिसंपत्तियों के आधार पर आंका गया था और 20,00,000 रुपए के निवेश में हानि को वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान परियोजना विकास व्यय में स्वीकारा गया था। चूंकि धनराशि वसूलनीय नहीं है, वर्ष के दौरान, उल्लिखित राशि को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 2.6.1 के अनुसार पूंजीगत कोष में अंतरित किया गया है।

36 **कंपनी के परिचालन पर कोविड-19 का प्रभाव**

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्राप्य और अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों की अर्जित राशि पर संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जो कोविड 19 महामारी के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। भविष्य की आर्थिक स्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर और इसके व्यवसाय की प्रकृति पर विचार करते हुए, प्रबंधन का अनुमान है कि इन परिसंपत्तियों की अर्जनीत राशि की वसूली हो जाएगी और कम से कम 12 महीनों के लिए व्यवसाय के संचालन को निधि देने के लिए पर्याप्त तरलता उपलब्ध है. इस प्रकार कोविड-19 महामारी से कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड**
**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)**
सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट**

37 चालू वर्ष के आंकड़ों की पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने के लिए जहां आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनःसमीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

समसंख्यक तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
**कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण सं. 000346एन**

हस्ता/

**सीए अंकुर भोयल**
**(साझेदार)**
**(सदस्यता सं. 099143)**

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के**
**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता.

**(के संजय मूर्ति)**
**सीईओ एवं प्रबंध निदेशक**
**(डीआईएन : 03532374)**

हस्ता.

**(राजेंद्र रत्नू)**
**निदेशक**
**(डीआईएन : 02855304)**

हस्ता.

**(पी. के. अग्रवाल)**
**मुख्य वित्तीय अधिकारी**

हस्ता.

**(अभिषेक चौधरी)**
**उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले,**
**मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त, 2021

यूडीआईएन: 21099143एएएएसी6093

# समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

**एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

## स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट
## नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए
## (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)

### समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

### अभिमत

हमने **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** (जिसे बाद में "नियंत्रक कंपनी" कहा गया है) और उसकी सहयोगी कंपनी (नियंत्रक कंपनी और सहयोगी कंपनी को साथ मिलाकर "समूह" कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल है।

हमारे अभिमत में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और उस पर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित विवरण अपेक्षित सूचना देते हैं जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षा की गई है और 31 मार्च, 2021 को समूह के मामलों की समेकित स्थिति और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और उनके समेकित नकदी प्रवाह पर भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य और सही दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं।

### अभिमत का आधार

हमने अधिनियम (लेखा परीक्षा मानक) की धारा 143(10) के अंतर्गत विर्दिनिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के *'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व'* खंड में आगे बताया गया है। हम, नैतिक आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत समेकित वितीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित है, सहित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, समूह से स्वतंत्र है और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार हमारे नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए उचित है।

### समेकित वित्तीय विवरणों और तत्संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से इतर सूचना

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, यदि कोई हो तो, शामिल है ( लेकिन समेकित वित्तीय विवरण और तत्संबंधी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है) जिसे इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् उपलब्ध होने की आशा है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारा अभिमत अन्य सूचना शामिल नहीं करता है और हम तत्संबंधी निकाले गए निष्कर्षों पर कोई आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

पृष्ठ 2 पर जारी

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व उपलब्ध होने पर उपरोक्त पहचानी गई अन्य सूचना का अध्ययन करना है और ऐसा करते हुए यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अथवा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से असंगत है या अन्य रूप से अस्पष्ट है।

जब हम निदेशक रिपोर्ट को अनुलग्नकों सहित, यदि कोई हो तो पढ़ते हैं, उसके के आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस बोर्ड रिपोर्ट में कोई गलतबयानी है, तो हमें उस तथ्य को प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व**

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का एक सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं।

समूह में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन दस्तावेजों की पर्याप्त रूप से देखरेख, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करना; उचित एवं विवेकदर्शी निर्णय लेना और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन में थे, जो समेकित वित्तीय विवरणों जो सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं और किसी भी गलत कथन, जो चाहे धोखाधडी से हो अथवा चूक से हो, उससे मुक्त रखते है, उसे तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है जिनका नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा ऊपर उल्लेख किए गए के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उपयोग में लिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल सतत् आधार पर जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का आकलन करने, सतत् आधार पर संबंधित मुद्दों को प्रकट करना, जहां लागू हो और लेखांकन पर सतत् आधार पर उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल समूह का व्यापार परिसमापन करना चाहता हो अथवा परिचालन रोकना चाहता हों अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई उपाय न हो।

कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी है।

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से किसी गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा चूक से, मुक्त है और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित रूप से आश्वासन, उच्च श्रेणी का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी भी मौजूद गलत कथन को सदैव ही ढूंढ लेगी। गलत कथन धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हो सकते हैं और अगर इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय चाहे वह निजी रूप से हो अथवा समग्र रूप में, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो, तो यह महत्वपूर्ण माने जाते है।

पृष्ठ 3 पर जारी

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है और लेखापरीक्षा में पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रणाली डिजाइन व निष्पादित करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप पता न लग पाने के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है;

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से न हो।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा प्रबंधक वर्ग द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के सतत् आधार और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो एक सतत् आधार में जारी रहने के लिए समूह की क्षमता पर संदेह पैदा करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापिx, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां समूह को सतत् आधार पर जारी रहने से रोक सकती है;

- प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु तथा यह मूल्यांकन करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाया गया हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओ अथवा व्यापार संबंधी गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' शीर्षक वाले खंड में वर्णित किया गया है।

हम, अन्य मामलों मे, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण मे पाई गई महत्वपूर्ण कमियां जिन्हे हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचाना, अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति, को सूचित करते हैं।

पृष्ठ 4 पर जारी

हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते है तथा जहां आवश्यक हो वहां उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

**अन्य मामले**

हमने एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड (इसके बाद "सहायक कंपनी" के रूप में संदर्भित) नामक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, 31 मार्च, 2021 को जिनके वित्तीय विवरण में 3,065.88 लाख रुपये की कुल संपत्ति और 635.11 लाख रुपये की कुल राजस्व दर्शाते हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद बहिर्वाह (शुद्ध) 348.63 लाख रुपये है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उसके लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटनों तक सीमित है और धारा 143 (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट पूर्ण रूप से इसके लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है ।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत और नीचे दी गई अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मुद्दों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के संबंध में आशोधित नहीं है।

**अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

जैसा कि अधिनियम की धारा **143(3)** द्वारा अपेक्षित है, हम प्रचलित सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट के अनुसार जांचे गए समेकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से रखे गए लेखों की संबंधित पुस्तकों के अनुसार है;

(घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016, अधिसूचित किए जाने तक, सहित पढ़ा जाए, के अंतर्गत लेखांकन मानकों के अनुपालन में है;

पृष्ठ 5 पर जारी

(ङ) 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी के निदेशक मंडल 31 मार्च, 2021 को अधिनियम की धारा 164 के उप खंड (2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं है;

(च) समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के अनुसार नियंत्रक कंपनी के इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभाविता के संबंध में और सहयोगी कंपनी जिसकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई (जैसा इसके लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है), संदर्भ के लिए **अनुलग्नक - 'क'** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखे;

(छ) धारा 197 के प्रावधानों जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाए, समूह पर लागू नहीं है क्योंकि नियंत्रक कंपनी और सहयोगी कंपनी सार्वजनिक कंपनी नहीं है जैसा अधिनियम की धारा 2(71) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, इसलिए यह खण्ड लागू नहीं होता है; और

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अन्य मुद्दों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन किया हैं - संदर्भ समेकित वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 26 देखे;

ii) समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभासी हानि नहीं थी; और

iii) कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसे समूह द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित किया जाना था।

**कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन**

हस्ता.

**अंकुर गोयल**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. 099143**
**यूडीआइएन 21099143एएएएसीजेड1696**

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 10 अगस्त, 2021**

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'क'

*(31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ (च) के संदर्भ में)*

### कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को और तक समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार, हमने उक्त तिथि को **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** ("नियंत्रक कंपनी") और उसकी सहयोगी कंपनी (नियंत्रक कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनी को "समूह" कहा गया है) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

#### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

नियंत्रक कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट" में ("गाइडेंस नोट") उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग अर्हता पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और चूक को रोकना एवं पहचान करना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं परिपूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित इसके व्यापार को उचित एवं प्रभावी रूप से करने को सुनिश्चित करना शामिल है।

#### लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उतरदायित्व समूह की हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। "आईसीएआई" द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट" ("गाइडेंस नोट") और लेखा परीक्षा मानकों, जिसे "आईसीएआई" द्वारा जारी किया गया है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार हमने हमारी लेखा परीक्षा की है, और दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। ये मानक और गाइडेंस नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करे और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करे कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और बनाया रखा गया था और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी भौतिक पहलूओं पर प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और निर्धारित किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की गलतबयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

पृष्ठ 2 पर जारी

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और पद्धतियां शामिल होती है जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित रूप से, समूह की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से दर्ज़ किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय को समूह के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति की अनुसार ही किया जा रहा है; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान के बारे में समय पर पता लगाना एवं रोकना जिसका वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं**

मिलीभगत की संभावना अथवा गतिविधियों पर अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, चूक अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जो स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों के अनुपालन में कमी अथवा पद्धतियों के क्षरण के कारण जोखिम के अध्यधीन है, अपर्याप्त हो सकता है।

**अभिमत**

हमारे अभिमत, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाऊंटैंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह में संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर सभी भौतिक मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण थे और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

पृष्ठ 3 पर जारी

**अन्य मामले**

जहां तक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उल्लिखित रिपोर्ट सहायक कंपनी अर्थात् एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड से संबंधित है, यह उक्त कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधरित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारा अभिमत आशोधित नहीं है।

**कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन**

हस्ता.

**अंकुर गोयल**
**साझेदार**
**सदस्यता सं. 099143**
**यूडीआइएन 21099143एएएसीजेड1696**

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 10 अगस्त, 2021**

# समेकित वित्तीय विवरण

## नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
## (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)

सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समेकित तुलन पत्र**

| विवरण | नोट | 31 मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 को (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **इक्विटी एवं दायित्वों** | | | | | |
| **शेयरधारकों की निधियां** | | | | | |
| (क) शेयर पूंजी | 3 | 1,00,00,00,000 | | 1,00,00,00,000 | |
| (ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष | 4 | 7,31,50,40,433 | 8,31,50,40,433 | 6,75,63,05,737 | 7,75,63,05,737 |
| **अथवा दायित्वाएं** | | | | | |
| (क) अन्य दीर्घकालिक दायित्वाएं | 5 | 5,46,44,500 | | 6,11,07,950 | |
| (ख) दीर्घकालिक प्रावधान | 6 | 54,02,957 | 6,00,47,457 | 42,16,285 | 6,53,24,235 |
| **चालू दायित्वाओं** | | | | | |
| (क) व्यापार देय | 7 | | | | |
| (i) सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को कुल बकाया देय | | 1,36,26,869 | | 14,575 | |
| (ii) सूक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर देनदारों को कुल बकाया | | 19,49,90,539 | | 34,69,37,709 | |
| (ख) अन्य चालू दायित्वाएं | 8 | 4,51,48,417 | | 4,39,85,674 | |
| (ग) अल्पकालिक प्रावधान | 9 | 19,17,688 | 25,56,83,513 | 6,44,638 | 39,15,82,596 |
| **जोड़** | | | **8,63,07,71,403** | | **8,21,32,12,568** |
| **परिसंपत्तियां** | | | | | |
| **गैर-चालू परिसंपत्तियां** | | | | | |
| (क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 10 | 24,76,47,887 | | 29,58,64,122 | |
| (ख) अमूर्त परिसंपत्तियां | 10 | 19,23,095 | | 29,12,543 | |
| (ग) चालू पूंजीगत कार्य | | 8,96,784 | | 3,12,797 | |
| (घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 11 | 75,72,564 | | 66,06,475 | |
| (ङ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम | 12 | 14,20,510 | | 7,02,000 | |
| (च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां | 13 | 6,74,17,95,338 | 7,00,12,56,178 | 6,13,88,56,958 | 6,44,51,54,895 |
| **चालू परिसंपत्तियां** | | | | | |
| (क) व्यापार प्राप्य | 14 | 2,26,95,535 | | 1,81,34,715 | |
| (ख) रोकड़ और बैंक शेष | 15 | 1,52,52,57,272 | | 1,62,57,01,518 | |
| (ग) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम | 16 | 49,85,476 | | 27,59,063 | |
| (घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 17 | 7,65,76,942 | 1,62,95,15,225 | 12,14,62,377 | 1,76,80,57,673 |
| **जोड़** | | | **8,63,07,71,403** | | **8,21,32,12,568** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | | | | |
| संलग्न नोटों के नोट समेकित वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग है | 3 - 42 | | | | |

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

हस्ता.

सीए अंकुर गोयल
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 099143)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 10 अगस्त, 2021
यूडीआइएन: 21099143एएएएसीजेड1696

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03532374)

हस्ता.

(पी. के. अग्रवाल)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.

(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन : 02855304)

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

## नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
## (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

### 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण

| विवरण | नोट | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|---|
| परिचालन से आमदनी | 18 | 31,14,34,377 | 22,89,02,844 |
| अन्य आय | 19 | 7,12,04,057 | 9,08,48,945 |
| **कुल आमदनी** | | **38,26,38,434** | **31,97,51,789** |
| **व्यय** | | | |
| - उपभोज्य सामग्री की लागत | 20 | 900 | 4,41,25,766 |
| - कर्मचारी हितलाभ व्यय | 21 | 5,96,18,409 | 5,46,59,298 |
| - वित्त लागत | 22 | - | 7,54,788 |
| - मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 23 | 2,88,65,987 | 3,50,52,490 |
| - अन्य व्यय | 24 | 11,15,04,506 | 14,23,09,012 |
| **कुल व्यय** | | **19,99,89,802** | **27,69,01,354** |
| **कर पूर्व लाभ** | | **18,26,48,632** | **4,28,50,435** |
| **कर व्यय** | | | |
| - चालू कर | | 5,96,97,079 | 1,42,41,215 |
| - पूर्ववर्ती वर्ष | | 58,795 | 7,732 |
| - आस्थगित कर | | (10,66,099) | (14,91,921) |
| **वर्ष के लिए लाभ** | | **12,39,58,847** | **3,00,93,409** |
| **आमदनी प्रति इक्विटी शेयर (सममूल्य 10 रुपए प्रति शेयर )** | 25 | | |
| - प्रति शेयर मूल आमदनी | | 1.24 | 0.30 |
| - प्रति शेयर तनुकृत आमदनी | | | |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | | |
| संलग्न लेखों के नोट समेकित वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग है | 3 - 42 | | |

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

हस्ता.

सीए अंकुर गोयल
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 099143 )

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03532374)

हस्ता.

(पी. के. अग्रवाल)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.

(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन : 02855304)

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 10 अगस्त, 2021

यूडीआइएन: 21099143एएएसीजे1696

## नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
## (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

### 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | |
| कर पूर्व शुद्ध लाभ | 16,26,45,632 | 4,28,50,435 |
| **समायोजन के लिए:** | | |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 2,88,65,987 | 3,50,52,490 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि | 1,81,33,857 | 2,11,348 |
| वित्त लागत | - | 7,54,788 |
| ब्याज आय | (6,22,45,676) | (8,38,09,671) |
| कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ | 14,74,02,800 | (49,40,612) |
| **समायोजन के लिए:** | | |
| सामग्रियों में (वृद्धि)/कमी | - | 15,56,041 |
| व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी | (45,80,820) | (2,37,08,885) |
| अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी | 1,87,52,510 | 5,98,71,671 |
| व्यापार देयों में वृद्धि/(कमी) | (13,83,34,876) | 5,61,43,481 |
| अन्य देयों में वृद्धि/(कमी) | 13,35,321 | (41,66,527) |
| **परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी/(प्रयुक्त)** | (12,28,07,865) | 8,96,95,781 |
| भुगतान किए कर (रिफंड का शुद्ध) | (3,74,63,068) | (2,34,85,770) |
| **परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)** | 71,31,867 | 6,12,09,399 |
| **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | |
| परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियां | 45,00,00,000 | 52,70,00,000 |
| परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों से अर्जित ब्याज | 92,26,079 | 2,07,33,907 |
| परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता | (62,45,81,511) | (74,52,54,031) |
| स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियां | 10,00,000 | - |
| स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज | 203 | - |
| स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता | (10,00,000) | - |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की (खरीद) | (53,63,965) | (2,50,17,946) |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री | 64,30,507 | - |
| बैंकों के साथ निक्षेपों (वृद्धि)/कमी | (9,94,81,710) | 97,36,618 |
| ब्याज आय | 6,22,45,676 | 8,38,09,671 |
| भूमि के लिए किश्त का भुगतान | (54,63,450) | (54,63,450) |
| पूंजीगत वस्तुओं के लिए अग्रिम में वृद्धि/(कमी) | (69,652) | (1,32,965) |
| **निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)** | (20,70,57,823) | (13,45,86,196) |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | |
| वित्त लागत | - | (7,54,788) |
| एनआईसीडीआईटी से ऋण | - | (2,50,00,000) |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)** | - | (2,57,54,788) |
| **रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)** | (19,99,25,956) | (9,90,73,585) |
| वर्ष की शुरूआत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य | 1,62,57,01,518 | 1,72,47,75,103 |
| **वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (संदर्भ नोट 15)** | 1,42,57,75,562 | 1,62,57,01,518 |
| **रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक :** | | |
| रोकड़ हस्ते | 6,707 | 12,821 |
| चालू खातों में बैंक के पास शेष | 12,20,48,028 | 6,48,436 |
| अवधि जमाओं में बैंक के पास शेष | 1,30,37,20,827 | 1,62,50,40,261 |
| | 1,42,57,75,562 | 1,62,57,01,518 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 2 | |
| संलग्न लेखों के नोट समेकित वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग है | 3 - 42 | |

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

हस्ता.

मेसर्स अंकुर गोयल
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 099143)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03532374)

हस्ता.

(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन : 02855304)

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 10 अगस्त, 2021

यूडीआइएन: 21099143एएएएसीजेड1696

हस्ता.

(पी. के. अग्रवाल)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**

**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)**

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट**

**नोट 1 - समूह की सूचना**

भारत सरकार ने प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में विनिर्माण के साथ नियोजित शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और देश के औद्योगिक/विनिर्माण विकास को मजबूत गति देने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 2007 में पहले औद्योगिक गलियारे के रूप में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) परियोजना की अवधारणा की घोषणा की।

तदनुसार, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) (धारक कंपनी) को डीएमआईसी परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के रूप में 7 जनवरी 2008 को निगमित किया गया था।

सितंबर, 2011 में, भारत सरकार ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट में औद्योगिक शहरों के विकास हेतु डीएमआईसी प्रोजेक्ट की वित्तीय और संस्थानिक संरचना को अनुमोदन दिया और डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के रूप में एक परिक्रमी कार्पस के साथ समर्पित निधि सृजन को भी अनुमोदन दिया।

डीएमआईसीडीसी नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए विभिन्न पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरिंग अध्ययन करने के लिए एक परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य करती है। डीएमआईसीडीसी को डीएमआईसी-पीआईटीएफ के लिए और डीएमआईसी क्रियान्वित करने के लिए सभी एसपीवी और राज्य सरकार एजेंसियों के लिए भी परियोजना विकास पार्टनर/नॉलेज पार्टनर का अधिदेश है।

दिसंबर, 2016 में भारत सरकार ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के अधिदेश को विस्तारित किया और देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट के रूप में पुनर्नामित किया।

डीएमआईसीडीसी को अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए नॉलेज पार्टनर नियुक्त होने तक डीएमआईसी कार्य के अलावा सभी औद्योगिक गलियारों के संबंध में एनआईसीडीआईटी के लिए एक नालेज पार्टनर के रूप में कार्य करने का अधिदेश दिया गया था।

विस्तारित अधिदेश को देखते हुए 17 फरवरी 2020 से कंपनी का नाम बदलकर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) से बदलकर नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) कर दिया गया।

इसके बाद, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के समग्र ढांचे के भीतर औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 4 थीमों में विकसित किए जाने के लिए 32 परियोजनाओं सहित 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं (पहले अनुमोदित 5 औद्योगिक गलियारों सहित) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।

धारक कंपनी की एक सहायक कंपनी है, अर्थात् एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड (जिसे पहले डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)। संलग्न समेकित वित्तीय विवरण नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी), जो धारक कंपनी है और इसकी सहायक कंपनी (एक साथ "ग्रुप" के रूप में संदर्भित) से संबंधित हैं।

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**

**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)**

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट**

**नोट 2 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

**2.1 समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार**

कंपनी के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), अधिसूचित एवं लागू किए जाने की सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों जो कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय है, जिस तरह से आवश्यक है, प्रोद्भवन आधार पर परंपरागत ऐतिहासिक लागत पर तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

**2.2 अनुमानों का उपयोग**

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ('जीएएपी') के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आवश्यकतानुसार आकलन और अनुमान लगाने की ज़रूरत होती है, जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और मान्यताएं सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित एवं विवेकपूर्ण आधार पर तैयार किए जाते हैं, और इस तरह के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिणाम ज्ञात/साकार होते हैं।

**2.3 समेकन का आधार**

समेकित वित्तीय विवरणों को निम्न आधार पर तैयार किया गया है:

**लेखांकन का आधार:**

i) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को धारक कंपनी की उसी रिपोर्टिंग तिथि पर तैयार किया गया है।

ii) समेकित वित्तीय विवरणों को एएस-21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार बनाया गया है।

**समेकन का सिद्धांत:**

i) धारक कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अंत:समूह शेषों और अंत:समूह लेन-देनों और गैर-वसूले गए लाभ एवं हानियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पश्चात् परिसंपत्तियों, दायित्वाओं, आय और व्यय की एक समान मदों की बुक वैल्यू को साथ जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति आधार पर जोड़ा जाता है।

ii) जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों को एकसमान लेन-देनों और उसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाता है और उसी तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसा कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में हो, अन्यथा जैसा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया हो।

iii) सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध संपत्ति पर सहायक कंपनियों में निवेश की लागत के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में गुडविल या पूंजी आरक्षित कोष के रूप में, जैसा भी मामला हो, मान्यता दी जाती है।

धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्न कंपनी के परिणाम शामिल हैं:

| कंपनी का नाम | किस देश में निगमित की गई | 31.03.2021 को शेयरधारिता का अनुपात (प्रतिशत) | 31.03.2020 को शेयरधारिता का अनुपात (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड | भारत | 100% | 100% |

2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को लागत मॉडल अर्थात संचयी मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाकर लागत पर प्रकट किया गया है;

ii) अधिग्रहण/निर्माण की लागत में भाड़ा, निर्माण और कमीशन प्रभार, शुल्क और कर, निर्माण अवधि के दौरान अधिग्रहण/स्थापना की तारीख तक व्यय और निर्माण/स्थापना चरण के दौरान किए गए अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं।

iii) जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक हिस्से के अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु से संबंधित बाद के खर्च को उसके बुक वैल्यू में तभी जोड़ा जाता है जब वे मौजूदा परिसंपत्ति से प्रदर्शन के पिछले आकलन से भविष्य के लाभों को आगे बढ़ाते हैं। मरम्मत और रखरखाव की लागत को जब भी खर्च किया जाता है, उन्हें लाभ और हानि के समेकित विवरण में दिखाया जाता है।

v) सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली हानि, अथवा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से उत्पन्न होने वाली लाभ/हानि, जिसे लागत पर किया जाता हैं, सेवानिवृत्ति/निपटान के वर्ष में समेकित लाभ एवं हानि विवरण में प्रदर्शित किया जाता हैं।

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास, लागत के 5 प्रतिशत को अवशिष्ट मूल्य रखते हुए उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित विधि से लगाया जाता है। हालांकि, यदि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए प्रबंधन का अनुमान पूर्वोक्त अनुसूची में परिकल्पित से कम है, तो प्रबंधन के उपयोगी/शेष जीवन के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास उच्च दर पर लगाया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार और प्रबंधन द्वारा अनुमान के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

| परिसंपत्ति | उपयोगी जीवन (वर्षों में) |
|---|---|
| फर्नीचर और फिक्सचर | 10 |
| कार्यालय उपकरण | 5 |
| विद्युत संस्थापना और उपकरण | 10 |
| कम्प्यूटर - डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि जैसे अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण | 3 |
| कम्प्यूटर - सर्वर और नेटवर्क | 6 |

इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनी की निम्न उल्लिखित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को निम्नानुसार माना गया है:

| परिसंपत्तियां | मूल्यह्रास | औचित्य |
|---|---|---|
| सोलर पैनल | - निस्तारण मूल्य 10 प्रतिशत समझा जाता है और पूंजीगत लागत के 90 प्रतिशत के रूप में अवक्षयी परिसंपत्ति माना गया है।<br>- उपयोगी जीवन वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 25 वर्ष माना गया है।<br>- प्रथम 13 वर्षों के लिए मूल्यह्रास दर 5.28 प्रतिशत और परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के दौरान शेष मूल्यह्रास प्रसारित किया गया है।<br>- मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया गया है । | यह केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग नियम 2017 के अनुसार है। |
| लैंडस्केपिंग और बागवानी कार्य | मूल्यह्रास योग्य राशि को इकल्यूडीवी विधि से 5 वर्षों की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है। | उपयोगी जीवन 5 वर्ष समझी जाती है। |
| लीजहोल्ड भूमि | कब्जे की तिथि से लीज की शेष अवधि (97 वर्ष 106 दिन) के लिए स्ट्रैट लाइन मैथड से परिशोधित किया जाता है। | यह भूमि विकास प्राधिकरण अर्थात आरआईआईडीसीओ के साथ निष्पादित पट्टा विलेख के अनुसार है। |

vii) 5,000 रुपये तक की लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से अवमूल्यन किया जाता है।

viii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अतिरिक्त मूल्यह्रास पर संपत्ति के अनुमानित शेष उपयोगी जीवन पर संपत्ति के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख से आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है। परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/नष्ट/ध्वस्त करने पर मूल्यह्रास परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान की तिथि तक, जैसा भी मामला हो, प्रभारित किया जाता है।

ix) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित समय-समय पर मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है

x) यदि कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त या निपटान के लिए रखे गए हैं, उन्हें लागत (शुद्ध संचित मूल्यह्रास) या अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर बताया जाता है।

xi) लीजहोल्ड भूमि की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

xii) निर्माणाधीन संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और परिसंपत्ति की लागत जो वर्ष के अंत से पहले उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में दिखाया गया है।

xiii) प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

xiv) सहायक कंपनी द्वारा लैंडस्केपिंग और बागवानी कार्यों पर किए गए व्यय को वित्तीय वर्ष 2019-20 तक पूंजीकृत किया गया था। सीएण्डएजी के प्रेक्षणों के आधार पर, 31 मार्च, 2020 की स्थिति में लिखित मूल्य को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया था और अब से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाएगा।

xv) सहायक कंपनी द्वारा 99 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए लीज पर अधिग्रहित भूमि को लीजहोल्ड भूमि के रूप में माना जाता है

xvi) न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (एनईडीओ), जापान द्वारा सहायक कंपनी को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किए गए उपकरणों को परियोजना के पूरा होने के बाद सभी वास्तविक अधिकारों के साथ उपकरणों के स्वामित्व के हस्तांतरण तक ₹ 1/- के मामूली मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है।

## 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त संपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जहां यह संभावना है कि संपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ व्यवसाय को प्राप्त होंगे और संपत्ति की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता और व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि के समेकित विवरण में परिलक्षित होता है जिसमें व्यय किया गया है।

अमूर्त संपत्ति में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं और इसे संचित परिशोधन की लागत को घटाते हुए अधिग्रहण/कार्यान्वयन की लागत पर बताया जाता है। इसे 5 साल की अवधि अथवा स्ट्रेट लाइन के आधार पर लाइसेंस अवधि, जो भी पहले हो, में परिशोधित किया जाता है।

## 2.6 परिसंपत्तियों का परिशोधन

एक परिसंपत्ति को तभी परिशोधित माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में परिसंपत्तियों की अपणी राशि की समीक्षा की जाती है और यदि आंतरिक/बाहरी कारणों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो हानि को मान्यता दी जाती है। कोई हानि उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में तब प्रभारित की जाती है जिस अवधि में किसी परिसंपत्ति को परिशोधित के रूप में पहचाना जाता है। जहां वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है वहां पूर्व लेखा अवधि में पहचानी गई परिशोधित हानि को बढ़ाया/घटाया जाता है। वसूली योग्य मूल्य परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य एवं उपयोग में मूल्य, जो भी अधिक हो, होती है।

## 2.7 सहायता अनुदान

### 2.7.1 परियोजना विकास निधि (पीडीएफ)

भारत सरकार ने विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए विभिन्न परियोजना विकास/प्रारंभिक गतिविधियां करने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड की स्थापना को स्वीकृति दी है जिसके लिए कंपनी को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से विदित, के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है जिसे आरक्षित कोष एवं अधिशेष के अंतर्गत पूंजीगत कोष में प्रदर्शित किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईसीडीआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त, फंड में से परियोजना विकास/प्रारंभिक गतिविधियों पर वहन किए गए व्ययों को निम्नानुसार प्रबंधित किया जाता है:

क) कंपनी की सहायक कंपनियों और उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जिनके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच अलग-अलग विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) बनाई गयी हो, जहां भी शेयरधारकों के समझौते की शर्तों के अनुसार वसूली योग्य हो, संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी से वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाता है और 'अन्य गैर-चालू संपत्ति' के तहत प्रकटन किया जाता है,

ख) जिन परियोजनाओं के लिए खर्च नहीं किया जाना है या आगे कोई गतिविधियां नहीं की जानी हैं या एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार (सरकारों)/नोडल एजेंसी के बीच शेयरधारकों के समझौते में वसूली का प्रावधान नहीं है, उन्हें 'पूंजी आरक्षित कोष' के तहत परियोजना विकास निधि के शेष से कम किया जाता है; और

ग) उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जो प्रगति पर हैं और जहां शेयरधारकों के समझौते का निष्पादन न होने के कारण एसपीवी को अभी तक निगमित नहीं किया गया है अथवा जहां एनआईसीडीआईटी/ सीसीईए द्वारा निवेश के लिए परियोजनाओं को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है या उपरोक्त पैरा (क) और (ख) के तहत शामिल नहीं किए गए किसी भी अन्य व्यय को "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" के शीर्ष के तहत परियोजना विकास व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

2.7.2 **परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ)**

भारत सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए सरकार से धारक कंपनी द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त होता है। भारत का नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट और इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के माध्यम से और 'आरक्षित और अधिशेष' के तहत पूंजी भंडार के रूप में प्रकटन किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईसीडीआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस निधि में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है।

2.7.3 **स्वच्छता कार्य योजना निधि (एसएपी)**

भारत सरकार ने स्वच्छता कार्य योजना के प्रति व्ययों की पूर्ति के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) की स्थापना को स्वीकृति दी है जिसके लिए कंपनी को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से विदित, के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है जिसे आरक्षित कोष एवं अधिशेष के अंतर्गत पूंजीगत कोष में प्रदर्शित किया गया है। फंड से भारत सरकार/एनआईसीडीआईटी को किसी राशि के वापसी योग्य होने पर उक्त राशि को उस वर्ष में रिफंड के शेष से घटाया जाता है।

इस निधि में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है और गैर-वसूलनीय व्ययों को निधि शेष से पूरा किया जाता है।

**2.8 निवेश**

चालू निवेश का लागत अथवा उद्धत मूल्य पर उल्लेख किया जाता है।

निवेशों के निपटान पर, शुद्ध निपटान आय और अवशोषित राशियों के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

**2.9 राजस्व मान्यता**

क) कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त आमदनी को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभावना है कि आर्थिक लाभ धारक कंपनी को प्राप्त होंगे और जब व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें लागू करने योग्य हैं, सेवाएं वितरित की गई हैं, संग्रहणीयता यथोचित रूप से सुनिश्चित है और राजस्व को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तदनुसार, सेवाओं से प्राप्त आमदनी को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

(i) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किए गए निधियों की 1% की दर से सेवा शुल्क जिसे एनआईसीडीआईटी में 26 जुलाई 2016 को हुई बैठक में अनुमोदित किए अनुसार एक वर्ष में ₹ 20,00,00,000 की अधिकतम सीमा तक मान्यता दी गई है।

(ii) नॉलेज पार्टनर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वार्षिक आंतरिक प्रोद्भवन के 1% की दर से सेवा शुल्क आईआईसीसी के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन में निर्धारित अनुसार 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर न्यूनतम ₹ 5,00,00,000 और अधिकतम ₹ 10,00,00,000 प्रति वर्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ख) सहायक कंपनी द्वारा बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व को ग्राहकों के साथ सहमत दरों पर मासिक आधार पर निर्यात की गई इकाइयों की शुद्ध संख्या के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग) ब्याज आय को बकाया राशि और ब्याज की लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय आनुपातिक आधार पर स्वीकारा जाता है।

घ) लाभांश का लेखांकन तब किया जाता है, जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

**2.10 लीज**

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान मूल रूप से स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से रखता है। लीज एग्रीमेंट के अनुसार परिचालन लीज भुगतानों को प्रोद्भवन आधार पर लाभ एवं हानि लेखा के समेकित विवरण में दिखाया जाता है।

**2.11 विदेशी मुद्रा में लेन-देन**

विदेशी मुद्रा लेनदेन उक्त तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद विदेशी मुद्रा में मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों को उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। भारत के बाहर किसी देश से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशि और देनदारियों के मामले में विनिमय दरों के अंतर को इसकी लागत में समायोजित किया जाता है। अन्य सभी विनिमय अंतर लाभ और हानि समेकित विवरण में पहुचाने जाते हैं। वायदा विनिमय अनुबंध पर प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि के दौरान व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। इस तरह के अनुबंध पर विनिमय अंतर को रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन होता है। वायदा अनुबंध के रद्द अथवा नवीनीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान आय और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

**2.12 मालसूची**

उपभोज्य, भंडार और कलपूर्जों के स्टॉक को फर्स्ट-इन, फर्स्ट आउट (फीफो) आधार पर लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर मूल्यांकन किया जाता है।

**2.13 कर्मचारी हितलाभ**

**क) अल्पकालिक अवधि हितलाभ:**

इन्हें उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के समेकित विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन लाभों में सरकारी कर्मचारियों को कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान शामिल है, जिसका हिसाब केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार है, संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जो वर्ष के अंत से 12 महीनों के भीतर प्राप्त या भुनाए जाने की उम्मीद है।

**ख) परिभाषित अंशदान योजना:**

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार वैधानिक भविष्य निधि, पेंशन योजना में वर्ष के दौरान भुगतान या देय कंपनी के योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी सेवाएं प्रदान करता है।

**ग) परिभाषित हितलाभ योजना:**

ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का दायित्व वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक द्वारा निर्धारित बीमांकिक लाभ या हानि को उस वर्ष के दौरान लाभ और हानि के समेकित विवरण में पहचाना जाता है जिसका बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

**2.14 खंडवार रिपोर्टिंग**

परिचालन खंडों की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और निर्णय लेने के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। लेखांकन मानक 17 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से समूह का "मुख्य संचालन निर्णय निर्माता" या "सीओडीएम" है।

**2.15 प्रति शेयर आमदनी**

कंपनी "प्रति शेयर कमाई" पर लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय (ईपीएस) को रिपोर्ट करती है।

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिसे सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां सभी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर के परिणाम एंटी-डिल्यूटिव हैं।

**2.16 आय पर कर**

क) कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर दोनों शामिल होते हैं।

ख) वर्तमान आयकर, परिसंपत्तियों और दायित्वाओं के लिए कर निर्धारण अधिनियम,1961 में कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा सम्मिलित कर व्यवस्था और भारत में अधिनियमित आयकर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके कर प्राधिकरणों से भुगतान की जाने वाली या वसूली योग्य राशि पर मापा जाता है।

ग) आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के परिणामस्वरूप आस्थगित कर दायित्व जो उत्तरवर्ती लेखा अवधि में बदलने में सक्षम है, उसे रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित अथवा वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों में लेखाबद्ध किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है। उनकी वसूली के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

घ) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) उस वर्ष के दौरान वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि के समेकित विवरण पर लगाया जाता है जिसमें इसका भुगतान किया जाता है। कंपनी एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को केवल उस हद तक मान्यता देती है कि इस बात के उपयुक्त साक्ष्य हैं कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यानी वह अवधि जिसके लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है। कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन पर गाइडेंस नोट के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देती है, उक्त परिसंपत्ति को समेकित लाभ और हानि स्टेटमेंट में क्रेडिट के माध्यम से बनाया गया है और "न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता" के रूप में दिखाया गया है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर "न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता" संपत्ति की समीक्षा करती है और परिसंपत्ति को उस हद तक लेखाबद्ध करती है, जिस हद तक कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि वह निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य कर का भुगतान करेगी।

**2.17 प्रावधान, आकस्मिक दायित्वाएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

लेखों में किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना(ओं) के परिणामस्वरूप मौजूदा दायित्व हो और यह संभावना हो कि संसाधनों के बहिर्वाह के संबंध में दायित्व का निपटान करने की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रावधानों को उनकी मौजूदा कीमत पर बट्टागत नहीं किया जाता और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट्स में तब किया जाता है जब पिछली घटना(ओं) से उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्व होते है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने/ना-होने से की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटना (ओं) से उत्पन्न होता है, जहां यह या तो संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा या एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

**2.18 रोकड़ और समतुल्य रोकड़**

नकद और नकद समकक्षों में शामिल, हाथ में नकद, चैक, हाथ में ड्राफ्ट/ट्रांजिट में प्रेषण, बैंक शेष और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि शामिल है और जो नकद और नकद समकक्ष की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जिनकी कीमतों में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

**2.19 रोकड़ प्रवाह विवरण**

रोकड़ प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष विधि" द्वारा तैयार किया जाता है जैसा कि "रोकड़ प्रवाह विवरण" पर लेखांकन मानक 3 में निर्धारित किया गया है और कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत करता है।

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रस्तुत किए गए रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में हाथ में नकद, चैक, हाथ में ड्राफ्ट/ट्रांजिट में प्रेषण, बैंक बैलेंस और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले डिपॉजिट शामिल हैं और जो रोकड़ और रोकड़ समतुल्य की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं।

## 31 मार्च, 2021 को समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 3: शेयर पूंजी** | | |
| **प्राधिकृत** | | |
| 10/- रुपए वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (पूर्व वर्ष में 10,00,00,000/- इक्विटी शेयर) | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| **निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी** | | |
| 10/- रुपए वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (पूर्व वर्ष में 10,00,00,000/- इक्विटी शेयर) | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| **जोड़** | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |

**3.1 वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों की संख्या में सामंजस्य :**

| | 31 मार्च, 2021 को | | 31 मार्च, 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | (₹) | शेयरों की संख्या | (₹) |
| वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान जारी शेयर | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |

**3.2 इक्विटी शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार**

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका सममूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित और वितरित नहीं किया गया था (लाभांश के बारे में अधिक जानकारी के लिए नोट 35 भी देखें)। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी वरीयता प्राप्त राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

**3.3 समूह में 5 प्रतिशत से अधिक धारित रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा:**

| | 31 मार्च, 2021 को | | 31 मार्च, 2020 को | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | धारिता % | शेयरों की संख्या | धारिता % |
| भारत के राष्ट्रपति (सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं उनके नामितों द्वारा) | 4,90,00,000 | 49.00 | 4,90,00,000 | 49.00 |
| जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) | 2,60,00,000 | 26.00 | 2,60,00,000 | 26.00 |
| हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड | 1,99,00,000 | 19.90 | 1,99,00,000 | 19.90 |

**3.4** समूह ने बोनस शेयरों को जारी नहीं किया है, नकदी प्राप्त किए बिना शेयरों को जारी नहीं किया है अथवा तुलन पत्र की तिथि से पिछले पांच वर्षों के दौरान किन्हीं भी शेयरों को वापिस नहीं खरीदा है।

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 को (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **नोट 2 : आरक्षित और अधिशेष** | | | | | |
| **(क.) पूंजी आरक्षित निधि - के लिए प्राप्त सहायता अनुदान:** (संदर्भ नोट 2.7) | | | | | |
| **(i) परियोजना विकास निधि** | | | | | |
| अंतिम तुलन पत्र के अनुसार | | 6,35,20,27,000 | | 5,82,50,27,000 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान | | 45,00,00,000 | 6,80,20,27,000 | 52,70,00,000 | 6,35,20,27,000 |
| **जोड़ें: परियोजना विकास निधि पर अर्जित ब्याज, आदि** | | | | | |
| अंतिम तुलन पत्र के अनुसार | | 31,33,51,562 | | 29,26,17,655 | |
| वर्ष के दौरान सावधि जमा पर ब्याज और कर रिफंड | | 92,26,079 | 32,25,77,641 | 2,07,33,907 | 31,33,51,562 |
| (घटाएं): पिछले तुलन पत्र के अनुसार | | | | | |
| परियोजना विकास व्यय जिन्हें वसूला न जा सका | | (37,98,70,926) | | (33,40,67,373) | |
| बंद सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्य में कमी | | (20,00,000) | | - | |
| वर्ष के दौरान व्यय | | (2,16,43,131) | (40,35,14,057) | (4,58,03,553) | (37,98,70,926) |
| (घटाएं): परियोजनाजा विकास निधि में अर्जित ब्याज पर कर प्रभाव | | | (22,51,993) | | - |
| | (i) | | 6,71,88,38,591 | | 6,28,55,07,636 |
| **(ii) परियोजना कार्यान्वयन निधि** | | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार (संदर्भ 4.1) | | | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 |
| | (ii) | | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 |
| **(iii) स्वच्छता कार्य योजना** | | | | | |
| वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान | | | 10,00,000 | | - |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान सावधि जमा पर ब्याज | | | 203 | | - |
| (घटाएं): वर्ष के दौरान वहन किया गया व्यय | | | (10,00,000) | | - |
| | (iii) | | 203 | | - |
| **(iv) सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त उपकरण (संदर्भ नोट 2.4.xvi और 38)** | | | 1 | | - |
| | (iv) | | 1 | | - |
| **उप-जोड़** | | | 6,84,88,38,795 | | 6,41,55,07,636 |
| **(ख) अधिशेष** | | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार | | 34,07,98,101 | | 31,07,04,692 | |
| जोड़ें: बंद सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्य में कमी | | 20,00,000 | | - | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ | | 12,39,58,847 | | 3,00,93,409 | |
| (घटाएं): लैंडस्केपिंग और बागवानी कार्य का लिखित मूल्य (संदर्भ नोट 2.4.xiv और 40 देखें) | | (5,55,310) | 46,62,01,638 | - | 34,07,98,101 |
| **जोड़** | | | 7,31,50,40,433 | | 6,75,63,05,737 |

4.1 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, 6.00 मैगा वाट मॉड्यल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश के लिए एसपीसी यथा एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड, पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य निधि/पूंजी निधि में से नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (जिसे पूर्व में डीएमआईसीडीसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के रूप में जाना जाता था) द्वारा एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपए) की राशि अंतरित की गई थी। इस प्रकार के निवेश से वापसी एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आएंगे।

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्वएं** | | |
| भूमि के लिए देय राशि (संदर्भ नोट 5.1) | 5,46,34,500 | 6,00,97,950 |
| निष्पादन प्रतिभूति | 10,000 | 10,10,000 |
| **जोड़** | 5,46,44,500 | 6,11,07,950 |

5.1 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने परियोजना स्थल के लिए 21 नवंबर, 2012 को 1,000/- रुपए प्रति वर्ग मीटर की रिआयती दर पर 1,45,692 वर्ग मीटर भूमि सहायक कंपनी को आवंटित की। कुल विकास शुल्क (डीसी) में से, 25% भूमि के आवंटन के समय अग्रिम भुगतान किया गया था और शेष राशि 20 जनवरी, 2013 से 20 समान वार्षिक ब्याज मुक्त किश्तों में देय है।

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 6 : दीर्घकालिक प्रावधान** | | |
| **कर्मचारी हितलाभ प्रावधान** | | |
| - ग्रेच्यूएटी (संदर्भ नोट सं. 27) | 54,02,957 | 42,16,285 |
| **जोड़** | 54,02,957 | 42,16,285 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 7 : व्यापार देय** | | |
| सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को कुल देय बकाया (संदर्भ नोट सं. 7.1) | 1,36,26,869 | 14,575 |
| सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं का कुल देय बकाया | 19,49,90,539 | 34,69,37,709 |
| **जोड़** | 20,86,17,408 | 34,69,52,284 |

7.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार सूचना नीचे दी गई है। यह सूचना समूह के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है।

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| i) वर्ष के अंत में एमएसएमईडी अधिनियम के तहत शामिल किए गए किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन और उस पर देय ब्याज | | |
| -मूलधन | 1,36,26,869 | 14,575 |
| - ब्याज | - | - |
| ii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार समूह द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि | - | - |
| iii) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना | - | - |
| iv) वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि; तथा | - | - |
| v) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से, बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की गई हो | - | - |

**31 मार्च, 2021 को समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट**

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 8 - अन्य चालू दायित्वाएं** | | |
| सांविधिक दायित्वाएं | 2,38,59,157 | 1,91,44,142 |
| अर्जित व्यय | 20,60,226 | 19,42,358 |
| व्ययों के लिए ऋणदाता | 82,06,535 | 1,69,76,666 |
| कर्मचारी संबंधित देय | 4,75,137 | 2,85,206 |
| बोली प्रतिभूति | 50,00,000 | - |
| दीर्घकालिक दायित्वाओं की चालू परिपक्वता (रीको भूमि) | 54,63,450 | 54,63,450 |
| अन्य देय | 38,910 | 89,000 |
| निष्पादन प्रतिभूति | 45,000 | 15,000 |
| पूंजीगत वस्तुओं के लिए ऋणदाता | - | 69,652 |
| **जोड़** | **4,51,48,417** | **4,39,85,674** |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 को (₹) | |
|---|---|---|---|---|
| **नोट 9 : अल्पकालिक प्रावधान** | | | | |
| **कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान** | | | | |
| - ग्रेच्यूएटी (संदर्भ नोट 27) | 3,79,194 | | 4,74,026 | |
| - अवकाश नकदीकरण | 1,81,697 | 5,60,891 | 1,70,612 | 6,44,638 |
| **अन्य प्रावधान** | | | | |
| -- कर के लिए प्रावधान (6,05,92,276/- रुपए का शुद्ध अग्रिम कर ) | | 13,56,797 | | - |
| **जोड़** | | **19,17,688** | | **6,44,638** |

नोट 10 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास/परिशोधन | | | | शुद्ध ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल, 2020 को | वर्ष के दौरान संवर्धन | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समाप्तीकरण | 31 मार्च, 2021 को | 1 अप्रैल, 2020 को | वर्ष के लिए (संदर्भ नोट 10.2) | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समाप्तीकरण | 31 मार्च, 2021 को | 31 मार्च, 2021 को | 31 मार्च, 2020 को |
| I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | | | | | | | | | | |
| भूमि - लीजहोल्ड (99 वर्ष) | 15,61,68,910 | - | - | 15,61,68,910 | 90,72,582 | 16,05,183 | - | 1,06,77,765 | 14,54,91,145 | 14,70,96,328 |
| भवन | | | | | | | | | | |
| क) आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से इतर भवन | 1,21,70,609 | - | - | 1,21,70,609 | 39,76,670 | 7,79,010 | - | 47,55,680 | 74,14,929 | 81,93,939 |
| ख.) फेंसिंग | 1,13,60,905 | - | (4,07,548) | 1,09,53,357 | 1,02,92,639 | 3,19,387 | (2,78,017) | 1,03,34,009 | 6,19,348 | 10,68,266 |
| ग.) ट्यूबवैल | 10,52,350 | - | - | 10,52,350 | 8,73,064 | 81,456 | - | 9,54,520 | 97,830 | 1,79,286 |
| सड़क | | | | | | | | | | |
| क.) कारपेट्ड - आरसीसी से इतर | 7,42,326 | - | - | 7,42,326 | 6,93,546 | 11,664 | - | 7,05,210 | 37,116 | 48,780 |
| ख.) गैर-कॉरपेट्ड सड़कें | 76,47,896 | - | - | 76,47,896 | 72,65,501 | - | - | 72,65,501 | 3,82,395 | 3,82,395 |
| संयंत्र एवं मशीनरी | | | | | | | | | | |
| क.) संयंत्र एवं मशीनरी (सामान्य) [संदर्भ नोट 39(iii)] | 22,12,21,817 | - | (4,72,98,991) | 17,39,22,826 | 11,72,22,273 | 1,62,96,270 | (2,21,71,664) | 11,13,46,879 | 6,25,75,947 | 10,39,99,544 |
| ख.) सौलर पैनल | 1,36,68,750 | 61,684 | - | 1,37,30,434 | 24,39,357 | 10,28,483 | (34,319) | 34,33,521 | 1,02,96,913 | 1,12,29,393 |
| ग) सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त उपकरण | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| फर्नीचर एवं फिक्सचर | 54,30,929 | 13,599 | - | 54,44,528 | 13,19,087 | 10,66,743 | - | 23,85,830 | 30,58,698 | 41,11,842 |
| कार्यालय उपकरण | 1,33,56,563 | 14,64,009 | (21,900) | 1,47,98,672 | 61,69,553 | 36,01,229 | (20,805) | 97,49,977 | 50,48,695 | 71,87,010 |
| विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण | 13,80,839 | - | - | 13,80,839 | 2,20,892 | 3,01,247 | - | 5,22,139 | 8,58,700 | 11,59,947 |
| कम्प्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट | 49,13,529 | 20,99,998 | 12,881 | 70,26,408 | 35,62,146 | 14,15,859 | 5,152 | 49,83,157 | 20,43,251 | 13,51,383 |
| पट्टाधृत सुधार (कार्यालय नवीकरण) | 1,41,51,474 | 14,21,007 | - | 1,55,72,481 | 48,50,775 | 9,98,787 | - | 58,49,562 | 97,22,919 | 93,00,699 |
| लैंडस्केपिंग एवं बागवानी कार्य (संदर्भ नोट 40) | 29,78,699 | - | (29,78,699) | (0) | 24,23,389 | - | (24,23,389) | - | (0) | 5,55,310 |
| चालू वर्ष का जोड़ | 46,62,45,596 | 50,60,298 | (5,06,94,257) | 42,06,11,637 | 17,03,81,474 | 2,75,05,318 | (2,49,23,042) | 17,29,63,750 | 24,76,47,887 | 29,58,64,122 |
| पिछले वर्ष का जोड़ | 44,03,68,485 | 2,85,80,657 | 27,03,546 | 46,62,45,596 | 13,93,67,863 | 3,34,55,219 | (24,41,608) | 17,03,81,474 | 29,58,64,122 | |

नोट 10 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास/परिशोधन | | | | शुद्ध ब्लॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल, 2020 को | वर्ष के दौरान संवर्धन | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समायोजन | 31 मार्च, 2021 को | 1 अप्रैल, 2020 को | वर्ष के लिए (संदर्भ नोट 10.2) | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समायोजन | 31 मार्च, 2021 को | 31 मार्च, 2021 को | 31 मार्च, 2020 को |
| II. अमूर्त परिसंपत्तियां | | | | | | | | | | |
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 83,09,341 | 3,78,950 | (12,881) | 86,75,410 | 53,96,798 | 13,60,669 | (5,152) | 67,52,315 | 19,23,095 | 29,12,543 |
| चालू वर्ष का जोड़ | 83,09,341 | 3,78,950 | (12,881) | 86,75,410 | 53,96,798 | 13,60,669 | (5,152) | 67,52,315 | 19,23,095 | 29,12,543 |
| पिछले वर्ष का जोड़ | 82,67,816 | 41,525 | - | 83,09,341 | 37,99,527 | 15,97,271 | - | 53,96,798 | 29,12,543 | - |

10.1) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में हानि का निर्धारण करने के लिए कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी "एएस28- संपत्ति की हानि" के अनुसार समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि संपत्ति की वसूली योग्य राशि संयंत्र और उपकरण इसकी वहन राशि से कम नहीं है, इसलिए समूह के स्वामित्व वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

10.2) वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास का सामंजस्य

| | संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | | अमूर्त परिसंपत्तियां |
|---|---|---|---|
| | कम्प्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट | पट्टाधृत सुधार (कार्यालय नवीकरण) | कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर |
| उपरोक्त नोट 10 के अनुसार मूल्यह्रास | 14,15,859 | 9,98,787 | 13,60,669 |
| पूर्ववर्ती वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन | 1,53,626 | (4,490) | 2,48,489 |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास | 15,69,485 | 9,94,297 | 16,09,158 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 11 -आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | | |
| **आस्थगित कर परिसंपत्तियां:** | | |
| - लेखा और कर के अनुसार मूल्यह्रास/परिशोधन के बीच अंतर | 59,05,174 | 51,57,761 |
| - भुगतान आधार पर अनुमेय करों के कारण समय अंतराल | 16,67,390 | 13,48,714 |
| **जोड़** | 75,72,564 | 65,06,475 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 12: दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम** | | |
| (असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे जाने वाले) | | |
| प्रतिभूति निक्षेप | 14,18,500 | 7,02,000 |
| पूर्वदत्त व्यय | 2,010 | - |
| **जोड़** | 14,20,510 | 7,02,000 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **Note 13 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां** | | |
| (असुरक्षित, लेकिन अच्छा माना जाता है) | | |
| **परियोजना विकास निधि में से परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट 2.7.1)** | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार | 1,03,56,58,606 | 98,34,71,322 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय [₹ 91,50,000/- की शुद्ध बिड प्रोसेसिंग फीस (पिछले वर्ष: कुछ नहीं)] | 62,45,81,511 | 74,64,16,179 |
| | 1,66,02,40,117 | 1,72,98,87,501 |
| (घटाएं): सहयोगी कंपनियों/एसपीवी को अंतरित राशि | (54,71,07,299) | (64,84,25,342) |
| (घटाएं): परियोजना विकास निधि को अंतरण | (2,16,43,131) | (4,58,03,553) |
| **उप-जोड़** | 1,09,14,89,687 | 1,03,56,58,606 |
| **एसपीवी से वसूली योग्य परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट 2.7.1, 13.1 and 13.2)** | | |
| - औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड | 2,02,62,02,357 | 1,76,93,26,213 |
| - धौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 3,17,83,68,542 | 2,91,46,67,473 |
| - धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड | - | 6,59,998 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड | 8,89,66,426 | 8,48,64,336 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड | 5,48,59,660 | 4,84,10,060 |
| - डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड | 6,87,98,061 | 6,87,12,587 |
| - डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 5,07,54,677 | 5,07,54,677 |
| - इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड | 8,80,82,730 | 7,45,06,230 |
| - एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 9,42,73,176 | 9,19,36,776 |
| | 5,65,03,05,651 | 5,10,36,58,350 |
| (घटाएं) - अन्य चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (संदर्भ नोट 17) | - | (6,59,998) |
| **उप-जोड़** | 5,65,03,05,651 | 5,10,31,98,352 |
| **जोड़** | 6,74,17,95,338 | 6,13,88,56,958 |

13.1 नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (डीएमआईसीपीआईटीएफ) ने 6 मार्च, 2018 को हुई अपनी तीसरी बैठक में धारक कंपनी को निर्देश दिया है कि वह संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी को अनुदान-सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली परियोजना विकास निधियों में से सहायक कंपनियों/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में धारक कंपनी द्वारा वहन किए गए परियोजना विकास व्यय को स्थानांतरित करे और इसकी वसूली को तब तक स्थगित कर जब तक कि एसपीवी पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करने में सक्षम न हो। संबंधित सहायक कंपनियां/एसपीवी पर्याप्त अधिशेष निधियां उत्पन्न नहीं कर पाई हैं इसलिए उनसे वसूली की जा सकने वाली राशि 31 मार्च, 2021 तक वसूली के कारण कम नहीं हुई है।

13.2 एसपीवी से वसूले जाने योग्य परियोजना विकास व्यय का संघटक

31 मार्च, 2021 को

| एसपीवी | 31 मार्च, 2020 को (₹) | वर्ष के दौरान वहन किया गया व्यय (₹) | वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹) | 31 मार्च 2021 को शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|
| - औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड | 1,76,93,26,213 | 25,68,76,144 | - | 2,02,62,02,357 |
| - धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 2,91,46,67,473 | 26,37,01,069 | - | 3,17,83,68,542 |
| - धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड | 6,59,998 | - | (6,59,998) | - |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड | 8,48,84,336 | 40,82,092 | - | 8,89,66,428 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड | 4,84,10,060 | 64,49,600 | - | 5,48,59,660 |
| - डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड | 6,87,12,587 | 85,494 | - | 6,87,98,081 |
| - डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 5,07,54,677 | - | - | 5,07,54,677 |
| - इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप यैटर नोएडा लिमिटेड | 7,45,06,230 | 1,35,76,500 | - | 8,80,82,730 |
| - एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 9,19,36,776 | 23,36,400 | - | 9,42,73,176 |
| | 5,10,38,58,360 | 54,71,07,299 | (8,59,998) | 5,65,03,05,661 |

31 मार्च, 2020 को

| एसपीवी | 31 मार्च, 2019 को (₹) | वर्ष के दौरान वहन किया गया व्यय (₹) | वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹) | 31 मार्च 2020 को शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|
| - औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड | 1,46,97,03,648 | 29,96,22,565 | - | 1,76,93,26,213 |
| - धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 2,59,99,60,739 | 31,47,06,734 | - | 2,91,46,67,473 |
| - धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड | 50,91,152 | 11,62,148 | (55,93,302) | 6,59,998 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड | 8,08,02,244 | 40,82,092 | - | 8,48,84,336 |
| - एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड | 3,88,65,417 | 95,44,643 | - | 4,84,10,060 |
| - डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड | 6,87,12,587 | - | - | 6,87,12,587 |
| - डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड | 5,07,54,677 | - | - | 5,07,54,677 |
| - इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप यैटर नोएडा लिमिटेड | 7,45,06,230 | - | - | 7,45,06,230 |
| - एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड | 7,26,29,616 | 1,93,07,160 | - | 9,19,36,776 |
| | 4,46,10,26,310 | 64,84,25,342 | (55,93,302) | 5,10,38,58,350 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 14: व्यापार प्राप्त** | | |
| (असुरक्षित, लेकिन अच्छे समझे जाते हैं) | | |
| अन्य प्राप्य * (संदर्भ नोट 14.1) | 2,26,95,535 | 1,81,34,715 |
| जोड़ | 2,26,95,535 | 1,81,34,715 |
| 14.1 निम्न से बकाया राशि शामिल है: | | |
| इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबीशन सेंटर लिमिटेड - उद्यम जिन पर प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का महत्वपूर्ण प्रभाव है | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| जोड़ | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |

* वसूले जाने की तिथि से

## 31 मार्च, 2021 को समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

| विवरण | | | 31 मार्च, 2021 को (₹) | | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| **नोट 15: रोकड़ और बैंक शेष** | | | | | |
| **रोकड़ और नकद समतुल्य** | | | | | |
| रोकड़ हस्ते | | | 6,707 | | 12,821 |
| चालू खातों में बैंक के पास शेष | | | | | |
| - परियोजना विकास निधि | 2,22,651 | | | 2,02,324 | |
| - स्वच्छता कार्य योजना | 289 | | | - | |
| - समूह निधि | 12,18,25,091 | 12,20,48,028 | 4,46,112 | | 6,48,436 |
| सावधि जमाओं में बैंकों के पास शेष | | | | | |
| - परियोजना विकास निधि | 7,89,25,000 | | 48,05,55,897 | | |
| - समूह निधि | 1,22,47,95,827 | 1,30,37,20,827 | 1,14,44,84,364 | | 1,62,50,40,261 |
| **अन्य बैंक शेष** | | | | | |
| चालू खातों में बैंक के पास शेष | | | | | |
| - परियोजना विकास निधि | | 9,94,81,710 | | | - |
| जोड़ | | 1,52,52,57,272 | | | 1,62,57,01,518 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 16 : लघुकालिक ऋण और अग्रिम** | | |
| (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है) | | |
| विक्रेताओं को अग्रिम | 2,78,992 | 3,84,122 |
| कार्मिक अग्रिम | 50,996 | 3,70,055 |
| पूर्वदत्त व्यय | 30,06,929 | 13,88,886 |
| राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष | 9,85,559 | - |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य | 6,63,000 | 6,36,000 |
| | 49,85,476 | 27,59,063 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 17 : अन्य चालू परिसंपत्तियां** | | |
| सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज [ पीडीएफ खाते के ₹ 7,24,085/- शामिल (पिछले वर्ष -₹ 41,75,663/-)] | 5,05,81,237 | 7,20,28,238 |
| आयकर से रिफंड योग्य [संदर्भ नोट 26(iii)] | 2,01,44,724 | 3,17,43,989 |
| बिजली की बिक्री पर प्रोद्भूत आय [बिल नहीं की गई आमदनी (छूट का शुद्ध)] | 57,50,818 | 54,41,413 |
| अन्य वसूली योग्य | 90,163 | - |
| एसपीवी से वसूली योग्य | - | 6,59,998 |
| अग्रिम कर (पिछले वर्ष के लिए कर हेतु शुद्ध प्रावधान ₹ 1,42,41,215/-) | - | 1,15,88,739 |
| | 7,65,76,942 | 12,14,62,377 |

| विवरण | | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **नोट 18: परिचालन से आमदनी** | | | | |
| क) निम्न के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में सेवा फीस ( संदर्भ नोट 2.9) | | | | |
| नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट | 20,00,00,000 | | 8,28,00,400 | |
| इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) | 5,00,00,000 | 25,00,00,000 | 5,00,00,000 | 13,28,00,400 |
| ख) बिजली की बिक्री * | | 6,14,34,377 | | 9,61,02,444 |
| [70,05,060 किलो वाट यूनिट (पिछले वर्ष: 99,41,452 किलो वाट यूनिट) और अन्य समायोजन] | | | | |
| **जोड़** | | **31,14,34,377** | | **22,89,02,844** |

* एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड को बिल नहीं कि गई ₹ 58,68,182/- राशि सहित (6,69,120 किलो वाट @ ₹ 8.77 प्रति यूनिट)

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 19: अन्य आय** | | |
| समूह की निधियों के सावधि जमा पर ब्याज | 6,22,45,676 | 8,38,09,671 |
| आयकर रिफंड पर ब्याज | 15,56,597 | - |
| इंडिया इंटरनेशनल कवन्शन एंड एक्जाबिशन सेंटर लिमटेड से उधार व्यया का प्रतिभारजन | 72,00,000 | 66,44,305 |
| स्क्रैप बिक्री | 1,66,652 | - |
| विविध आय | 35,132 | 3,94,969 |
| **जोड़** | **7,12,04,057** | **9,08,48,945** |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 20: उपभोग की गई सामग्रियों की लागत** | | |
| डीजल व्यय | - | 4,41,25,116 |
| माल भाड़ा व्यय | 900 | 650 |
| **जोड़** | **900** | **4,41,25,766** |

## 31 मार्च, 2021 को समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 21: कर्मचारी हितलाभ व्यय** | | |
| वेतन, मजदूरी, बोच्यूएटी, अवकाश क्षतिपूर्ति, भते आदि | 5,36,77,908 | 4,86,20,396 |
| भविष्य निधि/पेंशन निधि में योगदान | 37,23,093 | 32,63,075 |
| कार्मिक कल्याण व्यय | 22,17,408 | 27,75,827 |
| जोड़ | 5,96,18,409 | 5,46,59,298 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 22: वित्त लागत** | | |
| ऋणों पर ब्याज | - | 7,54,788 |
| जोड़ | - | 7,54,788 |

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 23: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय** | | |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास | 2,75,05,318 | 3,34,55,219 |
| अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन | 13,60,669 | 15,97,271 |
| जोड़ | 2,88,65,987 | 3,50,52,490 |

## 31 मार्च, 2021 को समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **नोट 24 : अन्य व्यय** | | |
| किराया ( संदर्भ नोट 24.1 और 30) | 4,86,03,024 | 5,66,79,394 |
| **लेखापरीक्षकों को भुगतान (संदर्भ नोट 24.2)** | | |
| लेखापरीक्षा फीस | 4,30,300 | 4,30,300 |
| प्रमाणन फीस | 5,500 | 1,05,100 |
| विज्ञापन और व्यापार संवर्धन | 81,06,776 | 4,44,22,050 |
| कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (संदर्भ नोट 32) | 15,39,684 | 44,02,256 |
| बिजली | 10,01,052 | 8,39,673 |
| हाउसकीपिंग | 17,42,671 | 15,54,785 |
| सुरक्षाकर्मी | 8,55,544 | 6,79,488 |
| पेशेवर और परामर्श प्रभार | 44,31,452 | 35,21,609 |
| बैठक और जलपान | 2,07,080 | 4,13,894 |
| मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय | 38,57,397 | 37,77,248 |
| मरम्मत और अनुरक्षण - कम्प्यूटर | 26,86,034 | 29,21,718 |
| प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | 19,19,731 | 19,33,021 |
| सूचना एवं डाक प्रभार व्यय | 16,95,191 | 15,93,394 |
| यात्रा एवं परिवहन व्यय | 28,44,921 | 59,90,855 |
| बीमा | 5,63,298 | 3,60,978 |
| निदेशकों के बैठक में उपस्थित होने हेतु फीस | - | 2,87,200 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि | 1,81,33,857 | 2,11,346 |
| पूर्व अवधि व्यय (संदर्भ नोट 24.3) | 2,52,806 | 33,315 |
| छात्रवृति | 3,00,548 | 2,79,145 |
| विविध व्यय | 26,23,178 | 38,87,906 |
| 1 मेगा वाट प्लांट को बंद एवं चालू करने के लिए व्यय | 14,09,144 | - |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर कमीशन | 4,14,752 | - |
| जल प्रभार | 86,436 | 1,01,755 |
| परिचालन और अनुरक्षण व्यय | 46,57,088 | 44,13,355 |
| भूमि सेवा प्रभार | 14,20,500 | 14,20,500 |
| बिजली की बिक्री पर छूट | 12,16,532 | 10,48,727 |
| अक्षय उर्जा विकास व्यय | 5,00,000 | 10,00,000 |
| **जोड़** | **11,15,04,506** | **14,23,09,012** |

24.1 किराए में लीज अनुबंध के अनुसार, पट्टेदाता को ₹1,03,07,412/- नगरपालिका कर (पिछले वर्ष: ₹1,03,07,412/-) का भुगतान शामिल है।

24.2 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक ₹ 4,35,100/- धारक कंपनी के पिछले लेखा परीक्षकों को किए गए भुगतान से संबंधित है।

24.3 पूर्व अवधि व्ययों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| विज्ञापन और व्यापार संवर्धन | 2,25,277 | - |
| सूचना एवं डाक प्रभार व्यय | 11,021 | - |
| यात्रा एवं परिवहन व्यय | 16,108 | - |
| पेशेवर और परामर्श प्रभार | 400 | 25,000 |
| प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | - | 8,315 |
| | **2,52,806** | **33,315** |

25 प्रति शेयर आमदनी

मूल आमदनी प्रति इक्विटी शेयर की गणना कर पश्चात लाभ को वर्ष के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग करके की जाती है।

| | विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|---|
| क | इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात् लाभ | 12,39,58,847 | 3,00,93,409 |
| ख | ईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या) | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| ग | मूल/तनुकृत आमदनी प्रति शेयर (क/ख) | 1.24 | 0.30 |
| घ | प्रति इक्विटी शेयर का सम मूल्य | 10.00 | 10.00 |

26 आकस्मिक दायित्वः और प्रतिबद्धता (उपलब्ध न कराए जाने की सीमा तक के लिए):

(i) आकस्मिक दायित्वाएं

| | | |
|---|---|---|
| -समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। | - | - |
| -समूह की ओर से बैंक द्वारा जारी गारंटियां | - | - |

(ii) प्रतिबद्धताएं

| अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है : | | |
|---|---|---|
| - परियोजना विकास गतिविधियों के लिए परामर्श अनुबंध | 1,61,58,92,643 | 1,08,92,27,425 |
| - मूंजी मद पर अनुबंध | 2,36,000 | - |
| - सीएसआर गतिविधियों के अनुबंध | - | 70,800 |

(iii) कराधान मामले

क) धारक कंपनी द्वारा अपील/संशोधन के अंतर्गत आयकर मामले

| कंपनी | आकलन वर्ष | दावा किया गया रिफंड (₹) | आदेश के अनुसार प्राप्त रिफंड (₹) | रुका हुआ शेष रिफंड (₹) | रोकने का कारण | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धारक | 2017-18 | 52,64,553 | 45,85,504 | 6,79,049 | एओ ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26.12.2019 के आदेश द्वारा 17,12,903 रुपए के व्यय की अनुमति नहीं दी। | 06.01.2020 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की प्रतीक्षा है। |
| | 2018-19 | 49,71,760 | 32,24,650 | 17,47,110 | एओ ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26.04.2021 के आदेश द्वारा 4,34,057/- रुपए के व्यय की अनुमति नहीं दी और 58,89,181/- रुपए की आय को दोबारा जोड़ दिया गया। | 13.05.2021 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की प्रतीक्षा है। |
| | 2019-20 | 97,58,870 | 69,14,080 | 28,44,790 | धारा 143(1) के अंतर्गत दिनांक 23.10.2020 की सूचना में 28,44,790/-रुपए के टीडीएस क्रेडिट का मिलान नहीं हुआ | 19.05.2021 को पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई है, लिपटान की प्रतीक्षा है। |
| | जोड़ | | | 51,70,949 | | |

ख) सहायक कंपनी द्वारा अपील के अंतर्गत आयकर मामले

| कंपनी | आकलन वर्ष | दावा किया गया रिफंड (₹) | जारी की गई मांग (₹) | मांग जारी करने का कारण | अंतिम आदेश पारित होने की तिथि | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सहायक | 2017-18 | 1,16,36,420 | 37,01,758 | दावा किए गए विदेशी कर क्रेडिट और अन्य की अनुमति न देना | धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 25 दिसंबर, 2019 | 6 जनवरी, 2020 को सीआईटी(ए) के पास धारा 246ए के अंतर्गत दर्ज अपील |
| | 2018-19 | 210 | 1,00,09,520 | | धारा 143(1) के अंतर्गत दिनांक 25 जनवरी, 2021 | 17 फरवरी, 2021 को सीआईटी(ए) के पास धारा 246ए के अंतर्गत दर्ज अपील |
| | जोड़ | | 1,37,11,278 | | | |

समूह इन मांगों का विरोध कर रहा है और समूह के सलाहकारों सहित प्रबंधन का मानना है कि ये मांगें अपीलीय स्तर पर टिकने लायक नहीं हैं। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से समूह की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। समूह इन आकस्मिक देनदारियों के संबंध में किसी भी क्षतिपूर्ति की उम्मीद नहीं करता है, और अपीलकर्ता कार्यवाही के संभावित समाधान के लिए इन मामलों के संबंध में नकद बहिर्वाह के समय, यदि कोई हो, का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(iv) 31 मार्च, 2021 को धारक कंपनी पर दर्ज मामलें जिनका कंपनी के ऊपर कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है, निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | याचिका सं, वर्ष तिथि | याचिकाकर्ता | प्रतिवादी | विचाराधीन विषय | संक्षिप्त ब्यौरा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9282/2015 | सुभ राम एवं अन्य. | एनआईसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य | राजस्थान राज्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित | कऊउर एफिडेविट में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि पार्टियों की सरणी से एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का नाम हटाया जाए और याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत की गई है।<br><br>याचिकाकर्ता ने मामले में टर्ज याचिका को संशोधित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।<br><br>संशोधित याचिका के संबंध में एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) द्वारा भी प्रत्युत्तर में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।<br><br>कंपनी का नाम डीएमआईसीडीसी से बदल कर एनआईसीडीसी करने का अनुरोध 8 सितंबर, 2020 को माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।<br><br>सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है। |
| 2 | 8649/2016 | इरशाद मोहम्मद खान<br><br>एवं अन्य | एनआईसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य | औरंगाबाद में जयकवाड़ी डैम से शेंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क तक पानी की पाइपलाइन से संबंधित | 18.01.2019 को एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का प्रतिवादी के रूप में नाम हटाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत नियम 10 के आदेश 1 के अंतर्गत आवेदन मुंबई, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद को इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि याचिका के लिए आवेदक न तो उचित पार्टी है और न ही आवश्यक पार्टी।<br><br>सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है। |

**27 कर्मचारी हितलाभों पर लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रकटन:**

क) विभिन्न परिभाषित कर्मचारी योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

**i) शर्पपरिभाषित अंशदान योजना**

**अविष्य निधि (पीएफ)** – अविष्य निधि के प्रति अंशदान को क्षेत्रीय अविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। भुगतान की गई राशि को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में प्रभारित किया जाता है।

**iii परिभाषित हितलाभ योजनाएं**

क. ग्रेच्युएटी (अनिधिक) – समूह के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित हितलाभ योजना है। ग्रेच्युएटी योजना के अंतर्गत, प्रत्येक कर्मचारी जिसने कम से कम पांच वर्ष की सेवाएं प्रदान की हो, उसके जाने पर निर्धारित 20,00,000/- रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के 15 दिनों की ग्रेच्युएटी के पात्र है। ग्रेच्युएटी के प्रति दायित्व अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा से बर्खास्तगी, विकलांगता अथवा मृत्यु के कारण होती है। ग्रेच्युएटी के संबंध में समूह की दायित्व प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकारा जाता है।

ख. अवकाश नकदीकरण (अनिधिक): नीति के अनुसार, कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 30 छुट्टियों के हकदार हैं, जिनमें से वर्ष के दौरान ही अधिकतम 10 छुट्टियों को भुनाया जा सकता है और शेष छुट्टियों को अधिकतम 90 दिनों के अध्यधीन आगे बढ़ाया जा सकता है। संचित अवकाश जो अधिवर्षिता, त्यागपत्र, समाप्ति, निःशक्तता या मृत्यु के समय भुनाया नहीं जा सकता है। तदनुसार, छुट्टी नकदीकरण के प्रति समूह के दायित्व की गणना मूल वेतन की राशि के आधार पर शेष अवधि के लिए आनुपातिक अवकाश पर की जाती है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में कर्मचारी हितलाभों पर एएस-15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत अपेक्षा अनुसार अन्य प्रकटन निम्नानुसार है:

**i) परिभाषित अंशदान योजना**

वर्ष के लिए व्यय के रूप में स्वीकारा गया परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान, निम्नानुसार है:

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| अविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान | 31,04,083 | 27,47,649 |

**ii) परिभाषित हितलाभ योजना**

**ग्रेच्युएटी (अनिधिक)**

निम्नलिखित तालिकाएं लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में पहचाने गए शुद्ध लाभ व्यय के घटकों, वित्तपोषित/अनिधिक स्थिति और परिभाषित लाभ योजना के लिए समेकित तुलन पत्र में पहचानी गई राशियों को प्रभावित करती हैं।

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **लाभ एवं हानि समेकित विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ** | | |
| मौजूदा सेवा लागत | 10,74,105 | 9,14,447 |
| पिछली सेवा लागत | - | - |
| लाभ दायित्व पर ब्याज लागत | 3,16,141 | 2,37,027 |
| वर्ष में स्वीकारी गई शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि | 4,13,182 | 2,58,578 |
| लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ | 18,03,428 | 14,10,052 |

## 31 मार्च, 2021 को समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को (₹) | 31 मार्च, 2020 को (₹) |
|---|---|---|
| **समेकित तुलन पत्र में स्वीकारी गई राशि** | | |
| परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मान | 57,82,151 | 46,90,311 |
| नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मान | - | - |
| समेकित तुलन पत्र में पहचानी गई परिसंपत्तियां/(दायित्व) | 57,82,151 | 46,90,311 |
| **परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मान में परिवर्तन** | | |
| वर्ष की शुरुआत में परिभाषित हितलाभ दायित्व | 46,90,311 | 35,11,513 |
| मौजूदा सेवा लागत | 10,74,105 | 9,14,447 |
| पिछली सेवा लागत | - | - |
| ब्याज लागत | 3,16,141 | 2,37,027 |
| भुगतान किया गया हितलाभ | (7,11,588) | (2,31,254) |
| दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानियां | 4,13,182 | 2,58,578 |
| वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व | 57,82,151 | 46,90,311 |
| **परिभाषित हितलाभ दायित्व का ब्रेकअप** | | |
| अचल | 54,02,957 | 42,16,285 |
| चल | 3,79,194 | 4,74,026 |
| | 57,82,151 | 46,90,311 |

**दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य सिद्धांत:**

| | |
|---|---|
| प्रयुक्त विधि | प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि |
| मृत्यु सारणी | आईएएलएम 2012-14 |
| 30/ 44 वर्ष/ 44 वर्ष से अधिक तक आहरण दर (%) | धारक कंपनी के लिए 8.00% प्रति वर्ष ; सहायक कंपनी के लिए 10.00% प्रति वर्ष |
| कटौती दर (%) | 6.75% प्रति वर्ष (सहायक कंपनी के लिए 6.50% प्रति वर्ष) — 6.75% प्रति वर्ष |
| भविष्य वेतन वृद्धि (%) | 6.50% प्रति वर्ष — 6.00% प्रति वर्ष |
| रिटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या) | 60 वर्ष |

28 **खंडवार रिपोर्टिंग**

समूह ने दो प्राथमिक व्यवसाय खंडों की पहचान की है, बिजली उत्पादन और परियोजना विकास प्रभाग। खंडों की पहचान और रिपोर्ट, सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिम और रिटर्न, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसके अलावा, दोनों प्राथमिक खंड देश के भीतर एक ही भौगोलिक स्थान पर में काम कर रहे हैं, अतएव कोई दूसरा भौगोलिक खंड नहीं है।

क. खंड के लिए आमदनी और व्यय को खंड की परिचालन गतिविधियों के संबंध के आधार पर पहचाना गया है।

ख. खंड की परिसंपत्तियां और दायित्वाएं संबंधित खंड की परिसंपत्तियों और दायित्वाओं को प्रस्तुत करती है।

ग. प्रमुख व्यापार खंडों के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

| विवरण | बिजली उत्पादन (₹) | परियोजना विकास (₹) | जोड़ (₹) |
|---|---|---|---|
| आमदनी | | | |
| बाहरी आमदनी | 6,35,11,352 | 31,91,27,082 | 38,26,38,434 |
| | (9,71,25,851) | (22,26,25,938) | (31,97,51,789) |
| अंतः खंड आमदनी | Nil | 23,00,866 | 23,00,866 |
| | (Nil) | (26,16,178) | (26,16,178) |
| कुल आमदनी | 6,35,11,352 | 32,14,27,948 | 38,49,39,300 |
| | (9,71,25,851) | (22,52,42,116) | (32,23,67,967) |
| जोड़ें: आवंटन योग्य अन्य आय | Nil | Nil | Nil |
| | (Nil) | (Nil) | (Nil) |
| खंड आमदनी | 6,35,11,352 | 32,14,27,948 | 38,49,39,300 |
| | (9,71,25,851) | (22,52,42,116) | (32,23,67,967) |
| खंड परिणाम (मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व) | 2,38,63,862 | 18,72,36,600 | 21,11,00,462 |
| | (2,99,78,130) | (4,74,53,882) | (7,74,32,012) |
| कर पूर्व लाभ/हानि [-] | 36,36,377 | 17,86,96,098 | 18,22,34,475 |
| | (17,49,289) | (4,06,30,233) | (4,23,79,522) |
| कर व्यय | 64,53,974 | 5,33,01,900 | 5,97,55,874 |
| | (20,25,149) | (1,22,23,798) | (1,42,48,947) |
| आस्थगित कर व्यय/(प्रतिलेखन करना) [-] | 83,986 | -11,50,075 | -10,66,089 |
| | (-8,52,089) | (-6,39,832) | (-14,91,921) |
| कर पश्चात लाभ/(हानि) [-] | -28,99,583 | 12,64,44,273 | 12,35,44,690 |
| | (6,76,229) | (2,90,46,267) | (2,96,22,496) |

**अन्य सूचना**

| विवरण | बिजली उत्पादन (₹) | परियोजना विकास (₹) | जोड़ (₹) |
|---|---|---|---|
| खंड परिसंपत्तियां | 30,65,88,500 | 8,45,67,91,867 | 8,76,33,80,367 |
| | (31,07,99,974) | (8,03,57,84,690) | (8,34,65,81,664) |
| खंड दायित्वाएं | 6,74,00,226 | 25,25,51,950 | 31,99,52,176 |
| | (6,81,53,808) | (39,13,20,204) | (45,94,74,012) |
| पूंजीगत व्यय | 75,264 | 53,63,964 | 54,39,228 |
| | (13,51,338) | (2,72,26,786) | (2,85,78,124) |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | 2,92,25,485 | 86,40,502 | 2,88,66,987 |
| | (2,82,28,841) | (68,23,649) | (3,50,52,490) |
| मूल्यह्रास और परिशोधन से इतर गैर-नकदी व्यय | 1,82,85,126 | 18,33,856 | 2,01,18,982 |
| | (1,46,393) | (16,80,550) | (18,26,943) |

नोट: कोष्ठक () में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते हैं।

## 29 संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखांकन मानक-18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" की आवश्यकताओं के अनुसार, संबंधित पार्टी के नाम जिनके पास महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने के लिए नियंत्रण/क्षमता मौजूद है, साथ ही लेनदेन की कुल मात्रा और उनके साथ वर्ष के अंत में शेष, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना और प्रमाणित किया गया है, नीचे बताया गया है: .

**I संबंधित पार्टियों की सूची और संबंध की प्रकृति जहां नियंत्रण मौजूद है**

**क कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले उपक्रम**

जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी)

**ख संयुक्त/सहयोगी**

हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

**ग प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)**

| | |
|---|---|
| श्री के संजय मूर्ति (18 नवंबर, 2019 से) | सीईओ और पदेन निदेशक |
| श्री अल्केश कुमार शर्मा (15 सितंबर, 2019 तक) | सीईओ और प्रबंध निदेशक |
| श्री प्रशांत कुमार बनसावर (17 जून 2019 से 5 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए) | सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार |
| श्री राजेंद्र रत्नू (19 सितंबर 2019 से 17 नवंबर, 2019 तक की अवधि के लिए) | सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार |
| श्री पी. के. अग्रवाल | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| श्री अभिषेक चौधरी | उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन और कंपनी सचिव |
| श्री श्रीकांत कोल्हम् | सहायक कंपनी के निदेशक |
| श्री सूर्या प्रकाश | सहायक कंपनी के कंपनी सचिव |

**घ उपक्रम जिनके ऊपर प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का महत्वपूर्ण प्रभाव है**

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (17 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक, 28 नवंबर, 2020 से 13 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए और 30 जून, 2021 से)

**II व्यापार की सामान्य अवधि में संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:**

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **पेतन/पारिश्रमिक** | | |
| श्री के संजय मूर्ति | 56,92,743 | 19,00,183 |
| श्री अल्केश कुमार शर्मा | - | 32,30,880 |
| श्री पी.के. अग्रवाल | 53,82,579 | 51,83,446 |
| श्री अभिषेक चौधरी | 52,88,520 | 50,81,023 |
| श्री सूर्या प्रकाश | 7,15,313 | 6,98,449 |
| **प्रतिपूर्ति** | | |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | - | 4,232 |
| **उपरि व्ययों का संविभाजन** | | |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | 6,00,000 | 8,44,305 |
| **सेवा फीस** | | |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर | - | 1,25,00,000 |

**III वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के साथ बकाया शेष**

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| **व्यापार प्राप्य** | | |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| **अन्य अवधि ऋण और अग्रिम** | | |
| इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड | 6,63,000 | 6,36,000 |
| **वेतन/पारिश्रमिक देय** | | |
| श्री के संजय मूर्ति | 4,30,086 | 2,03,420 |
| श्री पी. के. अग्रवाल | 1,03,561 | 1,02,561 |
| श्री अभिषेक चौधरी | 81,754 | 1,20,456 |
| श्री सूर्या प्रकाश | - | - |

## 30 परिचालन लीज

धारक कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था 8वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में अपने लीज कार्यालय परिसर से संबंधित परिचालन पट्टे के संबंध में है, जिसे 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया है। ₹ 4,86,03,024/- का कुल पट्टा किराया (पिछले वर्ष: ₹ 5,66,79,394/- जिसमें अशोका होटल में कार्यालय स्थान के लिए ₹ 80,76,370/- का पट्टा किराया शामिल है जो 31.05.2020 को खाली किया गया था।) भुगतान की लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी गई है और नोट 24 में इसका प्रकटन किया गया है।

31 विदेशी मुद्रा में व्यय

| विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|
| - यात्रा | - | 3,18,704 |
| | - | 3,18,704 |

32 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, धारक और सहायक कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समितियों का गठन किया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) के आधार पर सीएसआर खर्चों के लिए 14,92,484/- रुपए की राशि (पिछले वर्ष: ₹ 22,84,992/-) देय है। वर्ष के दौरान खर्च की गई /खर्च किए जाने के लिए लंबित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

| | विवरण | 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (₹) | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (₹) |
|---|---|---|---|
| I | समूह द्वारा व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि | | |
| | वार्षिक सीएसआर आबंटन | 14,92,484 | 22,84,992 |
| | पिछले वर्ष से अग्रेषित (अधैतनिक दायित्व सहित) | 1,98,222 | 22,26,486 |
| | **व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि** | **16,90,706** | **45,11,478** |
| II | **वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि** | | |
| | नकद में | 16,90,706 | 43,13,256 |
| | जिनका नकद भुगतान अभी किया जाना है | - | 1,98,222 |
| | | 16,90,706 | 45,11,478 |
| III | **उद्देश्य जिनके लिए सीएसआर व्यय किया गया है** | | |
| | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान (पीएमएनआरएफ) | 14,92,484 | 23,00,333 |
| | ई-शिक्षण सुविधा सहित कम्प्यूटर लैब की स्थापना द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन | 1,98,222 | - |
| | डिजीटल साइंस लैब और लैंग्वेज लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एनजीओ को योगदान | 99,000 | 10,68,000 |
| | कौशल और तकनीकी सक्षमता प्रशिक्षण के लिए योगदान | - | 9,43,923 |
| | | 16,90,706 | 43,13,256 |
| IV | **उद्देश्य जिन पर सीएसआर व्यय का अभी भी लकड़ में भुगतान किया जाना बाकी है** | | |
| | ई-शिक्षण सुविधा सहित कम्प्यूटर लैब की स्थापना द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन | - | 1,98,222 |
| | डिजीटल साइंस लैब और लैंग्वेज लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एनजीओ को योगदान | - | 99,000 |
| | | - | 1,98,222 |

33 प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अलावा अन्य संपत्ति के मूल्य में व्यापार की सामान्य अवधि में वसूली पर अमूर्त संपत्ति का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिसमें ये समेकित तुलन पत्र में बताए गए हैं। इसके अलावा, सभी ज्ञात देनदारियों के लिए सही खातों में पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है।

34 व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, व्यापार देय और अन्य पार्टियों आदि के अंतर्गत दिखाई देने वाले शेष सामंजस्य/पुष्टि किए जाने के अध्यधीन हैं। पुष्टिकरण/सामंजस्य के होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो तो, उन्हें पुष्टिकरण/सामंजस्य के वर्ष में लिया जाएगा, जो प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होंगे।

35 लिवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016-नीति द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अध्यधीन, कर पश्चात लाभ के 30% या निवल संपत्ति के 5% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

डीआईपीएएम ने दिनांक 17 दिसंबर, 2018 के का.ज्ञा.सं. 5/3/2018-नीति (खंड II) और दिनांक 18 मार्च 2021 के का.ज्ञा. सं. 4(30) (1)/2018-डीआईपीएएम-I(पीटी) के द्वारा कंपनी को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों से छूट प्रदान की है।

डीआईपीएएम ने सहायक कंपनी को दिनांक 17 दिसंबर, 2018 के का.ज्ञा.सं. 5/3/2018-नीति (खंड II) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों से छूट प्रदान की और दिनांक 18 मार्च 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4(30) (1)/2018-डीआईपी एएम-आई(पीटी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों से छूट प्रदान की।

धारक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम लाभांश के भुगतान से छूट की मंजूरी प्राप्त करने हेतु 25 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से डीआईपीएएम को आवेदन किया है, जिसका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

इसी तरह, धारक और सहायक कंपनियां वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और स्वीकरण के बाद वित्त वर्ष 2020-21 के लिए न्यूनतम लाभांश के भुगतान से छूट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव करती है, इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में लाभांश के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

36 समूह के परिचालन पर कोविड-19 का प्रभाव

समूह ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्राप्य और अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों की अरोपित राशि पर संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जो कोविड 19 महामारी के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। भविष्य की आर्थिक स्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर और इसके व्यवसाय की प्रकृति पर विचार करते हुए, प्रबंधन का अनुमान है कि इन परिसंपत्तियों की अगणीत राशि की वसूली हो जाएगी और कम से कम 12 महीनों के लिए व्यवसाय के संचालन को निधि देने के लिए पर्याप्त तरलता उपलब्ध है, इस प्रकार कोविड-19 महामारी से समूह के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

37 समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां जैसे कि डीएमआईसीडीसी गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड, डीएमआईसीडीसी इंदापुर पावर कंपनी लिमिटेड, डीएमआईसीडीसी बाघोल पावर कंपनी लिमिटेड और डीएमआईसीडीसी घिरे भाड़ पावर कंपनी लिमिटेड को बंद कर दिया गया है और दिनांक 09.08.2018 के नोटिस संख्या आरओसी/डीई.जेओ/248(5)/ एसटीके7/4893 द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2018 से उनके नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिए गए हैं।

उपरोक्त उल्लिखित तिथि पर इन सहायक कंपनियों में रखे गए शेयरों को संबंधित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अनुसार उनकी परिसंपत्तियों के आधार पर आंका गया था और 20,00,000 रुपए के निवेश में हानि को वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान परियोजना विकास व्यय में स्वीकारा गया था। चूंकि धनराशि वसूलनीय नहीं है, वर्ष के दौरान, उल्लिखित राशि को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 2.7 के अनुसार पूंजीगत कोष में अंतरित किया गया है।

38 जापान सरकार के न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलोजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (एनईडीओ), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और धारक कंपनी के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुच्छेद 16 के अनुसार, पीवी मॉड्यूल, संबंधित उपकरणों के साथ पीसीएस, माइक्रो ग्रिड नियंत्रण के लिए नियंत्रण सर्वर, ट्रांसमिशन प्रणाली और अन्य सहायक उपकरण एनईडीओ द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किए गए हैं।

उसी अनुच्छेद के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन के दौरान, एनईडीओ द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों का स्वामित्व एनईडीओ का होगा। तत्पश्चात, परियोजना के पूरा होने पर और सभी वास्तविक अधिकारों के साथ स्वामित्व के हस्तांतरण पर, इन उपकरणों को ₹ 1/- के नाममात्र मूल्य पर रखा गया है जो कि सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन मानक -12 के अनुसार है।

**39 ऊर्जा क्रय अनुबंध**

सहायक कंपनी ने ऊर्जा की बिक्री के लिए निम्न ऊर्जा क्रय अनुबंधों को निष्पादित किया है:

(i) दिनांक 05.06.2015 को ₹ 7.77 प्रति किलोवाट घंटे की दर से 25 वर्षों की अवधि के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन), नई दिल्ली के साथ 5 मेगा वाट सोलर प्लांट से सौर ऊर्जा बिक्री के लिए।

(ii) आपान की न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलोजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मध्यस्थता में, मिकुनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमआईपीएल), एक कंपनी जिसका नीमराणा में संयंत्र है, के साथ दिनांक 17.06.2016 को ₹ 11.99 प्रति किलोवाट घंटे की दर से 10 वर्षों की अवधि के लिए डीजल जनरेटर से सृजित ऊर्जा के साथ सौर ऊर्जा पैदा करने वाले 1 मेगा वाट एसीकृत ऊर्जा संयंत्र से बिजली की बिक्री के लिए समझौता।

ऊर्जा सृजन की उच्च लागत और एमआईपीएल द्वारा ऊर्जा आपूर्ति दर बढ़ाने से मना करने के कारण, प्रदर्शन अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, नेडो की अनुमति से पीपीए को आपसी सहमति से 20.02.2020 को बंद कर दिया गया है।

(iii) "उपरोक्त नोट 39 (ii) के अनुसार पीपीए को बंद करने के बाद, मेसर्स टोयोटा गोसी मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीजीएमआईपीएल), एक कंपनी जिसका नीमराना में संयंत्र है, के साथ 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति के लिए, सौर ऊर्जा की आपूर्ति शुरू होने की तारीख से 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए, एक और पीपीए 12.02.2020 को क्रियान्वित किया गया है, जिसे आपसी सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार और 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिजली आपूर्ति का यूनिट मूल्य उस तारीख से पहले 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 4.60 प्रति किलोवाट घंटे की दर पर स्थिर रहेगा जब सहायक कंपनी टीजीएमआईपीएल को सौर ऊर्जा की आपूर्ति शुरू करती है। बिजली आपूर्ति दर को छठे वर्ष की शुरुआत में आपसी सहमति के नियमों और शर्तों पर ऊपर की ओर संशोधित किया जाएगा।

राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 के तहत सौर ऊर्जा की तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए टीजीएमआईपीएल के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के संदर्भ में, सहायक कंपनी ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल), राजस्थान राज्य सरकार की नोडल एजेंसी, के साथ खुद को पंजीकृत किया है। नतीजतन, बिजली केता को बिजली निकासी योजना में सीधे आपूर्ति से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के राज्य ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति में परिवर्तन हो रहा है।

बिजली निकासी योजना में बदलाव के कारण, जो संपत्तियां अब उपयोग में नहीं थीं, उनका निपटान ई-नीलामी प्रक्रिया द्वारा एमएसटीसी लिमिटेड, भारत सरकार के एक उद्यम जो इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण में है, के माध्यम से किया गया है।"

**40 सहायक कंपनी द्वारा लेखांकन नीति में परिवर्तन**

लेखा नीति सं. 2.4.xiv में परिवर्तन के कारण, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों के अनुसार, 31 मार्च 2020 को भूमि निर्माण और बागवानी कार्यों का परिलेखन मूल्य 5,55,310/- रुपए आरक्षित और अधिशेष से वसूल किया गया है। लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण चालू वित्तीय वर्ष के लाभ-हानि से ₹ 2,52,058/- की मूल्यह्रास राशि वसूल नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष के लिए सहायक कंपनी के लाभ में ₹ 2,52,058/- की वृद्धि हुई है।

**41** सहायक कंपनी के रूप में समेकित उद्यमों की कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक अतिरिक्त जानकारी

| कंपनी का नाम | शुद्ध परिसंपत्तियां अर्थात कुल दायित्वों को घटाते हुए कुल परिसंपत्तियां | | लाभ/हानि में हिस्सा | |
|---|---|---|---|---|
| | समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में | धन राशि (₹) | समेकित लाभ/हानि के % के रूप में | धन राशि (₹) |
| **धारक कंपनी** | | | | |
| नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) | 98.71 | 8,20,74,48,365 | 100.15 | 12,41,43,433 |
| **पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी** | | | | |
| एमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित) | 1.29 | 10,75,92,068 | (0.15) | (1,84,587) |

**42** वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुसार जहां कहीं आवश्यक समझा गया हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:संयोजित किया गया है।

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
**कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी**
**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**
**फर्म पंजीकरण सं. 000346एन**

हस्ता.

**श्री अंकुर गोयल**
**(साझेदार)**
**(सदस्यता संख्या 099143)**

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 10 अगस्त, 2021
यूडीआईएन: 21099143एएएसीजे1596

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता.

**(के. संजय मूर्ति)**
**सीईओ एवं प्रबंध निदेशक**
**[डीआईएन : 03532374]**

हस्ता.

**(पी. के. अग्रवाल)**
**(मुख्य वित्तीय अधिकारी)**

हस्ता.

**(राजेंद्र रत्नू)**
**निदेशक**
**(डीआईएन : 02855304)**

हस्ता.

**(अभिषेक चौधरी)**
**(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)**

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)**

**फार्म एओसी-1**

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम प्रतिबंध जिसे नियम 5 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार)

**कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहयोगी कंपनी, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को समाविष्ट करने वाला विवरण**

**भाग क : सहयोगी कंपनियां**

| क्र.सं. | सहयोगी कंपनी का नाम | एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित) |
|---|---|---|
| 1 | तिथि जब सहायक कंपनी को अधिगृहीत किया गया था | 18 मार्च, 2014 |
| 2 | सहयोगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से किसी प्रकार विभिन्न हो | धारक कंपनी के समान |
| 3 | रिपोर्टिंग मुद्रा | भारतीय रुपए |
| 4 | शेयर पूंजी | 13,00,00,000 |
| 5 | आरक्षित एवं अधिशेष | 10,91,88,274 |
| 6 | कुल परिसंपत्तियां | 30,66,88,500 |
| 7 | कुल दायित्वाएं | 6,74,00,226 |
| 8 | निवेश | कुछ नहीं |
| 9 | बिक्री | 6,14,34,377 |
| 10 | कर पूर्व लाभ/(हानि) | 36,38,377 |
| 11 | कर के लिए प्रावधान | 65,37,960 |
| 12 | कर के पश्चात लाभ/(हानि) | (28,99,583) |
| 13 | प्रस्तावित लाभांश | कुछ नहीं |
| 14 | शेयरधारिता का % | 100% |

**भाग ख: संबद्ध/संयुक्त उपक्रम**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संबंध अथवा संयुक्त उपक्रमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू किया जाना शेष है | कुछ नहीं |
| 2. | वर्ष के दौरान परिसमाप्त की गई अथवा बेचे गए संबंध अथवा संयुक्त उपक्रमों के नाम | कुछ नहीं |
| | | |

**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड**
**के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता.

**(के. संजय मूर्ति)**
**सीईओ एवं प्रबंध निदेशक**
**(डीआईएन : 03532374)**

हस्ता.

**(राजेंद्र रत्नू)**
**निदेशक**
**(डीआईएन : 02855304)**

हस्ता.

**(पी. के. अग्रवाल)**

**(मुख्य वित्तीय अधिकारी)**

हस्ता.

**(अभिषेक चौधरी)**

**(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)**

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 10 अगस्त, 2021

# NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NICDC LTD.)

## (formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

## CIN: U45400DL2008PLC172316

NICDC
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
*India Reimagined*

# FINANCIAL YEAR 2020-21

**Proforma for furnishing the relevant details in respact of the Organization referred to on para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha Secretariat**

**Name of the Ministry**: Ministry of Commerce and Industry
**Name of the Department**: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
**Name of Organization**: National Industrial Corridor Development Corporation Limited
(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

| Sr. No. | Particulars | Remark | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc. | Corporation | | |
| 2 | The Year of inception of the organisation | 2008 | | |
| 3 | Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned | Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) | | |
| 4 | The Act/Rule/Regulation governing the Organization | Companies Act, 2013<br>and<br>General Financial Rules (GFR), 2017 | | |
| 5 | Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? **(Indicate YES or NO)**<br>*(Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)* | Yes<br>(Rule 237 of GFR, 2017 are attached) | | |
| 6 | If answer to SL No.5 above is **YES**, indicate the time frame stipulated therein for laying these reports. | 31st December | | |
| 7 | Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Depattment concerned. | Annually | | |
| 8 | Whether the Annual Reports and Audited Accounts cifthe Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception **(Indicate YES or NO)** | Yes | | |
| 9 | If answer to SL No. 8 above is **YES**, indicate the date(s) of laying the requisite documents on the table of the House for the last three years i.e., 2016-17, 2017-18 and 2018-19. | Year | Lok Sabha | Raiya Sabha |
| | | FY 2017-18 | 17.12.2018 | 17.12.2018 |
| | | FY 2018-19 | 04.12.2019 | 06.12.2019 |
| | | FY 2019-20 | 15.12.2021 | 12.02.2021 |
| 10 | If the answer to SL. No. 8 above is **NO**; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House. | Not Applicable | | |

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

**Rule 236** **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

**Rule 236** **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

**Rule 237** **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

**Rule 238** **(1) Utilization Certificates.** In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

**Rule 238** **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

**Rule 238** **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

**Rule 238** **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

# 13th ANNUAL REPORT
# AND
# FINANCIAL STATEMENTS
# (F.Y. 2020-21)

NICDC
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
*India Reimagined*

# NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NICDC LTD.)

## (formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

**CIN: U45400DL2008PLC172316**

# CONTENTS


| S. No. | PARTICULARS | PAGE No. |
|---|---|---|
| 1. | COMPANY PROFILE | 142 – 144 |
| 2. | CHAIRMAN'S MESSAGE | 145 – 146 |
| 3. | CORPORATE INFORMATION | 147 |
| 4. | ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE | 148 – 157 |
| 5. | BOARD OF DIRECTOR'S REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021 | 158 – 193 |
| 6. | C&AG AUDIT REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021 | 194 – 196 |
| 7. | AUDITOR'S REPORT ON STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021 | 197 – 209 |
| 8. | STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021 | 210 – 232 |
| 9. | AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021 | 233 – 240 |
| 10. | CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021 | 241 - 267 |

## ABOUT THE COMPANY

In order to embark on the process of planned urbanization with manufacturing as the key economic driver and to give a strong impetus to the country's industrial/ manufacturing development, the Government of India (GoI) announced the concept of Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project as the first Industrial Corridor in 2007. The project aims to create smart, sustainable industrial cities by leveraging the high speed, high-capacity connectivity backbone provided by the Western Dedicated Freight Corridor (DFC) to reduce logistic costs in an enabling policy framework. A Special Purpose Vehicle i.e. Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) was accordingly incorporated in January, 2008 for the development and implementation of DMIC project.

To facilitate the funding for the development of a world class infrastructure at the Industrial Cities for DMIC as a global manufacturing and investment destination, the Government of India has approved the creation of a dedicated fund with a corpus known as the DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) in September, 2011. Later on, for coordinated and unified development of all the Industrial Corridors including DMIC, GoI has approved the expansion of the scope of existing DMIC-PITF and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT). NICDIT functions under the administrative control of DPIIT.

Under the project, greenfield smart cities are being developed by using funds from Govt. of India and investment into project SPV's either as equity or debt directly by NICDIT from Project Implementation Funds (PIF) and land coming as equity from the respective State Govt. DMICDC is acting as a project development Company which undertakes various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new greenfield industrial smart cities. It also undertakes the project development of various individual projects. In order to carry out these project development activities, Project Development Funds (PDF) is being released to DMICDC as a grant to carry out various project development activities.

DMICDC functions as a knowledge partner to NICDIT, downstream city level SPV's and Project level SPV's. The scope of DMICDC Limited has expanded due to expansion of the scope and mandate of NICDIT and DMICDC has been entrusted with the responsibility of carrying out project development activities for all Industrial Corridor Projects which has been announced by Govt. of India or which will come up in the future. Therefore, the name of the company was changed from DMICDC to NICDC (National Industrial Corridor Development Corporation Limited) with effect from 17th February, 2020.

The current equity shareholders in NICDC include Government of India (49%), represented through the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (26%) and financial institutions such as Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) (19.9%), India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) (4.1%) & Life Insurance Corporation (LIC) (1.0%).

**Company Institutional and Financial Structure: -**

The Government of India in 2011 approved the financial and institutional structure for DMIC Project with a budgetary support of Rs. 17,500 crore (at an average of Rs.2,500 crore for each of the 7 nodes subject to a maximum of Rs.3,000 crore) to be provided over a period of five years for the development of industrial cities in Phase-I of the DMIC project. An additional corpus of Rs. 1,000 crore has been provided as budgetary support to carry out project development under DMIC.

Further, for coordinated and unified development of various other Industrial Corridor projects including Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project, Govt. of India had expanded the mandate of existing DMIC PITF and renamed it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) in December, 2016.

In addition to the corpus of Rs. 18,500 crore, an additional corpus of Rs. 1,584 crore (including Rs 84 crore for meeting administrative expenditure of NICDIT) was sanctioned totalling to Rs. 20,084 crore for undertaking various project development and implementation related works for all the other corridor projects.

The budgetary support from GoI flows to NICDIT and NICDIT provides equity and/or debt to Special Purpose Vehicles (SPVs) incorporated as joint ventures between GoI and the respective State Governments for developing Industrial cities /nodes/projects. Investment into project SPV's is done either as equity or debt directly by NICDIT and respective State Govt. transfers land as equity.

Govt. of India is developing various Industrial Corridor projects and NICDC has been entrusted with the responsibility of carrying out project development activities in respect of Eleven (11) Industrial corridors comprising of 32 nodes/projects to be developed in 04 Phases till 2024-25 as part of the National Master Plan on multimodal connectivity.

Industrial Corridor Programme is aimed at supplementing the efforts for realising the manufacturing potential of the country and raising its contribution to GDP. Enabled with ease of access, the industrial corridors are conceived to foster global manufacturing and investment destination hubs and smart cities with the best in-class infrastructure. The objective is to create quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments into manufacturing and positioning India as a strong player in the Global Value Chain. The industrial corridor nodes are being developed as sustainable, smart and resilient manufacturing hubs. Under the Industrial Corridor Programme Greenfield Industrial Smart Cities/nodes are developed with sustainable infrastructure & make available Plug and Play infrastructure at the plot level. State Govt.(s) are required to make available contiguous land parcels with confirmed allocation of Water/Power and site connectivity for the development of these industrial nodes.

Trunk infrastructure activities have been completed at Integrated Industrial Township (IITGN) at Greater Noida (747 acres), Uttar Pradesh and Integrated Industrial Township (IITVUL) at Vikram Udyogpuri (1,100 acres), Ujjain in Madhya Pradesh. Whereas, trunk infrastructure activities are nearing completion at Dholera Special Investment Region (DSIR) (22.5 sq. kms), Gujarat and Shendra Bidkin Industrial Area (AURIC) (18.55 sq. kms), Aurangabad, Maharashtra.

A total of 126 plots admeasuring nearly 742.75 acres have been allotted to companies with investment to the tune of more than Rs. 16,750 crore including investors like HYOSUNG (South Korea), NLMK (Russia), HAIER (China), TATA Chemicals & AMUL so far.

Apart from the above allotted plots, 6,882 acres [Shendra 1,233 acres; Bidkin 1,746 acres; Dholera 2,619 acres, Vikram Udyogpuri 841 acres; Greater Noida 443 acres)] of developed land parcels are available for immediate allotment to Industry & other uses (e.g., Commercial & Residential).

# Chairman's Message

Dear Shareholders,

I welcome all the esteemed shareholders to the 13th Annual General Meeting of the Company. It gives me immense pleasure to present your Company's operational performance for the financial year 2020-21. The last year has been tough and challenging due to Covid-19 pandemic. Infrastructure Sector also got severely impacted due to labour migration, difficulties in their re-mobilization, disrupted supply chains leading to delays in project planning and execution. Despite these difficulties and challenges, your Company was able to perform and achieve its goals.

Trunk infrastructure activities have been completed at Integrated Industrial Township (IITGN) at Greater Noida (747 acre), Uttar Pradesh and Integrated Industrial Township (IITVUL) at Vikram Udyogpuri (1,100 acre), Ujjain in Madhya Pradesh and are nearing completion at Dholera Special Investment Region (DSIR) (22.5 sq. km), Gujarat and Shendra Bidkin Industrial Area (AURIC) (18.55 sq. km), Aurangabad. Thus far, total of 11,002.64 acre of land has been developed and is available for allotment out of which 6,365.31 acre is for industrial use and 4637.33 acre is for commercial, residential and institutional uses.

Further, total 138 plots admeasuring nearly 758 acre have been allotted with anchor investors like HYOSUNG (South Korea), NLMK (Russia), HAIER (China), TATA Chemicals & AMUL attracting a combined investment of Rs. 16,750 crore. During the year, funds amounting to Rs. 2600 Crore were sanctioned and released to NICDIT for project development and implementation, the highest ever budget allocation and utilization. These funds have been released to the SPVs.

On 30th December 2020, Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) had approved the development of 11 (Eleven) Industrial Corridors with 32 nodes/projects proposed to be developed in 04 phases by 2024-25. Further, the proposals for construction of various trunk infrastructure for Krishnapatnam Industrial Area (Andhra Pradesh), Tumakuru Industrial Area (Karnataka) and Multi Modal Logistics Hub (MMLH) & Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Greater Noida (Uttar Pradesh) with a combined estimated cost of Rs. 7,725.05 crore have also been approved.

NICDC has been mandated for development of these Industrial corridors. Government has approved PM GatiShakti National Master Plan for providing multimodal connectivity to these economic zones. Hon'ble Prime Minister has launched PM GatiShakti National Master Plan on 13th October 2021. PM GatiShakti is a holistic infrastructure development programme which will facilitate integration of various infrastructure projects of all concerned Ministries and will address the missing gaps to ensure seamless movement of people, goods & services. It aims to enhance ease of living, ease of doing business, minimize disruptions and expedite completion of works with cost efficiency. Your company was closely involved in the preparation of this National Master Plan.

NICDC's Logistics Data Bank (LDB) project is currently operational across 17 Ports in India covering approximately 170 Container Freight Stations /Inland Container Depots, around 60 Toll plazas, 4 Integrated Check Posts and 9 Special Economic Zones for providing complete enhanced visibility of EXIM container movement. Through LDB 42 million containers have so far been successfully tracked.

Further, your Company also acts as a knowledge partner to one of the Asia's largest Convention and Exhibition Centre Project i.e., India International Convention and Exhibition Centre Limited (IICC) at Dwarka, New Delhi where the construction activities are in full swing and the project is expected to be completed next year.

Your Company has sought financial assistance to the tune of USD 500 million from Asian Bank Development Bank as Policy Based Loan (PBL) for Industrial Corridor Development Programme which will be released in two tranches. Recently, the Board of ADB has approved first tranche of loan of USD 250 million.

We have travelled a long way since project completion, yet the remaining challenges which any emerging economy face, continue to persist. The primary ones being the accelerated rate of urbanisation, optimum utilization of available resources and maintaining the integration amongst various development initiatives to achieve concerted economic outcomes. All these factors demand greater degree of involvement and devotion on our part. The projects being envisaged under Industrial Corridor Project address these challenges by providing infrastructure that is sustainable, reliable and resilient thus, meeting world-class benchmarks. I strongly believe that we shall stand the test of time in striving to our best for delivering results.

Our outlook for the future remains positive which is strongly reflected in our resolve to propel economic progress by means of sustained and integrated development with inclusive growth. With our expertise in creating smart infrastructure facilities, we assume greater accountability in the national efforts to steer India's transformation to a first-world economy. I would like to put on record my appreciation to our members of the Board of Directors for their unstinted support, exemplary foresight and generous contribution in terms of valuable advice. Lastly, our proficient manpower deserves commendation and credit for their stellar work and our resilience as a multifunctional organization.

Sd/-
(Anurag Jain)
Chairman

# CORPORATE INFORMATION

## BOARD OF DIRECTORS

Shri Anurag Jain, IAS
*Chairman*

Shri Shailendra Singh, IAS
*Director*

Shri Amrit Lal Meena, IAS
*Chief Executive Officer and Managing Director*

Shri Rajendra Ratnoo, IAS
*Director*

Shri Kazushige Gobe
*Director*

Shri Toshihiko Kurihara
*Director*

Shri M. Nagaraj
*Director*

Dr. Subrahmanyam Durvasula
*Director*

## AUDIT COMMITTEE

Shri Rajendra Ratnoo
*Director*

Shri Toshihiko Kurihara
*Director*

Dr. Subrahmanyam Durvasula
*Director*

## NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Shri Rajendra Ratnoo
*Director*

Shri Toshihiko Kurihara
*Director*

Dr. Subrahmanyam Durvasula
*Director*

## CORPORATE SOCIAL RESONSIBILITY COMMITTEE

Shri Rajendra Ratnoo
*Director*

Shri Toshihiko Kurihara
*Director*

Dr. Subrahmanyam Durvasula
*Director*

## CHIEF FINANCIAL OFFICER

Shri Pradeep Kumar Agarwal

## VP-CORPORATE AFFAIRS, HR & COMPANY SECRETARY

Shri Abhishek Chauddhary

## STATUTORY AUDITOR

M/s S.P Chopra & Associates,
Chartered Accountants

## INTERNAL AUDITOR

M/s VSPV & Co., Chartered Accountants

## SECRETARIAL AUDITOR

M/s Vikas Gera & Associates, Company Secretaries

## BANKERS

Central Bank of India , Hotel Ashok, Chanakyapuri, New Delhi

## REGISTERED OFFICE

08th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building, 124, Connaught Place, New Delhi – 110001

# ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE

# NOTICE

Notice is hereby given that the 13th (Thirteenth) Annual General Meeting of the Members of National Industrial Corridor Development Corporation Limited (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) will be held on Monday, the 13th day of December, 2021 at 04:30 P.M. at the Registered Office of the Company situated at 08th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi -110001 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business: -

**ORDINARY BUSINESS: -**

1. To receive, consider & adopt the Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) as at 31st March, 2021 and the reports of the Board of Directors' and the Auditor's thereon for the period ended on that date.

2. **To appoint a Director in place of Shri Rajendra Ratnoo, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment** and in this regard to consider, and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following resolution as an ***Ordinary Resolution*: -**

   "**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Rajendra Ratnoo, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible has offered himself for re-appointment, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

3. **To appoint a Director in place of Shri Toshihiko Kurihara, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment** and in this regard to consider, and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following resolution as an ***Ordinary Resolution*: -**

   "**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Toshihiko Kurihara, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible has offered himself for re-appointment, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

4. **To appoint and fix remuneration of Statutory Auditors of the Company as may be nominated by the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG)** and in this regard to consider, and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as an ***Ordinary Resolution*: -**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the appointment of M/s S. P. Chopra & Co, Chartered Accountants, New Delhi (ICAI Firm Registration No. 000346N) as nominated by the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) as the Statutory Auditor of the Company for the financial year 2021-22 vide its letter No. CA. V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC (0)/216 dated 18th August, 2021, a copy of which has been placed before the meeting, be and is hereby approved/taken note of."

"**RESOLVED FURTHER THAT** CEO & Managing Director of the Company be and is hereby authorized to fix the terms and conditions including the determination of the audit fee payable to the Statutory Auditors as recommended by the office of the C&AG."

**SPECIAL BUSINESS: -**

5. **To regularize the appointment of Shri Anurag Jain (DIN:01779759) as Director of the Company** and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an ***Ordinary Resolution*: -**

"**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Anurag Jain (DIN:01779759), who was appointed as an Additional Director with effect from 27th September, 2021 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting, in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 of the Act, proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."

6. **To regularize the appointment of Shri Kazushige Gobe (DIN:09276761) as Director of the Company** and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an ***Ordinary Resolution*: -**

"**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Kazushige Gobe (DIN:09276761) who was appointed as an Additional Director with effect from 10th August, 2021 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting, in respect of whom the Company has received a notice in writing from him under Section 160 of the Act, proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."

7. **To regularize the appointment of Shri Amrit Lal Meena (DIN:06626193) as Director of the Company** and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an ***Ordinary Resolution*: -**

**"RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Amrit Lal Meena (DIN:06626193) who was appointed as an Additional Director with effect from 05th November, 2021 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting, in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 of the Act, proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."

8. **To appoint Shri Amrit Lal Meena (DIN:06626193) as Managing Director of the Company** and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an ***Ordinary Resolution*: -**

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 196, 197 read with Schedule V and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial personnel) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment (s) thereof for the time being in force), the consent of the members be and is hereby accorded for the appointment of Shri Amrit Lal Meena, (DIN: 06626193) as CEO & Managing Director of the Company for a period of 3 years with effect from 05th November, 2021 or until further order whichever is earlier, liable to retire by rotation."

**"RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to the Section 203 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013, Shri Amrit Lal Meena, CEO & Managing Director of the Company be and is hereby designated as Key Managerial Personnel (KMP) of the Company with effect from 05th November, 2021."

**"RESOLVED FURTHER THAT** Shri Amrit Lal Meena shall not be entitled to any remuneration or perquisite as CEO & Managing Director of the Company."

**By order of the Board**
**For National Industrial Corridor Development Corporation limited**

**Sd/-**

**(Abhishek Chauddhary)**
**VP-Corporate Affairs, HR**
**& Company Secretary**
**Membership No. - F6701**

**Date: 16th November, 2021**
**Place: New Delhi**

## NOTES:

1. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ('MCA") has vide its General Circular dated 13th January, 2021 read with General Circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 and 05th May, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') has permitted the holding of Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members.

2. As per the Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

3. The Members can join AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting.

4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

5. Corporate members are requested to send a duly certified copy of the Board Resolution / Power of Attorney authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the Annual General Meeting.

6. In conformity with the provisions of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out at item nos. 5 to 8 to be transacted at the Annual General Meeting (AGM) is annexed hereto.

7. Details of Directors seeking appointment at the ensuing Meeting are provided in the "Annexure" to the notice.

8. The Notice convening the 13th AGM and Annual Report 2020-21 has been uploaded on the website of the Company at www.nicdc.in.

9. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM may send their request in writing to the Company at abhishekchaudhary@nicdc.in.

10. Members may attend the AGM, by following the invitation link sent to their registered email ID. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

## EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013: -

### ITEM NO.2

Shri Rajendra Ratnoo, Director of the Company, liable to retire by rotation, vacates his office by rotation at this Annual General Meeting. Shri Rajendra Ratnoo being eligible offers himself for re-appointment and is proposed to be re-appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Hence the resolution is proposed.

Except Shri Rajendra Ratnoo, being an appointee, none of the Director and Key Managerial personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 2 of this notice.

### ITEM NO.3

Shri Toshihiko Kurihara, Director of the Company, liable to retire by rotation, vacates his office by rotation at this Annual General Meeting. Shri Toshihiko Kurihara being eligible offers himself for re-appointment and is proposed to be re-appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Hence the resolution is proposed.

Except Shri Toshihiko Kurihara, being an appointee, none of the Directors and Key Managerial personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 3 of this notice.

### ITEM NO. 4

The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) vide its letter No. CA. V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC (0)/216 dated 18th August, 2021 has nominated M/s S. P. Chopra & Co., Chartered Accountants as the Statutory Auditor of the Company as per Section 139 of the Companies Act, 2013 for the financial year 2021-22. The Supplementary Audit of the Company for the financial year 2021-22 pursuant to Section 143 (6) & (7) of the Companies Act, 2013 has been entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex- Officio Member Audit Board - I.

Hence the resolution is proposed.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 4 of this notice.

### ITEM NO.5:

Shri Anurag Jain (DIN: 01779759) was appointed as an Additional Director by the Board of Directors w.e.f. 27th September, 2021 in accordance with the provisions of Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013, the Additional Director holds office up to the date of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notice in writing from a member under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing his candidature for the office of Director of the Company.

Except Shri Anurag Jain being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No.5 of this notice.

The Board recommends the resolution set forth in item no. 5 for approval of the members.

**ITEM NO.6:**

Shri Kazushige Gobe (DIN: 09276761) was appointed as an Additional Director by the Board of Directors w.e.f. 10th August, 2021 in accordance with the provisions of Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013, the Additional Director holds office up to the date of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notice in writing from him under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing his candidature for the office of Director of the Company.

Except Shri Kazushige Gobe being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 6 of this notice.

The Board recommends the resolution set forth in item no. 6 for approval of the members.

**ITEM NO. 7 & 8:**

Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry vide its office order no. P-40022/10/2018-ID.I dated 05th November, 2021 has communicated that consequent upon appointment of Shri K. Sanjay Murthy, CEO & MD, National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC Ltd.) as Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education; Shri Amrit Lal Meena, Additional Secretary, (Logistics), Department of Commerce shall hold additional charge to the post of CEO & MD, National Industrial Corridor Development Corporation Limited for a period of 3 years with effect from 05th November, 2021 till new appointment to the post is made or until further order, whichever is earlier.

Accordingly, as per Section 161 (1) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company in its meeting held on 08th November, 2021 has appointed Shri Amrit Lal Meena as an Additional Director on the Board of the Company and as per Section 160 of the Companies Act, 2013 also recommended his appointment as Director to the Shareholders of the Company. The Company has received notice in writing from a member under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing his candidature for the office of Director of the Company.

Further, the Board of Directors has also appointed Shri Amrit Lal Meena as CEO & Managing Director on the Board of the Company, subject to the approval of shareholders of the Company.

Except Shri Amrit Lal Meena being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 7 & 8 of this notice.

The Board recommends the resolution set forth in item no. 7 & 8 for approval of the members.

**BY ORDER OF THE BOARD**
**For National Industrial Corridor Development Corporation Limited**

**Sd/-**

**(Abhishek Chauddhary)**
**VP-Corporate Affairs, HR**
**& Company Secretary**
**Membership No. -F6701**

**Date: 16th November, 2021**
**Place: New Delhi**

## BRIEF RESUME OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT AT 13TH ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to Clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India

| Name | Shri Anurag Jain (DIN: 01779759) | Shri Kazushige Gobe (DIN:09276761) |
|---|---|---|
| Age | 56 Years | 49 years |
| Qualification | B. Tech in Electrical Engineering from IIT, Kharagpur. | Bachelor's degree in Law from University of Tokyo. |
| Experience | Shri Anurag Jain is an Indian Administrative Service (IAS) Officer of 1989 Batch in Madhya Pradesh Cadre. He assumed the charge of office of Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) on 27th September, 2021.<br><br>He has vast experience of Finance Sector, Information Technology, District Administration and Rural Development. He has served as Secretary to Chief Minister, Madhya Pradesh (5.5 years) and Joint Secretary to Prime Minister (3.5 years). He was Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of Madhya Pradesh and was heading Finance Department for 2 years. Before assuming present assignment, he was Vice Chairman of Delhi Development Authority.<br><br>He as Joint Secretary in the Ministry of Finance is credited with conceptualizing and implementing one of the most successful initiatives 'Pradhan Mantri Jan Dhan | Shri Kazushige Gobe currently holds the position of Director General, Social Infrastructure Finance Department, Infrastructure and Environment Finance Group at Japan Bank for International Cooperation (JBIC). In his current assignment, he leads JBIC's global footprint in supporting social infrastructure projects including road, railways, OFN, telecom, ICT etc. He also supervises JBIC's operations in India.<br><br>Soon after completing his Bachelor's degree in Law from University of Tokyo in March 1994, he joined erstwhile Export Import Bank of Japan (now JBIC).<br><br>Over 26 years he gained rich experience across business sectors and organizational functions including treasury operations. He immensely contributed in supporting Japanese manufacturing companies in expanding their trade and investments across Asia, Latin America & Africa. Apart from manufacturing sector, he also supported overseas transportation sector projects from 2011 to 2013.<br><br>From 1998 to 2000, he was seconded to Japan Executive |

| | | |
|---|---|---|
| | Yojana', the largest financial inclusion programme in the World. As Secretary to Chief Minister, Madhya Pradesh, he was the prime mover of enactment of Public Service Delivery Management Act, an innovative concept adopted by more than a dozen States in the country. As Secretary, Information Technology, Govt. of Madhya Pradesh, he was instrumental in taking the State to top rungs in e-Readiness Assessment of States and Union Report | Director's Office in International Monetary Fund (IMF). He also served as Chief Representative of JBIC Representative office in Paris from 2017 to 2020 leading JBIC initiatives in EU member countries (except UK & Ireland) and other European and African countries.<br><br>In his previous role as Senior Advisor, he played a key role in the steering committee of Blue Dot Network, enhanced the Initiative of the Trilateral Infrastructure Partnership with USDFC and DFAT and designing policy for supporting global challenges of Japanese businesses. |
| **Terms and Conditions of appointment or re-appointment** | Appointment as per the provisions of the Companies Act, 2013. | Appointment as per the provisions of the Companies Act, 2013. |
| **Remuneration last drawn (including sitting fees, if any)** | - | - |
| **Remuneration proposed to be paid** | - | - |
| **Date of first appointment on the Board** | 27th September, 2021 | 10th August, 2021 |
| **No. of shares held in NICDC** | Nil | Nil |
| **Relationship with other Directors/ KMP** | No inter se related to any Director of the Company | No inter se related to any Director of the Company |
| **Number of meetings of the Board attended during the financial year 2020-21.** | Not applicable | Not applicable |
| **Directorship held in other companies** | Nil | Nil |
| **Membership/ Chairmanship of Committees of other companies** | Nil | Nil |

## BRIEF RESUME OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT AT 13TH ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to Clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India

| | |
|---|---|
| **Name** | **Shri Amrit Lal Meena** (DIN:06626193) |
| **Age** | 56 Years |
| **Qualification** | B. Tech in Electrical Engineering and Post-Graduation diploma in Public Policy and Management from IIM, Bangalore. |
| **Experience** | Shri Amrit Lal Meena, IAS is presently Additional Secretary (Logistics) in Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Earlier he was Secretary in Government of Bihar looked after various Departments including Rural Development, Urban Development, Building Corporation. He also worked as Principal Secretary / Additional Chief Secretary in Road Construction Department, Government of Bihar building a better and sustainable network of roads in Bihar. Roads and bridges infrastructure projects have got massive speed during his tenure. There has been commendable addition of new bridges on major rivers and four lanning of highways.<br><br>Shri Meena had earlier worked as Joint Secretary in Ministry of Food Processing Industries, Government of India. He had also worked for Ministry of rural Development, Government of India. He had served as District Magistrate in five districts of Bihar State for over nine years. |
| **Terms and Conditions of appointment or re-appointment** | Appointment as per the provisions of the Companies Act, 2013. |
| **Remuneration last drawn (including sitting fees, if any)** | - |
| **Remuneration proposed to be paid** | - |
| **Date of first appointment on the Board** | 05th November, 2021 |
| **No. of shares held in NICDC** | Nil |
| **Relationship with other Directors/ KMP** | No inter se related to any Director of the Company |
| **Number of meetings of the Board attended during the financial year 2020-21.** | Not applicable |
| **Directorship held in other companies** | Nil |
| **Membership/ Chairmanship of Committees of other companies** | Nil |

# BOARD OF DIRECTOR's REPORT

## DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors have pleasure in presenting the **13th (Thirteenth) Directors' Report** on the affairs of the Company for the year ended on 31st March, 2021.

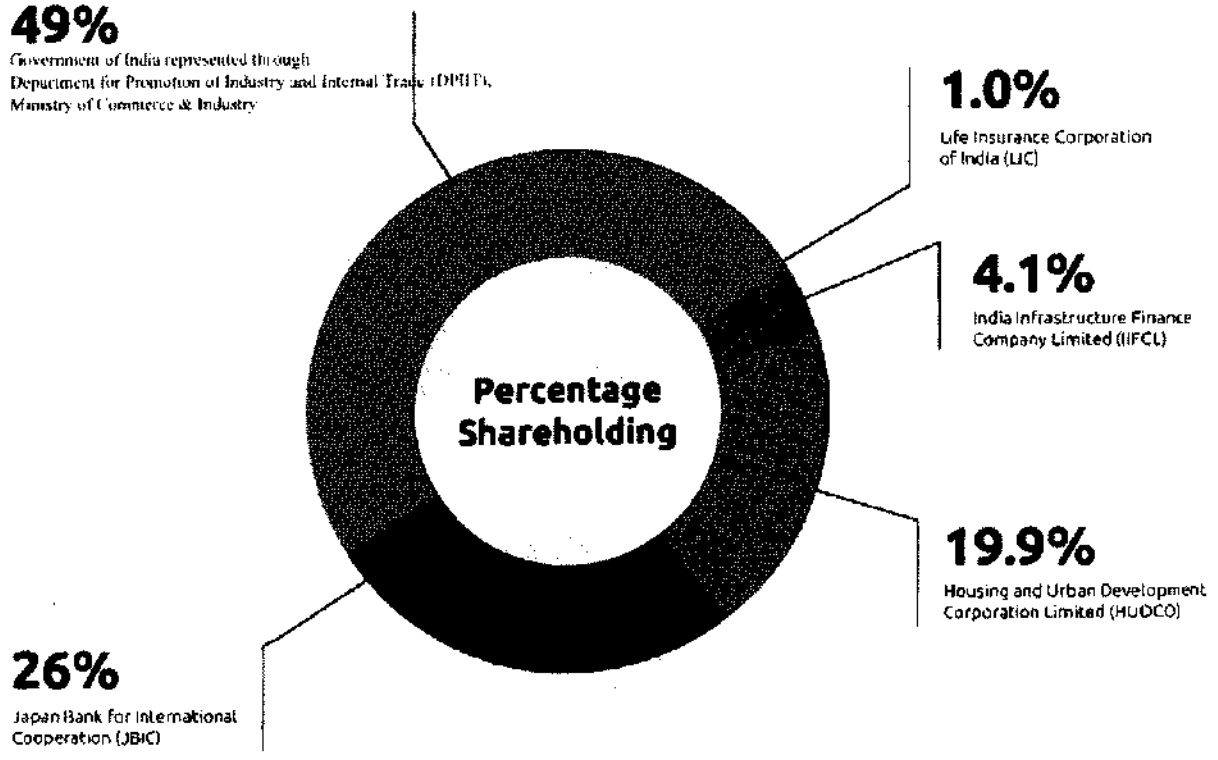
National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) is a Joint Venture Company incorporated between Government of India, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) and Life Insurance Corporation of India Ltd. (LIC).

The **Company is entrusted** with carrying out **project** development activities in respect of **various Industrial Corridor** Projects being **developed** or under implementation, under the flagship **National Industrial Corridor Development** Programme. The **Company is acting as** the project **development** partner **and knowledge** partner to varied **industrial townships,** industrial node/clusters and integrated manufacturing clusters.

Department for Promotion **of** Industry and **Internal Trade** (DPIIT), Ministry of **Commerce** & Industry has been **designated** as the Nodal **Agency from** Government of India **for the** Industrial Corridor Projects .

Industrial Corridor (IC) **Project is** a flagship **programme** of **Government** of India with the aim of creating futuristic **Industrial** Cities by **leveraging** the **"High Speed** - High Capacity" connectivity backbone provided by Dedicated Freight Corridor (DFC).

The shareholding pattern of the Company is as follows:



## 1. FINANCIAL STATEMENTS SUMMARY:

The Financial Statements summary of the Company for the financial year ended 31st March, 2021 is summarized below:

*(Amount in Rs.)*

| Particulars | 2020-21 | 2019-20 |
|---|---|---|
| Total Income | 32,14,27,948 | 22,52,42,116 |
| Total Expenses | 14,28,31,850 | 18,46,11,883 |
| Tax Expense | 5,21,51,825 | 1,15,83,966 |
| **Profit / (Loss) for the year after Tax** | **12,64,44,273** | **2,90,46,267** |

## 2. STATUS OF COMPANY'S AFFAIRS:

Industrial Corridor Programme is aimed at supplementing the efforts for realising the manufacturing potential of the country and raising its contribution to GDP. Enabled with ease of access, the industrial corridors are conceived to foster global manufacturing and investment destination hubs and smart cities with the best in-class infrastructure. The objective is to create quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments into manufacturing and positioning India as a strong player in the Global Value Chain. The industrial corridor nodes are being developed as sustainable, smart and resilient manufacturing hubs. Under the Industrial Corridor Programme Greenfield Industrial Smart Cities/nodes are developed with sustainable infrastructure & make available Plug and Play infrastructure at the plot level. State Govt.(s) are required to make available contiguous land parcels with confirmed allocation of Water/Power and site connectivity for the development of these industrial nodes.

GoI has approved the development of 11 Industrial Corridors with 32 Projects to be developed in 04 phases forming part of National Infrastructure Pipeline (NIP).

### A. Delhi Mumbai Industrial Corridor Project

Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) was the first Industrial Corridor project which was announced and various projects were approved by Govt. of India in 2014-15 wherein substantial progress has been achieved in last couple of years. Details of progress are as follows:

#### 1. Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat:

- DSIR has been planned over an area of approximately 920 sq. km and Phase I Activation area of 22.5 sq. km has been carved out wherein trunk infrastructure works are nearing completion;
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 2784.82 crore divided into five packages for activation area;
- State Govt. has transferred 44.26 sq. kms to DICDL (SPV) and matching equity amounting to Rs. 2551.94 crore has been released;
- 04 plots admeasuring 245 acres have been allotted with TATA Chemicals as anchor investor;

- 1,290 acres industrial land is readily available for allotment;
- Out of the 1000 MW of Solar Park, 300 MW awarded to Tata Solar Power Ltd.;
- Further, as part of regional connectivity to DSIR, external connectivity projects of 6-lane greenfield Expressway from Ahmedabad to Dholera by NHAI, award of construction packages completed, Dholera International Airport and Bhimnath Dholera Rail link are being implemented;
- NICDIT has approved the inclusion of Mandal-Becharaji Special Investment Region (MBSIR) covering an area of 102 sq. kms in the state of Gujarat as 2nd node of DMIC under National Industrial Corridor Programme.

2. **Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA), Maharashtra**

- Part I of SBIA covers an area of 40.2 sq. km;
- State Govt. has transferred entire 8.39 sq kms for Shendra Industrial Area and 28.8 sq. kms for Bidkin Industrial Area to the SPV. Matching equity amounting to Rs. 602.80 crore and 2397.20 crore respectively has also been released;
- For Shendra Industrial Area, GoI has approved the tender packages for various infrastructure components for Rs. 1533 crore. Major trunk infrastructure packages have been completed;
- Hon'ble Prime Minister has dedicated the project to the nation on 7th September, 2019;
- For Shendra, land allotment policy has been finalized and 93 plots admeasuring 310 acres have been allotted including one to HYOSUNG (100 acres) as the anchor investor. 09 companies have started their commercial operations as well;
- For Bidkin Industrial Area, GoI has approved the infrastructure packages worth Rs. 6414.21 crore to be developed in 3 phases. The trunk infrastructure works for Sector A (10.32 sq. km) are nearing completion;
- 1,350 acres industrial land is readily available for allotment in SBIA.

3. **Integrated Industrial Township Project, Greater Noida, Uttar Pradesh**

- Land admeasuring 747.5 acres has been transferred to the SPV of the project and matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released;
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 1,097.5 crore. Major trunk infrastructure works have been completed;
- Land allotment policy has been finalized and 05 plots admeasuring 153.89 acres have been allotted with HAIER (123.7 acres) as the anchor investor;
- 170 acres Industrial Land is readily available for allotment.

4. **Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain, Madhya Pradesh**

- State Govt. has transferred 1026 acres land to the SPV and matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released;

- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 749.1 crore. Major trunk infrastructure works have been completed;
- Land allotment policy has been finalized and 04 plot admeasuring 31 acres with AMUL as anchor investor;
- 450 acres of Industrial Land is readily available for allotment.

5. **Khushkheda Bhiwadi Neemrana Investment Region (KBNIR), Rajasthan**

- State Govt. on 12th October, 2020 informed that Development Plan of KBNIR has been notified as Special Investment Region (SIR);
- RIICO (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) has been appointed as Regional Development Authority;
- Consultant for detailed master planning and preliminary engineering for an area of 558 Ha has been appointed in April, 2021.

6. **Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA), Rajasthan**

- State Govt. on 12th October, 2020 informed that Development Plan of JPMIA has been notified as Special Investment Region (SIR);
- Consultant appointed for detailed master planning and preliminary engineering in March 2021 for an area of 2659 Ha for development in two phases;
- 700 Ha out of 1459 Ha (Phase I) area is in possession of State Govt.

7. **Dighi Port Industrial Area (DPIA), Maharashtra**

- In Jan, 2021, State Govt. confirmed availability of 2,402 Ha (5,935 acres) of land out of which 1,466 Ha (3,622 acres) is in possession of State Govt.
- Detailed Master planning and preliminary engineering works for the land parcels underway

**B. Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and its extension to Kochi via Coimbatore**

1. **Krishnapatnam node in Andhra Pradesh**

- Out of 12,798 acres, detailed master planning and preliminary engineering activities for an area of 2,500 acres as Activation Area have been completed;
- Project was approved by GoI on 30th December, 2020;
- State Govt. has transferred 1814.51 acres land to SPV and matching equity amounting to Rs. 453.22 crore has been released;
- EPC tendering works for implementation of trunk infrastructure is being taken up.

2. **Tumakuru node in Karnataka**

- Out of 8,483 acres, detailed master planning and preliminary engineering activities for an area of 1,736 acres as Activation Area has been completed;
- Project was approved by GoI on 30th December, 2020;
- State Govt. has transferred 1668.30 acres land to SPV and matching equity amounting to Rs. 586.74 crore has been released;
- Bids received for EPC tender for appointment of contractor for implementation of trunk infrastructure are under evaluation.

3. **Ponneri node in Tamil Nadu**

- Consultant appointed in Oct 2020 for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for an area of 4,000 acres;
- In May, 2021, State Govt. has informed that approx. 3,375 acres is available and has been notified for Ponneri industrial area.

C. **CBIC extension to Kochi via Coimbatore:**

1. **Palakkad node in Kerala**

- Land area of 1,878 acres has been identified and notified by State Govt. and acquisition process underway;
- Consultant has been appointed for detailed master planning and preliminary engineering in September, 2020.

2. **Dharmapuri node in Tamil Nadu**

- Land area of 1,773 acres has been identified by State Govt.;
- Consultant has been appointed for detailed master planning and preliminary engineering in September, 2020.

D. **Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC)**

1. **Raghunathpur, 2,483 acres in West Bengal**

- Detailed Master Planning has been completed and activities related to Environmental Clearance for the project is underway;
- As per the latest communication received from WBIDC dated 22nd June, 2021, the project is on hold pending clarity about funding strategy of EDFC from Sonnagar to Dankuni.

2. **Khurpia Farms, 1,002 acres in Uttarakhand**

- State Govt. in Aug, 2020 confirmed the availability of 1002 acres land for the project;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed in Jan, 2021 and works are under progress.

3. **Hisar, 1,605 acres in Haryana**

- State Govt. in Dec, 2020 confirmed the availability of 1605 acres land for the project;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed in Feb, 2021 and works are under progress.

4. **Rajpura-Patiala, 1,100 acres in Punjab**

- State Govt. in Feb, 2021 confirmed the availability of 1100 acres land for the project;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities has been appointed in Feb, 2021 and works are under progress.

5. **Agra, 1,059 acres in Uttar Pradesh**

- State Govt. in Jan, 2021 confirmed the availability of 1059 acres land for the project;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities being appointed by end of July, 2021;
- NICDIT has approved the inclusion of brownfield site at Prayagraj (1,141 acres) to be developed as 2nd node in Uttar Pradesh under AKIC.

6. **Gaya, 1,670 acres in Bihar**

- State Govt. in March, 2021 confirmed the availability of 1670 acres land for the project;
- Consultant for carrying out Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities to be appointed shortly.

7. **Jharkhand**

- State Govt. in Jan 2021 has informed that the earlier site at New Bahri is not available therefore an alternate site is being identified. Confirmation on the land details of alternate site is awaited.

- NICDIT approved the inclusion of Baddi Barotiwala Nalagarh (BBN) area (2000 acres) in the state of Himachal Pradesh as an industrial node under AKIC & to initiate the project development activities for establishment of IMC.

**E. Vizag- Chennai Industrial Corridor:**

- NICDIT had accorded its approval for development of Vishakhapatnam and Chittoor as priority nodes in Phase-1 of VCIC. State Govt. has also requested for inclusion of Kadappa as an additional node in the State of Andhra Pradesh
  1. **Chittoor Node:** Consultants have been appointed for preparation of detailed master planning & preliminary engineering for 8,967 acres and works are under progress;
  2. **Kadappa Node:** Consultants have been appointed for preparation of detailed master planning & preliminary engineering for 5,076 acres and works are under progress;
  3. **Visakhapatnam (Nakapalli Cluster, 1,100 acres):** State Govt. is undertaking project development for this node on its own.

**F. Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC)**

1. Govt. of Karnataka in Jan, 2021 confirmed that 6,400 acres of land is available for development of industrial node at **Dharwad**. Project development activities have been initiated for the said node. Consultant has been appointed for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering in July, 2021;
2. Govt. of Maharashtra in March, 2021 has confirmed the availability of 5,000 Ha land at **Satara** for development of industrial node. Tender document for selection of consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering was issued in May, 2021. Consultant is likely to be appointed by August, 2021.

**G. Hyderabad Warangal Industrial Corridor (HWIC):**

- NICDIT approved in Aug, 2020 the proposal of inclusion of Hyderabad Warangal Industrial Corridor in the State of Telangana;
- State Govt. has prepared Master-Planning and cost estimates for **Hyderabad Pharma City** under Hyderabad-Warangal Industrial Corridor in the State of Telangana;
- For Pharma City project, State Govt. to confirm regarding their participation with GoI for development of the project.

**H. Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC):**

- NICDIT approved in Aug, 2020 the proposal of inclusion of Hyderabad Nagpur Industrial Corridor in the state of Telangana;
- State Govt. has prepared Master-Planning and cost estimates for **Zaheerabad Industrial Area** under Hyderabad-Nagpur Industrial Corridor in Telangana;
- For Zaheerabad Industrial area, State Govt. has submitted the Preliminary Design Report (PDR) cum Business Plan report and the same will be placed for consideration of NICDIT.

## I. Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC):

- NICDIT approved in Aug, 2020 the inclusion of HBIC and priority node at **Orvakal** in the State of Andhra Pradesh;
- Consultant for Detailed Master Planning and Preliminary Engineering for Orvakal node, 9,800 acres (Andhra Pradesh) has been appointed in January, 2021.

## J. Odisha Economic Corridor (OEC) Project:

- NICDIT approved in Aug, 2020 the inclusion of OEC and project development activities initiated for two priority nodes, namely,
  - Gopalpur – Bhubaneswar – Kalinganagar (**GBK node**); and
  - Paradip – Kendrapada – Dhamra – Subarnarekha (**PKDS node**).
- Consultant appointed for detailed Master Planning and preliminary engineering for GBK and PKDS node comprising total area of 11,366 acres.

## K. Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC)

- Delhi Nagpur Industrial Corridor has been conceptualized along the North-South Corridor of DFC. The proposed Industrial Corridor will leverage on the existing NH network and the future North-South DFC;
- Tender has been issued for selection of consultant for preparation of Perspective Plan for overall DNIC region in July, 2021.

### Other Projects

### 1. Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- The project for 5MW has been commissioned & power feeding to grid has commenced since 24th July, 2015;
- 1 MW Micro Grid commissioned on 1st June, 2021 and supply of power commenced after execution of PPA.

### 2. Logistic Data Services Project:

- The project of Logistic Data Bank (LDB) was envisaged as Service for tracking container cargo movement, integrate the existing IT systems of various stakeholder (ports, customs, trains, ICD etc.) across the supply chain to provide near real time information within a single window;
- Operations started at JNPT from 1st July, 2016;
- Service is operational at pan India level at all major and some minor ports and more than 38 million containers have been tagged/de-tagged till 30th June, 2021.

## Logistics Projects

### 1. Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary, Haryana

- Project approved by GoI in May, 2018;
- Land admeasuring approx. 886 acres has been identified in District Mahendergarh for the project and 686 acre has been transferred to project SPV and matching equity amounting to Rs. 208.05 crore has been released by NICDIT;
- Approx. 158 acres land is under litigation and matter is pending with Hon'ble High Court of Punjab and Haryana. State Govt. has been requested to get this resolved at the earliest. Next date of hearing is 13th October, 2021;
- For external connectivity works related to water, power & road, State Govt. agencies have initiated works on deposit basis;
- 25 acres to be acquired by DFCCIL under Railways Act for providing connectivity and further, DFCCIL will be executing works for external rail connectivity upto project site on deposit basis. Tender preparation works for internal rail siding is underway.

### 2. Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida, Uttar Pradesh

- Projects approved by GoI in Dec, 2020;
- Out of total land area required for MMLH and MMTH of 479 Ha, 369 Ha already under possession of GNIDA and ~84 Ha land parcels being acquired by GNIDA through LARR Act. Further, ~23 Ha of land to be acquired by DFCCIL/NCR under Railways Act;
- 227.48 Ha land transferred to Project SPV and matching equity amounting to Rs. 853.05 crore has been released by NICDIT;
- For MMLH - DPR works for external Rail Siding connectivity underway;
- For MMTH – Final Project report along with updated ESP submitted to North Central Railway (NCR) and other stakeholders. General Consultant for the project being appointed.

### 3. Multi Modal Logistic Park (MMLP) at Sanand, Gujarat

- State Govt. in Nov, 2020 confirmed availability of 199 Ha of land and shared the tentative valuation of land in Feb, 2021 based on which viability of the project has been assessed;
- Techno-Economic Feasibility report shared with State Govt. in June, 2021;
- Response from State Govt. is awaited for moving ahead in the project.

**IICC Project at Dwarka, New Delhi**

- Union Cabinet in its meeting held on November 10, 2017 approved the development of Exhibition-cum-Convention Centre and allied infrastructure in PPP and non-PPP mode at an estimated cost of Rs.25,703 crore. The project will be developed by India International Convention & Exhibition Centre Limited (IICC Ltd.), a Special Purpose Company wholly owned by Government of India through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).

- The project is being developed in two phases. Phase-I estimated to cost Rs.5,178 crore (including financial cost of Rs. 197 crore), consisting of Convention Centre, two Exhibition Halls and related trunk infrastructure facilities and is currently under development. L&T has been appointed as EPC Contractor for the development of Phase-I components including trunk infrastructure for the entire project. The project was originally planned to be completed and commissioned by October 2019 revised to Aug, 2020. The progress of works as on 16th July 2021 is 69.21%. Phase-II will include construction of three more Exhibition Halls, Arena, and commercial development of complimentary infrastructure like Hotels, Retail and Office spaces. Government of India would provide additional budgetary support of Rs.2,442.39 crore as equity for Phase-I development. Further requirement of funds for Phase-I and II is being met by IICC Ltd. from internal accruals and loans from Bank.

- There have been instances of stoppage of work due to NGT ban and lockdown due to Covid-19 in 2020 and 2021. There were delays in initial handing over the land to contractor as well as delays on several fronts at the project site by the contractor.

- As per the project reviews taken at the highest level in the Ministry, the EPC contractor has committed to complete the work by May 2022 in all aspects by deputing additional man and material resources.

- Efforts were made to monetize the land parcels for Hotel and Office, however, the response received from the market was subdued and much below the expectation. Attempts will be made after market assessment post Covid scenario.

## 3. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES:

The Company has only one subsidiary namely NICDC Neemrana Solar Power Limited (formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) as on 31st March, 2021.

During the year under review, the Board of Directors reviewed the affairs of the subsidiary.

Further, the report on the performance and financial position of the subsidiary and salient features of the Financial Statements in the prescribed Form AOC-1 is enclosed with the Financial Statements.

## 4. DIVIDEND:

No dividend has been recommended during the financial year.

A proposal for exemption from the applicability of the provisions related to payment of dividend on the guidelines issued by DIPAM, Ministry of Finance, GoI, vide OM NO. 5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) was sent by NICDC to DIPAM through DPIIT for the financial year 2018-19 and 2019-20. In the Meeting of the Committee for Monitoring of Capital Management & Dividend in CPSEs (CMCDC) held under the Chairmanship of Secretary, DIPAM on 12th March, 2021, NICDC Limited was considered for exemption from the compliance of Capital Restructuring Guidelines relating to declaration of Minimum Dividend for the FY 2018-19.

However, proposal for the FY 2019-20 was inadvertently left out by DIPAM and could not be considered as an agenda item for the above meeting. During the course of meeting, NICDC requested DIPAM to consider proposal for the FY 2019-20 in addition to the proposal for 2018-19. Secretary, DIPAM mentioned that the proposal for the FY 2019-20 will be taken up in the forthcoming meeting of DIPAM and allowed the exemption for the FY 2018-19.

On the similar lines, the Company will seek exemption from payment of Minimum Divided for the FY 2020-21, accordingly no provision has been made for the Current financial Year.

## 5. RESERVES:

During the period under review, Rs. 12,64,44,273/- has been transferred to the reserves by the Company.

## 6. CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY:

There was no change in the nature of the business of the Company during the financial year ended on 31st March, 2021.

## 7. DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

M/S VSPV & CO., Chartered Accountants were appointed as Internal Auditors of the Company for the financial year 2020-21 pursuant to Section 138(1) of the Companies Act, 2013 in the Board Meeting of the Company held on 29th July, 2020. The Board feels that the scope of Internal Audit and Internal Financial Control having regard to the size of the Company are adequate.

## 8. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE:

During the financial year ended on 31st March, 2021, no order has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

## 9. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2021 AND THE DATE OF THE REPORT:

There are no material changes occurred in between the financial year ended on 31st March, 2021 and date of the report of the Company which affects the financial position of the Company.

## 10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

During the year under review, the Company is required to comply with the provisions related to Corporate Social Responsibility in pursuance to the provisions of the Section 135 of the Companies Act, 2013. The details of CSR activities are mentioned in Annual Report on CSR activities enclosed at **Annexure-"A"**.

## 11. DEPOSITS:

During the financial year ended on 31st March, 2021, the Company has not accepted any deposits nor any deposits remained unpaid or unclaimed.

## 12. STATUTORY AUDITORS:

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) vide their letter no. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC (0)/423 dated 18th August, 2020 has appointed M/s S. P. Chopra & Co., Chartered Accountants (ICAI Firm Registration No. 000346N) as the Statutory Auditors of the Company as per the provisions enumerated under Section 139 of the Companies Act, 2013 (read with other applicable provisions) for the financial year 2020-21. Also the Supplementary Audit of the Company for the financial year 2020-21 has been entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex- Officio Member Audit Board - I.

On similar lines, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) will be nominating the Statutory Auditors for the financial year 2021-22. Also, the Supplementary Audit of the Company for the financial year 2021-22 will be entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex- Officio Member Audit Board - I.

The Statutory Auditors of the Company as may be appointed by the office of Comptroller and Auditor General of India (C&AG) will hold office till the conclusion of the 14th Annual General Meeting of the Company.

## 13. AUDITORS' REPORT:

The Auditors' Report submitted by Statutory Auditor do not contain any qualifications. The notes to the accounts referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and therefore do not call for any further comments of Directors.

Review and Comments of C&AG, if any, on the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31st March, 2021 forms part of Financial Statements.

## 14. SECRETARIAL AUDITORS:

M/s Vikas Gera & Associates, Company Secretaries had been appointed in the Board Meeting of the Company held on 29th July, 2020 to conduct the Secretarial Audit of the Company for the financial year 2020-21 as per Section 204 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. The Secretarial Audit Report for the financial year ended on 31st March, 2021 is attached at **Annexure-"B"**.

## 15. SECRETARIAL AUDITORS' REPORT:

The Secretarial Auditors has given following observation in their report: -

| Secretarial Auditors' comment | Management Remarks |
|---|---|
| The Company was required to appoint Women Director as per the provision of Section 149(1) of the Companies Act, 2013 which the Company has not done. | As NICDC works under the administrative control of Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) , Ministry of Commerce and Industry, which hold 49% of total paid-up share capital of the Company. Therefore, as a matter of practice, DPIIT would be suggesting the name of the Woman Director on the Board of the Company.<br>Accordingly, NICDC vide letters dated 11th April, 2020, 12th May, 2020, 11th June, 2020, 13th July, 2020, 21st August, 2020, 05th October, 2020, 07th December, 2020, 09th February, 2021, 27th April, 2021 and 27th May, 2021 has been following up with DPIIT for suggesting the name of Woman Director on the Board of the Company at the earliest.<br><br>The said matter has also been duly discussed/deliberated at the 59th Board meeting of the Company held on 10th June, 2021 for filling up the post of Woman Director on the Board of the Company and NICDC vide its letter dated 30th June, 2021 has requested DPIIT requesting for nomination of any officer by DPIIT as Woman Director to comply with the provisions of the Companies Act, 2013. |

## 16. CAPITAL STRUCTURE:

The authorized, issued and paid-up share capital of the Company is Rs. 100,00,00,000/- (Rupees One Hundred crore Only) divided into 10,00,00,000 (Ten crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

## 17. EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN UNDER SECTION 92(3):

In accordance with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the extract of the Annual Return as provided under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 in Form No. MGT-9 is attached at **Annexure - "C"**.

## 18. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

The details of conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo are as follows:-

**A) Conservation of energy*:**

i. the steps taken or impact on conservation of energy : **Not Applicable**

ii. the steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy : **Not Applicable**

iii. the capital investment on energy conservation equipment's : **Not Applicable**

**B) Technology absorption:**

i. the efforts made towards technology absorption : **Not Applicable**

ii. the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution : **Not Applicable**

iii. in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) : **Not Applicable**
(a) The details of technology imported;
(b) the year of import;
(c) whether the technology been fully absorbed;
(d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and

iv. the expenditure incurred on Research and Development : **Not Applicable**

**C) Foreign exchange earnings and Outgo:**

i. The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year : **NIL**

ii. The Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual Outflows : **NIL**

*[*Note: The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/ economic regions/industrial nodes/special economic zones/townships with state-of-art industrial, physical and social infrastructure. The conservation of energy and technology absorption is not applicable. However, the Company is doing its best efforts for the conservation of energy through various project development activities.]*

## 19. BOARD OF DIRECTORS:

### (A) Changes in Directors and Key Managerial Personnel:

| S. No. | Name of the Director/Key Managerial Personnel | Date of Appointment | Date of Cessation |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Muniappa Nagaraj | 17th July, 2020 | - |

Shri Giridhar Aramane, IAS, Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), (Additional Charge), Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has been appointed as an Additional Director on the Board of NICDC Ltd. with effect from 10th June, 2021.

***Retirement by Rotation:*** -

In accordance with the provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013 and the Articles of Association of the Company, Shri Rajendra Ratnoo and Shri Toshihiko Kurihara, Directors of the Company retires by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible have offered themself for re-appointment.

**(B) Number of Meetings of the Board of Directors:**

Four (04) meetings of the Board of Directors of the Company were held in the financial year 2020-21. The details of the Board Meeting are as under:-

| S.No. | Particulars | Date of Board Meeting |
|---|---|---|
| 1. | 55th Board Meeting | 27th May, 2020 |
| 2. | 56th Board Meeting | 29th July, 2020 |
| 3. | 57th Board Meeting | 06th November, 2020 |
| 4. | 58th Board Meeting | 28th December, 2020 |

## 20. COMMITTEES OF THE BOARD:

The Board of Directors has following three Committees:-

**Audit Committee:**

As per Section 177 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the constitution of the Audit Committee* of the Board of Directors of the Company is as follows: -

| Sl. No | Name of Director | Category | Designation |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry | Non Executive Director | Chairman |
| 2. | Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) | Non Executive Director | Member |
| 3. | Dr. D. Subrahmanyam, Sr. Executive Director (Operations), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) | Non Executive Director | Member |

*Consequent to cessation of tenure of Shri Jai Prakash Batra as an Independent Director of the Company with effect from 30th March, 2020, the Board of Directors in its 55th meeting held on 27th May, 2020, had re-constituted the Audit Committee of the Board, with all non-executive Directors forming part thereof.

During the year 2020-21, two meetings of the Audit Committee were held on 29th July, 2020 and 06th November, 2020.

**Nomination and Remuneration Committee**:

As per the Section 178 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the constitution of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors of the Company is as follows:-

| Sl. No | Name of Director | Category | Designation |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry | Non Executive Director | Chairman |
| 2. | Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) | Non Executive Director | Member |
| 3. | Dr. D. Subrahmanyam, Sr. Executive Director (Operations), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) | Non Executive Director | Member |

*Consequent to cessation of tenure of Shri Jai Prakash Batra as an Independent Director of the Company with effect from 30th March, 2020, the Board of Directors had at their 55th meeting held on 27th May, 2020, re-constituted the Nomination and Remuneration Committee of the Board, with all non-executive Directors forming part thereof.

During the year, two meetings of Nomination and Remuneration Committee were held on 06th November, 2020 and 28th December, 2020.

**Corporate Social Responsibility Committee:**

As per the Section 135 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company had re-constituted the Corporate Social Responsibility Committee at its 55th meeting held on 27th May, 2020 as follows:-

| Sl. No | Name of Director | Category | Designation |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry | Non Executive Director | Chairman |
| 2. | Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) | Non Executive Director | Member |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Dr. D. Subrahmanyam, Sr. Executive Director (Operations), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) | Non Executive Director | Member |

During the year, one meeting of Corporate Social Responsibility Committee was held on 28th December, 2020.

## 21. REMUNERATION PAID TO KEY MANAGERIAL PERSONNELS (KMPs):

The Company during the financial year 2020-21 has paid remuneration to Shri K. Sanjay Murthy, CEO & Managing Director; Shri Pradeep Kumar Agarwal, Chief Financial Officer and Shri Abhishek Chauddhary, VP - Corporate Affairs, HR and Company Secretary. The details of the remuneration paid during the financial year 2020-21 is mentioned in VI (A) and Clause VI (C) of Form No. MGT – 9.

## 22. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186:

No loan or guarantee has been given and investment has been made under Section 186 of the Companies Act, 2013 by the Company during the financial year under review.

## 23. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES UNDER SECTION 188(1):

No contracts or arrangements were entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 during the financial year under review.

## 24. RISK MANAGEMENT AND INTERNAL ADEQUACY:

The Company has adequate risk management process to identify and notify the Board of Directors about the risks or opportunities that could have an adverse impact on the Company's operations or could be exploited to maximize the gains. The processes and procedures are in place to act in a time bound manner to manage the risks or opportunities.

The Company's internal control systems are commensurate with the nature of its business and the size and complexity of its operations. These are routinely tested and certified by Statutory as well as Internal Auditors. Significant audit observations and follow up actions thereon are reported to the Audit Committee.

## 25. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

In pursuance to clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013 it is stated that:-

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## 26. RIGHT TO INFORMATION:

The status of RTI applications/appeals received during the financial year 2020-21 is as follows:

| RTI Application/ Appeals received | | RTI applications | | | | Pending Applications as on 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rejected | Information provided | Transferred to other public Authority | Returned to Applicant | |
| Applications | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Appeals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 27. PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS:

The Directors of your Company are in a fiduciary position, empowered to oversee the management functions with a view to ensure its effectiveness and enhancement of stakeholders' value.

## 28. COST AUDITORS:

As per the provisions of the Companies Act, 2013, the Company is not required to appoint the Cost Auditors.

## 29. POLICY IN COMPLIANCE OF THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

The Company has constituted an Internal Compliants Committee in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. The committee spread awareness amongst the employees regarding 'Zero Tolerance' for sexual harassment at work place.

There were no cases filed during the financial year ended 31st March, 2021.

## 30. VIGILANCE:

There were no vigilance cases reported during the financial year 2020-21 and there are also no previous pending vigilance cases in the Company.

## 31. SECRETARIAL STANDARDS:

The Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Companies Secretaries of India from time to time.

## 32. EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE:

The report of Statutory Auditor is free from qualification, reservation or adverse remark or disclaimer and explanation on the qualification by Secretarial Auditors has been presented in this report at point No.15.

## 33. ACKNOWLEDGEMENTS:

The Board of Directors of the Company wish to place on record, their thanks and appreciation to all workers, staff members and executives for their contribution to the operations of the Company. The Directors are thankful to the Government of India, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), India Infrastructure Finance Corporation Limited (IIFCL) and Life Insurance Corporation of India (LIC), and its Bankers. The Directors also place on record their sincere thanks to the shareholders for their continued support, co-operation and confidence in the Management of the Company.

**For and on behalf of the Board of Directors**

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

**(Giridhar Aramane)**
**Chairman**
**Add: B9, Tower 7, South Moti Bagh,**
**South West Delhi - 110021**

**Date:** 10/08/2021
**Place: New Delhi**

Annexure- "A"

## ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

**(For Financial Year starting from 01st April, 2020 to 31st March, 2021)**

1. **Brief outline on CSR Policy of the Company.**

   NICDC envisions to act in a socially responsible manner to contribute to the socio-economic development of the communities and operate in, by building stronger, developed sustainable communities & raise the quality of life of people of the Country.

2. **Composition of CSR Committee:**

   The composition of the CSR Committee of the Board of Directors of the Company and their attendance at the 04th CSR Committee meeting held on 28th December, 2020 is as below:-

| Sl. No. | Name of Director | Designation / Nature of Directorship | Number of meetings of CSR Committee held during the year | Number of meetings of CSR Committee attended during the year |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry | Non-executive Director | 1 | 1 |
| 2. | Dr. D. Subrahmanyam, Sr. Executive Director (Operations), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) | Non-executive Director | 1 | 1 |
| 3. | Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) | Non-executive Director | 1 | 1 |

3. **Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the company.**

   Web-link disclosing the composition of the CSR committee and CSR policy of the Company is as below: -

   **https://www.nicdc.in/download.aspx?mpgid=34&pgidtrail=34&utid=11**

4. **Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).**

   Not Applicable.

5. **Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:-**

| Sl. No. | Financial Year | Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs) | Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs) |
|---|---|---|---|
| NIL | | | |

6. **Average net profit of the company as per Section 135(5):- Rs. 5,98,28,334/-**

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5): **Rs. 11,96,567/-**
   (b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: Nil
   (c) Amount required to be set off for the financial year, if any: Nil
   (d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c): **Rs. 11,96,567/-**

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

| Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.) | Amount Unspent (in Rs.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6). | | Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5). | | |
| | Amount. | Date of transfer. | Name of the Fund | Amount. | Date of transfer. |
| 11,96,567 * | Not Applicable | | Not Applicable | | |

** CSR funds of Rs. 11,96,567/- have been contributed to the Prime Minister's National Relief Fund (Scheduled Fund under Schedule VII of the Companies Act, 2013) on 31st March, 2021*

(b) Details of CSR amount spent **against ongoing projects** for the financial year:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl. No. | Name of the Project | Item from the list of activities in Schedule VII to the Act. | Local area (Yes/No) | Location of the project. | | Project duration | Amount allocated for the project (in Rs.). | Amount spent in the current financial Year (in Rs.). | Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.). | Mode of Implementation - Direct (Yes/No) | Mode of Implementation - Through Implementing Agency | |
| | | | | State | District | | | | | | Name | CSR Registration number |
| Not Applicable | | | | | | | | | | | | |

(c) Details of CSR amount spent against **other than ongoing projects** for the financial year:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Name of the Project** | **Item from the list of activities in schedule VII to the Act** | **Local area (Yes/ No)** | **Location of the project** | | **Amount spent for the project (in Rs.)** | **Mode of implement ation - Direct (Yes/No)** | **Mode of implementation - Through implementing agency** | |
| | | | | **State** | **District** | | | **Name** | **CSR registration number** |
| Not Applicable | | | | | | | | | |

(d) Amount spent in Administrative Overheads: Nil

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: Not Applicable

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): Nil

(g) Excess amount for set off, if any: Nil

| **Sl. No.** | **Particular** | **Amount (in Rs.)** |
|---|---|---|
| (i) | Two percent of average net profit of the company as per section 135(5) | 11,96,567 |
| (ii) | Total amount spent for the Financial Year | 11,96,567 |
| (iii) | Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)] | Nil |
| (iv) | Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any | Nil |
| (v) | Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)] | Nil |

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

| **Sl. No.** | **Preceding Financial Year.** | **Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)** | **Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).** | **Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.** | | | **Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Name of the Fund** | **Amount (in Rs).** | **Date of transfer.** | |
| Not Applicable | | | | | | | |

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl. No. | Project ID | Name of the Project | Financial Year in which the project was commenced | Project duration. | Total amount allocated for the project (in Rs.) | Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs) | Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year (in Rs.) | Status of the project - Completed /Ongoing |
| Not Applicable | | | | | | | | |

**10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details).**

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s): Nil

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset: Nil

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.: Not Applicable

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset): Not Applicable

**11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).**

Not Applicable

| | |
|---|---|
| (Chief Executive Officer and Managing Director) | (Chairman, CSR Committee) |

VIKAS GERA & ASSOCIATES
Company Secretaries B.Com., LL.B., F.C.S

**Form No. MR-3**

**SECRETARIAL AUDIT REPORT**

For The Financial Year Ended 31st March, 2021

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
**NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)
08th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building,
124 Connaught Place,
New Delhi - 110001

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **"NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)"** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute-books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financially year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

Vikas Gera & Associates * New Delhi * Company Secretaries

1) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

2) Foreign Exchange Management Act, 1999 and Regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

3) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

4) Other laws as are and to the extent applicable to the Company as per the Management representations, given below:

   (i) The Employee Provident Fund Miscellaneous Provisions Act, 1952.

   (ii) The Payment of Gratuity Act, 1972.

   (iii) Delhi Shops & Establishment Act, 1954.

   (iv) Indian Stamp Act, 1999.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to General and Board meetings .

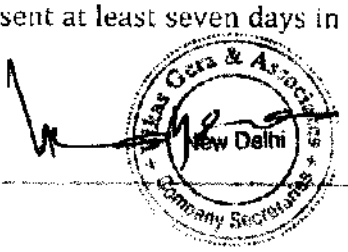
(ii) The Company has not entered into listing agreements with any Stock Exchange, being an unlisted entity.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above and there is no non-compliance/observation/audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of above paras.

**I further report that**

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. There is change in the composition of the Board of Directors during the period under review. The company was required to appoint Woman Director as per the provision of Section 149(1) of the Companies Act, 2013 which company has not done.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for



seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

**I further report that**

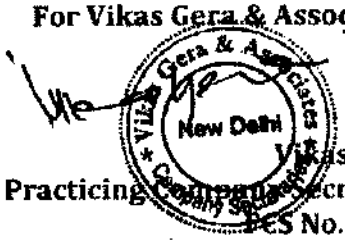
There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

**I further report that**

There is no non-compliance/observation/audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the Board Structures/system and processes relating to the Audit period.

**Place: New Delhi**
**Date: 10th August, 2021**
**UDIN: F005248C000754150**

**For Vikas Gera & Associates**




**Vikas Gera**
**Practicing Company Secretary**
**FCS No. 5248**
**C P No.: 4500**

**NOTE:** This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure A** and forms an integral part of this report.

To,

**'Annexure A'**

The Members,
**NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)
08th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building,
124 Connaught Place,
New Delhi – 110001

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company as the same have been subject to review by the Statutory Financial Auditor and any other designated professional.

4. The Compliances done by the company of the applicable Financial Laws like Direct and Indirect Tax Laws have not been reviewed by us as the same have been subject to review by the Statutory Financial Auditor and any other designated professional.

5. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

6. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

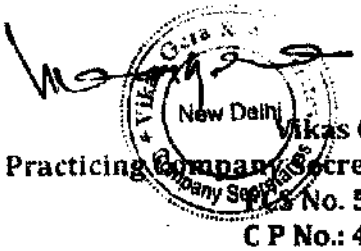
7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.



8. Due to the COVID -19 we have carried out Secretarial Audit based on the online information provided to us and we believe that all the information so made available to us in soft copy are originated from original records of the company.

**Place: New Delhi**
**Date: 10th August, 2021**

**For Vikas Gera & Associates**




**Vikas Gera**
**Practicing Company Secretary**
**FCS No. 5248**
**C P No.: 4500**

**Form No. MGT-9**

**EXTRACT OF ANNUAL RETURN**
**As on the financial year ended on 31st March, 2021**

[Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

| I | REGISTRATION & OTHER DETAILS | |
|---|---|---|
| i) | CIN | U45400DL2008PLC172316 |
| ii) | Registration Date | 07th January, 2008 |
| iii) | Name of the Company | **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** *(formerly known as "Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited")* |
| iv) | Category/Sub-category of the Company | Company Limited by shares/Indian Non-Government Company |
| v) | Address of the Registered office & contact details | 08th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi -110001 |
| vi) | Whether listed company (Yes/No) | No |
| vii) | Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any. | NSDL Database Management Limited<br><br>04th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai – 400013 |

| II | PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY | | |
|---|---|---|---|
| **All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated** | | | |
| **S. No.** | **Name & Description of main products / services** | **NIC Code of the Product / service** | **% to total turnover of the company** |
| 1. | The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/ economic regions/industrial nodes/special economic zones /townships with state-of-art industrial, physical and social infrastructure. | 42909 (other civil engineering Project n.e.c.) | 100% |

| III | PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **S. No.** | **Name & Address of the Company** | **CIN/GLN** | **Holding/ Subsidiary/ Associate** | **% of Shares Held** | **Applicable Section** |
| **1.** | **NICDC Neemrana Solar Power Limited** (Formerly "DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited")<br><br>08th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi -110001 | **U40300DL2014 PLC266439** | **Subsidiary** | **100%** | **2(87)(ii)** |

**IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)**

**i. Category-wise Share Holding**

| Category of Shareholders | No. of Shares held at the beginning of the year | | | | No. of Shares held at the end of the year | | | | % Change during the year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | Demat | Physical | Total | % of Total Shares | |
| **A. Promoters** | | | | | | | | | |
| **(1) Indian** | | | | | | | | | |
| a) Individual / HUF | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| b) Central Govt. | 4,90,00,000 | 0 | 4,90,00,000 | 49.00 | 4,90,00,000 | 0 | 4,90,00,000 | 49.00 | 0.00 |
| c) State Govt(s) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| d) Bodies Corp. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| e) Bank / FI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| f) Others (Trusts) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| **Sub-total (A)(1)** | **4,90,00,000** | **0** | **4,90,00,000** | **49.00** | **4,90,00,000** | **0** | **4,90,00,000** | **49.00** | **0.00** |
| **(2) Foreign** | | | | | | | | | |
| a) NRIs - Individuals | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| b) Other - Individuals | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| c) Bodies Corp. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| d) Bank / FI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| e) Any other | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **Sub-total (A)(2)** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** |
| **Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)** | **4,90,00,000** | **0** | **4,90,00,000** | **49.00** | **4,90,00,000** | **0** | 4,90,00,000 | 49.00 | **0.00** |

| B. Public Shareholding | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Institutions** | | | | | | | | | |
| a) Mutual Funds | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| b) Bank / FI | 2,39,99,998 | 2 | 2,40,00,000 | 24.00 | 2,39,99,998 | 2 | 2,40,00,000 | 24.00 | 0.00 |
| c) Central Govt | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| d) State Govt(s) | | | | | | | | | |
| e) Venture Capital Funds | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| f) Insurance Companies | 10,00,000 | 0 | 10,00,000 | 1.00 | 10,00,000 | 0 | 10,00,000 | 1.00 | 0.00 |
| g) FIIs | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| h) Foreign Venture Capital Funds | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| i) Others<br>Foreign Holdings (FIIs/FCs/FFIs/NRIs/OCBs) | 2,60,00,000 | 0 | 2,60,00,000 | 26.00 | 2,60,00,000 | 0 | 2,60,00,000 | 26.00 | 0.00 |
| **Sub-total (B)(1)** | **5,09,99,998** | **2** | **5,10,00,000** | **51.00** | **5,09,99,998** | **2** | **5,10,00,000** | **51.00** | **0.00** |
| **2.Non - Institutions** | | | | | | | | | |
| a) Bodies Corp. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| b) Individuals | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| i. Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ii. Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| c) Others :<br>i. Clearing Members | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ii. Non Residents | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| iii. Foreign Company | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| iv. Trusts | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **Sub-total (B)(2)** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** |
| **Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)** | 5,09,99,998 | 2 | 5,10,00,000 | 51.00 | 5,09,99,998 | 2 | 5,10,00,000 | 51.00 | 0.00 |
| **C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** |
| **Grand Total (A+B+C)** | **9,99,99,998** | **2** | **10,00,00,000** | **100.00** | **9,99,99,998** | **2** | **10,00,00,000** | **100.00** | **0.00** |

**(ii) Share Holding of Promoters**

| S. No. | Shareholders Name | Shareholding at the beginning of the year | | | Shareholding at the end of the year | | | % change in shareholding during the year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of shares | % of total shares of the company | % of shares pledged/ encumbered to total shares | No. of shares | % of total shares of the company | % of shares pledged/ encumbered to total shares | |
| | President of India Through Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry | 4,89,99,998 | | - | 4,89,99,998 | | - | NIL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | of Commerce & Industries | | | | | | | |
| 1. | Shri Shailendra Singh, IAS, Additional Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industries | 01 | 49% | - | 01 | 49% | - | NIL |
| | Representative of President of India represented through Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industries | 01 | | - | 01 | | - | NIL |

| (iii) | Change in Promoters' Shareholding (please Specify, if there is no change) No Change | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | Shareholders Name | Shareholding at the beginning of the Year | | Cumulative Shareholding during the year | |
| | | No. of Shares | % of total shares of the company | No of shares | % of total shares of the company |
| NIL | | | | | |

| (iv) | Shareholding Pattern of top Ten Shareholders (other than Directors, Promoters & Holders of GDRs & ADRs) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | Shareholders Name | Shareholding at the beginning of the year | | Shareholding at the end of the year | |
| | | No. of shares | % of total shares of the company | No of shares | % of total shares of the company |
| 1. | Japan Bank for International Cooperation (JBIC) | 2,60,00,000 | 26.00% | 2,60,00,000 | 26.00% |
| 2. | Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) | 1,99,00,000 | 19.90% | 1,99,00,000 | 19.90% |
| 3. | India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) | 40,99,998 | 4.10% | 40,99,998 | 4.10% |
| | IIFCL jointly with Shri P.R. Jaishankar | 01 | | 01 | |
| | IIFCL jointly with Shri Rajeev Mukhija | 01 | | 01 | |
| 4. | Life Insurance Corporation of India (LIC) | 10,00,000 | 1.00% | 10,00,000 | 1.00% |

| (v) | Shareholding of Directors & KMP | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | For Each of the Directors & KMP | Shareholding at the beginning of the year | | Cumulative Shareholding during the year | |
| | | No. of shares | % of total shares of the Company | No of shares | % of total shares of the Company |
| | NIL | | | | |

| V | INDEBTEDNESS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment | | | | |
| | | Secured Loans excluding deposits | Unsecured Loans | Deposits | Total Indebtedness |
| 1 | Indebtedness at the beginning of the financial year | - | - | - | - |
| | i) Principal Amount | - | - | - | - |
| | ii) Interest due but not paid | - | - | - | - |
| | iii) Interest accrued but not due | - | - | - | - |
| | Total (i+ii+iii) | - | - | - | - |
| 2 | Change in Indebtedness during the financial year | - | - | - | - |
| | Additions | - | - | - | - |
| | Reduction | - | - | - | - |
| 3 | Net Change | - | - | - | - |
| 4 | Indebtedness at the end of the financial year | - | - | - | - |
| | i) Principal Amount | - | - | - | - |
| | ii) Interest due but not paid | - | - | - | - |
| | iii) Interest accrued but not due | - | - | - | - |
| Total (i+ii+iii) | | - | - | - | - |

| VI | REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL | | |
|---|---|---|---|
| A. | Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager: | | |
| S. No. | Particulars of Remuneration | Name of MD/WTD/ Manager (Shri K. Sanjay Murthy- CEO & Managing Director) | Total Amount (Rs) |
| 1 | Gross salary | 48,82,542 | 48,82,542 |
| | (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax. 1961. | | |
| | (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961 | 8,10,201 | 8,10,201 |
| | (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961 | - | - |
| 2 | Stock option | - | - |
| 3 | Sweat Equity | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Commission | - | - |
| | as % of profit | - | - |
| | others (specify) | - | - |
| 5 | Others, please specify | | |
| | **Total (A)** | **56,92,743** | **56,92,743** |
| | **Ceiling as per the Act** | - | - |

| **B. Remuneration to other Directors** | | | |
|---|---|---|---|
| **Sr. No.** | **Particulars of Remuneration** | **Name of Directors** | **Total** |
| 1. | • Fee for attending board/ committee meetings to Independent Directors | **Nil** | |
| | • Commission | | |
| | • Others, please specify | | |
| **Total (1)** | | | |
| 2 | Other Non-Executive Directors | **Nil** | |
| | • Fee for attending board/ committee meetings | | |
| | • Commission | | |
| | • Others, please specify | | |
| **Total (2)** | | | |
| **Total (B)= (1)+(2)** | | | |
| **Total (A+B)** | | | |

| C. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **S. No.** | **Particulars of Remuneration** | **Key Managerial Personnel Other than MD/Manager/WTD** | | |
| | **Gross Salary** | **Shri Abhishek Chauddhary (Company Secretary)** | **Shri P. K. Agarwal (CFO)** | **Total Amount** |
| 1 | Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961. | 46,01,820 | 47,79,204 | 93,81,024 |
| | Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961 | 6,86,700 | 6,03,375 | 12,90,075 |
| | Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961 | - | - | - |
| 2 | Stock Option | - | - | - |
| 3 | Sweat Equity | - | - | - |
| 4 | Commission as % of profit | - | - | - |
| | others, specify | - | - | - |
| 5 | Others, please specify | - | - | - |
| **Total** | | **52,88,520** | **53,82,579** | **1,06,71,099** |

| VII | PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCE: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. No | Type | Section of the Companies Act | Brief Description | Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed | Authority (RD/NCLT/ Court) | Appeal made if any (give details) |
| A. | COMPANY | | | | | |
| | Penalty | | | NONE | | |
| | Punishment | | | | | |
| | Compounding | | | | | |
| B. | DIRECTORS | | | | | |
| | Penalty | | | NONE | | |
| | Punishment | | | | | |
| | Compounding | | | | | |
| C. | OTHER OFFICERS IN DEFAULT | | | | | |
| | Penalty | | | NONE | | |
| | Punishment | | | | | |
| | Compounding | | | | | |

**For and on behalf of the Board of Directors**

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

**(Giridhar Aramane)**
**Chairman**
**Add: B9, Tower 7, South Moti Bagh,**
**South West Delhi - 110021**

**Date:** 10/08/21
**Place: New Delhi**

# C&AG REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Trust in Public Interest

गोपनीय

संख्या/No. PDA/Infra/A/c/DMCDC/21-53/2021/160

**भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,**
**कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली**
**INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,**
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

**दिनांक/Dated** 6/10/21

सेवा मे,

सी.ई.ओ.एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
8 वां फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, 124 कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

**विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।**

महोदय,

मै इस पत्र के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) एवं 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करती हूँ। इन **शून्य** टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षको की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

संलग्नः शून्य टिप्पणियाँ

(रिना अकोइजम)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2021.**

The preparation of standalone financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **10 August, 2021.**

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the standalone financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** for the year ended 31 March 2021 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the**
**Comptroller and Auditor General of India**

**(Rina Akoijam)**
**Director General of Audit (Infrastructure)**
**New Delhi**

**Place: New Delhi**
**Dated: 6 October 2021**

## COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of consolidated financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **10 August, 2021**.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2021 under section 143(6) (a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED but did not conduct supplementary audit of the financial statements of its subsidiary viz. NICDC Neemrana Solar Power Company Limited. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the**
**Comptroller and Auditor General of India**



**Place: New Delhi**
**Dated: 6 October 2021**

**(Rina Akoijam)**
**Director General of Audit (Infrastructure)**
**New Delhi**

# AUDITOR'S REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

**S. P. CHOPRA & CO.**
Chartered Accountants

**Corporate Office**
**1505, Astralis Supernova**
**Sector-94, Gautam Buddha Nagar**
**Noida – 201 301**
**Phone 0120 - 4516921**
**www.spchopra.in**
**spc1949@spchopra.in**

## Compliance Certificate

We have conducted the audit of accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2021 in accordance with the directions/ sub-directions issued by the C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the directions/ sub-directions issued to us.

**For S.P. Chopra & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

**Ankur Goyal**
Partner
Membership No.099143

Place: New Delhi
Dated: August 10, 2021

**S. P. CHOPRA & CO.**
Chartered Accountants

Corporate Office
1505, Astralis Supernova
Sector-94, Gautam Buddha Nagar
Noida – 201 301
Phone 0120 - 4516921
www.spchopra.in
spc1949@spchopra.in

## Independent Auditor's Report
## To The Members of National Industrial Corridor Development Corporation Limited
## (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

### Report on the audit of the standalone financial statements

### Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** ("the Company"), which comprise the standalone balance sheet as at March 31, 2021, and the standalone statement of profit and loss and the standalone statement of cash flows for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021 and its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

### Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the *'Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements'* section of our report. We are independent of the company in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Information other than the standalone financial statements and auditor's report thereon

The company's board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the directors' report, including annexures, if any, thereon (but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon), which is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Contd..p/2

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance on conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report, including annexures, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

**Responsibility of management for the standalone financial statements**

The company's board of directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those board of directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

**Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

S.P. Chopra & Co. New Delhi Chartered Accountants

Contd..p/3

As part of an audit in accordance with the SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of internal financial controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

**Report on other legal and regulatory requirements**

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in **Annexure - 'A'**, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.




Contd..p/4

2. We are enclosing our report in terms of section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us by the management, in **Annexure - 'B'**, on the directions and sub-directions issued by Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

a) we have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

c) the standalone balance sheet, the standalone statement of profit and loss and the standalone statement of cash flows dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the accounting standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2016, to the extent notified;

e) on the basis of written representation received from the directors as at March 31, 2021 taken on record by the board of directors, none of the directors are disqualified as at March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of sub section (2) of section 164 of the Act;

f) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **Annexure - 'C'**;

g) the provisions of section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to company since the company is not a public company as defined under section 2(71) of the Act, hence this clause is not applicable; and

h) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements – Refer note 25 to the standalone financial statements;

ii) The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

S.P. Chopra & Co. New Delhi Chartered Accountants

Contd..p/5

iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company.

For S.P. CHOPRA & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000346N

Ankur Goyal
Partner
Membership No. 099143
UDIN 21099143AAAACY6093

Place: New Delhi
Dated: August 10, 2021

## Annexure - 'A' to Independent Auditor's Report

*(Referred to in paragraph '1' under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended March 31, 2021)*

Based on the audit procedures performed for the purpose of reporting a true and fair view on the standalone financial statements of the company and taking into consideration the information and explanations given to us and the books of account and other records examined by us in the normal course of audit, and to the best of our knowledge and belief, we report that:

(i) In respect of its property, plant and equipments;

a. The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and equipments.

b. As explained to us, the property, plant and equipments are physically verified by the management every year, which in our opinion is reasonable, having regard to the size of the company and nature of its property, plant and equipments. No material discrepancies were noticed on such physical verification.

c. The company does not hold immovable property hence the provisions of this clause is not applicable.

(ii) The Company does not hold inventory hence this clause is not applicable.

(iii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records, the company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Act.

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not entered into any transactions in respect of loans, investments, guarantees, and security covered under section 185 and 186 of the Act.

(v) As explained to us, the company has not accepted any deposits from the public within the meaning of section 73 to 76 of the Act and the rules framed thereunder to the extent notified.

(vi) Pursuant to the rules made by the Central Government of India, the company is not required to maintain cost records as specified under sub-section (1) of Section 148 of the Act, hence this clause is not applicable.

Contd..p/2

(vii) In respect of statutory dues:

a. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the undisputed statutory dues including provident fund, income-tax, goods and service tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues, as applicable have generally been regularly deposited with the appropriate authorities *though there have been delays in few cases* and no undisputed amounts payable in respect of aforesaid dues are outstanding as at March 31, 2021 for a period of more than six months from the date they became payable.

b. The disputed statutory dues aggregating to Rs. 51,70,949/- have been withheld by the department against the disallowances/ additions etc. against which company has filed appeal/ grievance before appropriate authorities as under:

| Sr. No. | Name of Statue | Nature of dues | Forum where dispute is pending | Period to which amount disputes relates | Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Income Tax Act, 1961 | Income-tax on completion of assessment | CIT (Appeals) | AY 2017-18 | 5,79,049 |
| 2 | | | | AY 2018-19 | 17,47,110 |
| 3 | | | Grievance to CPC | AY 2019-20 | 28,44,790 |
| | | | | **Total** | **51,70,949** |

(viii) According to the information and explanations given to us, the company has not taken loans and borrowings from the financial institution, bank, government or dues to debenture holders hence this clause is not applicable.

(ix) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has neither raised funds by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) nor availed any term loan during the year.

(x) In our opinion and according to the information and explanations given to us, no fraud by the company or material fraud on the company by its officers/ employees has been noticed or reported during the course of our audit.

(xi) The provisions of section 197 read with schedule V to the Act are not applicable to company since the company is not a public company as defined under section 2(71) of the Act, hence this clause is not applicable.

(xii) The company is not a nidhi company hence this clause is not applicable.

(xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable, and the requisite details of such transactions have been disclosed in the standalone financial statements, as required by the Accounting Standard 18 on Related Party Disclosures as specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2016, to the extent notified.

Contd..p/3

(xiv) As explained to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under audit.

(xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected with them.

(xvi) As explained to us, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For S.P. CHOPRA & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000346N

Ankur Goyal
Partner
Membership No. 099143
UDIN 21099143AAAACY6093

Place: New Delhi
Dated: August 10, 2021

## Annexure - '8' to Independent Auditor's Report

*(Referred to in paragraph 2 under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2021)*

Directions and Sub-Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 in respect of annual accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year 2020-21.

| Sr. No. | Directions/ Sub Directions | Auditor's Responses | Action taken thereon by management | Impact on standalone financial statements |
|---|---|---|---|---|
| A | **Directions** | | | |
| 1 | Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated. | According to information and explanations given to us, the accounting transcations of the company are accounted in 'Tally ERP9' accounting software and are not processed outside IT system. | No action is required | No Impact |
| 2 | Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? | According to information and explanations given to us, there is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan. | No action is required | No Impact |

Contd..p/2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Whether funds/ grants/ subsidy etc. received/ receivable for specific schemes from Central/ State government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation. | Government of India (GoI) approved setting up of project development fund (PDF) for undertaking various project development/ preparatory activities for various industrial corridor projects for which the company receives grant-in-aid from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) which is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'.<br><br>According to information and explanations given to us, grant-in-aid received during the year have been properly accounted for by the company as per its term and conditions and is disclosed in note 14 of the standalone financial statements. | No action is required | No Impact |
| B | Sub-Directions | | | |
| | NIL | | | |

For S.P. CHOPRA & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000346N

Ankur Goyal
Partner
Membership No. 099143
UDIN 21099143AAAACY6093

Place: New Delhi
Dated: August 10, 2021

## Annexure 'C' to Independent Auditor's Report

*(Referred to in paragraph 3(f) under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2021)*

**Report on the internal financial controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **'National Industrial Corridor Development Corporation Limited'** ("the Company") as at 31sl March, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the company for the year ended on that date.

**Management's responsibility for internal financial controls**

The board of directors of the company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the "Guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting" (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

**Auditor's responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting (the 'Guidance Note') and the standards on auditing, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

Contd..p/2



We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the company's internal financial controls system over financial reporting.

**Meaning of internal financial controls over financial reporting**

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

**Inherent limitations of internal financial controls over financial reporting**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Opinion**

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as at 31st March, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the guidance note on 'Audit of internal financial controls over financial reporting' issued by the 'Institute of Chartered Accountants of India'.

**For S.P. Chopra & Co.**
**Chartered Accountants**
**Firm Registration No. 000346N**

**Ankur Goyal**
**Partner**
**Membership No. 099143**
**UDIN 21099143AAAACY6093**

**Place: New Delhi**
**Date: August 10, 2021**

# FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

**National Industrial Corridor Development Corporation Limited**
**(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)**

CIN: U45400DL2008PLC172316

**Standalone Balance Sheet as at 31st March, 2021**

| Particulars | Note | | As at 31st March, 2021 (₹) | | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Equity & Liabilities** | | | | | |
| **Shareholders' funds** | | | | | |
| (a) Share capital | 3 | 1,00,00,00,000 | | 1,00,00,00,000 | |
| (b) Reserves and surplus | 4 | 7,20,42,39,917 | 8,20,42,39,917 | 6,64,44,64,486 | 7,64,44,64,486 |
| **Non-current liabilities** | | | | | |
| (a) Other long-term liabilities | 5 | - | | 10,00,000 | |
| (b) Long-term provisions | 6 | 50,82,006 | 50,82,006 | 40,34,648 | 50,34,648 |
| **Current liabilities** | | | | | |
| (a) Trade payables | 7 | | | | |
| (i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises | | 1,22,67,665 | | - | |
| (ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises | | 19,45,73,463 | | 34,67,21,642 | |
| (b) Other current liabilities | 8 | 3,92,32,340 | | 3,89,29,711 | |
| (c) Short-term provisions | 9 | 13,96,476 | 24,74,69,944 | 6,34,204 | 38,62,85,557 |
| Total | | | 8,45,67,91,867 | | 8,03,57,84,691 |
| **Assets** | | | | | |
| **Non-current assets** | | | | | |
| (a) Property, plant and equipment | 10 | 2,05,90,652 | | 2,29,08,194 | |
| (b) Intangible assets | 10 | 19,12,114 | | 28,72,205 | |
| (c) Non-current investments | 11 | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 | |
| (d) Deferred tax assets | 12 | 35,06,596 | | 23,56,521 | |
| (e) Long-term loans and advances | 13 | 5,54,010 | | 5,52,000 | |
| (f) Other non-current assets | 14 | 6,74,17,95,338 | 6,89,83,58,710 | 6,14,08,56,956 | 6,29,95,45,878 |
| **Current assets** | | | | | |
| (a) Trade receivables | 15 | 1,38,12,500 | | 1,32,50,000 | |
| (b) Cash and bank balances | 16 | 1,48,03,59,067 | | 1,61,56,66,589 | |
| (c) Short-term loans and advances | 17 | 66,37,827 | | 28,07,052 | |
| (d) Other current assets | 18 | 5,76,23,763 | 1,55,84,33,157 | 10,45,15,172 | 1,73,62,38,813 |
| Total | | | 8,45,67,91,867 | | 8,03,57,84,691 |
| Significant Accounting Policies | 2 | | | | |
| Notes to accounts attached form an integral part of the standalone financial statements | 3-37 | | | | |

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

Chhavi Goyal
(Partner)
(Membership No. 099143)

UDIN 21099143AAAACY6093

Place: New Delhi
Date : 10th August,2021

For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary

**National Industrial Corridor Development Corporation Limited**
**(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)**

CIN: U45400DL2008PLC172316

**Standalone Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2021**

| Particulars | Note | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|
| Revenue from operations | 19 | 25,00,00,000 | 13,28,00,400 |
| Other Income | 20 | 7,14,27,948 | 9,24,41,716 |
| **Total Revenue** | | **32,14,27,948** | **22,52,42,116** |
| **Expenses** | | | |
| - Employee benefits expense | 21 | 5,29,64,572 | 4,81,17,518 |
| - Depreciation and amortization expense | 22 | 86,40,502 | 68,23,649 |
| - Other expenses | 23 | 8,12,26,776 | 12,96,70,716 |
| **Total Expenses** | | **14,28,31,850** | **18,45,11,883** |
| **Profit before tax** | | **17,85,96,098** | **4,06,30,233** |
| **Tax expenses** | | | |
| - Current tax | | 5,32,43,105 | 1,22,16,066 |
| - Earlier year | | 58,795 | 7,732 |
| - Deferred tax | | (11,50,075) | (6,39,832) |
| **Profit for the year** | | **12,64,44,273** | **2,90,45,267** |
| **Earnings per equity share (face value of ₹ 10/- per share)** | 24 | | |
| - Basic earnings per share | | 1.26 | 0.29 |
| - Diluted earnings per share | | 1.26 | 0.29 |
| **Significant** Accounting Policies | 2 | | |
| **Notes** to accounts attached form an integral part of the **standalone** financial statements | 3-37 | | |

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

CA Ankur Goyal
(Partner)
(Membership No. 099143)

UDIN 21099143AAAAC46093

Place: New Delhi
Date : 10th August,2021

For and on behalf of the Board of Directors of

National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN 02855304)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Abhishek Chakradhary)
VP - Corporate Affairs, HR &
Company Secretary

**National Industrial Corridor Development Corporation Limited**
**(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)**
CIN: U45400DL2008PLC172316

**Standalone Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2021**

| Particulars | | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|
| **Cash flow from operating activities:** | | | |
| Profit before tax | | 17,85,96,098 | 4,06,30,233 |
| **Adjustments for:** | | | |
| Depreciation and amortization expense | | 86,40,502 | 68,23,649 |
| Loss on sale of property, plant and equipment | | 595 | 2,11,346 |
| Interest income | | (6,03,39,463) | (8,31,80,413) |
| Operating profit before working capital changes | | 12,68,97,732 | (3,85,15,185) |
| **Adjustments for :** | | | |
| (Increase)/ Decrease in trade receivables | | (5,62,500) | 2,39,72,026 |
| (Increase)/ Decrease in other receivables | | 1,93,09,667 | 85,85,342 |
| Increase/ (Decrease) in trade payables | | (13,98,80,514) | 5,82,84,662 |
| Increase/ (Decrease) in other payables | | 2,63,643 | (38,69,601) |
| **Cash generated from/ (used in) operating activities** | | 80,28,026 | 4,93,37,284 |
| Taxes paid (net of refunds) | | (3,09,56,320) | (2,20,21,272) |
| **Net cash from/ (used in) operating activities** | | (2,49,28,292) | 2,73,15,992 |
| **Cash flow from investing activities:** | | | |
| Funds received for project development expenses | | 45,00,00,000 | 52,70,00,000 |
| Interest earned on funds received for project development expense | | 92,26,079 | 2,07,33,908 |
| Utilisation of funds received for project development expenses | | (62,45,81,511) | (74,52,54,031) |
| Funds received for swachhta action plan | | 10,00,000 | - |
| Interest earned on funds received for swachhta action plan | | 203 | - |
| Utilisation of funds received for swachhta action plan | | (10,00,000) | - |
| (Purchase) of property, plant and equipment | | (53,63,964) | (2,37,17,201) |
| Sale of property, plant and equipment | | 500 | 50,593 |
| (Increase)/ Decrease in deposits with banks | | (9,94,81,710) | 97,36,618 |
| Interest income | | 6,03,39,463 | 8,31,80,413 |
| **Net cash from/ (used in) investing activities** | | (20,98,60,940) | (12,82,69,700) |
| **Cash flow from financing activities:** | | - | - |
| **Net cash from/ (used in) financing activities** | | - | - |
| **Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents** | | (23,47,89,232) | (10,09,53,708) |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the year | | 1,61,56,66,589 | 1,71,66,20,297 |
| **Cash and cash equivalents at the end of the year** | | 1,38,08,77,357 | 1,61,56,66,589 |
| **Components of cash and cash equivalents:** | | | |
| Cash on hand | | 2,153 | 8,373 |
| Balances with bank in current accounts | | 12,18,38,907 | 4,27,319 |
| Balances with bank in term deposits | | 1,25,90,36,297 | 1,61,52,30,897 |
| | | 1,38,08,77,357 | 1,61,56,66,589 |
| Significant Accounting Policies | 2 | | |
| Notes to accounts attached form an integral part of the standalone financial statements | 3-37 | | |

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

(CA Ankur Goyal)
(Partner)
(Membership No. 099143)

UDIN 21099143AAAAC46093

Place: New Delhi
Date : 10th August, 2021

For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02655304)

(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

**Note 1: Company Information**

The Government of India (GoI) announced the concept of Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project as the first industrial corridor in 2007 under Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry to embark on the process of planned urbanisation with manufacturing as the key economic driver and also to give a strong impetus to the country's industrial/ manufacturing development.

Accordingly, Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) was incorporated on 7th January 2008 as a Special Purpose Vehicle (SPV) for the development and implementation of DMIC project.

In September 2011, the Government of India approved the financial and institutional structure of DMIC project for the development of industrial cities in DMIC project and also approved the creation of dedicated fund with a revolving corpus known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF).

DMICDC is to act as a project development company to undertake various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new greenfield industrial smart cities. Also, DMICDC was mandated to act as the Project Development Partner/ Knowledge Partner to DMIC-PITF and also to all SPVs and State Government agencies for the implementation of DMIC.

The Government of India in December 2016, expanded the mandate of DMIC Project Implementation Trust Fund and redesignated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country

DMICDC was mandated to act as a knowledge partner to NICDIT in respect of all the industrial corridors in addition to DMIC work till Knowledge Partner(s) for other industrial corridors are put in place.

In view of the expanded mandate, the name of the company was changed from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC) with effect from 17th February 2020.

Subsequently, Government of India in December 2020 has approved the implementation of 11 Industrial Corridor projects (including 5 industrial corridors earlier approved) consisting of 32 projects, to be developed in 4 phases, under the industrial corridor programme, within the overall framework of National Master Plan for multi modal connectivity.

**Note 2: Significant Accounting Policies**

**2.1 Basis for preparation of standalone financial statements**

The accompanying standalone financial statements of the Company have been prepared and presented under the historical cost convention on accrual basis, as a going concern, in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (IGAAP), the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent notified and applicable and the mandatory accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, to the extent applicable and in the manner so required.

The accounting policies adopted in the preparation of financial statements have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The Company is a Level - III category enterprise under Small and Medium Sized Company (SMC) as defined in the General Instructions in respect of Accounting Standards notified under the Companies Act, 2013. Accordingly, the Company has complied with the Accounting Standards as applicable to a Small and Medium Sized Company.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle. Based on the nature of services and time between rendering of services and their realisation in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current or non-current classification of assets and liabilities.

**2.2 Use of estimates**

The preparation of standalone financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles ('GAAP') in India requires management to make estimates and assumptions, wherever necessary, that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of standalone financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Although such estimates and assumptions are made on a reasonable and prudent basis taking into account all available information, actual results could differ from these estimates and assumptions and such differences are recognized in the period in which the results are known/ materialized.

**2.3 Property, plant and equipment**

i) Property, Plant and Equipment (PPE) are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any

ii) Cost of acquisition/ construction is inclusive of freight, erection and commissioning charges, duties and taxes, expenditure during construction period upto the date of acquisition/ installation and other incidental expenses incurred during the construction/ installation stage.

iii) When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment.

iv) Subsequent expenditure related to an item of property, plant and equipment are added to its book value only if they increase the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. Repairs & maintenance costs are recognized in the statement of profit and loss as and when incurred.

v) Losses arising from the retirement, or profit/ losses arising from disposal of property, plant and equipment which are carried at cost, are recognised in the standalone statement of profit and loss in the year of retirement/ disposal.

vi) Depreciation on property, plant and equipment is charged on written down method over their estimated useful lives, in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013, retaining 5% of the cost as its residual value. However, if the management's estimate of the useful life of the asset is shorter than that envisaged in the aforesaid schedule, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful/ remaining life. The useful life of the assets in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013 and as estimated by the management is as under:

| Assets | Useful Life (in years) |
|---|---|
| Furniture and fixtures | 10 |
| Office equipment | 5 |
| Electrical installation and equipment | 10 |
| Computers - End user devices such as desktops, laptops etc. | 3 |
| Computers - Servers and networks | 6 |

vii) Property, plant and equipment costing upto ₹ 5,000/- each are fully depreciated in the year of acquisition.

viii) Depreciation on addition to property, plant and equipment is charged on pro-rata basis from the date the assets are ready for intended use over the estimated remaining useful life of the asset. Depreciation on sale/ discard/ destroy/ demolish of assets is charged upto the date of sale/ retrial of assets, as the case may be.

ix) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end

x) Property, plant and equipment, if any, retired from active use or held for disposal are stated at lower of cost (net of accumulated depreciation) or estimated net realizable value.

xi) The cost of leasehold improvement is amortised over the period of the lease

xii) Property, plant and equipment under construction and cost of assets not ready for intended use before the year-end, are shown as capital work in progress

xiii) Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under other non-current assets.

## 2.4 Intangible assets

Intangible assets are recognized where it is probable that the future economic benefit attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of assets can be measured reliably. Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in the standalone statement of profit and loss in the year in which the expenditure is incurred.

Intangible assets consist of computer software and are stated at cost of acquisition/ implementation less accumulated amortization. It is amortized over a period of 5 years or the license period on a straight line basis, whichever is earlier.

## 2.5 Impairment of assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date and if there is any indication of impairment based on internal/ external factors, the impairment loss is recognized. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is increased/ reversed where there has been change in the estimate of recoverable amount. The recoverable value is the higher of the assets' net selling price and value in use.

## 2.6 Grant-in-aid

### 2.6.1 Project Development Fund (PDF)

Government of India (GoI) approved setting up of project development fund (PDF) for undertaking various project development/ preparatory activities for various industrial corridor projects for which the Company receives grant-in-aid from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) which is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to GoI/ NICDIT from the fund will be reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance. Further, project development expenses (PDE) incurred on project development/ preparatory activities of various industrial corridors out of the fund are treated as under:

a) Expense related to subsidiaries of the Company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments, wherever recoverable in accordance with the stipulations in the Shareholders' Agreement are shown as recoverable from the concerned subsidiaries/ SPVs and disclosed under 'Other non-current assets';

b) Expense incurred for the projects which are not to be taken off or no further activities are to be carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s)./ Nodal Agency(ies) does not provide for recovery are reduced from the 'Project Development Funds' balance under 'Capital reserves'; and

c) Expense relating to the projects which are in progress and where the SPVs have not yet been incorporated due to the non execution of the Shareholders' Agreement or where the projects have not yet been approved for investment by NICDIT/CCEA or any other expense not covered under para (a) and (b) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head "Other non-current assets".

S.P. CHOPRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

2.6.2 Project Implementation Fund (PIF)

Government of India has approved setting up of a Project Implementation Fund (PIF) for undertaking various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project for which the grant-in-aid is received from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to GoI/ NICDIT from the fund will be reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance.

2.6.3 Swachhta Action Plan Fund (SAP)

Government of India has approved setting up of a Swachhta Action Plan Fund (SAP) for meeting the expenditure towards the Swachhta Action Plan for which the grant-in-aid is received from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to GoI/ NICDIT from the fund will be reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance and non-recoverable expenditure incurred therefrom is met out of fund balance.

2.7 Investments

Investments in subsidiaries are primarily meant to be held over long term period and are valued at cost less accumulated impairment losses, if any. Cost includes the acquisition cost and other incidental cost incurred for its acquisition. Provision is made in case there is a decline, other than temporary, in the carrying value of such investments. Indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investee's assets and results and the expected cash flows from the investments

Current investments are stated at the lower of cost or quoted price.

On disposal of investments, the difference between net disposal proceeds and the carrying amounts are recognized in the Statement of Profit and Loss.

2.8 Revenue Recognition

a) Revenue from provision of services rendered by the Company is recognised on accrual basis, to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Company and when the significant terms of arrangement are enforceable, services have been delivered, the collectability is reasonably assured and the revenue can be reliably measured. Accordingly, revenue on services is recognised as follows:

(i) Service fees @ 1% of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) is recognised to the maximum limit of ₹ 20,00,00,000 in a year, as approved by NICDIT in its meeting held on 26th July 2016.

(ii) Service fees @ 1% of yearly internal accruals towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited (IICC) as Knowledge Partner is recognized to a minimum of ₹ 5,00,00,000 and maximum of ₹ 10,00,00,000 per annum on pro-rata basis for an initial period of 10 years as stipulated in MOU executed with IICC

b) Interest income is recognized on time proportionate basis taking into account the amount outstanding and applicable rate of interest.

c) Dividend income is recognized when the company's right to receive dividend is established by the reporting date.

2.9 Leases

Lease arrangements, where the risk and rewards incidental to ownership of the assets, substantially vests with the lessor, are recognized as an operating lease. Lease payments under operating lease are recognized as an expense in the standalone statement of profit and loss on accrual basis.

2.10 Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency existing at the balance sheet date are translated at the exchange rate prevailing on that date. Exchange differences in case of borrowed funds and liabilities in foreign currency for the acquisition of property, plant and equipment from a country outside India are adjusted to its cost. All other exchange differences are recognized in the standalone statement of profit and loss. Premium or discount on forward exchange contract is amortized as expense or income over the life of the contract. Exchange difference on such contract is recognized in the standalone statement of profit and loss in the reporting period in which the exchange rates changes. Any profit or loss arising on cancellation or renewal of forward contract is recognized as income and expenditure during the period.

2.11 Employee benefits

a) Short term benefits:
These are recognized as an expense in the standalone statement of profit and loss for the year in which the related services are rendered. These benefits include leave salary and pension contribution to the government employees, on deputation to the company, which is accounted as per the prescribed rules of central government, accumulated compensated absences, which are expected to be availed or encashed within 12 months from the year end.

b) Defined contribution plan:
The company's contribution paid or payable during the year to statutory provident fund, pension scheme in accordance with Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 are recognized as an expense in the year in which the employee renders services.

c) Defined benefit plan:
Company's liability towards gratuity is determined by independent actuary, at the year-end using the projected unit credit method. Actuarial gains or losses as determined by the actuary are recognized in the standalone statement of profit and loss during the year in which actuarial valuation is done

**2.12 Segment reporting**

The operating segments are identified on the basis of internal reports used by the company's management to allocate resources and assess their performance for decision making. The Board of Directors is collectively the company's "chief operating decision maker" or "CODM" within the meaning of AS 17. The company has only one reporting segment of providing services as a knowledge partner for implementation of various industrial corridors and project(s) as approved by GoI.

**2.13 Taxes on income**

a) Tax expense comprises both current tax and deferred tax.

b) Current income tax, assets and liabilities are measured at the amount expected to be paid to or recoverable from the taxation authorities in accordance with the tax regime inserted by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 in the Income Tax Act, 1961, and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) enacted in India, by using tax rates and the tax laws that are enacted at the reporting date.

c) Deferred tax liability/ asset resulting from 'timing difference' between accounting income and taxable income, that is capable of reversal in subsequent accounting period is accounted for considering the tax rate and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the reporting date. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date for their realizability.

d) Minimum alternate tax (MAT) is charged to the standalone statement of profit and loss as current tax during the year in which it is paid. The company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent that there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e. the period for which MAT credit is allowed to be carried forward. The company recognizes MAT credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternative Tax under the Income-tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the standalone statement of profit and loss and shown as "MAT Credit Entitlement." The company reviews the "MAT credit entitlement" asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the company does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the specified period.

**2.14 Earnings per share**

The Company reports Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning Per Share".

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year, as adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares, except where the results of all dilutive potential equity shares, except where the results are anti-dilutive.

**2.15 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

Provisions are recognised when there is a present obligation as a result of a past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation on reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adopted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in the Notes when there is a possible obligation arising from past event(s), the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past event(s) where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle or a reliable estimate of the amount cannot be made.

Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

**2.16 Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalents include cash in hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with original maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalent and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

**2.17 Cash Flow Statements**

The cash flow statement is prepared by the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard 3 on "Cash Flow Statements" and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the Company.

Cash and cash equivalents presented in the standalone cash flow statement consist of cash in hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with original maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalent.

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 3: Share capital** | | |
| **Authorised** | | |
| 10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| **Issued, subscribed and fully paid up** | | |
| 10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| Total | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |

3.1 **Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the year:**

| | As at 31st March, 2021 | | As at 31st March, 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | No. of shares | (₹) | No. of shares | (₹) |
| Balance at the beginning of the year | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| Add: Shares issued during the year | - | - | - | - |
| Balance at the end of the year | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |

3.2 **Terms/ rights attached to equity shares**

The Company has only one class of equity shares having a par value of ₹ 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The Company may declare and pay dividend in Indian rupees. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting. During the year ended 31st March, 2021, no dividend was declared and distributed by the company. (Also refer note 34 for further details on dividend). In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

3.3 **Details of shareholders holding more than 5% shares in the company**

| | As at 31st March, 2021 | | As at 31st March, 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | No. of shares | % of Holding | No. of shares | % of Holding |
| The President of India (Through Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and its nominees) | 4,90,00,000 | 49.00 | 4,90,00,000 | 49.00 |
| Japan Bank for International Co-operation (JBIC) | 2,60,00,000 | 26.00 | 2,60,00,000 | 26.00 |
| Housing and Urban Development Corporation Limited | 1,99,00,000 | 19.90 | 1,99,00,000 | 19.90 |

3.4 The Company has not issued bonus shares, issued any shares without payment being received in cash or brought-back shares during five years immediately preceding the balance sheet date.

*(This space has been intentionally left blank)*

## Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | | | As at 31st March, 2021 (₹) | | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Note 4: Reserves and surplus** | | | | | |
| (a.) Capital reserves - Grant-in-aid received for: (Refer note 2.6) | | | | | |
| (i) Project development fund | | | | | |
| As per last balance sheet | | 6,35,20,27,000 | | 5,82,50,27,000 | |
| Add: Grant-in-aid received during the year | | 45,00,00,000 | 6,80,20,27,000 | 52,70,00,000 | 6,35,20,27,000 |
| Add: Interest etc. earned on project development fund | | | | | |
| As per last balance sheet | | 31,33,51,562 | | 29,26,17,655 | |
| Interest on term deposits and tax refunds during the year | | 92,26,079 | 32,25,77,641 | 2,07,33,907 | 31,33,51,562 |
| (Less): Project development expenses, to the extent not recoverable | | | | | |
| As per last balance sheet | | (37,98,70,926) | | (33,40,67,373) | |
| Expenses incurred during the year | | (2,36,43,131) | (40,35,14,057) | (4,58,03,553) | (37,98,70,926) |
| (Less): Tax impact on income earned on project development fund | | | (22,51,993) | | - |
| | (i) | | 6,71,88,38,591 | | 6,28,55,07,636 |
| (ii) Project implementation fund | | | | | |
| As per last balance sheet (Refer note 11.1) | | | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 |
| | (ii) | | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 |
| (iii) Swachhta Action Plan | | | | | |
| Grant-in-aid received during the year | | | 10,00,000 | | - |
| Add: Interest on term deposits during the year | | | 203 | | - |
| (Less): Expenses incurred during the year | | | (10,00,000) | | - |
| | (iii) | | 203 | | - |
| Sub-total | | | 6,84,88,38,794 | | 6,41,55,07,636 |
| (b.) Surplus | | | | | |
| As per last balance sheet | | 22,89,56,850 | | 19,99,10,583 | |
| Add: Profit for the year | | 12,64,44,273 | 35,54,01,123 | 2,90,46,267 | 22,89,56,850 |
| Total | | | 7,20,42,39,917 | | 6,64,44,64,486 |

*(This space has been intentionally left blank)*

## Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 5 : Other long-term liabilities** | | |
| Performance security | - | 10,00,000 |
| Total | - | 10,00,000 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 6 : Long-term provisions** | | |
| Provision for employee benefits<br>- Gratuity (Refer note 26) | 50,82,006 | 40,34,648 |
| Total | 50,82,006 | 40,34,648 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 7 : Trade payables** | | |
| Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer note 7.1) | 1,22,67,665 | - |
| Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises | 19,45,73,463 | 34,67,21,642 |
| Total | 20,68,41,128 | 34,67,21,642 |

7.1 Information pursuant to the provisions of Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is given below. This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| i) The principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier covered under MSMED Act at the end of the year | | |
| - Principal | 1,22,67,665 | - |
| - Interest | - | - |
| ii) The amount of interest paid by the Company in terms of section 16 of the MSMED Act, 2006 alongwith the amount of the payment made to the suppliers beyond the appointed day during the year | - | - |
| iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act 2006 | - | - |
| iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year; and | - | - |
| v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act 2006 | - | - |

**Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021**

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 8 : Other current liabilities** | | |
| Statutory liabilities | 2,39,19,126 | 2,00,42,380 |
| Accrued expenses | 16,31,541 | 16,25,258 |
| Creditors for expenses | 82,06,535 | 1,69,76,866 |
| Employee related payable | 4,75,139 | 2,85,207 |
| Bid security | 50,00,000 | - |
| Total | 3,92,32,340 | 3,89,29,711 |

| Particulars | | As at 31st March, 2021 (₹) | | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **Note 9 : Short-term provisions** | | | | |
| **Provision for employee benefits** | | | | |
| - Gratuity (Refer note 26) | 3,78,464 | | 4,73,546 | |
| - Leave encashment | 1,69,397 | 5,47,861 | 1,60,658 | 6,34,204 |
| **Other provisions** | | | | |
| - Provision for taxation (net of advance tax of ₹ 5,46,46,464/- (Previous year : ₹ 2,43,65,442/-)] | | 8,48,615 | | - |
| Total | | 13,96,476 | | 6,34,204 |

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

**National Industrial Corridor Development Corporation Limited**
**(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)**
CIN: U45400DL2008PLC172316

**Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021**

**Note 10 : Property, plant and equipment and intangible assets**

(₹)

| Particulars | Gross block | | | | Depreciation/ Amortization | | | | Net block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at 1st April, 2020 | Additions during the year | Sales/ disposal/ adjustments during the year | As at 31st March, 2021 | As at 1st April, 2020 | For the year (Refer note 10.2) | Sales/ disposal/ adjustments during the year | As at 31st March, 2021 | As at 31st March, 2021 | As at 31st March, 2020 |
| Furniture and fixtures | 52,42,629 | - | - | 52,42,629 | 12,14,426 | 10,44,258 | - | 22,58,684 | 29,83,945 | 40,28,203 |
| Office equipment | 1,29,45,071 | 14,64,009 | (21,900) | 1,43,87,180 | 58,43,723 | 35,62,682 | (20,805) | 93,85,600 | 50,01,580 | 71,01,348 |
| Electrical installations and equipment | 13,80,839 | - | - | 13,80,839 | 2,20,892 | 3,01,247 | - | 5,22,139 | 8,58,700 | 11,59,947 |
| Computer and data processing units | 45,46,554 | 20,99,998 | 12,881 | 66,59,433 | 32,28,557 | 14,02,216 | 5,152 | 46,35,925 | 20,23,508 | 13,17,997 |
| Leasehold Improvements (Office Renovation) | 1,41,51,474 | 14,21,007 | - | 1,55,72,481 | 48,50,775 | 8,98,787 | - | 58,49,562 | 97,22,919 | 93,00,699 |
| **Current year's total** | **3,82,66,567** | **49,85,014** | **(9,019)** | **4,32,42,562** | **1,53,58,373** | **73,08,190** | **(15,653)** | **2,26,51,910** | **2,05,90,652** | **2,29,08,194** |
| **Previous year's total** | **1,37,84,852** | **2,71,85,261** | **27,03,546** | **3,82,66,567** | **1,26,44,243** | **52,55,736** | **(24,41,606)** | **1,53,58,373** | **2,29,08,194** | |
| Intangible assets | | | | | | | | | | |
| Computer software | 81,62,543 | 3,78,950 | (12,881) | 85,28,612 | 52,90,338 | 13,31,312 | (5,152) | 66,16,498 | 19,12,114 | 28,72,205 |
| Current year's total | 81,62,543 | 3,78,950 | (12,881) | 85,28,612 | 52,90,338 | 13,31,312 | (5,152) | 66,16,498 | 19,12,114 | 28,72,205 |
| **Previous year's total** | **81,21,018** | **41,525** | **-** | **81,62,543** | **37,22,427** | **15,87,911** | **-** | **52,90,338** | **28,72,205** | |

10.1) Pursuant to "AS28- Impairment of Asset" issued by the Central Government under the Companies (Accounting Standard) Rule 2006 for determining impairment in carrying amount of property, plant and equipment, the company has concluded that since recoverable amount of property, plant and equipment is not less than its carrying amount, therefore, no provision for impairment is required in respect of property, plant and equipment owned by the Company.

**10.2) Reconciliation of depreciation charged during the year**

| | Property, plant and equipment | | Intangible assets |
|---|---|---|---|
| | Computer and data processing units | Leasehold Improvements (Office renovation) | Computer Software |
| Depreciation as per note 10 above | 14,02,216 | 9,98,787 | 13,31,312 |
| Depreciation/Amortisation for earlier year | 1,53,626 | (4,490) | 2,48,489 |
| **Depreciation for the year** | **15,55,842** | **9,94,297** | **15,79,801** |

## Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 11: Non-current investments** | | |
| (Unquoted, at cost) | | |
| Non-trade investment in 1,30,00,000 (Previous year: 1,30,00,000) fully paid-up equity shares of ₹ 10/- each of NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited), wholly owned subsidiary company out of project implementation fund.(Refer note 11.1) | 13,00,00,000 | 13,00,00,000 |
| (Less) : Diminution in value of investments | - | - |
| Total | 13,00,00,000 | 13,00,00,000 |

**11.1 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- was transferred to NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust Fund (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund) out of Main Corpus/ Capital Funds of the Trust during the financial year 2013-14 for onward release to SPV namely "NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited)" towards 100% equity investment of the Trust through NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) for the implementation of 8 MW model solar power project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Ltd (Formerly known as DMICDC Limited). The amount received from the Trust has been shown as Project Implementation Fund (PIF) under capital reserves in note 4.**

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 12 : Deferred tax assets** | | |
| Deferred tax assets: | | |
| - Difference between depreciation/ amortisation as per account and as per tax | 19,28,317 | 10,58,091 |
| - Timing difference on account of expenses allowable on payment basis | 15,78,279 | 12,98,430 |
| Total | 35,06,596 | 23,56,521 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 13 : Long-terms loans and advances** | | |
| (Unsecured, considered good) | | |
| Security deposits | 5,52,000 | 5,52,000 |
| Prepaid expenses | 2,010 | - |
| Total | 5,54,010 | 5,52,000 |

*(This space has been intentionally left blank)*






| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 14 : Other non-current assets** | | |
| (Unsecured, considered good) | | |
| **Project development expenditure (PDE) against project development fund (Refer note 2.6.1)** | | |
| As per last balance sheet | 1,03,76,58,606 | 98,54,71,322 |
| **Add:** Expense incurred during the year [Net of bid processing fee of ₹ 91,50,000/- (Previous year: Nil)] | 62,45,81,511 | 74,84,16,179 |
| | 1,66,22,40,117 | 1,73,18,87,501 |
| (Less) Transferred to subsidiary/ SPVs | (54,71,07,299) | (64,84,25,342) |
| (Less): Transferred to project development funds | (2,36,43,131) | (4,58,03,553) |
| **Sub-total** | 1,09,14,89,687 | 1,03,76,58,606 |
| **Project development expenses recoverable from SPVs (Refer note 2.6.1, 14.1 and 14.2)** | | |
| - Aurangabad Industrial Township Limited | 2,02,62,02,357 | 1,76,93,26,213 |
| - Dholera Industrial City Development Limited | 3,17,83,68,542 | 2,91,46,67,473 |
| - Dholera International Airport Company Limited | - | 6,59,998 |
| - NICDC Haryana Global City Project Ltd | 8,89,56,428 | 8,48,84,336 |
| - NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited | 5,48,59,660 | 4,84,10,060 |
| - DMIC Haryana MRTS Project Limited | 6,87,98,081 | 6,87,12,587 |
| - DMIC Vikram Udyogpuri Limited | 5,07,54,677 | 5,07,54,677 |
| - Integrated Industrial Township Greater Noida Limited | 8,80,82,730 | 7,45,06,230 |
| - NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited | 9,42,73,176 | 9,19,36,776 |
| | 5,65,03,05,651 | 5,10,38,58,350 |
| (Less): Dholera International Airport Company Limited transferred to other current assets (Refer note 16) | - | (6,59,998) |
| **Sub-total** | 5,65,03,05,651 | 5,10,31,98,352 |
| **Total** | 6,74,17,95,338 | 6,14,08,56,958 |

14.1 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) in its 3rd meeting held on 6th March 2018 has directed the Company to transfer the project development expenditure incurred by the Company in relation to projects of the subsidiaries/ SPVs out of project development funds provided as Grant-in-aid to the respective subsidiaries/ SPVs and to defer its recovery till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds. The respective subsidiaries/ SPVs have not been able to generate sufficient surplus funds hence the amount recoverable from them has not fallen due for recovery as at 31st March, 2021

14.2 **Movement of project development expenditure recoverable from SPVs**

**As at 31st March, 2021**

| SPV | Balance as at 31st March, 2020 (₹) | Expenditure incurred during the year (₹) | Amount received during the year (₹) | Balance as at 31st March, 2021 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| - Aurangabad Industrial Township Limited | 1,76,93,26,213 | 25,68,76,144 | - | 2,02,62,02,357 |
| - Dholera Industrial City Development Limited | 2,91,46,67,473 | 26,37,01,069 | - | 3,17,83,68,542 |
| - Dholera International Airport Company Limited | 6,59,998 | - | (6,59,998) | - |
| - NICDC Haryana Global City Project Ltd. | 8,48,84,336 | 40,82,092 | - | 8,89,66,428 |
| - NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited | 4,84,10,060 | 64,49,600 | - | 5,48,59,660 |
| - DMIC Haryana MRTS Project Limited | 6,87,12,587 | 85,494 | - | 6,87,98,081 |
| - DMIC Vikram Udyogpuri Limited | 5,07,54,677 | - | - | 5,07,54,677 |
| - Integrated Industrial Township Greater Noida Limited | 7,45,06,230 | 1,35,76,500 | - | 8,80,82,730 |
| - NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited | 9,19,36,776 | 23,36,400 | - | 9,42,73,176 |
| | 5,10,38,58,350 | 64,71,07,299 | (6,59,998) | 5,68,03,05,651 |

## Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021

As at 31st March, 2020

| SPV | Balance as at 31st March, 2019 (₹) | Expenditure incurred during the year (₹) | Amount received during the year (₹) | Balance as at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| - Aurangabad Industrial Township Limited | 1,46,97,03,648 | 29,96,22,565 | - | 1,76,93,26,213 |
| - Dholera Industrial City Development Limited | 2,59,99,60,739 | 31,47,06,734 | - | 2,91,46,67,473 |
| - Dholera International Airport Company Limited | 50,91,152 | 11,62,148 | (55,93,302) | 6,59,998 |
| - NICDC Haryana Global City Project Ltd. | 8,08,02,244 | 40,82,092 | - | 8,48,84,336 |
| - NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited | 3,89,65,417 | 95,44,643 | - | 4,84,10,060 |
| - DMIC Haryana MRTS Project Limited | 6,87,12,587 | - | - | 6,87,12,587 |
| - DMIC Vikram Udyogpuri Limited | 5,07,54,677 | - | - | 5,07,54,677 |
| - Integrated Industrial Township Greater Noida Limited | 7,45,06,230 | - | - | 7,45,06,230 |
| - NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited | 7,26,29,616 | 1,93,07,160 | - | 9,19,36,776 |
| | 4,48,10,26,310 | 64,84,25,342 | (55,93,302) | 5,10,38,58,350 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 15 : Trade receivables** | | |
| (Unsecured, considered good) | | |
| Other receivables* (Refer note 15.1) | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| **Total** | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| 15.1 Includes amount due from: | | |
| India International Convention and Exhibition Centre Limited - Enterprise over which KMP exercise significant influence | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| **Total** | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |

* since realised

*(This space has been intentionally left blank)*

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | | As at 31st March, 2021 (₹) | | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **Note 16 : Cash and bank balances** | | | | |
| **Cash and cash equivalents** | | | | |
| Cash on hand | | 2,153 | | 8,373 |
| Balances with banks in current accounts | | | | |
| - Project Development Fund | 2,22,651 | | 2,02,324 | |
| - Swachhta Action Plan | 288 | | - | |
| - Company Fund | 12,16,15,970 | 12,18,38,907 | 2,24,995 | 4,27,319 |
| Balance with banks in term deposits | | | | |
| - Project Development Fund | 7,69,25,000 | | 48,05 55,897 | |
| - Company Fund | 1,18,01,11,297 | 1,25,80,36,297 | 1,13,46,75,000 | 1,61,52,30 897 |
| **Other bank balances** | | | | |
| Balance with banks in term deposits | | | | |
| - Project Development Fund | | 9,94,81,710 | | - |
| **Total** | | 1,48,03,59,067 | | 1,61,56,66,589 |

| Particulars | | As at 31st March, 2021 (₹) | | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **Note 17 : Short-term loans and advances** | | | | |
| (Unsecured, considered good) | | | | |
| Advance to vendors | | 2,49,163 | | 64,494 |
| Staff advance | | 50,996 | | 3,70,055 |
| Prepaid expenses | | 20 80,144 | | 9 28,044 |
| Balance with revenue authorities | | 9.85.559 | | - |
| Recoverable on account of apportionment of overheads from | | | | |
| (i) NICDC Neemrana Solar Power Limited | 26,08,965 | | 8,08,459 | |
| (ii) India International Convention and Exhibition Centre Limited | 6,63,000 | 32,71 965 | 5,36,000 | 14,44,459 |
| **Total** | | 66,37,827 | | 28,07,052 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 18 : Other current assets** | | |
| Interest accrued on term deposits [includes on account of PDF of ₹ 7,24,085/- (Previous Year-₹ 41,75,663/-)] | 4,91,37 995 | 7 17,10,610 |
| Income tax refundable [Refer note 25(iii)] | 83,95,605 | 1,99,95,188 |
| Other recoverable | 90,163 | - |
| Recoverable from SPV | - | 6 59 998 |
| Advance tax (Net of provision for taxation for Previous year of ₹ 1,22,16,066/-) | - | 1,21,49,376 |
| **Total** | 5,78,23,763 | 10,45,15,172 |

*(This space has been intentionally left blank)*

## Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 19 : Revenue from operations** | | |
| **Service fees as knowledge partner** to (Refer note 2.8) | | |
| National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) | 20,00,00,000 | 8,28,00,400 |
| India International Convention and Exhibition Centre Limited (IICC) | 5,00,00,000 | 5,00,00,000 |
| **Total** | **25,00,00,000** | **13,28,00,400** |

| Particulars | | Year ended 31st March, 2021 (₹) | | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **Note 20 : Other income** | | | | |
| Interest on term deposits on company funds | | 6,03,39,463 | | 6,31,80,413 |
| Interest on income tax refund | | 15,56,597 | | - |
| Apportionment of overheads from (Refer **note 20.1**): | | | | |
| (i) India International Convention and **Exhibition** Centre Limited | 72,00,000 | | 86,44,305 | |
| (ii) NICDC Neemrana Solar Power Limited | 23,00,866 | 95,00,866 | 26,16,178 | 92,60,483 |
| Miscellaneous income | | 31,022 | | 820 |
| **Total** | | **7,14,27,948** | | **9,24,41,716** |

**20.1** Overhead cost towards office premises and other administrative support provided by the company is recovered from the respective company on proportionate basis, as per past practise.

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 21: Employee benefits expense** | | |
| Salary, wages, gratuity, compensated absence, allowances etc. | 4,70,34,980 | 4,21,14,060 |
| Contribution to provident and other funds | 37,23,093 | 32,63,075 |
| Staff welfare expenses | 22,06,499 | 27,40,383 |
| **Total** | **5,29,64,572** | **4,81,17,518** |

*(This space has been intentionally left blank)*

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 22: Depreciation and amortization expense** | | |
| Depreciation on property, plant and equipment | 73,09,190 | 52,55,738 |
| Amortization of intangible assets | 13,31,312 | 15,67,911 |
| **Total** | **86,40,502** | **68,23,649** |

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 23: Other expenses** | | |
| Rent ( Refer note 23.1 and 29) | 4,86,03,024 | 5,66,79,394 |
| **Payment to Auditors (Refer note 23.2)** | | |
| Audit fees | 3,30,000 | 3,30,000 |
| Certification fees | 5,500 | 1,05,100 |
| Advertisement and business promotion | 81,06,775 | 4,41,90,512 |
| Corporate social responsibility expense (Refer note 31) | 11,96,567 | 21,20,824 |
| Electricity | 10,01,062 | 8,39,673 |
| Housekeeping | 17,42,671 | 15,54,785 |
| Security | 8,55,544 | 6,79,488 |
| Professional and consultancy charges | 38,56,542 | 26,45,172 |
| Meeting and refreshment | 2,01,549 | 3,88,728 |
| Repair and maintenance - office | 38,57,398 | 37,77,248 |
| Repair and maintenance - computers | 26,86,034 | 29,21,718 |
| Printing and stationery | 19,19,731 | 19,33,021 |
| Communication and postage | 15,65,381 | 14,63,594 |
| Travelling and conveyance | 26,52,634 | 57,99,852 |
| Insurance | 25,355 | 25,119 |
| Director's sitting fees | - | 2,40,000 |
| Loss on sale of property, plant and equipment | 595 | 2,11,346 |
| Prior period expenses (Refer note 23.3) | 2,52,806 | 33,315 |
| Stipend | 3,00,548 | 2,79,145 |
| Miscellaneous expenses | 20,67,049 | 34,52,682 |
| **Total** | **8,12,26,776** | **12,96,70,716** |

23.1 Rent includes municipal taxes of ₹ 1,03,07,412/- (Previous Year ₹ 1,03,07,412/-) paid to lessor in terms of lease agreement.

23.2 Auditors remuneration for the year ended 31st March, 2020 pertains to payment made to previous auditors.

**23.3 Details of prior period expenses are as under :**

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| Advertisement and business promotion | 2,25,277 | - |
| Communication and postage | 11,021 | - |
| Travelling and conveyance | 16,108 | - |
| Professional and consultancy charges | 400 | 25,000 |
| Printing and stationery | - | 8,315 |
| | **2,52,806** | **33,315** |

*(This space has been intentionally left blank)*

24 **Earnings per share**

Basic earnings per equity share have been computed by dividing profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year

| Particulars | Year ended 31st March,2021 (₹) | Year ended 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| a Profit after tax attributable to equity shareholders | 12,64,44,273 | 2,80,46,267 |
| b Weighted average of number of equity shares used as denominator for calculating EPS (Nos.) | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| c Basic/ Diluted Earnings per share (a/b) | 1.26 | 0.29 |
| d Face value per equity share | 10.00 | 10.00 |

25 **Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):**

**(i) Contingent liabilities**

- Claims against the Company not acknowledged as debts -
- Guarantees issued by Bank on behalf of the Company -

**(ii) Commitments**

Estimated amount of consultancy contracts for project development activities remaining to be executed and not provided for 1,61,58,82,643 1,08,92,27,425

**(iii) Taxation matters**

Income tax matters under appeal/ rectification

| Assessment Year | Refund claimed (₹) | Refund received as per order (₹) | Balance refund withheld (₹) | Reason for withheld | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 52,64,553 | 45,85,504 | 6,79,049 | AO has disallowed the expense of ₹ 17,12,903/- vide order dated 26.12.2019 u/s 143(3) | Appeal has been filed to CIT on 08.01.2020, date of hearing is awaited |
| 2018-19 | 49,71,780 | 32,24,850 | 17,47,110 | AO has disallowed the expense of ₹ 4,34,057/- and made addition of income of ₹ 58,89,181/- vide order dated 26.04.2021 u/s 143(3) | Appeal has been filed to CIT on 13.05.2021, date of hearing is awaited |
| 2019-20 | 97,58,870 | 69,14,080 | 28,44,790 | TDS credit mismatch of ₹ 28,44,790/- in the intimation received u/s 143(1) dated 23.10.2020 | Grievance has been filed on the portal on 19.06.2021, redressal of same is awaited |
| Total | | | 51,70,949 | | |

The Company is contesting these demands and the management including its advisers are of the view that these demands may not be sustainable at the appellate level. The management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the Company's financial position and results of operations. The Company does not expect any reimbursement in respect of these contingent liabilities, and it is not practicable to estimate the timing of cash outflows, if any, in respect of these matters, pending resolution of the appellant proceedings.

(iv) The status of legal cases filed against the company with no financial implication as at 31 March, 2021 is as under:

| Sr. No. | Writ Petition No. & Date | Petitioners | Respondents | Subject Matter | Brief Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9282/2015 | Subh Ram & Ors | NICDC Ltd. & Ors | Related to Land Acquisition in the State of Rajasthan. | Counter affidavit requesting the Court to delete the name of NICDC (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties has been filed with the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench<br><br>The Petitioners have filed an application for amending the Writ Petition. The said application has been allowed by the Hon'ble High Court.<br><br>The counter affidavit has been submitted by NICDC in respect of the amended Writ Petition also<br><br>An application requesting change of name of Company from DMICDC to NICDC has been filed before the Hon'ble Court on 8th September, 2020.<br><br>Next date of hearing is awaited |
| 2 | 6649/2016 | Irshad Mohd. Khan and Ors | NICDC Ltd. & Ors | Related to water pipeline laid down from Jayakwadi Dam to Shendra Industrial Park in Aurangabad | An application has been filed before the Hon'ble High Court of Bombay, Aurangabad Bench on 18-01-2019 under Order 1 Rule 10 of Code of Civil Procedure, 1908 requesting the Court to delete the name of NICDC Ltd. (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties on the ground that the applicant is neither a proper party nor a necessary party to the Writ Petition<br><br>Next date of hearing is awaited |

26 **Disclosures as per Accounting Standard 15 (Revised 2005) on "Employee Benefits":**

a) General description of various defined employee schemes are as under:

**i) Defined contribution plan**

Provident Fund (PF) - The contribution towards the Provident Fund is deposited with the Regional Provident Fund Commissioner. The amount so paid is charged to the standalone statement of profit and loss

**ii) Defined benefit plans**

a. **Gratuity (unfunded):** The Company has a defined benefit gratuity plan for its employees. Under the gratuity plan, every employee who has rendered continuous service of at least five years is entitled for gratuity on departure at 15 days of last drawn salary (basic salary and dearness allowance) for each completed year of service subject to a prescribed maximum limit of ₹ 20,00,000/-. The liability towards gratuity arises on superannuation, resignation, termination, disablement or death. The Company's obligation in respect of the gratuity plan is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

b. **Leave encashment (unfunded):** As per the policy , the employees are entitled to 30 leaves for each calendar year, out of which maximum of 10 leaves can be encashed during the year itself and balance leaves can be carried forward subject to maximum of 90 days accumulated leaves which are non encashable at the time of superannuation, resignation, termination, disablement or death . Accordingly, the Company's obligation towards leave encashment is calculated on proportionate leaves for balance period based on amount of basic salary.

b) Other disclosures as required under AS-15 (Revised 2005) on Employee Benefits in respect of Defined Benefit Plan are as under:

**i) Defined contribution plan**

Contribution to defined contribution plan, recognised as expense for the year is as under:

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| Employer's contribution to provident fund | 31,04,083 | 27,47,849 |

**ii) Defined benefit plans**

Gratuity (unfunded)

The following tables summarize the components of net benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss, the funded/ unfunded status and amounts recognized in the standalone balance sheet for defined benefit plan

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Employee benefit expense recognised in the standalone statement of profit and loss** | | |
| Current service cost | 9,81,476 | 8,49,601 |
| Past service cost | - | - |
| Interest cost on benefit obligation | 3,04,303 | 2,31,586 |
| Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year | 3,78,085 | 2,27,359 |
| Employee benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss | 16,63,864 | 13,08,546 |
| **Amount recognized in the standalone balance sheet** | | |
| Present value of defined benefit obligation | 54,60,470 | 45,08,194 |
| Fair value of plan assets | - | - |
| Asset/ (liability) recognized in the standalone balance sheet | (54,60,470) | (45,08,194) |
| **Changes in the present value of the defined benefit obligation** | | |
| Defined benefit obligation at the beginning of the year | 45,08,194 | 34,30,902 |
| Current service cost | 9,81,476 | 8,49,601 |
| Past service cost | - | - |
| Interest cost | 3,04,303 | 2,31,586 |
| Benefits paid | (7,11,568) | (2,31,254) |
| Actuarial (gains)/ losses on obligation | 3,78,085 | 2,27,359 |
| Defined benefit obligation at the end of the year | 54,60,470 | 45,08,194 |
| **Breakup of the defined benefit obligation** | | |
| Non-current | 50,82,006 | 40,34,648 |
| Current | 3,78,464 | 4,73,546 |
| | 54,60,470 | 45,08,194 |
| **The principal assumptions used in determining obligations:** | | |
| Method used | Projected unit credit method | Projected unit credit method |
| Mortality table | IALM 2012-14 | IALM 2012-14 |
| Withdrawal rate upto 30/ 44 years/ above 44 years (%) | 8.00% per annum | 8.00% per annum |
| Discount rate (%) | 6.75% per annum | 6.75% per annum |
| Future salary increase (%) | 6.50% per annum | 6.00% per annum |
| Retirement age (No. of years) | 60 years | 60 years |

27 **Segment reporting**

The Company's principal business is being the knowledge partner for implementation and development of various industrial corridors and other project(s) as approved by Government of India and there are no other geographical segment in accordance with AS 17 - "Segment Reporting".

## 26 Related party disclosures

In accordance with the requirements of Accounting standard-18 "Related party disclosure", the names of the related party where control/ ability to exercise significant influence exists, along with the aggregate amounts of transactions and year end balances with them, as identified and certified by the management are given below

### I List of related parties and nature of relationship where control exists

**a Enterprises having significant influence/control over the company**
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)

**b Subsidiaries**
NICDC Neemrana Solar Power Limited
(Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd.)

**c Affiliates/ Associates**
Housing and Urban Development Corporation Limited

**d Key Management Personnel (KMP)**

| | |
|---|---|
| Shri K Sanjay Murthy (w.e.f 18th November 2019) | CEO and Managing Director |
| Shri Alkesh Kumar Sharma (till 15th September 2019) | CEO and Managing Director |
| Shri Prashanth Kumar Salsavar (For the period 17th June 2019 to 5th July 2019) | Additional Charge as CEO and Managing Director |
| Shri Rajendra Ratnoo (For the period 19th September 2019 to 17th November 2019) | Additional Charge as CEO and Managing Director |
| Shri P K Agarwal | Chief Financial Officer |
| Shri Abhishek Chaudhary | VP-Corporate Affairs, HR and Company Secretary |

**e Enterprises over which KMP exercises significant influence**
India International Convention and Exhibition Centre Ltd (For the period 17th June 2019 to 5th July 2019, 28th November 2020 to 13th December 2020 and w.e.f 30th June 2021)

### II The following transactions were carried out with related parties in the ordinary course of business:

| Particulars | Year ended 31st March,2021 (₹) | Year ended 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Salary/ remuneration** | | |
| Shri K Sanjay Murthy | 56,92,743 | 19,00,183 |
| Shri Alkesh Kumar Sharma | - | 32,30,880 |
| Shri P K Agarwal | 53,82,579 | 51,83,445 |
| Shri Abhishek Chaudhary | 52,98,520 | 50,81,023 |
| **Reimbursements** | | |
| NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd.) | 8,07,306 | 6,48,445 |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd | - | 4,232 |
| **Apportionment of overheads** | | |
| NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd.) | 23,00,886 | 26,16,178 |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd | 6,00,000 | 6,44,305 |
| **Service fee** | | |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd | - | 1,25,00,000 |

### III Balance outstanding with related parties at the year end

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Short term loans and advances** | | |
| NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd.) | 26,08,955 | 8,09,459 |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd | 6,63,000 | 6,36,000 |
| **Trade receivables** | | |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| **Salary/ remuneration payable** | | |
| Shri K Sanjay Murthy | 4,30,066 | 2,03,420 |
| Shri P K Agarwal | 1,03,551 | 1,02,561 |
| Shri Abhishek Chaudhary | 61,754 | 1,20,458 |

S.S. CHOPRA & CO. NEW DELHI

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

29 **Operating Lease**

The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating lease relating to its leased office premises at 8th Floor, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi which has been taken on lease for an initial period of 10 years. The aggregate lease rent of ₹ 4,86,03,024/- (Previous year: ₹ 5,66,79,394/- which includes lease rent of ₹ 80,76,370/- towards office space at Ashoka Hotel which has been vacated on 31.05.2020) paid has been recognized in the standalone statement of profit and loss and disclosed in note 23.

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| 30 **Expenditure in foreign currency** | | |
| - Traveling | - | 3,18,704 |
| | - | 3,18,704 |

31 **Corporate Social Responsibility (CSR)**

As per section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) committee has been constituted by the Company. The amount of ₹ 11,96,567/- (Previous year: ₹ 11,76,901/-) is payable towards CSR expenses based on average net profit (calculated as per section 198 of the Companies Act, 2013) of the preceding three financial years. The details of the amount spent/ pending to be spent during the year is as under:

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| i **Gross amount required to be spent by the Company** | | |
| Annual CSR allocation | 11,96,567 | 11,76,901 |
| Brought forward from previous year | - | 9,43,923 |
| Gross amount required to be spent | 11,96,567 | 21,20,824 |
| ii **Amount spent during the year** | | |
| In cash | 11,96,567 | 21,20,824 |
| Total | 11,96,567 | 21,20,824 |
| iii **Purposes on which CSR expenses has been spent** | | |
| Contribution to Prime minister's national relief fund (PMNRF) | 11,96,567 | 11,76,901 |
| Contribution for conducting skill and technical support training | - | 9,43,923 |
| | 11,96,567 | 21,20,824 |

32 In the opinion of the management, the value of assets other than property, plant and equipments and intangible assets on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the standalone balance sheet. Further, the provision for all known liabilities have been adequately made in the books of accounts.

33 Balances appearing under trade receivables, loans & advances, trade payables and other parties etc. are subject to reconciliation/ confirmation. The impact, if any, subsequent to the confirmation/ reconciliation will be taken in the year of confirmation/ reconciliation, which in view of the management will not be material.

34 Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, GoI, vide OM No. 5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 issued the Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs), as per which, every CPSE is required to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the Net worth, whichever is higher, subject to maximum dividend permitted under the extant legal provisions.

DIPAM vide OM no. 5/3/2018-Policy(Vol II) dated 17th December, 2018 and OM no. 4(30) (1)/2018-DIPAM-I(Pt) dated 18th March 2021 granted the exemption to the Company from above guidelines for the financial year 2017-18 and 2018-19 respectively.

The Company for the financial year 2019-20, has applied to DIPAM through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) on 25th September 2020 for obtaining the approval for exemption from payment of minimum dividend as per the above guidelines, which is awaited till date.

Similarly, the Company proposes to apply for obtaining the approval for exemption from the payment of minimum dividend for the FY 2020-21 subsequent to the approval and adoption of the standalone financial statements hence no provision towards payment of dividend has been made in the current financial year.

35 The Company's wholly owned subsidiary companies namely DMICDC Guna Power Company Limited, DMICDC Indapur Power Company Limited, DMICDC Vaghei Power Company Limited and DMICDC Villa Bhagad Power Company Limited have been winded up and their names have been struck off from the Register of Companies with effect from 09.08.2018 vide Notice no. ROC/DE.JO/248(5)/STK7/4893 dated 9th August, 2018.

On the aforesaid date, the equity shares held in these subsidiaries were valued on the basis of their assets and results as per financial statements of respective subsidiaries and loss towards diminution in investments of Rs. 20,00,000 was recognized under project development expenses during the financial years 2016-17 and 2017-18. Since the amount is not recoverable, the said amount, during the year, has been transferred to the capital reserve in accordance with the significant accounting policy no. 2.6.1.

36 **Impact of COVID-19 on the operations of the Company**

The Company has considered the possible effects that may result from the Covid-19 pandemic on the carrying amounts of property, plant and equipment, receivables and other current assets. Based on the current indicators of future economic conditions and also considering the nature of its business, management estimates that the carrying amount of these assets will be recovered and sufficient liquidity is available to fund the business operations for at least another 12 months thus the operations of the Company are not likely to be impacted adversely by COVID -19 pandemic.

37 Previous year figures have been regrouped/ rearranged, wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

CA Ashish Goyal
(Partner)
(Membership No. 099143)

UDIN 21099143AAAAC46093

Place: New Delhi
Date: 10th August, 2021

For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN: 03532374)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN: 02855304)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, IR
& Company Secretary

# AUDITOR'S REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (CONSOLIDATED)

**S. P. CHOPRA & CO.**
Chartered Accountants

**Corporate Office**
**1505, Astralis Supernova**
**Sector-94, Gautam Buddha Nagar**
**Noida – 201 301**
**Phone 0120 - 4516921**
**www.spchopra.in**
**spc1949@spchopra.in**

## Independent Auditor's Report
## To The Members of National Industrial Corridor Development Corporation Limited (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

### Report on the audit of the consolidated financial statements

### Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** (hereinafter referred to as the "Holding Company") and its subsidiary (the Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group"), which comprise the consolidated balance sheet as at March 31, 2021, and the consolidated statement of profit and loss and the consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the group as at March 31, 2021 and its consolidated profit, and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

### Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the *'Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements'* section of our report. We are independent of the group in accordance with the *code of ethics* issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Information other than the consolidated financial statements and auditor's report thereon

The holding company's board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the directors' report, including annexures, if any, thereon (but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon), which is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance on conclusion thereon.

Contd..p/2

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Directors' Report, including annexures, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

**Responsibility of management for the consolidated financial statements**

The holding company's board of directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. The respective board of directors of the companies included in the group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the directors of the holding company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective board of directors of the companies included in the group are responsible for assessing the group's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective board of directors of the companies included in the group are responsible for overseeing the financial reporting process of the group.

**Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.




Contd..p/3

As part of an audit in accordance with the SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of internal financial controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the consolidated financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described in section titled 'Other Matters' in this audit report.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.




Contd..p/4

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

**Other matters**

We did not audit the financial statements of subsidiary company namely NICDC Neemrana Solar Power Limited (hereinafter referred to as the "Subsidiary Company") whose financial statements reflect total assets of Rs. 3,065.88 lakhs as at 31st March, 2021, and total revenues of Rs. 635.11 lakhs and cash outflows (net) of Rs. 348.63 lakhs for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements.

The financial statements of subsidiary company have been audited by its auditor's whose report have been furnished to us by the holding company's management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far it relates to the amounts and disclosures included in respect of the subsidiary and our report in terms of Section 143(3), in so far it relates to the subsidiary is based solely on the report of its auditor.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our Report on other legal and regulatory requirements below, is not modified in respect of above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements/ financial information certified by the management.

**Report on other legal and regulatory requirements**

As required by Section 143(3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:

a) we have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements;

b) in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors;

c) the consolidated balance sheet, the consolidated statement of profit and loss and the consolidated statement of cash flows dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements;

d) in our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the accounting standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2016, to the extent notified;




Contd..p/5

e) on the basis of written representation received from the directors as at March 31, 2021 taken on record by the board of directors of the holding and subsidiary company, none of the directors of the holding and subsidiary company are disqualified as at March 31, 2021 from being appointed as a director in respective company in terms of sub section (2) of section 164 of the Act;

f) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements and operating effectiveness of such controls of the holding company as audited by us, and of the subsidiary company not audited by us (as reported by its auditors), refer to our separate report in **Annexure - 'A'**;

g) the provisions of section 197 read with schedule V to the Act are not applicable to the group since the holding company and subsidiary company are not public company as defined under section 2(71) of the Act, hence this clause is not applicable; and

h) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on its financial position in its consolidated financial statements – Refer note 26 to the consolidated financial statements;

ii) The group has not entered into any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the group.

**For S.P. CHOPRA & CO.**
**Chartered Accountants**
**Firm Regn. No. 000346N**

**Ankur Goyal**
**Partner**
**Membership No. 099143**
**UDIN 21099143AAAACZ1696**

**Place: New Delhi**
**Dated: August 10, 2021**

## Annexure - 'A' to Independent Auditor's Report

*(Referred to in paragraph (f) under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the consolidated financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended March 31, 2021)*

**Report on the internal financial controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **'National Industrial Corridor Development Corporation Limited'** ("the Holding Company") and its subsidiary (the Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group") for the year ended March 31, 2021, in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the group for the year ended on that date.

**Management's responsibility for internal financial controls**

The respective board of directors of the holding company and its subsidiary are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the "Guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting" (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

**Auditor's responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the group's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting (the 'Guidance Note') and the standards on auditing, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error.

Contd..p/2



We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the group's internal financial controls system over financial reporting.

**Meaning of internal financial controls over financial reporting**

The group's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The group's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the group; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that the receipts and expenditures of the group are being made only in accordance with the authorizations of management and directors of the respective company within the group; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the group's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

**Inherent limitations of internal financial controls over financial reporting**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Opinion**

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the holding company and its subsidiary, have, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to the consolidated financial statements and such internal financial controls with reference to the consolidated financial statements were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective company in the group considering the essential components of internal control stated in the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Contd..p/3



**Other matters**

Our aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to the financial statements insofar as it relates to the subsidiary company namely NICDC Neemrana Solar Power Limited, is based on the corresponding report of the auditor of the said company.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

**For S.P. Chopra & Co.**
**Chartered Accountants**
**Firm Registration No. 000346N**

**Ankur Goyal**
**Partner**
**Membership No. 099143**
**UDIN 21099143AAAACZ1696**

**Place: New Delhi**
**Date: August 10, 2021**

# FINANCIAL STATEMENTS (CONSOLIDATED)

## National Industrial Corridor Development Corporation Limited
## (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

CIN: U45400DL2008PLC172316

### Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2021

| Particulars | Note | As at 31st March, 2021 (₹) | | As at 31st March, 2020 (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Equity & Liabilities** | | | | | |
| **Shareholders' funds** | | | | | |
| (a) Share capital | 3 | 1,00,00,00,000 | | 1,00,00,00,000 | |
| (b) Reserves and surplus | 4 | 7,31,50,40,433 | 8,31,50,40,433 | 6,75,63,05,737 | 7,75,63,05,737 |
| **Non-current liabilities** | | | | | |
| (a) Other long-term liabilities | 5 | 5,46,44,500 | | 6,11,07,950 | |
| (b) Long-term provisions | 6 | 54,02,957 | 6,00,47,457 | 42,16,285 | 6,53,24,235 |
| **Current liabilities** | | | | | |
| (a) Trade payables | 7 | | | | |
| (i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises | | 1,36,26,669 | | 14,575 | |
| (ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises | | 19,49,90,539 | | 34,69,37,709 | |
| (b) Other current liabilities | 8 | 4,51,48,417 | | 4,39,85,674 | |
| (c) Short-term provisions | 9 | 19,17,688 | 25,56,83,313 | 6,44,638 | 39,15,82,596 |
| **Total** | | | **8,63,07,71,403** | | **8,21,32,12,568** |
| **Assets** | | | | | |
| **Non-current assets** | | | | | |
| (a) Property, plant and equipment | 10 | 24,76,47,887 | | 29,58,64,122 | |
| (b) Intangible assets | 10 | 19,23,095 | | 29,12,543 | |
| (c) Capital work-in-progress | | 8,96,784 | | 3,12,797 | |
| (d) Deferred tax assets | 11 | 75,72,564 | | 65,06,475 | |
| (e) Long-term loans and advances | 12 | 14,20,510 | | 7,02,000 | |
| (f) Other non-current assets | 13 | 6,74,17,95,336 | 7,00,12,56,178 | 6,13,88,56,958 | 6,44,51,54,895 |
| **Current assets** | | | | | |
| (a) Trade receivables | 14 | 2,26,95,535 | | 1,81,34,715 | |
| (b) Cash and bank balances | 15 | 1,52,52,57,272 | | 1,52,57,01,518 | |
| (c) Short-term loans and advances | 16 | 49,85,476 | | 27,59,063 | |
| (d) Other current assets | 17 | 7,65,76,942 | 1,62,95,15,225 | 12,14,62,377 | 1,76,80,57,673 |
| **Total** | | | **8,63,07,71,403** | | **8,21,32,12,568** |
| Significant Accounting Policies | 2 | | | | |
| Notes to accounts attached form an integral part of the consolidated financial statements | 3 - 42 | | | | |

As per our Report of even date attached

For CHORDIA & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 001178N
NEW DELHI

(Partner)
(Membership No. 099143)

For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

(P.K. Agarwal)
(Chief Financial Officer)

(Abhishek Chaudhary)
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

Place: New Delhi
Date : 10th August, 2021

UDIN: 21099143AAAAC21696

## National Industrial Corridor Development Corporation Limited
## (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

CIN: U45400DL2008PLC172316

### Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | Note | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|
| Revenue from operations | 18 | 31,14,34,377 | 22,89,02,844 |
| Other Income | 19 | 7,12,04,057 | 9,08,48,945 |
| **Total Revenue** | | **38,26,38,434** | **31,97,51,789** |
| **Expenses** | | | |
| - Cost of material consumed | 20 | 900 | 4,41,25,766 |
| - Employee benefit expense | 21 | 5,98,18,409 | 5,46,59,298 |
| - Finance cost | 22 | - | 7,54,788 |
| - Depreciation and amortization expense | 23 | 2,88,65,987 | 3,50,52,490 |
| - Other expenses | 24 | 11,15,04,506 | 14,23,09,012 |
| **Total Expenses** | | **19,99,89,802** | **27,69,01,354** |
| **Profit before tax** | | **18,26,48,632** | **4,28,50,435** |
| **Tax expenses** | | | |
| - Current tax | | 5,96,97,079 | 1,42,41,215 |
| - Earlier year | | 58,795 | 7,732 |
| - Deferred tax | | (10,66,089) | (14,91,921) |
| **Profit for the year** | | **12,39,58,847** | **3,00,93,409** |
| **Earnings per equity share (face value of ₹ 10/- per share)** | 25 | | |
| - Basic earnings per share | | 1.24 | 0.30 |
| - Diluted earnings per share | | | |
| Significant Accounting Policies | 2 | | |
| Notes to accounts attached form an integral part of the consolidated financial statements | 3 - 42 | | |

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

(Membership No. 099143 )

For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

(P.K. Agarwal)
(Chief Financial Officer)

(Abhishek Chaudhary)
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

Place: New Delhi
Date : 10th August,2021

UDIN: 21099143AAAACZ1696

## National Industrial Corridor Development Corporation Limited
## (Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)
CIN: U45400DL2008PLC172316

### Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Cash flow from operating activities:** | | |
| Profit before tax | 16,26,48,632 | 4,28,50,435 |
| **Adjustment** for: | | |
| Depreciation and amortization expense | 2,86,65,987 | 3,50,52,490 |
| Loss on sale of property, plant and equipment | 1,81,33,857 | 2,11,346 |
| Finance cost | - | 7,54,788 |
| Interest income | (6,22,45,676) | (8,38,09,671) |
| Operating profit before working capital changes | 16,74,02,800 | (49,40,612) |
| **Adjustments for :** | | |
| (Increase)/ Decrease in inventories | - | - |
| (Increase)/ Decrease in trade receivables | (45,60,620) | 15,56,041 |
| (Increase)/ Decrease in other receivables | 1,87,52,510 | (2,37,08,885) |
| Increase/ (Decrease) in trade payables | (13,83,34,876) | 5,98,71,871 |
| Increase/ (Decrease) in other payables | 13,35,321 | 5,61,43,481 |
| **Cash generated from/ (used in) operating activities** | (12,26,07,865) | (41,66,527) |
| | | 8,86,96,781 |
| Taxes paid (net of refunds) | (3,74,83,068) | (2,34,85,770) |
| **Net cash from/ (used in) operating activities** | 71,31,867 | 6,12,69,399 |
| **Cash flow from investing activities:** | | |
| Funds received for project development expense | 45,00,00,000 | 52,70,00,000 |
| Interest earned on funds received for project development expense | 92,26,079 | 2,07,33,907 |
| Utilisation of funds received for project development expense | (62,45,81,511) | (74,52,54,031) |
| Funds received for swachhta action plan | 10,00,000 | - |
| Interest earned on funds received for swachhta action plan | 203 | - |
| Utilisation of funds received for swachhta action plan | (10,00,000) | - |
| (Purchase) of property, plant and equipment | (53,63,965) | (2,50,17,946) |
| Sale of property plant and equipment | 64,30,507 | - |
| (Increase)/ Decrease in deposit with banks | (9,94,81,710) | 97,38,618 |
| Interest income | 6,22,45,676 | 8,38,09,671 |
| Payment of instalment towards land | (54,63,450) | (54,63,450) |
| Increase/ (Decrease) in advance for capital goods | (89,652) | (1,32,968) |
| **Net cash from/ (used in) investing activities** | (20,70,57,823) | (13,45,88,199) |
| **Cash flow from financing activities:** | | |
| Finance cost | - | (7,54,788) |
| Loan from NICDIT | - | (2,50,00,000) |
| **Net cash from/ (used in) financing activities** | - | (2,57,54,788) |
| **Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents** | (19,99,25,956) | (9,90,73,588) |
| **Cash** and cash equivalents at the beginning of the year | 1,62,57,01,518 | 1,72,47,75,103 |
| **Cash and cash equivalents at the end of the year (Refer note 15)** | 1,42,57,75,562 | 1,62,57,01,518 |
| **Components of cash and cash equivalents:** | | |
| **Cash** on hand | 6,707 | 12,821 |
| **Balances** with bank in current accounts | 12,20,48,028 | 6,48,436 |
| **Balances** with bank in term deposits | 1,30,37,20,827 | 1,62,50,40,261 |
| | 1,42,57,75,562 | 1,62,57,01,518 |
| **Significant** Accounting Policies | 2 | |
| **Notes** to accounts attached form an integral part of the consolidated financial **statements** | 3 - 42 | |

As per our Report of even date attached
For S. [illegible] & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000756N

(Membership No. 089143)

For and on behalf of the Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(Rajendra [illegible])
Director
(DIN : 02855304)

(P.K. Agarwal)
(Chief Financial Officer)

(Abhishek Chaudhary)
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

Place: New Delhi
Date: 10th August,2021

UDIN: 21089143AAAAC21696

## Note 1: Group Information

The Government of India (GoI) announced the concept of Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project as the first industrial corridor in 2007 under Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry to embark on the process of planned urbanisation with manufacturing as the key economic driver and also to give a strong impetus to the country's industrial/ manufacturing development.

Accordingly, Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) (the holding company) was incorporated on 7th January 2008 as a Special Purpose Vehicle (SPV) for the development and implementation of DMIC project.

In September 2011, the Government of India approved the financial and institutional structure of DMIC project for the development of industrial cities in DMIC project and also approved the creation of dedicated fund with a revolving corpus known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF).

DMICDC is to act as a project development company to undertake various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new greenfield industrial smart cities. Also, DMICDC was mandated to act as the Project Development Partner/ Knowledge Partner to DMIC-PITF and also to all SPVs and State Government agencies for the implementation of DMIC.

The Government of India in December 2016, expanded the mandate of DMIC Project Implementation Trust Fund and redesignated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country.

DMICDC was mandated to act as a knowledge partner to NICDIT in respect of all the industrial corridors in addition to DMIC work till Knowledge Partner(s) for other industrial corridors are put in place.

In view of the expanded mandate, the name of the company was changed from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC) with effect from 17th February 2020.

Subsequently, Government of India in December 2020 has approved the implementation of 11 Industrial Corridor projects (including 5 industrial corridors earlier approved) consisting of 32 projects, to be developed in 4 phases, under the industrial corridor programme, within the overall framework of National Master Plan for multi modal connectivity.

The holding company has a subsidiary company i.e. NICDC Neemrana Solar Power Limited (formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited). The accompanying consolidated financial statements relate to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC), being the holding company and its subsidiary company (together referred as "The Group").

## Note 2: Significant Accounting Policies

### 2.1 Basis for preparation of consolidated financial statements

The accompanying consolidated financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, in accordance with the generally accepted accounting principles in India ("GAAP"), the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent notified and applicable and the mandatory accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, to the extent applicable and in the manner so required.

### 2.2 Use of estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with GAAP in India requires the management to make estimates and assumptions, wherever necessary, that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of consolidated financial statements, and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. On an ongoing basis, estimates are evaluated based on historical experience and on various other assumptions that are believed to be reasonable, the results of which forms the basis for making judgments about the carrying value of assets and liabilities. Actual results could differ from those estimates. Any revision to estimates or difference between the actual result and estimates are recognised in the period in which the results are known/ materialised.

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P CHOPRA & CO CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

**2.3 Basis of consolidation**

The consolidated financial statements have been prepared on the following basis:

**Basis of accounting:**

i) The financial statements of the subsidiary companies are drawn up to the same reporting date as of the holding company.

ii) The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Accounting Standard-21 on "Consolidated Financial Statements".

**Principles of consolidation:**

i) The financial statements of the holding company and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after fully eliminating the intra-group balances and intra-group transactions and unrealized profits or losses in accordance with Accounting Standard - 21 on "Consolidated Financial Statements",

ii) The consolidated financial statements have been prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the holding company's separate financial statements except as otherwise stated in the Significant Accounting Policies.

iii) The difference between the costs of investments in the subsidiaries over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiaries is recognized in the consolidated financial statements as Goodwill or Capital Reserve as the case may be.

The consolidated financial statements of the holding company include the results of following entity:

| Name of Company | Country of incorporation | Proportion (%) of shareholding as at 31.03.2021 | Proportion (%) of shareholding as at 31.03.2020 |
|---|---|---|---|
| NICDC Neemrana Solar Power Limited | India | 100% | 100% |

**2.4 Property, plant and equipment**

i) Property, Plant and Equipment (PPE) are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any

ii) Cost of acquisition/ construction is inclusive of freight, erection and commissioning charges, duties and taxes, expenditure during construction period upto the date of acquisition/ installation and other incidental expenses incurred during the construction/ installation stage.

iii) When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment.

iv) Subsequent expenditure related to an item of property, plant and equipment are added to its book value only if they increase the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. Repairs and maintenance costs are recognized in the consolidated statement of profit & loss as and when incurred.

v) Losses arising from the retirement, or profit/ losses arising from disposal of property, plant and equipment which are carried at cost, are recognised in the consolidated statement of profit and loss in the year of retirement/ disposal.

vi) Depreciation on property, plant and equipment is charged on written down method over their estimated useful lives, in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013, retaining 5% of the cost as its residual value. However, if the management's estimate of the useful life of the asset is shorter than that envisaged in the aforesaid schedule, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful/ remaining life. The useful life of the assets in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013 and as estimated by the management is as under:

| Assets | Useful Life (in years) |
|---|---|
| Furniture and fixtures | 10 |
| Office equipment | 5 |
| Electrical installation and equipments | 10 |
| Computers - End user devices such as desktops, laptops etc. | 3 |
| Computers - Servers and networks | 6 |

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

Further, the useful life of following assets of subsidiary company are considered as under:

| Assets | Depreciation | Justification |
|---|---|---|
| Solar panels | - The salvage value is considered as 10% and depreciable assets is considered as 90% of capital cost.<br><br>- The useful life is considered as 25 years from the date of commercial operation.<br><br>- Depreciation rate is 5.28% per annum for first 13 years and remaining depreciation is spread during remaining useful life of the assets.<br><br>- Depreciation shall be charged on pro-rata basis. | This is as per the Central Electricity Regulatory Commission Regulations, 2017. |
| Landscaping and horticulture works | The depreciable amount is depreciated over a period of 5 years on written down value method. | Useful life is considered as 5 years. |
| Leasehold land | Amortised on straight line method for the remaining period of lease (97 years 106 days) from the date of possession. | This is as per the lease deed executed with the Land Development Authority i.e. RIICO. |

vii) Property, plant and equipment costing upto ₹ 5,000/- each are fully depreciated in the year of acquisition.

viii) Depreciation on addition to property, plant and equipment is charged on pro-rata basis from the date the assets are ready for intended use over the estimated remaining useful life of the asset. Depreciation on sale/ discard/ destroy/ demolish of assets is charged upto the date of sale/ retrial of assets, as the case may be.

ix) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end

x) Property, plant and equipment, if any, retired from active use or held for disposal are stated at lower of cost (net of accumulated depreciation) or estimated net realizable value.

xi) The cost of leasehold improvement is amortised over the period of the lease.

xii) Property, plant and equipment under construction and cost of assets not ready for intended use before the year-end, are shown as capital work in progress.

xiii) Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under other non-current assets.

xiv) The expenditure incurred by subsidiary company on landscaping and horticulture works was capitalised upto the financial year 2019-20. Based on the observation of C&AG, the written down value as on 31st March 2020, was charged off as revenue expenditure and hitherto such expenditure will be charged off as revenue expenditure

xv) Land acquired by subsidiary company on lease for 99 years or less is treated as leasehold land

xvi) Equipments provided by New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO), Japan to subsidiary company as grant in aid is accounted at a nominal value of ₹ 1/- on transfer of ownership of equipment with all bonafide rights after the completion of the project.

**2.5 Intangible assets**

Intangible assets are recognized where it is probable that the future economic benefit attributable to the asset will flow to the group and the cost of assets can be measured reliably. Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in the consolidated statement of profit and loss in the year in which the expenditure is incurred.

Intangible assets consist of computer software and are stated at cost of acquisition/ implementation less accumulated amortization. It is amortized over a period of 5 years or the license period on a straight line basis, whichever is earlier.

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

**2.6 Impairment of assets**

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date and if there is any indication of impairment based on internal/ external factors, the impairment loss is recognized. 'An impairment loss is charged to the consolidated statement of profit and loss in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is increased/ reversed where there has been change in the estimate of recoverable amount. The recoverable value is the higher of the assets' net selling price and value in use.

**2.7 Grant-in-aid**

**2.7.1 Project Development Fund (PDF)**

Government of India (GoI) approved setting up of project development fund (PDF) for undertaking various project development/ preparatory activities for various industrial corridor projects for which the holding company receives grant-in-aid from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) which is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to GoI/ NICDIT from the fund will be reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance. Further, Project Development Expenses (PDE) incurred on project development/ preparatory activities of various industrial corridors out of the fund are treated as under:

a) Expense related to subsidiaries of the holding company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments, wherever recoverable in accordance with the stipulations in the shareholders' agreement are shown as recoverable from the concerned subsidiaries/ SPVs and disclosed under 'Other non-current assets';

b) Expense incurred for the projects which are not to be taken off or no further activities are to be carried out or the shareholders' agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s)./ Nodal Agency(ies) does not provide for recovery are reduced from the 'Project Development Funds' balance under 'Capital reserves'; and

c) Expenses relating to the projects which are in progress and where the SPVs have not yet been incorporated due to the non execution of the shareholders' agreement or where the projects have not yet been approved for investment by NICDIT/CCEA or any other expense not covered under para (a) and (b) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head "Other non-current assets".

**2.7.2 Project Implementation Fund (PIF)**

Government of India has approved setting up of a Project Implementation Fund (PIF) for undertaking various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project for which the grant-in-aid is received by the holding company from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to GoI/ NICDIT from the fund will be reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance.

**2.7.3 Swachhta Action Plan Fund (SAP)**

Government of India has approved setting up of a Swachhta Action Plan Fund (SAP) for meeting the expenditure towards the Swachhta Action Plan for which the grant-in-aid is received by the holding company from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to GoI/ NICDIT from the fund will be reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance and non-recoverable expenditure incurred therefrom is met out of fund balance.

**2.8 Investments**

Current investments are stated at the lower of cost or quoted price.

On disposal of investments, the difference between net disposal proceeds and the carrying amounts are recognized in the consolidated statement of profit and loss.

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

**2.9 Revenue recognition**

a) Revenue from provision of services rendered by the holding company is recognised on accrual basis, to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the holding company and when the significant terms of arrangement are enforceable, services have been delivered, the collectability is reasonably assured and the revenue can be reliably measured. Accordingly, revenue on services is recognised as follows:

(i) Service fees @ 1% of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) is recognised to the maximum limit of ₹ 20,00,00,000 in a year, as approved by NICDIT in its meeting held on 26th July 2016

(ii) Service fees @ 1% of yearly internal accruals towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited (IICC) as Knowledge Partner is recognized to a minimum of ₹ 5,00,00,000 and maximum of ₹ 10,00,00,000 per annum on pro-rata basis for an initial period of 10 years as stipulated in MOU executed with IICC.

b) Revenue from the sale of power by the subsidiary company is recognized on the basis of net number of units exported on monthly basis at the rates agreed upon with the customers.

c) Interest income is recognized on time proportionate basis taking into account the amount outstanding and applicable rate of interest.

d) Dividend income is recognized when the company's right to receive dividend is established by the reporting date.

**2.10 Leases**

Lease arrangements, where the risk and rewards incidental to ownership of the assets, substantially vests with the lessor, are recognized as an operating lease. Lease payments under operating lease are recognized as an expense in the consolidated statement of profit and loss on accrual basis.

**2.11 Foreign currency transactions**

Foreign currency transactions are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency existing at the balance sheet date are translated at the exchange rate prevailing on that date. Exchange differences in case of borrowed funds and liabilities in foreign currency for the acquisition of property, plant and equipment from a country outside India are adjusted to its cost. All other exchange differences are recognized in the consolidated statement of profit and loss. Premium or discount on forward exchange contract is amortized as expense or income over the life of the contract. Exchange difference on such contract is recognized in the consolidated statement of profit and loss in the reporting period in which the exchange rates changes. Any profit or loss arising on cancellation or renewal of forward contract is recognized as income and expenditure during the period.

**2.12 Inventories**

Inventories of consumables, stores and spares are valued at the lower of the cost or net realisable value, on First-in, First-out (FIFO) basis.

**2.13 Employee Benefits**

a) **Short term benefits:**
These are recognized as an expense in the consolidated statement of profit and loss for the year in which the related services are rendered. These benefits include leave salary and pension contribution to the Government employees, on deputation to the group, which is accounted as per the prescribed rules of Central Government, accumulated compensated absences, which are expected to be availed or encashed within 12 months from the year end.

b) **Defined contribution plan:**
The Group's contribution paid or payable during the year to statutory provident fund, pension scheme in accordance with Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 are recognized as an expense in the year in which the employee render services.

c) **Defined benefit plan:**
The Group's liability towards gratuity is determined by independent actuary, at the year-end using the projected unit credit method. Actuarial gains or losses as determined by the actuary are recognized in the consolidated statement of profit and loss during the year in which actuarial valuation is done.

**2.14 Segment reporting**

The operating segments are identified on the basis of internal reports used by the group's management to allocate resources and assess their performance for decision making. The Board of Directors is collectively the group's "chief operating decision maker" or "CODM" within the meaning of AS 17.

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

**2.15 Earnings per share**

The group reports Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning Per Share".

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year, as adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares, except where the results are anti-dilutive.

**2.16 Taxes on income**

a) Tax expense comprises both current tax and deferred tax.

b) Current income tax, assets and liabilities are measured at the amount expected to be paid to or recoverable from the taxation authorities in accordance with the tax regime inserted by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 in the Income Tax Act, 1961, and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) enacted in India, by using tax rates and the tax laws that are enacted at the reporting date.

c) Deferred tax liability/ asset resulting from 'timing difference' between accounting income and taxable income, that is capable of reversal in subsequent accounting period is accounted for considering the tax rate and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the reporting date. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date for their realizability.

d) **Minimum alternate tax (MAT)** is **charged to the consolidated statement** of profit and loss as current tax during **the year** in which it is paid. The **company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent** that there is convincing evidence that the **company** will pay normal income **tax during the specified period, i.e. the period for which MAT credit** is allowed to be carried forward. The company recognizes MAT credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternative Tax under the Income-tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the consolidated statement of profit and loss and shown as "MAT Credit Entitlement." The company reviews the "MAT credit entitlement" asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the company does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the specified period.

**2.17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

Provisions are recognised when there is a present obligation as a result of a past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation on reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adopted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are **disclosed** in the Notes when there is a possible obligation arising from past event(s), the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-**occurrence** of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the group or a present obligation that arises from past event(s) where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle or a reliable estimate of the amount cannot be made.

Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

**2.18 Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalents include cash in hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with original maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalent and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

**2.19 Cash flow statements**

The cash flow statement is prepared by the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard 3 on "Cash Flow Statements" and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the group.

Cash and cash equivalents presented in the consolidated cash flow statement consist of cash in hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with original maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalent.

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

## Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 3: Share capital** | | |
| **Authorised** | | |
| 10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| **Issued, subscribed and fully paid up** | | |
| 10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| Total | 1,00,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |

3.1 **Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the year:**

| | As at 31st March, 2021 | | As at 31st March, 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | No. of shares | (₹) | No. of shares | (₹) |
| Balance at the beginning of the year | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |
| Add: Shares issued during the year | - | - | - | - |
| Balance at the end of the year | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 | 10,00,00,000 | 1,00,00,00,000 |

3.2 **Terms/ rights attached to equity shares**

The group has only one class of equity shares having a par value of ₹ 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The group may declare and pay dividend in Indian rupees. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting. During the year ended 31st March, 2021, no dividend was declared and distributed by the group (Also refer note 35 for further details on dividend). In the event of liquidation of the holding company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders

3.3 **Details of shareholders holding more than 5% shares in the group**

| | As at 31st March, 2021 | | As at 31st March, 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | No. of shares | % of Holding | No. of shares | % of Holding |
| The President of India (Through Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and its nominees) | 4,90,00,000 | 49.00 | 4,90,00,000 | 49.00 |
| Japan Bank for International Co-operation (JBIC) | 2,60,00,000 | 26.00 | 2,60,00,000 | 26.00 |
| Housing and Urban Development Corporation Limited | 1,98,00,000 | 19.90 | 1,99,00,000 | 19.90 |

3.4 The group has not issued bonus shares, issued any shares without payment being received in cash or brought-back shares during five years immediately preceding the balance sheet date.

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. * CHARTERED ACCOUNTANTS * NEW DELHI

National Industrial Corridor Development Corporation Limited * New Delhi

## Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | | | As at 31st March, 2021 (₹) | | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Note 4: Reserves and surplus** | | | | | |
| (a.) | **Capital reserves - Grant-in-aid received for:** (Refer note 2.7) | | | | |
| | **(i) Project development fund** | | | | |
| | As per last balance sheet | 6,35,20,27,000 | | 5,82,50,27,000 | |
| | Add: Grant-in-aid received during the year | 45,00,00,000 | 6,80,20,27,000 | 52,70,00,000 | 6,35,20,27,000 |
| | **Add: Interest etc. earned on project development fund** | | | | |
| | As per last balance sheet | 31,33,51,562 | | 29,26,17,655 | |
| | Interest on term deposits and tax refunds during the year | 92,25,079 | 32,25,77,641 | 2,07,33,907 | 31,33,51,562 |
| | (Less): Project development expenses, to the extent not recoverable | | | | |
| | As per last balance sheet | (37,98,70,926) | | (33,40,67,373) | |
| | Diminution in value of investments in closed subsidiaries | (20,00,000) | | - | |
| | Expenses incurred during the year | (2,16,43,131) | (40,35,14,057) | (4,58,03,553) | (37,98,70,926) |
| | (Less): Tax impact on income earned on project development fund | | (22,51,993) | | - |
| | **(i)** | | 5,71,88,38,591 | | 6,28,55,07,636 |
| | **(ii) Project implementation fund** | | | | |
| | As per last balance sheet (Refer note 4.1) | | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 |
| | **(ii)** | | 13,00,00,000 | | 13,00,00,000 |
| | **(iii) Swachhta action plan** | | | | |
| | Grant-in-aid received during the year | | 10,00,000 | | - |
| | Add: Interest on term deposits during the year | | 203 | | - |
| | (Less): Expenditure incurred during the year | | (10,00,000) | | - |
| | **(iii)** | | 203 | | - |
| | **(iv) Equipment received as Grant-in-aid (Refer note 2.4.xvi and 38)** | | | | |
| | **(iv)** | | 1 | | - |
| | | | 1 | | - |
| | **Sub-total** | | 5,84,88,39,795 | | 6,41,55,07,636 |
| (b) | **Surplus** | | | | |
| | As per last balance sheet | 34,07,98,101 | | 31,07,04,692 | |
| | Add: Diminution in value of investments in closed subsidiaries | 20,00,000 | | - | |
| | Add: Profit for the year | 12,39,58,847 | | 3,00,93,409 | |
| | (Less): Written down value of landscaping and horticulture work (Refer note 2.4.xiv and 40) | (5,55,310) | 46,62,01,638 | - | 34,07,98,101 |
| | **Total** | | 7,31,50,40,433 | | 6,75,63,05,737 |

4.1 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- was transferred to NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust Fund (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund) out of Main Corpus/ Capital Funds of the Trust during the financial year 2013-14 for onward release to SPV namely "NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited)" towards 100% equity investment of the Trust through NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) for the implementation of 6 MW model solar power project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Ltd (Formerly known as DMICDC Limited).

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 5 : Other long-term liabilities** | | |
| Amount payable towards land (Refer note 5.1) | 5,46,34,500 | 6,00,97,950 |
| Performance security | 10,000 | 10,10,000 |
| **Total** | 5,46,44,500 | 6,11,07,950 |

5.1 Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited (RIICO) on 21st November, 2012 allotted 145692 sq.m. of land for the project site of subsidiary company at the concessional rate of ₹ 1,000/- per sq.m. Out of the total Development Charges (DC), 25% was paid upfront at the time of allotment of land and the balance amount is payable in 20 equal annual interest free instalments, with effect from 20th January, 2013.

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

## Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 6 : Long-term provisions** | | |
| **Provision for employee benefits** | | |
| -Gratuity (Refer note 27) | 54,02,957 | 42,18,285 |
| **Total** | **54,02,957** | **42,18,285** |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 7 : Trade payables** | | |
| Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer note 7.1) | 1,36,26,869 | 14,575 |
| Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises | 19,49,90,539 | 34,69,37,709 |
| **Total** | **20,86,17,408** | **34,69,52,284** |

7.1 Information pursuant to the provisions of Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is given below. This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Group.

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| i) The principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier covered under MSMED Act at the end of the year | | |
| - Principal | 1,36,26,869 | 14,575 |
| - Interest | - | - |
| ii) The amount of interest paid by the group in terms of section 16 of the MSMED Act, 2006 along with the amount of the payment made to the suppliers beyond the appointed day during the year | - | - |
| iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act 2006 | - | - |
| iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year; and | - | - |
| v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006 | - | - |

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 8 : Other current liabilities** | | |
| Statutory liabilities | 2,38,59,157 | 1,91,44,142 |
| Accrued expenses | 20,60,228 | 19,42,358 |
| Creditors for expenses | 82,06,535 | 1,69,76,856 |
| Employee related payable | 4,75,137 | 2,85,206 |
| Bid security | 50,00,000 | - |
| Current maturities of long-term liabilities (RIICO Land) | 54,63,450 | 54,63,450 |
| Other payable | 38,910 | 89,000 |
| Performance security | 45,000 | 15,000 |
| Creditors for capital goods | - | 69,652 |
| Total | 4,51,48,417 | 4,39,85,674 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | | As at 31st March, 2020 (₹) | |
|---|---|---|---|---|
| **Note 9 : Short-term provisions** | | | | |
| **Provision for employee benefits** | | | | |
| - Gratuity (Refer note 27) | 3,79,194 | | 4,74,026 | |
| - Leave encashment | 1,81,697 | 5,60,891 | 1,70,612 | 6,44,638 |
| **Other provisions** | | | | |
| - Provision for taxation ( net of advance tax of ₹ 6,05,92,276/- ) | | | | |
| Total | | 13,56,797<br>19,17,688 | | -<br>6,44,638 |

*(This space has been intentionally left blank)*

**National Industrial Corridor Development Corporation Limited**
**(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)**
CIN: U45400DL2008PLC172316

**Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021**

**Note 10 : Property, plant and equipment and intangible assets**

(₹)

| Particulars | Gross block | | | | Depreciation/ Amortization | | | | Net block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at 1st April, 2020 | Additions during the year | Sales/ disposal/ adjustments during the year | As at 31st March, 2021 | As at 1st April, 2020 | For the year (refer note 10.2) | Sales/ disposal/ adjustments during the year | As at 31st March, 2021 | As at 31st March, 2021 | As at 31st March, 2020 |
| **I. Property, plant and equipment** | | | | | | | | | | |
| Land - Leasehold (99 years) | 15,61,68,910 | - | - | 15,61,68,910 | 90,72,582 | 16,05,183 | - | 1,06,77,765 | 14,54,91,145 | 14,70,96,328 |
| Buildings | | | | | | | | | | |
| a) Building other than RCC frame structure | 1,21,70,609 | - | - | 1,21,70,609 | 39,78,670 | 7,78,010 | - | 47,56,680 | 74,14,929 | 81,93,939 |
| b) Fencing | 1,13,60,905 | - | (4,07,548) | 1,09,53,357 | 1,02,92,698 | 3,19,387 | (2,78,017) | 1,03,34,069 | 6,19,348 | 10,68,266 |
| c) Tubewell | 10,52,350 | - | - | 10,52,350 | 8,73,064 | 81,456 | - | 9,54,520 | 97,830 | 1,79,286 |
| Roads | | | | | | | | | | |
| a) Carpeted - other than RCC | 7,42,326 | - | - | 7,42,326 | 6,93,546 | 11,664 | - | 7,05,210 | 37,116 | 48,780 |
| b) Non-carpeted roads | 76,47,896 | - | - | 76,47,896 | 72,65,501 | - | - | 72,65,501 | 3,82,395 | 3,82,395 |
| Plant and machineries | | | | | | | | | | |
| a) Plant and machineries (General) [Refer note 39(iii)] | 22,12,21,817 | - | (4,72,98,991) | 17,39,22,826 | 11,72,22,273 | 1,62,96,270 | (2,21,71,664) | 11,13,46,879 | 6,25,75,947 | 10,39,99,544 |
| b) Solar panels | 1,36,58,750 | 61,684 | - | 1,37,20,434 | 24,39,357 | 10,28,483 | (34,319) | 34,33,521 | 1,02,98,913 | 1,12,29,393 |
| c) Equipment received as grant-in-aid | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Furniture and fixtures | 54,30,929 | 13,599 | - | 54,44,528 | 13,19,087 | 10,66,743 | - | 23,85,830 | 30,58,698 | 41,11,842 |
| Office equipment | 1,33,56,563 | 14,64,009 | (21,900) | 1,47,98,672 | 61,69,553 | 36,01,229 | (20,805) | 97,49,977 | 50,48,695 | 71,87,010 |
| Electrical installations and equipment | 13,80,839 | - | - | 13,80,839 | 2,20,682 | 3,01,247 | - | 5,22,139 | 8,58,700 | 11,59,947 |
| Computer and data processing units | 49,13,529 | 20,99,996 | 12,881 | 70,26,406 | 35,62,146 | 14,15,659 | 5,152 | 49,83,157 | 20,43,251 | 13,51,383 |
| Leasehold improvements (Office Renovation) | 1,41,51,474 | 14,21,007 | - | 1,55,72,481 | 48,50,775 | 9,98,787 | - | 58,49,562 | 97,22,919 | 93,00,699 |
| Landscaping and horticulture works (Refer note 40) | 29,78,589 | - | (29,78,589) | (0) | 24,23,389 | - | (24,23,389) | - | (0) | 5,55,310 |
| **Current year's total** | **46,82,45,696** | **50,69,296** | **(5,98,94,257)** | **41,34,20,737** | **17,03,81,474** | **2,75,05,318** | **(2,49,23,042)** | **17,29,63,750** | **24,04,57,087** | **29,51,64,122** |
| **Previous year's total** | **44,03,88,485** | **2,85,80,857** | **27,03,546** | **46,82,45,596** | **13,93,67,883** | **3,34,55,219** | **(24,41,628)** | **17,03,81,474** | **29,58,64,122** | |
| **II. Intangible assets** | | | | | | | | | | |
| Computer softwares | 83,09,341 | 3,78,850 | (12,881) | 86,75,410 | 53,96,798 | 13,80,669 | (5,152) | 67,52,315 | 19,23,095 | 29,12,543 |
| **Current year's total** | **83,09,341** | **3,78,850** | **(12,881)** | **86,75,410** | **53,96,798** | **13,80,669** | **(5,152)** | **67,52,315** | **19,23,095** | **29,12,543** |
| **Previous year's total** | **82,67,816** | **41,525** | - | **83,09,341** | **37,99,527** | **15,97,271** | - | **53,96,798** | **29,12,543** | - |

10.1) Pursuant to "AS28- Impairment of Asset" issued by the Central Government under the Companies (Accounting Standard) Rule 2006 for determining impairment in carrying amount of property, plant and equipment, the group has concluded that since recoverable amount of property, plant and equipment is not less than its carrying amount, therefore, no provision for impairment is required in respect of property, plant and equipment owned by the group.

**10.2)** Reconciliation of **depreciation** charged during the year

| | Property, plant and equipment | | Intangible assets |
|---|---|---|---|
| | Computer and data processing units | Leasehold improvements (Office renovation) | Computer Software |
| Depreciation as per note 10 above | 14,15,659 | 9,98,787 | 13,80,669 |
| Depreciation/Amortisation for earlier year | 1,53,626 | (5,480) | 2,48,488 |
| Depreciation for the year | 15,69,285 | 9,94,297 | 16,09,169 |

**Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021**

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 11 : Deferred tax assets** | | |
| **Deferred tax assets:** | | |
| - Difference between depreciation/ amortisation as per account and as per tax | 59,05,174 | 51,57,761 |
| - Timing difference on account of expenses allowable on payment basis | 16,67,390 | 13,48,714 |
| Total | 75,72,564 | 65,06,475 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 12 : Long-terms loans and advances** | | |
| (Unsecured, considered good) | | |
| Security deposits | 14,18,500 | 7,02,000 |
| Prepaid expenses | 2,010 | - |
| Total | 14,20,510 | 7,02,000 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 13 : Other non-current assets** | | |
| (Unsecured, considered good) | | |
| **Project development expenditure (PDE) against project development fund (Refer note 2.7.1)** | | |
| As per last balance sheet | 1,03,56,59,606 | 98,34,71,322 |
| Add: Expense incurred during the year [Net of Bid processing fee of ₹ 91,50,000/- (Previous Year: Nil)] | 62,45,81,511 | 74,84,18,179 |
| | 1,66,02,40,117 | 1,73,18,89,501 |
| (Less): Transferred to subsidiary SPVs | (54,71,07,299) | (64,84,25,342) |
| (Less): Transfer to project development funds | (2,16,43,131) | (4,58,03,553) |
| Sub-total | 1,09,14,89,687 | 1,03,56,59,606 |
| **Project development expenses recoverable from SPVs (Refer note. 2.7.1, 13.1 and 13.2)** | | |
| - Aurangabad Industrial Township Limited | 2,02,82,02,357 | 1,76,93,25,213 |
| - Dholera Industrial City Development Limited | 3,17,83,68,542 | 2,91,46,87,473 |
| - Dholera International Airport Company Limited | - | 6,59,998 |
| - NICDC Haryana Global City Project Limited | 9,89,68,428 | 9,48,84,336 |
| - NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited | 5,48,59,860 | 4,84,10,060 |
| - DMIC Haryana MRTS Project Limited | 6,97,98,061 | 6,87,12,587 |
| - DMIC Vikram Udyogpuri Limited | 5,07,54,677 | 5,07,54,677 |
| - Integrated Industrial Township Greater Noida Limited | 8,60,82,730 | 7,45,06,230 |
| - NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited | 9,42,73,176 | 9,19,36,776 |
| | 5,65,03,05,651 | 5,10,38,58,350 |
| (Less): Dholera International Airport Company Limited shown as other current assets (Refer note17) | - | (6,59,998) |
| Sub-total | 5,65,03,05,651 | 5,10,31,98,352 |
| Total | 6,74,17,95,338 | 6,13,88,56,958 |

13.1 National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) in its 3rd meeting held on 6th March, 2018 has directed the holding company to transfer the project development expenditure incurred by the holding company in relation to projects of the subsidiaries/ SPVs out of project development funds provided as Grant-in-aid to the respective subsidiaries/ SPVs and to defer its recovery till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds. The respective subsidiaries/ SPVs have not been able to generate sufficient surplus funds hence the amount recoverable from them has not fallen due for recovery as at 31st March, 2021.

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

13.2 Movement of project development expenditure recoverable from SPVs

As at 31st March, 2021

| SPV | Balance as at 31st March, 2020 (₹) | Expenditure incurred during the year (₹) | Amount received during the year (₹) | Balance as at 31st March, 2021 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| - Aurangabad Industrial Township Limited | 1,76,93,26,213 | 25,68,75,144 | - | 2,02,62,02,357 |
| - Dholera Industrial City Development Limited | 2,91,46,67,473 | 26,37,01,069 | - | 3,17,83,68,542 |
| - Dholera International Airport Company Limited | 6,59,998 | - | (6,59,998) | - |
| - NICDC Haryana Global City Project Limited | 8,48,84,336 | 40,82,092 | - | 8,89,66,428 |
| - NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited | 4,84,10,060 | 64,49,600 | - | 5,48,59,660 |
| - DMIC Haryana MRTS Project Limited | 6,87,12,587 | 85,494 | - | 6,87,98,081 |
| - DMIC Vikram Udyogpuri Limited | 5,07,54,677 | - | - | 5,07,54,677 |
| - Integrated Industrial Township Greater Noida Limited | 7,45,06,230 | 1,35,76,500 | - | 8,80,82,730 |
| - NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited | 9,19,36,776 | 23,36,450 | - | 9,42,73,179 |
| | 5,10,38,58,350 | 54,71,07,299 | (6,59,998) | 5,65,03,05,851 |

As at 31st March, 2020

| SPV | Balance as at 31st March, 2019 (₹) | Expenditure incurred during the year (₹) | Amount received during the year (₹) | Balance as at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| - Aurangabad Industrial Township Limited | 1,46,97,03,848 | 29,96,22,565 | - | 1,76,93,26,213 |
| - Dholera Industrial City Development Limited | 2,59,99,60,739 | 31,47,06,734 | - | 2,91,46,67,473 |
| - Dholera International Airport Company Limited | 50,91,152 | 11,62,148 | (55,93,302) | 6,59,998 |
| - NICDC Haryana Global City Project Limited | 8,08,02,244 | 40,82,092 | - | 8,48,84,336 |
| - NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited | 3,88,65,417 | 95,44,643 | - | 4,84,10,060 |
| - DMIC Haryana MRTS Project Limited | 6,87,12,587 | - | - | 6,87,12,587 |
| - DMIC Vikram Udyogpuri Limited | 5,07,54,677 | - | - | 5,07,54,677 |
| - Integrated Industrial Township Greater Noida Limited | 7,45,06,230 | - | - | 7,45,06,230 |
| - NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited | 7,26,29,816 | 1,93,07,160 | - | 9,19,36,776 |
| | 4,48,10,26,310 | 64,84,25,342 | (55,93,302) | 5,10,38,58,350 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 14 : Trade receivables** | | |
| (Unsecured, considered good) | | |
| Other receivables* (Refer note 14.1) | 2,26,95,535 | 1,81,34,715 |
| Total | 2,26,95,535 | 1,81,34,715 |
| 14.1 Includes amount due from: | | |
| India International Convention and Exhibition Centre Limited - Enterprise over which KMP exercise significant influence | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| Total | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |

* since realised

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. * CHARTERED ACCOUNTANTS * NEW DELHI

National Industrial Corridor Development Corporation Limited * New Delhi

**Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021**

| Particulars | | As at 31st March, 2021 (₹) | | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **Note 15 : Cash and bank balances** | | | | |
| **Cash and cash equivalents** | | | | |
| Cash on hand | | 6,707 | | 12,821 |
| Balances with banks in current accounts | | | | |
| - Project Development Fund | 2,22,851 | | 2,02,324 | |
| - Swachhta Action Plan | 266 | | - | |
| - Group Fund | 12,18,25,091 | 12,20,48,028 | 4,45,112 | 6,48,436 |
| Balance with banks in term deposits | | | | |
| - Project Development Fund | 7,89,25,000 | | 48,05,55,897 | |
| - Group Fund | 1,22,47,95,827 | 1,30,37,20,827 | 1,14,44,84,364 | 1,62,50,40,261 |
| **Other bank balances** | | | | |
| Balance with banks in term deposits | | | | |
| - Project Development Fund | | 9,94,81,710 | | - |
| Total | | 1,52,52,17,272 | | 1,62,57,01,518 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 16 : Short-term loans and advances** | | |
| (Unsecured, considered good) | | |
| **Advance to vendors** | 2,78,992 | 3,64,122 |
| Staff advance | 50,996 | 3,70,055 |
| Prepaid expenses | 30,06,929 | 13,68,886 |
| Balance with revenue authorities | 9,65,559 | - |
| Recoverable on account of apportionment of overheads from India International Convention and Exhibition Centre Limited | 6,83,000 | 6,36,000 |
| | 49,85,476 | 27,59,063 |

| Particulars | As at 31st March, 2021 (₹) | As at 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 17 : Other current assets** | | |
| Interest accrued on term deposits [includes on account of PDF of ₹ 7,24,085/- (previous year ₹ 41,75,663/-)] | 5,05,91,237 | 7,20,28,238 |
| Income tax refundable [Refer note 25 (iii)] | 2,01,44,724 | 3,17,43,989 |
| Income accrued on sale of electricity [Unbilled revenue (net of rebate)] | 57,50,818 | 54,41,413 |
| Other recoverable | 90,163 | - |
| **Recoverable from SPV** | - | 8,59,998 |
| Advance tax (Net of provision for taxation for previous year of ₹ 1,42,41,215/-) | - | 1,15,88,739 |
| | 7,65,76,942 | 12,14,62,377 |

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

## Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | | Year ended 31st March, 2021 (₹) | | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **Note 18 : Revenue from operations** | | | | |
| a) Service fees as knowledge partner to (Refer note. 2.9) | | | | |
| National Industrial Corridor Development and Implementation Trust | 20,00,00,000 | | 8,28,00,400 | |
| India International Convention and Exhibition Centre Limited (IICC) | 5,00,00,000 | 25,00,00,000 | 5,00,00,000 | 13,28,00,400 |
| b) Sale of power* | | 6,14,34,377 | | 9,61,02,444 |
| [70,06,060 kwh units (previous year: 99,41,452 kwh units) and other adjustments] | | | | |
| Total | | 31,14,34,377 | | 22,89,02,844 |

* Includes an amount of unbilled revenue of ₹ 58,68,182/- to NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (6,69,120 kwh @ ₹ 8.77 per unit)

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 19 : Other income** | | |
| Interest on term deposits on group funds | 6,22,45,675 | 8,38,09,671 |
| Interest on income tax refund | 15,56,597 | - |
| Apportionment of overheads from India International Convention and Exhibition Centre Limited | 72,00,000 | 66,44,305 |
| Scrap sale | 1,66,852 | - |
| Miscellaneous Income | 35,132 | 3,94,969 |
| Total | 7,12,04,057 | 9,08,48,945 |

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 20 : Cost of material consumed** | | |
| Diesel expense | - | 4,41,25,116 |
| Freight expense | 900 | 650 |
| Total | 900 | 4,41,25,766 |

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

## Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 21: Employee benefit expense** | | |
| Salary, wages, gratuity, compensated absence, allowances etc. | 5,36,77,908 | 4,86,20,396 |
| Contribution to provident/ pension fund | 37,23,093 | 32,63,075 |
| Staff welfare expenses | 22,17,408 | 27,75,827 |
| Total | 5,96,18,409 | 5,46,59,298 |

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 22 : Finance cost** | | |
| Interest on borrowings | - | 7,54,788 |
| Total | - | 7,54,788 |

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 23: Depreciation and amortization expense** | | |
| Depreciation on property, plant and equipment | 2,75,05,318 | 3,34,55,219 |
| Amortization of intangible assets | 13,60,669 | 15,97,271 |
| Total | 2,88,65,987 | 3,50,52,490 |

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

## Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Note 24: Other expenses** | | |
| Rent (Refer note 24.1 and 30) | 4,86,03,024 | 5,66,79,394 |
| **Payment to Auditors (Refer note 24.2)** | | |
| Audit fees | 4,30,300 | 4,30,300 |
| Certification fee | 5,500 | 1,05,100 |
| Advertisement and business promotion | 81,06,776 | 4,44,22,050 |
| Corporate social responsibility expense (Refer note 32) | 15,39,684 | 44,02,256 |
| Electricity | 10,01,062 | 8,39,673 |
| Housekeeping | 17,42,671 | 15,54,785 |
| Security | 8,55,544 | 6,79,488 |
| Professional and consultancy charges | 44,31,452 | 35,21,609 |
| Meeting and refreshment | 2,07,080 | 4,13,894 |
| Repair and maintenance - office | 38,57,397 | 37,77,248 |
| Repair and maintenance - computers | 26,86,034 | 29,21,718 |
| Printing and stationery | 19,19,731 | 19,33,021 |
| Communication and postage | 16,95,191 | 15,93,394 |
| Travelling and conveyance | 28,44,921 | 59,90,855 |
| Insurance | 5,63,296 | 3,60,978 |
| Director's sitting fee | - | 2,87,200 |
| Loss on sale of property, plant and equipment | 1,81,33,857 | 2,11,346 |
| Prior period expenses (Refer note 24.3) | 2,52,806 | 33,315 |
| Stipend | 3,00,548 | 2,79,145 |
| Miscellaneous expenses | 26,23,178 | 38,67,906 |
| Decommissiong and commissiong expenses of 1 mw plant | 14,09,144 | - |
| Commission on sale of assets | 4,14,752 | - |
| Water charges | 86,436 | 1,01,755 |
| Operation and maintenance expenses | 46,67,088 | 44,13,355 |
| Service charges on land | 14,20,500 | 14,20,500 |
| Rebate on sale of power | 12,16,532 | 10,48,727 |
| Renewable energy development charges | 5,00,000 | 10,00,000 |
| **Total** | **11,15,04,506** | **14,23,09,012** |

24.1 Rent includes municipal taxes of ₹1,03,07,412/- (previous year: ₹1,03,07,412/-) paid to lessor in terms of lease agreement.

24.2 Auditors remuneration of ₹ 4,35,100/- for the year ended 31st March, 2020 pertains to payment made to previous auditors of holding company.

24.3 Details of prior period expenses are as under :

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| Advertisement and business promotion | 2,25,277 | - |
| Communication and postage | 11,021 | - |
| Travelling and conveyance | 16,108 | - |
| Professional and consultancy charges | 400 | 25,000 |
| Printing and stationery | - | 8,315 |
| | **2,52,806** | **33,315** |

*(This space has been intentionally left blank)*

25 Earnings per share

Basic earnings per equity share have been computed by dividing profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

| Particulars | Year ended 31st March, 2021 (₹) | Year ended 31st March, 2020 (₹) |
|---|---|---|
| a. Profit after tax attributable to equity shareholders | 12,39,58,947 | 3,00,93,409 |
| b. Weighted average of number of equity shares used as denominator for calculating EPS (Nos.) | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| c. Basic/ Diluted Earnings per share (a/b) | 1.24 | 0.30 |
| d. Face value per equity share | 10.00 | 10.00 |

28 Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):

(i) Contingent liabilities
- Claim against the group not acknowledged as debts
- Guarantees issued by the bank on behalf of the group

| | | |
|---|---|---|
| | - | - |
| | - | - |

(ii) Commitments
Estimated amount of contracts remaining to be executed and not provided for:

| | | |
|---|---|---|
| - consultancy contracts for project development activities | | |
| - contracts on capital account | 1,61,58,92,643 | 1,08,92,27,425 |
| - contracts on CSR activities | 2,36,000 | - |
| | - | 70,800 |

(iii) Taxation matters

a) Income tax matters under appeal/ rectification by holding company

| Company | Assessment Year | Refund claimed (₹) | Refund received as per order | Balance refund withheld (₹) | Reason for withheld | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holding | 2017-18 | 52,64,553 | 46,85,504 | 5,79,049 | AO has disallowed the expense of ₹ 17,12,903/- vide order dated 25.12.2019 u/s 143(3) | Appeal has been filed to CIT on 06.01.2020, date of hearing is awaited. |
| | 2018-19 | 49,71,760 | 32,24,650 | 17,47,110 | AO has disallowed the expense of ₹ 4,34,057/- and made addition of income of ₹ 58,89,161/- vide order dated 26.04.2021 u/s 143(3) | Appeal has been filed to CIT on 13.05.2021, date of hearing is awaited |
| | 2019-20 | 97,58,870 | 69,14,080 | 28,44,790 | TDS credit mismatch of ₹ 28,44,790/- in the intimation received u/s 143(1) dated 23.10.2020 | Grievance has been filed on the portal on 19.06.2021, redressal of same is awaited |
| | Total | | | 51,70,949 | | |

b) Income tax matters under appeal by subsidiary company

| Company | Assessment Year | Refund claimed (₹) | Demand Issued (₹) | Reason for demand issued | Last order passed | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidiary | 2017-18 | 1,16,38,420 | 37,01,758 | Disallowance of claim of foreign tax credit and others | u/s 143(3) dated 25th Dec 2019 | Appeal filed u/s 246A with CIT(A) on 6th Jan 2020 |
| | 2018-19 | 219 | 1,00,09,520 | | u/s 143(1) dated 25th Jan 2021 | Appeal filed u/s 246A with CIT(A) on 17th Feb 2021 |
| | Total | | 1,37,11,278 | | | |

The group is contesting these demands and the management including its advisers are of the view that these demands may not be sustainable at the appellate level. The management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the group's financial position and results of operations. The group does not expect any reimbursement in respect of these contingent liabilities, and it is not practicable to estimate the timing of cash outflows, if any, in respect of these matters, pending resolution of the appellant proceedings

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

(iv) The status of legal cases filed against the holding company with no financial implication as at 31 March, 2021 is as under:

| Sr. No. | Writ Petition No. & Date | Petitioners | Respondents | Subject Matter | Brief Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9282/2015 | Sukh Ram & Ors | NICDC Ltd & Ors | Related to Land Acquisition in the State of Rajasthan | Counter affidavit requesting the Court to delete the name of NICDC (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties has been filed with the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench.<br><br>The Petitioners have filed an application for amending the Writ Petition. The said application has been allowed by the Hon'ble High Court.<br><br>The counter affidavit has been submitted by NICDC in respect of the amended Writ Petition also<br><br>An application requesting change of name of Company from DMICDC to NICDC has been filed before the Hon'ble Court on 8th September, 2020.<br><br>Next date of hearing is awaited |
| 2 | 6649/2016 | Irshad Mohd Khan and Ors | NICDC Ltd & Ors | Related to water pipeline laid down from Jayakwadi Dam to Shendra Industrial Park in Aurangabad | An application has been filed before the Hon'ble High Court of Bombay, Aurangabad Bench on 18-01-2019 under Order 1 Rule 10 of Code of Civil Procedure, 1908 requesting the Court to delete the name of NICDC Ltd. (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties on the ground that the applicant is neither a proper party nor a necessary party to the Writ Petition.<br><br>Next date of hearing is awaited |

**27 Disclosures as per Accounting Standard 15 (Revised 2005) on "Employee Benefits":**

a) General description of various defined employee schemes are as under:

**(i) Defined contribution plan**

Provident Fund (PF) - The contribution towards the provident fund is deposited by the holding company with the Regional Provident Fund Commissioner. The amount, so paid, is charged to the consolidated statement of profit and loss

**(ii) Defined benefit plans**

a. Gratuity (unfunded): The group has a defined benefit gratuity plan for its employees. Under the gratuity plan, every employee who has rendered continuous service of at least five years is entitled for gratuity on departure at 15 days of last drawn salary (basic salary and dearness allowance) for each completed year of service subject to a prescribed maximum limit of ₹ 20,00,000/-. The liability towards gratuity arises on superannuation, resignation, termination, disablement or death. The group's obligation in respect of the gratuity plan is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method

b. Leave encashment (unfunded): As per the policy, the employees are entitled to 30 leaves for each calendar year, out of which maximum of 10 leaves can be encashed during the year itself and balance leaves can be carried forward subject to maximum of 90 days accumulated leaves which are non encashable at the time of superannuation, resignation, termination, disablement or death. Accordingly, the group's obligation towards leave encashment is calculated on proportionate leaves for balance period based on amount of basic salary

b) Other disclosures as required under AS-15 (Revised 2005) on Employee Benefits in respect of defined benefit plan are as under:

**i) Defined contribution plan**

Contribution to defined contribution plan, recognised as expense for the year is as under:

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| Employer's contribution to provident fund | 31,04,083 | 27,47,649 |

**ii) Defined benefit plans**

Gratuity (unfunded)

The following tables summarize the components of net benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss, the funded/ unfunded status and amounts recognized in the consolidated balance sheet for defined benefit plan

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Employee benefit expense recognised in the consolidated statement of profit and loss** | | |
| Current service cost | 10,74,105 | 9,14,447 |
| Past service cost | | |
| Interest cost on benefit obligation | 3,16,141 | 2,37,027 |
| Net actuarial (gain)/loss recognized in the year | 4,13,182 | 2,58,578 |
| Employee benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss | 18,03,428 | 14,10,052 |

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Amount recognized in the consolidated balance sheet** | | |
| Present value of defined benefit obligation | 57,82,151 | 46,90,311 |
| Fair value of plan assets | - | - |
| Assets/(liability) recognized in the consolidated balance sheet | 57,82,151 | 46,90,311 |
| **Changes in the present value of the defined benefit obligation** | | |
| Defined benefit obligation at the beginning of the year | 46,90,311 | 35,11,513 |
| Current service cost | 10,74,105 | 9,14,447 |
| Past service cost | - | - |
| Interest cost | 3,16,141 | 2,37,027 |
| Benefits paid | (7,11,588) | (2,31,254) |
| Actuarial (gains)/losses on obligation | 4,13,182 | 2,58,578 |
| Defined benefit obligation at the end of the year | 57,82,151 | 46,90,311 |
| **Breakup of the defined benefit obligation** | | |
| Non-current | 54,02,957 | 42,16,285 |
| Current | 3,79,194 | 4,74,026 |
| | 57,82,151 | 46,90,311 |
| **The principal assumptions used in determining obligations:** | | |
| Method used | Projected unit credit method | |
| Mortality table | IALM 2012-14 | |
| Withdrawal rate upto 30/ 40 years/above 44 years(%) | 8.00% per annum for holding company; 10.00% per annum for subsidiary company | |
| Discount rate (%) | 6.75% per annum (6.50% per annum for subsidiary company) | 6.75% per annum |
| Future salary increase (%) | 6.50% per annum | 6.00% per annum |
| Retirement age (No. of years) | 60 years | |

29 **Segment reporting**

The group has identified two primary business segments viz. power generation and project development division. Segments have been identified and reported taking into account the nature of the services, the differing risks and returns, the organizational structure and internal business reporting system. Further, both the primary segments are operating in same geographical location within the country thus there is no secondary geographical segment.

a Revenue and expenses have been identified to a segment on the basis of relationship to operating activities of the segment.

b Segment assets and segment liabilities represent assets and liabilities of respective segment.

c Information about primary business segments are as under:

| Particulars | Power generation (₹) | Project development (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|
| **Revenue** | | | |
| External revenue | 6,35,11,352 | 31,91,27,082 | 38,26,38,434 |
| | (9,71,25,851) | (22,26,25,936) | (31,97,51,788) |
| Inter-segment revenue | Nil | 23,00,866 | 23,00,866 |
| | (Nil) | (26,16,178) | (26,16,178) |
| Total revenue | 6,35,11,352 | 32,14,27,948 | 38,49,39,300 |
| | (9,71,25,851) | (22,52,42,114) | (32,23,67,966) |
| Add: Allocable other income | Nil | Nil | Nil |
| | (Nil) | (Nil) | (Nil) |
| Segment revenue | 6,35,11,352 | 32,14,27,948 | 38,49,39,300 |
| | (9,71,25,851) | (22,52,42,114) | (32,23,67,966) |
| **Segment result (before depreciation and amortization)** | 2,38,63,862 | 18,72,36,600 | 21,11,00,462 |
| | (2,99,76,130) | (4,74,53,882) | (7,74,30,012) |
| Profit/ Loss[-] before tax | 38,38,577 | 17,85,98,098 | 18,24,34,475 |
| | (17,49,289) | (4,06,30,233) | (4,23,79,522) |
| Tax expenses | 84,53,974 | 5,33,01,900 | 5,97,55,874 |
| | (20,25,149) | (1,22,23,798) | (1,42,48,947) |
| Deferred tax expenses/ write back[-] | 83,988 | -11,50,076 | -10,66,089 |
| | (-8,52,099) | (-6,39,832) | (-14,91,931) |
| Profit/ Loss[-] after tax | -28,99,583 | 12,64,44,273 | 12,35,44,690 |
| | (5,76,229) | (2,90,46,267) | (2,96,22,496) |

*(This space has been intentionally left blank)*

S.P. CHOPRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

**Other information**

| Particulars | Power generation (₹) | Project development (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|
| Segment assets | 30,65,68,500 | 8,45,67,81,887 | 8,76,33,80,387 |
| | (31,07,95,974) | (8,03,57,84,890) | (8,34,65,81,864) |
| Segment liabilities | 9,74,00,226 | 25,25,51,950 | 31,99,52,176 |
| | (6,81,53,808) | (39,13,20,204) | (45,94,74,012) |
| Capital expenditure | 78,284 | 53,63,964 | 54,39,248 |
| | (13,51,338) | (2,72,28,786) | (2,85,78,124) |
| Depreciation and amortization | 7,92,25,485 | 86,40,502 | 2,88,65,887 |
| | (2,82,28,841) | (68,23,646) | (3,50,52,488) |
| Non cash expenses other than depreciation and amortization | 1,82,65,129 | 18,33,856 | 2,01,18,982 |
| | (1,46,393) | (16,80,550) | (18,26,943) |

Note: Figures in bracket () represents previous year's figures

29 **Related party disclosures**

In accordance with the requirements of accounting standard – 18 "Related party disclosure", the names of the related party where control/ ability to exercise significant influence exists, along with the aggregate amounts of transactions and year end balances with them, as identified and certified by the management are given below:

I **List of related parties and nature of relationship where control exists**

a **Enterprises having significant influence/control over the group**
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)

b **Affiliates/ Associates**
Housing and Urban Development Corporation Limited

c **Key Management Personnel (KMP)**

| | |
|---|---|
| Shri K Sanjay Murthy (w.e.f 18th November 2019) | CEO and Managing Director |
| Shri Alkesh Kumar Sharma (till 15th September 2019) | CEO and Managing Director |
| Shri Prashanth Kumar Balsavar (For the period 17th June 2019 to 5th July 2019) | Additional Charge as CEO and Managing Director |
| Shri Rajendra Ratnoo (For the period 19th September 2019 to 17th November 2019) | Additional Charge as CEO and Managing Director |
| Shri P K Agarwal | Chief Financial Officer |
| Shri Abhishek Chauddhary | VP-Corporate Affairs, HR and Company Secretary |
| Shri Srikanth Kommu | Director of subsidiary company |
| Shri Surya Prakash | Company Secretary of subsidiary company |

d **Enterprises over which KMP exercises significant influence**

India International Convention and Exhibition Centre Ltd (For the period 17th June 2019 to 5th July 2019, 28th November 2020 to 13th December 2020 and w.e.f 30th June 2021)

II **The following transactions were carried out with related parties in the ordinary course of business:**

| Particulars | Year ended 31st March,2021 (₹) | Year ended 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Salary/ remuneration** | | |
| Shri K Sanjay Murthy | 56,92,743 | 19,00,183 |
| Shri Alkesh Kumar Sharma | - | 32,30,880 |
| Shri P K Agarwal | 53,82,579 | 51,83,446 |
| Shri Abhishek Chauddhary | 52,88,520 | 50,81,023 |
| Shri Surya Prakash | 7,16,313 | 6,88,449 |
| **Reimbursements** | | |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd | - | 4,232 |
| **Apportionment of overheads** | | |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd. | 6,00,000 | 6,44,305 |
| **Service fee** | | |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd. | - | 1,25,00,000 |

III **Balance outstanding with related parties at the year end**

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| **Trade receivables** | | |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd. | 1,38,12,500 | 1,32,50,000 |
| **Short-term loans and advances** | | |
| India International Convention and Exhibition Centre Ltd. | 6,63,000 | 5,36,000 |
| **Salary/ remuneration payable** | | |
| Shri K Sanjay Murthy | 4,30,066 | 2,03,420 |
| Shri P K Agarwal | 1,03,551 | 1,02,581 |
| Shri Abhishek Chauddhary | 81,754 | 1,20,456 |
| Shri Surya Prakash | - | - |

30 **Operating Lease**

The holding company's significant leasing arrangements are in respect of operating lease relating to its leased office premises at 8th Floor, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi which has been taken on lease for an initial period of 10 years. The aggregate lease rent of ₹ 4,86,03,024/- (Previous year: ₹ 5,66,79,394/- which includes lease rent of ₹ 80,76,370/- towards office space at Ashoka Hotel which has been vacated on 31.05.2020) paid has been recognized in the consolidated statement of profit and loss and disclosed in note 24

S.R. CHOPRA & CO NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

31 Expenditure in foreign currency

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| - Travelling | - | 3,16,704 |
| | - | 3,16,704 |

32 Corporate Social Responsibility (CSR)

As per section 135 of the Companies Act, 2013, Corporate Social Responsibility (CSR) committees have been constituted by the holding and subsidiary company. The amount of ₹ 14,92,484/- (previous year: ₹ 22,84,992/-) is payable towards CSR expenses based on average net profit (calculated as per section 198 of the Companies Act, 2013) of the preceding three financial years. The details of the amount spent/ pending to be spent during the year is as under:

| Particulars | As at 31st March,2021 (₹) | As at 31st March,2020 (₹) |
|---|---|---|
| I Gross amount required to be spent by the group | | |
| Annual CSR allocation | 14,92,484 | 22,84,992 |
| Brought forward from previous year (including unpaid liabilities) | 1,98,222 | 22,26,486 |
| Gross amount required to be spent | 16,90,706 | 45,11,478 |
| II Amount spent during the year | | |
| In cash | | |
| Yet to be paid in cash | 16,90,706 | 43,13,256 |
| | - | 1,98,222 |
| | 16,90,706 | 45,11,478 |
| III Purposes on which CSR expenses has been spent | | |
| Contribution to Prime minister's national relief fund (PMNRF) | | |
| Promotion of education through setting-up of computer lab with e-learning facility | 14,92,484 | 23,00,333 |
| Contribution to a NGO for setting up of digital science lab and language library | 1,09,222 | - |
| Contribution for conducting skill and technical support training | 89,000 | 10,69,000 |
| | - | 9,43,923 |
| | 16,90,706 | 43,13,256 |
| IV Purposes on which CSR expenses is yet to be paid in cash | | |
| Promotion of education through setting-up of computer lab with e-learning facility | - | - |
| Contribution to a NGO for setting up of digital science lab and language library | - | 1,09,222 |
| | - | 89,000 |
| | - | 1,98,222 |

33 In the opinion of the management, the value of assets other than property, plant and equipments and intangible assets on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the consolidated balance sheet. Further, the provision for all known liabilities have been adequately made in the books of accounts.

34 Balances appearing under trade receivables, loans & advances, trade payables and other parties etc. are subject to reconciliation/ confirmation. The impact, if any, subsequent to the confirmation/ reconciliation will be taken in the year of confirmation/ reconciliation, which in view of the management will not be material.

35 Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, GoI, vide OM No. 5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 issued the Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs), as per which, every CPSE is required to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the Net worth, whichever is higher subject to maximum dividend permitted under the extant legal provisions.

DIPAM vide OM no. 5/3/2018-Policy(Vol.II) dated 17th December, 2018 and OM no. 4(30) (1)/2018-DIPAM-I(PI) dated 18th March 2021 granted the exemption to the holding company from above guidelines for the financial year 2017-18 and 2018-19 respectively.

DIPAM vide OM no. 5/3/2018-Policy(Vol.II) dated 17th December, 2018 granted exemption from the above guidelines for the financial year 2017-18 and vide OM no. 4(30) (1)/2018-DIPAM-I(PI) dated 18th March 2021 granted exemption from the above guidelines for the financial year 2018-19 and 2019-20 to the subsidiary company.

The holding company for the financial year 2019-20, has applied to DIPAM through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) on 25th September 2020 for obtaining the approval for exemption from payment of minimum dividend as per the above guidelines, which is awaited till date.

Similarly, the holding and subsidiary companies proposes to apply for obtaining the approval for exemption from the payment of minimum dividend for the FY 2020-21 subsequent to the approval and adoption of the financial statements hence no provision towards payment of dividend has been made in the current financial year.

36 Impact of COVID-19 on the operations of the group

The group has considered the possible effects that may result from the Covid 19 pandemic on the carrying amounts of property, plant and equipment, receivables and other current assets. Based on the current indicators of future economic conditions and also considering the nature of its business, management estimates that the carrying amount of these assets will be recovered and sufficient liquidity is available to fund the business operations for at least another 12 months thus the operations of the group are not likely to be impacted adversely by COVID-19 pandemic.

37 The group's wholly owned subsidiary companies namely DMICDC Guna Power Company Limited, DMICDC Indapur Power Company Limited, DMICDC Vaghal Power Company Limited and DMICDC Vile Bhagad Power Company Limited have been winded up and their names have been struck off from the Register of Companies with effect from 09.08.2018 vide Notice no. ROC/DE:JD/246(3)/STK/74693 dated 9th August, 2018.

On the aforesaid date, the equity shares held by the group in these subsidiaries were valued on the basis of their assets and results as per financial statements of respective subsidiaries and loss towards diminution in investments of ₹ 20,00,000/- was recognized under project development expenses during the financial years 2016-17 and 2017-18. Since the amount is not recoverable, the said amount, during the year, has been transferred to the capital reserve in accordance with the accounting policy no. 2.7.1.

38 In terms of article 16 of the Memorandum of Understanding (MOU) executed amongst New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) of Japan, Government of Japan, Ministry of Finance, Government of India, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India and the holding company, PV modules, PCSs with related equipment, control servers for micro grid control, telecommunication systems and other ancillary equipment's are provided by NEDO as grant-in-aid.

In terms of same article, during the implementation of project, the ownership of the equipments provided by NEDO shall belong to NEDO. Thereafter, on completion of the project and on transfer of ownership with all bonafide rights, these equipments are accounted at a nominal value of ₹ 1/- which is in accordance with the accounting standard-12 for Government Grants.

S.P. CHOPRA & CO. NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

38 **Power purchase agreements**

The subsidiary company has executed the following power purchase agreements (PPAs) for sale of power :

(i) With NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVN), New Delhi on 05.06.2015 for sale of solar power from 5 MW solar power plant for a period of 25 years at a tariff of ₹ 8.77/ kwh.

(ii) With Mikuni India Pvt Ltd. (MIPL), a company having their plant at Neemrana on 17.05.2016 for sale of power from 1 MW integrated power plant generating solar power with power generated from diesel generators for a period of 10 years at a unit price of ₹ 11.99/ kwh in mediation with New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan.

Due to rising cost of power generation and refusal of MIPL to increase the power supply rate, the PPA, after successful completion of the demonstration period and with the permission of NEDO, has been mutually foreclosed on 20.02.2020.

(iii) After the foreclosure of the PPA as per Note 39 (ii) above, another PPA has been executed on 12.02.2020 with M/S Toyoda Gosei Minda India Private Limited (TGMIPL) , a Company having their plant at Neemrana for supply of power from 1MW solar power plant, for a period of 10 (Ten) years from the date of commencement of supply of solar power which may be extended for a further period of 10 (Ten) years as per mutual agreed terms and conditions. The Unit price of power supply shall remain fixed at ₹ 4.60 / kWh for a period of first 5 years from the date when the subsidiary company commences to supply solar power to TGMIPL. The power supply rate shall be revised upward at the beginning of sixth year at mutual agreed terms and conditions.

With reference to the PPA signed with TGMIPL for third party sale of solar power under Rajasthan Solar Energy Policy, 2019, the subsidiary company has registered itself with Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL), Rajasthan state government nodal agency. As a result, there is change in the power evacuation scheme from direct supply to supply through state grid of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited (JVVNL) to the power purchaser.

Due to the change in power evacuation scheme, the assets which were no longer in use have been disposed off by e-auction process through MSTC Limited, a Government of India enterprise under the control of Ministry of Steel, Government of India.

40 **Change in accounting policy by subsidiary company**

Due to change in accounting policy no. 2.4.xiv, in accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), the written down value of landscaping and horticulture works amounting to ₹ 5,55,310/- as on 31st March 2020 is charged off from Reserve and Surplus. Due to change in accounting policy, depreciation amount of ₹ 2,52,058/- is not charged off from profit and loss of the current financial year. As a result, the profit of the subsidiary company for the current financial year has increased by ₹ 2,52,058/-.

41 Additional information, as required under Schedule III to the Companies Act, 2013, of enterprises consolidated as subsidiary

| Name of the Company | Net assets, i.e. total assets minus total liabilities | | Share in profit/ loss | |
|---|---|---|---|---|
| | As % of consolidated net assets | Amount (₹) | As % of consolidated profit/ loss | Amount (₹) |
| **Parent** | | | | |
| National Industrial Corridor Development Corporation Limited (Formerly Known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) | 98.71 | 8,20,74,48,365 | 100.15 | 12,41,43,433 |
| **Wholly owned Indian subsidiary** | | | | |
| NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) | 1.29 | 10,75,92,068 | (0.15) | (1,84,567) |

42 Previous year figures have been regrouped/ rearranged, wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

As per our Report of even date attached
For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

(Partner)
(Membership No. 099143)

Place: New Delhi
Date : 10th August, 2021

UDIN: 21099143AAAAC21696

For and on behalf of Board of Directors of
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Dr. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(Rajendra Kumar)
Director
(DIN : 02855304)

(P.K. Agarwal)
(Chief Financial Officer)

(Abhishek Chaudhary)
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

**National Industrial Corridor Development Corporation Limited**
**(Formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)**

## FORM AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of Section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)
**Statement containing salient features of the financial statements of subsidiaries, associate companies and joint ventures as per the Companies Act, 2013**

**Part A : Subsidiaries**

| S.No. | Name of the Subsidiary | NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) |
|---|---|---|
| 1 | The date since when subsidiary was acquired | 18th March, 2014 |
| 2 | Reporting period for the subsidiary concerned, if any different from the holding company's reporting period | Same as that of the holding company |
| 3 | Reporting Currency | Indian Rupee |
| 4 | Share Capital | 13,00,00,000 |
| 5 | Reserves & surplus | 10,91,98,274 |
| 6 | Total Assets | 30,65,98,500 |
| 7 | Total Liabilities | 6,74,00,226 |
| 8 | Investments | Nil |
| 9 | Turnover | 6,14,34,377 |
| 10 | Profit / (Loss) before taxation | 36,38,377 |
| 11 | Provision for taxation | 65,37,960 |
| 12 | Profit / (Loss) after taxation | (28,99,583) |
| 13 | Proposed Dividend | Nil |
| 14 | % of shareholding | 100% |

**Part B: Associates / Joint Ventures**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations | Nil |
| 2. | Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year | Nil |
| | | |

**For and on behalf of Board of Directors of**
National Industrial Corridor Development Corporation Limited

**(K. Sanjay Murthy)**
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

**(Rajendra Ratnoo)**
Director
(DIN : 02855304)

**(P.K. Agarwal)**
(Chief Financial Officer)

**(Abhishek Chauddhary)**
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

Place: New Delhi
Date: 10th August, 2021




**NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**

**(*formerly* Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)**

CIN: U45400DL2008PLC172316
8th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building, 124,
Connaught Place, New Delhi – 110001.
Tel No.: 011-23317884-8, Fax: 011-23317889
Website: www.nicdc.in
Email: contactus@nicdc.in